वर्ष 19
अंक 174
20 पृष्ठ
मूल्य 5 रुपये

सोमवार, 7 सितंबर 2026

कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, **नई दिल्ली**, भोपाल, मुंबई और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड

पार्थो बनर्जी ▸▸ पृष्ठ 2

मारुति का प्रीमियम हैचबैक पर दांव

राजीव लक्ष्मण करंदीकर ▸▸ पृष्ठ 4

'जीडीपी आंकड़ों में भरोसे की कमी है राजनीतिक मुद्दा'

एक नज़र

गारंटीड रिटर्न वाली पेंशन योजना पर विचार

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एक ऐसी पेंशन योजना शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है जिसमें गारंटीड रिटर्न की पेशकश की जाएगी। लेकिन यह प्रस्ताव अभी भी चर्चा के दौर में है क्योंकि गारंटीड भुगतान की सुविधा देने के लिए कोष प्रबंधकों को बाजार जोखिम से बचाव (हेजिंग) करना होगा। अभी पेंशन फंडों को केवल डेरिवेटिव तक सीमित और सशर्त पहुंच की इजाजत है। पृष्ठ 4

कच्चे तेल के दाम तय करेंगे बाजार का रुख

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अमेरिका के महंगाई के आंकड़े इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय करेंगे। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और वैश्विक बाजारों का रुख भी बाजार की दिशा को प्रभावित करेगा। निवेशकों की नजर अमेरिका के उम्मीद से बेहतर रोजगार आंकड़ों के बाद फेडरल रिजर्व की सितंबर में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक को लेकर बदलती उम्मीदों पर रहेगी।

सागर में जहरीली शराब से 10 की मौत

मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील में जहरीली शराब पीने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 35 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया जबकि एक अधिकारी को मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। घटना सागर जिले के बंडा तहसील के गोगरा खुर्द, नौरोज, और पाटन गांवों में हुई।

दिल्ली: 5 मंजिला इमारत ढही, 3 छात्रों की मौत

दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के पास सत्य निकेतन की एक संकरी गली में छात्रावास के रूप में इस्तेमाल हो रही 50 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत रविवार अपराह्न ढह गई। इस हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। पुलिस ने बताया कि मलबे से अब तक 8 लोगों को निकाला गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मलबे के नीचे अब भी लगभग 40 से 50 लोग फंसे हो सकते हैं।

एमएफ में घटा खुदरा निवेशकों का हिस्सा

अभिषेक कुमार
मुंबई, 6 सितंबर

म्युचुअल फंड (एमएफ) द्वारा संभाली जाने वाली परिसंपत्तियों (एयूएम) में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार दूसरे साल घटी है। ऐसा तब हुआ जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में कुल निवेश धीरे-धीरे बढ़ रहा था। असल में शेयर बाजार के कमजोर प्रदर्शन की वजह से खुदरा निवेशकों के निवेश मूल्य में कमी आई है। दूसरी ओर एमएफ के एयूएम में धनाढ्य या अमीर निवेशकों (एचएनआई) की हिस्सेदारी बढ़ी है। बेशक वह इजाफा मामूली ही है।

म्युचुअल फंड की संस्था एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में एमएफ की कुल परिसंपत्तियों में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी 59.5 फीसदी रही जो मार्च 2024 में 62.2 फीसदी थी। इससे पहले कई वर्षों तक खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही थी।

यह गिरावट शेयर बाजार के कमजोर प्रदर्शन के साथ आई। खुदरा निवेशकों का शेयरों वाली परिसंपत्तियों में निवेश ज्यादा होता है इसलिए उन पर इसका असर ज्यादा पड़ा। सितंबर 2024 के बाद बाजार में उतार-चढ़ाव और गिरावट के कारण खुदरा निवेशकों को मार्क-टु-मार्केट नुकसान हुआ जिससे निवेशकों की दिलचस्पी कम हो गई।

मार्च 2024 तक के दो वर्षों में निफ्टी 50 में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 250 में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और निफ्टी मिडकैप 150 में 6 फीसदी की बढ़त हुई। इस साल स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में जबरदस्त रिकवरी देखी गई। हालांकि सितंबर 2024 से मार्च 2026 के बीच स्मॉलकैप शेयरों में उतार-चढ़ाव बना रहा। मार्च 2026 तक के दो वर्षों में निफ्टी स्मॉलकैप 250 ने 1 फीसदी से भी कम रिटर्न दिया।

मास्टर कैपिटल सर्विसेज की परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई में एवीपी आकांक्षा शुक्ला ने कहा, 'म्युचुअल फंड एयूएम में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी में गिरावट का अर्थ यह नहीं है कि खुदरा भागीदारी कम हुई है। इसका एक बड़ा हिस्सा बाजार की चाल को दर्शाता है। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट का असर खुदरा निवेशकों के अधिक हिस्सेदारी वाले पोर्टफोलियो पर संस्थागत निवेश की तुलना में ज्यादा पड़ा है।'

(शेष पृष्ठ 3 पर)

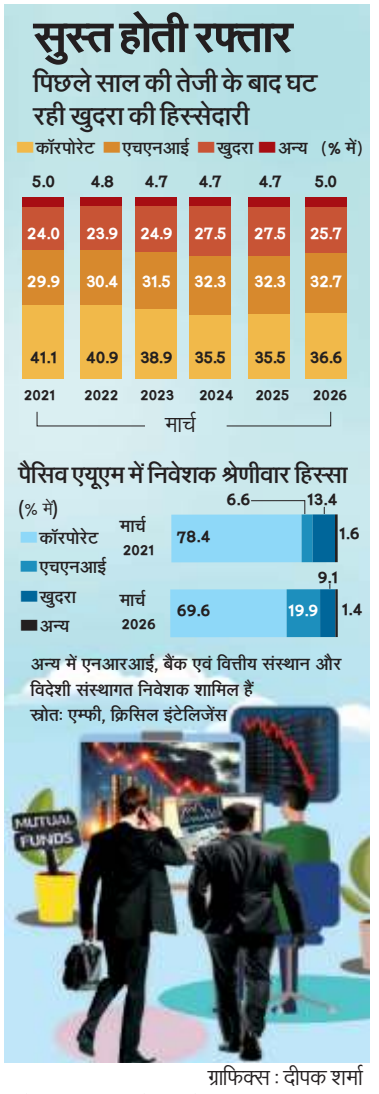

ग्राफिक्स : दीपक शर्मा

सवाल जवाब

भारत को आकर्षक बनाएगा नवाचार परिवेश

स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी नोवार्टिस एजी भारत में अपनी अत्याधुनिक नवाचार रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यहां उसका एक बड़ा अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) केंद्र इसी साल अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने पारंपरिक जेनेरिक दवा कारोबार से हटकर नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी वैश्विक रणनीति के तहत अपनी भारतीय सूचीबद्ध कंपनी नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड से बाहर निकलने की घोषणा की थी। नोवार्टिस की अध्यक्ष (एशिया-प्रशांत, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) जूडिथ लव और नोवार्टिस इंडिया के कंट्री प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक अमिताभ दुबे ने संकेत कौल और निवेदिता मुखर्जी से खास बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पेश हैं मुख्य अंशः

भारत में नोवार्टिस की प्राथमिकताएं क्या हैं और पिछले तमाम वर्षों के दौरान उनमें क्या बदलाव आया है?

जूडिथ लवः नोवार्टिस कई वर्षों से भारत के प्रति प्रतिबद्ध है। हम 1947 से ही भारत में मौजूद हैं। हम भारत में अपना वैश्विक कॉरपोरेट केंद्र खोलने वाली शुरुआती कंपनियों में थे और वह प्रतिबद्धता आज भी जारी है। इस साल हम अपने केंद्र की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक संगठन के रूप में हमारी प्रतिबद्धता नहीं बदली है। मगर अब हमें भारत के रणनीतिक महत्त्व और इसकी व्यापक संभावनाओं का पहले से अधिक एहसास हुआ है। भारत की आबादी बहुत बड़ी है, गैर-संचारी रोग (एनसीडी) बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और कई हितधारक नवाचार के लिए भारत के माहौल को अधिक अनुकूल बनाने के पक्ष में हैं। इन सब कारणों से भारत अब हमारे लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है जो पहले से भी महत्त्वपूर्ण था।

नोवार्टिस इंडिया से बाहर निकलने का फैसला क्यों लिया गया?

जूडिथ लवः यह फैसला इस बात से कम जुड़ा है कि कंपनी हमारे लिए सही है या नहीं। मुख्य बात यह है कि रणनीतिक रूप से हमें सबसे बड़ी जरूरत कहां पूरी करनी है। हमारे लिए वह जरूरत नवाचार को भारत तक पहुंचाना है। नोवार्टिस का मूल मंत्र है दवाओं की नई परिकल्पना। हम कैंसर के उपचार, हृदयरोग एवं कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोसाइंस और इम्यूनोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बेहद नवीन और अपनी श्रेणी की पहली दवाओं पर काम करते हैं। यही हमारा मुख्य फोकस बन गया है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये नई दवाएं उन मरीजों तक पहुंचें जिन्हें इनकी सबसे अधिक जरूरत है। भारत में बीमारी का सबसे बड़ा बोझ हृदयरोग और कैंसर का है। इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे अधिक नवाचार की जरूरत है।

क्या नोवार्टिस इंडिया से बाहर निकलने के फैसले पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है?

जूडिथ लवः नहीं, क्योंकि भारत में हमारी कई भारतीय कंपनियों के साथ बहुत अच्छी साझेदारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने उत्पाद भारत से हटा रहे हैं। हम अपने उत्पाद भारतीय मरीजों तक पहुंचा रहे हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी के जरिये। इसलिए इस फैसले को वापस लेने की हमारी कोई योजना नहीं है।

अमिताभ दुबेः मैं इसे सिर्फ कंपनी से बाहर निकलना या विनिवेश नहीं कहूंगा। यह एक ऐसी साझेदारी थी जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिला। हमारी रणनीति नवाचार पर केंद्रित रहना है। हम अब पूरी तरह नवाचार पर आधारित कंपनी हैं। भारत में अन्य कंपनियों की अपनी विशेष ताकत है। उनके जरिये हमारे उत्पाद मरीजों तक पहुंच सकते हैं।

जूडिथ लवः इससे दोनों कंपनियां अपने-अपने क्षेत्र पर बेहतर ध्यान दे सकती हैं और अंततः अधिक मरीजों को लाभ मिल सकता है। यही हमारा उद्देश्य है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

'बंगाल बेकंस' में दिखेगी औद्योगिक रूपरेखा की झलक

बीएस संवाददाता
कोलकाता, 6 सितंबर

क्या पश्चिम बंगाल अपनी बहुचर्चित क्षमता को सतत आर्थिक वृद्धि और तेज औद्योगीकरण में बदल पाएगा? राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता के समक्ष इस मार्ग को सुगम बनाने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। सोमवार को यहां होने वाले बिज़नेस स्टैंडर्ड राउंडटेबल के पहले संस्करण 'बंगाल बेकंस' में सबकी निगाहें दासगुप्ता पर होंगी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बनी सरकार के नेतृत्व में पचिम बंगाल में औद्योगिक पुनरुद्धार से निवेशकों को काफी उम्मीदें हैं।

दासगुप्ता कार्यक्रम के उद्घाटन भाषण और उसके बाद होने वाली फायरसाइड चैट के दौरान इसकी रूपरेखा की झलक पेश करेंगे। इसके बाद एक पैनल चर्चा होगी जिसमें बंगाल से गहराई से जुड़े दो उद्योगपति शिरकत करेंगे। इनमें से एक टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक उमेश चौधरी हैं, जिन्होंने राज्य में मजबूत विनिर्माण आधार बनाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके साथ लक्ष्मी समूह के प्रबंध निदेशक और ओबीटी के चेयरमैन रुद्र चटर्जी चर्चा करेंगे। इनके साथ अभिरूप सरकार भी पैनल में शामिल होंगे, जिन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय से करीबी नजर रखी है। भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक आर. नटराजन भी पैनल में अपने विचार रखेंगे।

कार्यक्रम का समापन स्पेशियलिटी रेस्टोरेंट्स के संस्थापक, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अंजन चटर्जी के साथ फायरसाइड चैट से होगा।

बिज़नेस स्टैंडर्ड राउंडटेबल

स्वप्न दासगुप्ता
वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल

नेपाल में बाढ़ से व्यापार व पर्यटन पर असर

सिद्धार्थ कलहंस
लखनऊ, 6 सितंबर

बाढ़ की आपदा से नेपाल में हजारों की जान गई है तो पड़ोसी देश भारत पर भी इस विपदा का असर पड़ा है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों से इस पहाड़ी देश के साथ करोड़ों रुपये का कारोबार होता है, जो इस समय लगभग ठप हो गया है। नेपाल में पर्यटन का सीजन शुरू हो रहा है, जब काफी भारतीय सैलानी वहां जाते हैं मगर हादसों की आशंका में पर्यटक बुकिंग रद्द करा रहे हैं। काठमांडू तथा पोखरा जैसे लोकप्रिय गंतव्यों का रुख करने वाले पर्यटकों की तादाद न के बराबर रह गई है।

नेपाल में सड़क और पुलों को नुकसान पहुंचने के कारण मालवाहक वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। इससे भारतीय निर्यातकों और ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेपाल की सीमा से सटे टनकपुर, पीलीभीत और बरेली से करोड़ों रुपये का माल वहां जाता है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि बरेली से नेपाल को हर महीने करीब 10 करोड़ रुपये का सामान निर्यात होता है मगर आपदा के कारण इस पर बहुत असर पड़ा है। नेपाल के व्यापारियों ने कई पुराने ऑर्डर रद्द कर दिए हैं या माल कुछ समय रुककर भेजने को कहा है। उनकी आपूर्ति आगे बढ़ा दी है।

गुप्ता के मुताबिक नेपाल के व्यापारी माल खरीदने अक्सर बरेली आते हैं और यहां से मसाले, खाद्य तेल, चीनी, आटा, चावल, दाल तथा लोहे का सामान नेपाल भेजा जाता है। बाढ़ की वजह से नेपाल के मैदानी और पहाड़ी इलाकों से संपर्क काफी कट गया है, जिससे माल भी नहीं जा रहा है।

बरेली से टनकपुर होते हुए नेपाल के महेंद्रनगर बॉर्डर तक की दूरी करीब 110 किलोमीटर है और दोनों देशों के बीच माल की ज्यादातर आवाजाही इसी रास्ते से होती है। मगर बरेली के ट्रांसपोर्टर राम कृष्ण शुक्ला ने बताया कि नेपाल में बाढ़ की वजह से कई ट्रक रास्ते में फंसे हैं। ट्रक खड़े रहने से ट्रांसपोर्टरों पर बेजा खर्च पड़ रहा है और नुकसान हो रहा है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

...ठप हुई माल की आवाजाही

- उत्तर प्रदेश से हर महीने करोड़ों रुपये का सामान नेपाल भेजा जाता है मगर बाढ़ के कारण निर्यात ठप पड़ गया है
- पोखरा व काठमांडू जाने वाले सैलानी जोखिम की आशंका में रद्द करा रहे अपनी बुकिंग
- माल के ट्रक सीमा पर फंस जाने से ट्रांसपोर्टरों को हो रहा नुकसान
- उत्तर प्रदेश से सब्जी, फल, अनाज, मसाले, खाद्य तेल और लोहे का सामान बड़ी मात्रा में भेजा जाता है नेपाल

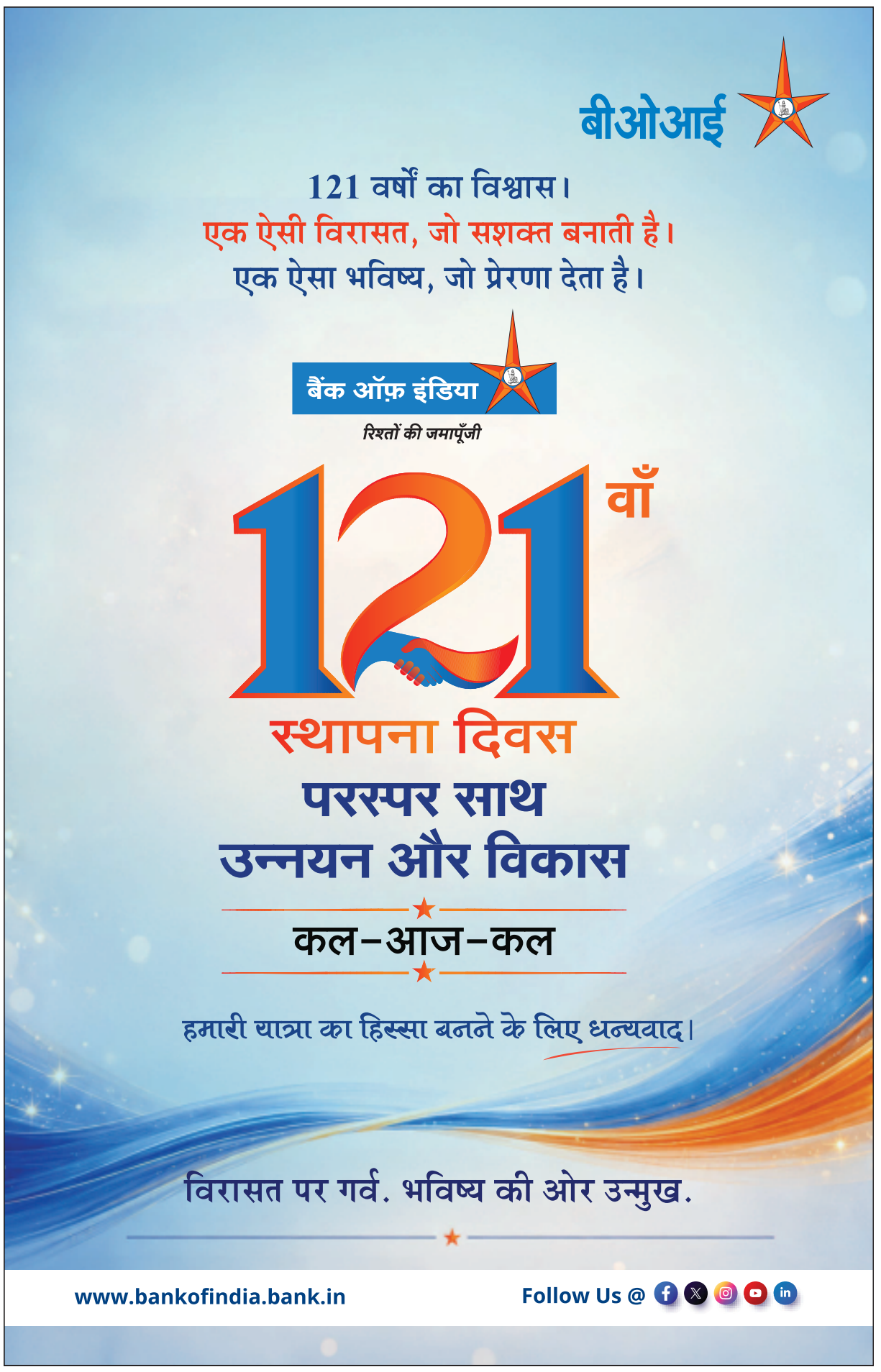

संक्षेप में

पश्चिम बंगाल की 2 फर्मों के लाइसेंस रद्द

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने स्वच्छता और साफ-सफाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पश्चिम बंगाल की कैलाश फॉर्मुलेशन और सैनेक्योर वाटर प्रोजेक्ट नामक दो कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इन दोनों कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। नियामक ने कहा, 'दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में चलाए गए प्रवर्तन अभियान में स्वच्छता, साफ-सफाई और अनुपालन संबंधी गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद कैलाश फॉर्मुलेशन और सैनेक्योर वाटर प्रोजेक्ट के एफएसएसएआई लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।' *भाषा*

शैले होटल्स का 5,500 कमरों का लक्ष्य

अतिथि-सत्कार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी शैले होटल्स लिमिटेड का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने कमरों की संख्या बढ़ाकर लगभग 5,500 करने का है। शैले होटल्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्य अधिकारी श्वेतांक सिंह ने बताया कि कंपनी अपने पारंपरिक परिसंपत्ति-स्वामित्व मॉडल से आगे बढ़कर यह विस्तार कर रही है। यह विस्तार शैले के व्यावसायिक मॉडल में आए बदलाव को दर्शाता है। *भाषा*

मारुति: प्रीमियम हैचबैक पर दांव

चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में इस श्रेणी ने समूचे उद्योग की तुलना में तेज इजाफा दर्ज किया

अंजलि सिंह
मुंबई, 6 सितंबर

पार्थो बनर्जी
वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन और बिक्री)
मारुति सुजूकी इंडिया

मारुति सुजूकी इंडिया प्रीमियम हैचबैक की अहमियत बरकरार रहने पर दांव लगा रही है। हालांकि यात्री वाहन बाजार में स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) का दबदबा बढ़ रहा है। यह ऐसे समय हो रहा है, जब चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीने के दौरान प्रीमियम हैचबैक श्रेणी ने समूचे उद्योग की तुलना में तेज इजाफा दर्ज किया है।

मारुति सुजूकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन और बिक्री) पार्थो बनर्जी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि फिलहाल प्रीमियम हैचबैक उद्योग का स्तर हर महीने लगभग 50,000 वाहन होने का अनुमान है और इस श्रेणी में मारुति सुजूकी की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है।

बनर्जी ने कहा कि मारुति की प्रीमियम हैचबैक बिक्री अप्रैल और अगस्त के बीच 28 प्रतिशत बढ़ी, जबकि उद्योग की वृद्धि 17 प्रतिशत रही। कंपनी नई बलेनो के साथ अपनी स्थिति और मजबूत करना चाह रही है। इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) समेत कई नई खूबियां हैं।

कंपनी को उम्मीद है कि साल 2030 तक देश में यात्री वाहनों का समूचा बाजार 61 लाख से 63 लाख वाहनों तक पहुंच जाएगा। अनुमान है कि तब तक बाजार में एसयूवी की हिस्सेदारी 62 से 63 प्रतिशत होगी, जबकि हैचबैक और मल्टी-पर्पज व्हीकल (एमपीवी) के लिए लगभग 37 से 38 प्रतिशत हिस्सेदारी ही बचेगी।

बनर्जी ने कहा, 'हमारा मानना है कि यह उद्योग लगभग 63 लाख वाहनों का होगा।' उन्होंने यह भी कहा कि मारुति को गैर-एसयूवी श्रेणी में काफी गुंजाइश दिख रही है। कंपनी का अनुमान है कि साल 2030 तक यह बाजार लगभग 25 लाख वाहनों तक पहुंच सकता है, जबकि इस क्षेत्र में उसका अपना कारोबार मौजूदा लगभग 6 लाख वाहनों से दोगुना बढ़कर 12 लाख वाहनों तक हो सकता है।

फिलहाल मारुति हर महीने लगभग 16,000 से 16,500 बलेनो बेचती है। उसकी फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर की लगभग 17,000 से 18,000 गाड़ियां बिकती हैं। दोनों मॉडल एक ही प्रोडक्शन लाइन पर बनाए जाते हैं। साथ ही कंपनी दोनों मॉडलों की प्रतीक्षा अवधि के आधार पर इनका उत्पादन घटाती-बढ़ाती है। कंपनी ने इस सप्ताहांत लगभग 6.1 लाख रुपये से शुरू होने वाली नई बलेनो बाजार में उतारेगी।

बढ़ेगी बाजार हिस्सेदारी

- प्रीमियम हैचबैक उद्योग की दर अनुमानित रूप से लगभग **50,000** वाहन प्रति माह है और इस श्रेणी में मारुति की हिस्सेदारी करीब **70** प्रतिशत है
- मारुति की प्रीमियम हैचबैक बिक्री अप्रैल और अगस्त के बीच **28** प्रतिशत बढ़ी, जबकि उद्योग की वृद्धि **17** प्रतिशत रही
- नई बलेनो के साथ अपनी स्थिति और मजबूत करना चाह रही है कंपनी, जिसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम समेत शामिल हैं कई खूबियां
- कंपनी को उम्मीद है कि साल 2030 तक देश में यात्री वाहनों का समूचा बाजार **61** लाख से **63** लाख वाहनों तक पहुंच जाएगा

डीमर्जर के बाद की तैयारी

एचईजी करेगी 5,500 करोड़ का पूंजीगत खर्च

सोहिनी दास
मुंबई, 6 सितंबर

एचईजी एडवांस्ड मैटेरियल्स डीमर्जर के बाद अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की योजना बना रही है। इसमें सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड मैटेरियल्स को वृद्धि के लिए सबसे अहम माना जा रहा है।

कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और ऊर्जा भंडारण से जुड़ी मांग को पूरा करने पर ध्यान दे रही है। एचईजी की योजना है कि वह वित्त वर्ष 2032 तक एनोड मैटेरियल की क्षमता को शुरुआती 20,000 टन से बढ़ाकर 60,000 टन करे। साथ ही, वह अपने बैटरी एनर्जी सॉल्यूशंस और ग्रीन-पावर बिजनेस का भी विस्तार करेगी। योजनाबद्ध निवेश में एनोड बिजनेस का हिस्सा सबसे ज्यादा होगा।

बिज़नेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए कंपनी के चेयरमैन, एमडी और सीईओ ऋजु झुनझुनवाला ने कहा, 'इस डीमर्जर का मकसद वैल्यू हासिल करना, निवेशकों को हर बिजनेस लाइन तक केंद्रित पहुंच देना और शेयरधारकों के लिए मूल्य बढ़ाना है।' उन्होंने कहा, 'इससे अलग हुई कंपनियों को बेहतर फंडिंग स्वायत्तता और एक खास व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा भी मिलेगी।' एचईजी लगभग 5,500 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये (इक्विटी के जरिये) और 4,000 करोड़ रुपये कर्ज से जुटाने की योजना बना रही है, जो 27:73 का अनुपात होगा। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक स्थिर रिटर्न हासिल करना है। इसमें नियोजित पूंजी पर प्रतिफल लगभग 17 प्रतिशत होगा।

एनोड मैटेरियल की क्षमता 60,000 टन करने की योजना बना रही कंपनी

सबसे पहले एनोड बिजनेस को वाणिज्यिक स्तर पर लाने पर ध्यान दिया जाएगा। 20,000 टन क्षमता वाले पहले चरण का काम चल रहा है और वित्त वर्ष 2028 की पहली तिमाही में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। इंजीनियरिंग का काम पूरा हो चुका है और खरीद का 85 फीसदी काम भी हो गया है। साथ ही, बाद में इस संयंत्र की क्षमता को बढ़ाकर 30,000 टन किया जा सकता है। कंपनी पिछले 12 महीनों से मध्य प्रदेश के मंडीदीप में 200 टन का डेमोंस्ट्रेशन प्लांट का भी संचालन कर रही है।

आरपीजी लाइफ की नजर बड़ी एपीआई परिसंपत्तियों पर

सोहिनी दास
मुंबई, 6 सितंबर

आरपीजी लाइफ साइंसेज पांच सप्ताहों में दो अधिग्रहणों पर लगभग 215 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद अब बड़ी ऐक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट (एपीआई) परिसंपत्तियों की तलाश कर रही है। यह दवा कंपनी अपने एपीआई व्यवसाय को तेजी से बढ़ाना और विदेशी बाजारों में अपनी मौजूदगी का विस्तार करना चाहती है।

प्रबंध निदेशक अशोक नायर ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हमारे पास 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी है और हम अपने एपीआई व्यवसाय को मजबूत करने के मौकों पर तेजी से विचार कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि कंपनी खास तौर पर ऐसे व्यवसाय पर विचार कर रही है जो अलग तरह की केमिस्ट्री, नियामकीय पहुंच और अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (यूएसएफडीए) से मंजूर क्षमताएं जोड़ सकें।

नायर ने कहा कि आगे होने वाले सौदों का समय पहले से तय अधिग्रहण की संख्या के बजाय रणनीतिक तालमेल, मूल्यांकन, समेकन की तैयारी और रिटर्न पर निर्भर करेगा।

आरपीजी लाइफ साइंसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई आरपीजी ऐक्टिव फार्मा (आरपीजीएपी) ने पिछले सप्ताह राघव लाइफ साइंसेज के एपीआई और इंटरमीडिएट्स बिजनेस को लगभग 135 करोड़ रुपये में खरीदने का फैसला किया। इससे पहले 29 जुलाई को उसने लगभग 80 करोड़ रुपये में एक्टिस जेनेरिक्स का अधिग्रहण किया था, जिससे सौदों की कुल कीमत लगभग 215 करोड़ रुपये हो गई। आरपीजी ने राघव के साथ हुई इस डील को एक बड़े और समेकित एपीआई बिजनेस बनाने की 'बाय-ऐंड-बिल्ड' रणनीति का हिस्सा बताया है।

इन दो सौदों ने व्यवसाय की दिशा बदली है। नायर के अनुसार आरपीजीएपी की निर्माण क्षमता 110 किलोलीटर (केएल) से बढ़कर 505 केएल हो गई है। उसके उत्पाद पोर्टफोलियो में 14 से 45 उत्पाद शामिल हो गए हैं और ग्राहक आधार 123 से बढ़कर 250 से ज्यादा हो गया है।

अशोक सूटा : एक उद्यमी, काम के धुनी

अभीक दास
बेंगलूरु, 6 सितंबर

एक के बाद एक नया कारोबार स्थापित करने वाले ज्यादातर उद्यमी जब 83 साल की उम्र में आराम करना, सक्रिय कार्यों से हटना और अपनी जिंदगी भर की मेहनत के फल का आनंद लेना पसंद करते हैं, ऐसे समय में भी अशोक सूटा अलग ही राह चुन रहे हैं। स्वास्थ्य और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रति जुनूनी 80 से ज्यादा उम्र वाले अशोक सूटा ने हाल में अपनी दूसरी कंपनी हैपिएस्ट माइंड्स में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी आईटीसी इन्फोटेक को बेचने का ऐलान किया है। सूटा हैपिएस्ट माइंड्स के नियंत्रक प्रवर्तक का पद छोड़ रहे हैं और उस कंपनी की हिस्सेदारी बेच रहे हैं जिसे उन्होंने साल 2011 में स्थापित किया और साल 2020 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया था। कंपनी 110 प्रतिशत के प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुई थी।

लगातार नए उद्यम स्थापित करने वाले सूटा अब अपनी डायग्नोस्टिक हेल्थकेयर और वेलनेस कंपनी हैपिएस्ट हेल्थ और बिना लाभ वाले चिकित्सा अनुसंधान ट्रस्ट स्कैन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

सूटा हैपिएस्ट माइंड्स में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी आईटीसी इन्फोटेक को बेचकर मिलने वाले पैसे से अपने दो उद्यमों का विस्तार करना चाहते हैं। इन्हें साल 2021 और 2022 के बीच शुरू किया गया था। इस सौदे के तहत उनकी लगभग 22.1 प्रतिशत हिस्सेदारी दो चरणों में 1,300 करोड़ रुपये नकद में आईटीसी की सहायक कंपनी को हस्तांतरित की जा रही है। विलय के बाद बनने वाली कंपनी में 7.55 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वह अल्पांश शेयरधारक बन जाएंगे।

यह तुरंत नहीं पता चल सका कि इस कमाई का कितना हिस्सा इन दो उद्यमों को जाएगा। मंगलवार को हुए संवाददाता सम्मेलन में वह शामिल नहीं थे।

मुथूट हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः टीसी नं. 14/2074–7, मुथूट सेन्टर, पुन्नेन रोड, थिरुवंतपुरम–695034, सीआईएन नं.: U65922KL2010PLC025624, कारपोरेट कार्यालयः 12/ए 01, 13वाँ तल, परिनी क्रिसेन्जो, प्लाट नं. सी38 एवं सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स–जी ब्लॉक (ईस्ट), मुंबई–400051 फोन नं.: 022–62728517, ईमेल आईडीः authorised.officer@muthoot.com

परिशिष्ट—IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि मेसर्स मुथूट हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 (2002 का अधिनियम नं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर एक मांग सूचना निम्नलिखित कर्जदार/ओं/जमानती/ओं को जारी की। उक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिनों की समाप्ति के बाद कर्जदार/ओं/जमानती/ओं द्वारा राशि चुकता करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार/ओं/जमानती/ओं और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती का नाम	मांग सूचना की तारीख	कुल बकाया राशि (रु.) लागू भविष्य की ब्याज	कब्जे की तारीख
1.	LAN No. 15100117288 & 15100124396 1. श्री जीवन पांडे, 2. श्रीमती अनुपमा पांडे	11 जून, 2026	रु. 13,37,979.07/– और रु. 1,53,175.38/– दि. 11 जून, 2026 को	01 सितंबर, 2026
	प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(ओं) का विवरणः आवासीय मकान प्लॉट नंबर 32–बी पर निर्मित, खसरा नंबर 273, वार्ड नंबर 0172, "खाटू श्याम एन्कलेव–II", गाँव दुहाई, परगना जलालबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201006, एरिया माप 63.33 वर्ग गज अर्थात 52.95 वर्ग मीटर, यह प्रॉपर्टी श्रीमती अनुपमा पांडे के नाम पर है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैंः पूर्वः रास्ता 22 फीट चौड़ा, पश्चिमः प्लॉट नंबर 71, उत्तरः प्लॉट नंबर 32–ए, दक्षिणः प्लॉट नंबर 33			
2.	LAN No. MHFLPROGZB000005014291 1. श्री योगेश कुमार, 2. श्री दयाचंद चौधरी 3. श्री भूषण कुमार	11 जून, 2026	रु. 19,44,503.93/– दि. 11 जून, 2026 को	03 सितंबर, 2026
	प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(ओं) का विवरणः आवासीय मकान नंबर 53, खसरा नंबर 158 एमआई, गाँव अकबरपुर, बेहरामपुर, परगना लोनी, तहसील और जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009, इसका क्षेत्रफल 195 वर्ग गज, अर्थात 163.03 वर्ग मीटर। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः– पूर्व–गजराज का घर, पश्चिम–6 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर–प्रकाश और संतराम का घर, दक्षिण–बृजपाल का घर			
3.	LAN No. MHFLCONMER000005017160 1. श्री राजेश कुमार, 2. श्रीमती पूनम राजेश कुमार	15 जून, 2026	रु. 2,17,622.15/– और दि. 11 जून, 2026 को	03 सितंबर, 2026
	प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(ओं) का विवरणः आवासीय मकान जिसका नगर निगम नंबर 40, माप 54 वर्ग गज अर्थात 45.15 वर्ग मीटर, गाँव मोहकमपुर, परगना और तहसील मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250103 के समस्त भाग व खंड और उसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः– पूर्व–14 फीट, उसके बाद 10 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः 14 फीट, उसके बाद राज सिंह का मकान, उत्तरः 34.71 फीट, उसके बाद श्री सूरज के पुत्र सोनू का मकान, दक्षिणः 34.71 फीट, उसके बाद धीर सिंह का घर			

विशेष रूप से कर्जदार/ओं/जमानती/ओं और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन उपरोक्त मांग राशि और इस पर आगे की ब्याज के लिए मुथूट हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः उत्तर प्रदेश, दिनांकः 07 सितंबर, 2026 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, हिते मुथूट हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

सनएयर होटल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः- ए-7, पहली मंजिल, गीतांजलि एनक्लेव, नई दिल्ली-110 017
CIN: U74899DL1977PLC008495
वेबसाइट- www.hotelmetdelhi.com
फोनः # (91 11) 41515250
ईमेलः sunairhotels@gmail.com

कंपनी की 49वीं वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में जानकारी

1) सनएयर होटल्स लिमिटेड के सदस्यों की 49वीं वार्षिक साधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से जूम मीटिंग लिंक https://us05web.zoom.us/j/83243332447?pwd=9a8UcgHdnlhKYnbT3ZO84OZ8TOgaaM.1 के मार्फत शुक्रवार 25 सितम्बर, 2026 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित की जाएगी।
2) कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित एमसीए साधारण परिपत्र सं. 03/2025, 09/2024, 09/2023, 10/2022, 02/2022, 02/2021, 20/2020, 14/2020 और 17/2020 दिनांक क्रमशः 22 सितंबर, 2025, 19 सितंबर, 2024, 25 सितंबर, 2023, 28 दिसंबर, 2022, 5 मई, 2022, 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के लागू प्रावधानों के अनुसार।
3) ऊपर उल्लेखित एमसीए परिपत्रों के अनुसार एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन सभी सदस्यों को भेज दिया गया है, जिनके ई-मेल का पता कंपनी/निदेशकों के पास उपलब्ध है। साथ ही, वित्त वर्ष 31.03.2026 के लिए वित्तीय विवरण की भौतिक प्रतिलिपियां एस. पोस्ट के माध्यम से सभी सदस्यों को भी भेज दी गई है, जिसमें वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम की अनुसूची का विवरण उल्लेखित है। सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 कंपनी की वेबसाइट www.hotelmetdelhi.com पर भी उपलब्ध है।
4) सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ईमेल आईडी/ईमेल आईडी एवं दूरभाष नं. में परिवर्तन तथा पता में किसी भी तरह के बदलाव के संबंध में जानकारी कंपनी के पास यथाशीघ्र प्रस्तुत करें तथा sunairhotels@gmail.com पर ईमेल भेजें एवं आगे वे 011-41515250 पर कॉल कर सकते हैं। अन्य विवरण www.hotelmetdelhi.com पर जारी किए जाएंगे।
5) सदस्यों द्वारा वोटिंग की मांग किए जाने पर बैठक के दौरान कंपनी के ईमेल पते पर ऑनलाइन वोटिंग होगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते सनएयर होटल्स लिमिटेड
हस्ता/-
दिनांकः 25/08/2026 नेहा राजपूत
स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव

AU SMALL FINANCE BANK
Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001.
www.au.bank.in

स्वर्ण ऋण (Loan Against Gold) – "जैसी स्थिति है, जहाँ स्थिति है" आधार पर नीलामी सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") से प्राप्त स्वर्ण ऋण सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। चूँकि उधारकर्ता(ओं) द्वारा अपनी देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अतः हम गिरवी रखी गई स्वर्ण वस्तुओं/आभूषणों की नीलामी **7 Oct 2026** को **प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे** (समय) के मध्य, नीचे उल्लिखित शाखाओं में, वहाँ निर्दिष्ट माध्यम/प्रक्रिया के अनुसार आयोजित करने हेतु बाध्य हैं। मृत उधारकर्ताओं के मामलों में, सभी शर्तें विधिक उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी। **कृपया ध्यान दें कि यदि उपरोक्त नीलामी असफल रहती है, तो बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

भौतिक नीलामी शाखा का विवरण

GOMTINAGAR LUCKNOW -L9001090156394291 | **PRAYAGRAJ** -L9001090156494661 | **BASTI** -L9001090157103432

नोट : 1. भौतिक नीलामी के विफल होने की स्थिति में, ई–नीलामी इस वेबलिंक का उपयोग करके आयोजित की जा सकती है – https://gold.samil.in
2. प्रस्तावित नीलामी के विफल होने की स्थिति में, कृपया इस सूचना को अगली नीलामी के लिए पूर्व–सूचना के रूप में स्वीकार करें।
3. नीलामी, बोली प्रारूप में उल्लिखित कुछ नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी, जो नीलामी प्रारंभ होने से पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ताक्षर/–
प्रबंधक
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

शमा इंजिन वाल्वस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः बी–28, महारानी बाग, नई दिल्ली–110065

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यवसायों के लेनदेन के लिए कंपनी **शमा इंजिन वाल्वस लिमिटेड** के सदस्यों की 65वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार 30 सितंबर 2026 को प्रातः 9.30 बजे, एस–1, दूसरी मंजिल, शॉप कम फैसिलिटी सेंटर, पॉकेट–ए, डीएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बवाना, दिल्ली–110039 पर होगी।

साधारण व्यवसायः
1. कंपनी के 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. श्रीमती रितिका जतिन आहूजा (DIN: 01746272) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करती हैं।
3. श्री मोहित कुकरेजा (DIN: 00254382) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं।

विशेष व्यवसायः
1. बकाया असुरक्षित ऋणों पर ब्याज के भुगतान को मंजूरी देना।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह./–
प्रीति सरीन
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
दिनांकः 04.09.2026 DIN: 01746292

SALASAR Building a stronger future

सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड
(CIN: L23201UP2001PLC209751)
पंजीकृत कार्यालयः खसरा नंबर 265, 281–288, ग्राम परसौन–डासना, पी.ओ.–जिंदल नगर, जिला हापुड–201015 (उ.प्र.)
फोनः 0120–6546670, ईमेल आईडीः compliance@salasartechno.com, वेबसाइटः www.salasartechno.com

25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 25वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को प्रातः 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। यह बैठक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022, संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022य संख्या 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, संख्या 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 तथा संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 ("मंत्रालयीय परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित, सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।
कंपनी की 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी, जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत है। कृपया ध्यान दें कि मंत्रालयीय परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के माध्यम से 25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रति सदस्यों को भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.salasartechno.com तथा उन शेयर बाजारों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध रहेंगे, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com।
कंपनी अपने सभी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मत देने हेतु दूरस्थ ई–मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी प्रदान कर रही है। दूरस्थ ई–मतदान/ई–मतदान की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई है, जो आपको शीघ्र ही भेजी जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक प्रतिवेदन का वेब–लिंक उपलब्ध कराने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजा जा रहा है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं। तथापि, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2025–26 का वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु यथाशीघ्र अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं।
सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण हेतु अपना ई–मेल पता एवं बैंक खाते का विवरण कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता ("आरटीए"), बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, को उपलब्ध कराएं। इसके पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित हैः
1. वे सदस्य जो भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करते हैं तथा जिनके ई–मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे यथाशीघ्र अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं। इसके लिए सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन प्रति भेजनी होगी, जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो संख्या, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (आगे एवं पीछे), कंपनी के अभिलेख में पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में स्व–सत्यापित पैन कार्ड की स्कैन प्रति तथा स्व–सत्यापित आधार कार्ड की स्कैन प्रति संलग्न हो। उक्त दस्तावेज investor.del@bigshareonline.com. पर ई–मेल द्वारा भेजकर वित्तीय वर्ष 2025–26 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक आम बैठक की सूचना ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपना ई–मेल पता अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अद्यतन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए ई–मतदान हेतु उपयोगकर्ता पहचान एवं कूटशब्द प्राप्त करने के लिए ivote@bigshareonline.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
2. कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर ई–मेल पते का अद्यतन/पंजीकरण केवल 25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक प्रतिवेदन को भेजने के उद्देश्य से किया जाएगा। अतः सदस्य को कंपनी के अभिलेखों में वास्तविक पंजीकरण हेतु उपर्युक्त दस्तावेजों की मूल/हार्ड प्रतियों के साथ ई–मेल आईडी अद्यतन करने का अनुरोध आरटीए को भेजना आवश्यक होगा, ताकि कंपनी की ओर से भविष्य में भेजे जाने वाले सभी संचार, जिनमें वार्षिक प्रतिवेदन, सूचनाएं, परिपत्र आदि सम्मिलित हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किए जा सकें।
डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपना ई–मेल पता अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अद्यतन कर सकते हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना में शेयरधारकों द्वारा दूरस्थ ई–मतदान अथवा वार्षिक आम बैठक के समय ई–मतदान के माध्यम से मतदान करने तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में सम्मिलित होने की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं वार्षिक प्रतिवेदन लागू कानूनों के अनुसार नियत समय में सदस्यों के पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजे जाएंगे।

कृते सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ता/–
स्थानः गाजियाबाद मोहित कुमार गोयल
दिनांकः 05 सितंबर, 2026 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, **मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि., पंजीकृत कार्यालयः एनएच बाईपास, पलरिवट्टोम कोच्चि-682028, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-4804000, 2396884, 2394712, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**31.08.2025** तक की अवधि के लिए **NPA** खाते और **31.05.2026** की अवधि तक के **कम टंच/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौती** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

GSTIN-09AABCT0343B1ZW (उत्तर प्रदेश)
प्रथम नीलामी की तिथि एवं समयः 07.10.2026, 04: 00 P.M.
द्वितीय नीलामी की तिथि एवं समयः 08.10.2026, 04: 00 P.M.
तृतीय नीलामी की तिथि एवं समयः 12.10.2026, 04: 00 P.M.
मुज़फ़्फ़रनगर (उप्र) (4691): MDL-1804, 1807, 1829, MHP-259, MUL-5806, 6075, 6102, 6159, 6172, 6216, **खतौली (उप्र) (4891):** MDL-538, 754, MEG-139, MUL-1565, 1570, RGL-2090, 2155, 2228, 2299, 2326, 2432, 2491, 2567, 2582, 2770, 2790, 2839, 2872, 2904, 2953, 2970, SRS-27, **मुज़फ़्फ़रनगर-अंसारी रोड (उप्र) (4903):** MUL-2128, 2264, 2270, 2287
कम टंच/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौतीः खतौली (उप्र) (4891): MSV-39
नीलामी केंद्रः मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, निचला तल, निकटवर्ती एसबीआई, रेलवे रोड, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.-251001
प्रथम नीलामी की तिथि एवं समयः 07.10.2026, 10:00 A.M.
द्वितीय नीलामी की तिथि एवं समयः 08.10.2026, 10:00 A.M.
तृतीय नीलामी की तिथि एवं समयः 12.10.2026, 10:00 A.M.
सहारनपुर-कोर्ट रोड (2378): BLS-20, MDL-2787, MUL-15075, 15165, 15390, 15399, 15442, 15477, 15498, 15929, 15938, 15944, 15979, SRS-212, 213, **सहारनपुर-चकराता रोड (4423):** MDL-2390, 2423, 2481, 2486, 2534, MEG-282, 294, MUL-12923, 13320, 13470, 13500, 13617, 13674, 13809, 13867, 13890, 13893, 13907, 13980, 14070, 14083, 14087, 14113, SRS-498, **सहारनपुर-अम्बाला रोड (4980):** MEG-221, MUL-2560, 2565, 2840, 2843, 3010, 3064, 3104, SRS-119
नीलामी केंद्रः मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, पहली मंजिल, गिल कॉलोनी, पार्श्वनाथ प्लाजा के सामने, कोर्ट रोड, सहारनपुर, उ.प्र.-247001
प्रथम नीलामी की तिथि एवं समयः 07.10.2026, 01: 00 P.M.
द्वितीय नीलामी की तिथि एवं समयः 08.10.2026, 01: 00 P.M.
तृतीय नीलामी की तिथि एवं समयः 12.10.2026, 01: 00 P.M.
शामली-(उप्र) (4781): BLS-30, 55, MDL-1036, 1265, 1293, MUL-2406, 2417, 2451, 2465, 2512, 2566, 2578, 2644, 2667, 2681, RGL-2147, 2223, 2278, 2678, 2689, SRS-185, 198, 204, 210, TMS-152, 153
कम टंच/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौतीः शामली-(उप्र) (4781): HVS-14, MDL-6282
नीलामी केंद्रः पहली मंजिल, खादी भारत के ऊपर, प्रॉपर्टी नं 275, वार्ड नं 20, बस स्टैंड के पास, बुढ़ाना रोड, जिला-शामली, उ.प्र.-247776

संबंधित शाखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए लोन खातों की नीलामी, ऊपर दिए गए विवरणों के अनुसार संबंधित नीलामी केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यदि निर्धारित प्रथम तिथि को नीलामियाँ सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होती हैं या पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में नीलामी (नीलामियों) का आयोजन/क्रमशः संचालन **द्वितीय नीलामी की तिथि एवं तृतीय नीलामी तिथि को, ऊपर उल्लिखित नीलामी केंद्रों** पर आयोजित की जाएगी/जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना जारी नहीं की जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्ती एडवोकेट, डी-72, लोअर ग्राउंड फ्लोर, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017

नोटः यदि नीलामी इसके बावजूद सफल/पूरी नहीं होती है, तो इसके बाद की तिथियों में उसी स्थान पर नीलामी जारी रहेगी। इस संबंध में कोई और सूचना नहीं दी जाएगी। ग्राहक **ईमेल आईडीः recoverynorth@muthootgroup.com** या **7834886464, 7994452462** पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

दिल्ली संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा नीतेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जागरण प्रकाशन लिमिटेड, डी-210-211, सेक्टर-63 नोएडा-201301 उ.प्र. और पृथ्वीस दास, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड 10, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर - 302015 से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 011-23720202/23762742
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं

ज्वैलरी रिटेलरों की वृद्धि रहेगी चमकदार

ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों में तेजी के बावजूद ब्रोकरेज हाउस उनकी संरचनात्मक वृद्धि को लेकर अभी सकारात्मक। जेपी मॉर्गन रिसर्च का टाइटन पर सकारात्मक नजरिया। भारत में सोने की कीमतों में पिछले साल से हुआ है इजाफा

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 6 सितंबर

पिछले एक साल में सूचीबद्ध प्रमुख ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों ने बड़े सूचकांकों और बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले छह महीनों और एक साल की अवधि में प्रमुख आभूषण निर्माताओं का औसत रिटर्न 50 प्रतिशत रहा है। सबसे ज्यादा बढ़त दिखाने वाली कंपनियों में स्काई गोल्ड ऐंड डायमंड्स, तंगामायिल ज्वैलरी, ब्लूस्टोन ज्वैलरी ऐंड लाइफस्टाइल और हाल में कल्याण ज्वैलर्स शामिल हैं। यह बेहतर प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि बेंचमार्क (निफ्टी 50) और बड़े सूचकांकों, दोनों ने ही साल की शुरुआत से अब तक और पिछले छह महीनों में कमजोर रिटर्न दिया है।

सोने के आभूषणों की मांग मजबूत बनी हुई है। यह तब है जब सोने पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है और सोने की कीमतें ऊंची और अस्थिर बनी हुई हैं। इन कारकों के अलावा इस क्षेत्र में और भी समेकन हुआ है। हाल के रुझानों से पता चलता है कि जीआरटी ज्वैलर्स ने त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी (टीबीजेड) का अधिग्रहण किया है। इसके लिए जीआरटी ज्वैलर्स ने 74 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले 1,033 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। भारत में सोने की कीमतों (24 कैरेट प्रति 10 ग्राम) में पिछले एक साल में बढ़ोतरी हुई है। ये कीमतें पिछले साल अक्टूबर में 1,21,467 रुपये के निम्न स्तर से पिछले महीने 1,67,965 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंची हैं।

ज्वैलरी रिटेल की बड़ी कंपनियों के शेयरों के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद ब्रोकरेज हाउस उनकी ढांचागत वृद्धि की कहानी को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि सूचीबद्ध बड़ी कंपनियां मौजूदा स्तरों से अच्छा रिटर्न देंगी। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस टाइटन और कल्याण ज्वैलर्स को अपनी मुख्य पसंद मानते हैं।

जेपी मॉर्गन रिसर्च संगठित आभूषण रिटेल क्षेत्र को लेकर सकारात्मक है। टाइटन पर उसका सकारात्मक नजरिया बरकरार है, भले ही टाइटन ने इस साल अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। टाइटन में 25 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई है, जबकि निफ्टी 50 सूचकांक में 7 प्रतिशत की गिरावट हुई है। ब्रोकरेज हाउस की विश्लेषक लतिका चोपड़ा का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी और तीसर तिमाही में भी आभूषणों की मांग बनी रहेगी। इस उम्मीद की कई वजह हैं: लंबा त्योहारी सीजन, शादी-ब्याह के दौरान मजबूत मांग और रिटेलरों की ओर से खरीदारों को आकर्षित करने तथा खरीदारी के मौके बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। ये सब तब हो रहा है जब सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव (पिछले एक महीने में 13 प्रतिशत की बढ़त) देखा जा रहा है।

सोने की ऊंची कीमतों के असर को कम करने में कई चीजें मदद कर रही हैं, जैसे आकर्षक गोल्ड-एक्सचेंज प्रोग्राम (जो सोने की कुल बिक्री का 50 प्रतिशत है), कम वजन और कम कैरेट वाले गहने (जिनमें कई 18 कैरेट वाले गहने भी शामिल हैं) और रोजाना पहनने लायक किफायती कलेक्शन (जैसे तनिष्क की 50,000 रुपये से कम कीमत वाली 'जॉय ऑफ ड्रेसिंग' रेंज)। ये सभी चीजें अलग-अलग कीमत वाले गहनों तक लोगों की पहुंच बढ़ा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ रही हैं।

जून तिमाही में बड़ी ज्वैलरी कंपनियों ने सालाना आधार पर औसतन 35 फीसदी की राजस्व वृद्धि दर्ज की। मई में कस्टम ड्यूटी बढ़ने के बावजूद सोने की बढ़ती कीमतों और शादियों व त्योहारों के मौसम के कारण ग्राहकों की लगातार मांग से इसे बढ़ावा मिला।

सिस्टमैटिक्स रिसर्च के चेतन महादिक और विजय जांगिड़ का कहना है कि जून तिमाही में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इस दौरान सोने की कीमतें सालाना आधार पर 60 प्रतिशत तक बढ़ गईं। सोने पर कस्टम ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से शुरू में मई में मांग कम हो गई थी। लेकिन जून में यह सामान्य हो गई। अक्षय तृतीया पर बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। मगर अधिक मास (अशुभ समय) की वजह से शादी-ब्याह से जुड़ी खरीदारी कुछ समय के लिए टल गई। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से आए अंतर को पाटने और ऊंची कीमतों पर भी ग्राहकों के बजट के हिसाब से चीजें उपलब्ध कराने के लिए, रिटेलरों ने अपने आभूषणों में 9-कैरेट, 14-कैरेट और 18-कैरेट वाले ज्यादा विकल्प शामिल किए। ब्रोकरेज फर्म ने ब्लूस्टोन ज्वैलरी के शेयर के लिए 'खरीदें' रेटिंग दी है।

मोतीलाल ओसवाल रिसर्च के पसंदीदा शेयरों में टाइटन और कल्याण ज्वैलर्स शामिल हैं। इसकी वजह है, इनका उद्योग में सबसे अच्छा काम करने का तरीका, बेहतर पूंजी निवेश और उपभोक्ता क्षेत्र की बाकी कंपनियों के मुकाबले लगातार अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता। उसने पीएन गाडगिल को 'खरीदें' रेटिंग और सेंको गोल्ड को 'न्यूट्रल' रेटिंग दी है।

उम्दा प्रदर्शन

कंपनी	मौजूदा बाजार भाव रुपये में	6 महीने में बदलाव फीसदी
टाइटन कंपनी	5,010	19.0
कल्याण ज्वैलर्स इंडिया	599	52.0
तंगामायिल ज्वैलरी	5,331	47.8
पीएन गाडगिल ज्वैलर्स	607	9.1
पीसी ज्वैलर	12	31.5
ब्लूस्टोन ज्वैलरी ऐंड लाइफस्टाइल	843	87.3
स्काई गोल्ड ऐंड डायमंड्स	781	134.1
सैंको गोल्ड	358	21.2
निफ्टी 50	23,306	-5.5
निफ्टी 500	21,478	-5.4

स्रोत : ब्लूमबर्ग संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

बाजार हलचल

फंडों की ज्यादा खरीद से शेयरों में मजबूत निवेश का संकेत

म्युचुअल फंडों ने अगस्त 2026 में लगभग 60,000 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इससे संकेत मिलता है कि पिछले महीने ऐक्टिव और पैसिव इक्विटी योजनाओं को अच्छा-खासा शुद्ध निवेश मिला। म्युचुअल फंडों में यह शुद्ध निवेश पिछले तीन महीनों में सबसे ज्यादा था। इक्विटी योजनाओं में शुद्ध निवेश के अलावा म्युचुअल फंडों की खरीदारी पर हाइब्रिड फंड के ऐसेट एलोकेशन और ऐक्टिव इक्विटी योजनाओं की कैश होल्डिंग में हुए बदलावों का भी असर पड़ा। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) इस हफ्ते अगस्त के लिए श्रेणी के हिसाब से शुद्ध निवेश का आंकड़ा जारी करने वाली है।

आईपीओ के सामने संकट

हाल में आईपीओ लाने वाली एक कंपनी के पूर्व निदेशक ने एनसीएलटी के बेंगलूरु पीठ में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि आरएम एम्प्लॉयी बेनिफिट ट्रस्ट को 2023 में बेचे गए उनके शेयरों की बिक्री को रद्द किया जाए और कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ पर रोक लगाई जाए। उनका आरोप था कि कंपनी ने उन्हें धोखा देकर अपनी 9.41 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए मजबूर किया था। इसके जवाब में कंपनी और उसके प्रवर्तक ने याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती दी है और शपथ देकर झूठे बयान का आरोप लगाते हुए अर्जी दायर की है। आरएचपी के अनुसार यह मामला अभी लंबित है। जब आईपीओ के निवेश बैंकरों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेबी ने इसे पहले ही हरी झंडी दिखा दी है और आईपीओ को मंजूरी मिल चुकी है।

प्री-ओपन ऑक्शन का होगा क्लोजिंग सेशन से जुड़ाव

स्टॉक एक्सचेंज 7 सितंबर से प्री-ओपन ऑक्शन सेशन के समय में बदलाव करेंगे ताकि नए शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) के साथ इसका तालमेल हो सके। नई समयसारणी के तहत सभी ऑर्डर के लिए ऑर्डर एंट्री सुबह 9:00 बजे से 9:05 बजे तक होगी। इसके बाद सुबह 9:10 बजे तक सिर्फ लिमिट-ऑर्डर वाली अवधि होगी। इसमें आखिरी दो मिनट में अचानक से क्लोजर होगा। ऑर्डर मैचिंग सुबह 9:10 बजे से 9:12 बजे के बीच होगी। इसके बाद जो ऑर्डर मैच नहीं हो पाएंगे, वे सुबह 9:15 बजे तक सतत कारोबारी सत्र में चले जाएंगे। ऑर्डर पूरे करने की प्राथमिकता इस तरह होगी - पहले मार्केट-टु-मार्केट ऑर्डर, फिर लिमिट ऑर्डर के मुकाबले बचे हुए मार्केट ऑर्डर और आखिर में बचे हुए लिमिट-टु-लिमिट मैच।

संकलन : अभिषेक कुमार और शिल्पा रंगराजन

म्युचुअल फंडों में सीधे निवेश करने में खुदरा निवेशक आगे

5 वर्षों में डायरेक्ट प्लान की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां 4 गुना बढ़ीं

अभिषेक कुमार
मुंबई, 6 सितंबर

म्युचुअल फंड में डायरेक्ट निवेश को बढ़ाने में खुदरा निवेशकों ने अहम भूमिका निभाई है। पिछले पांच सालों में उनके डू इट योरसेल्फ (डीआईवाई) के कारण इस तरह की परिसंपत्तियां चार गुना से ज्यादा बढ़ी हैं जबकि इसी दौरान रेग्युलर प्लान में प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) सिर्फ दोगुनी हुई हैं।

मार्च 2021 के 1.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2026 में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची खुदरा एयूएम में जबरदस्त बढ़ोतरी के कारण इस 5 साल की अवधि में डायरेक्ट निवेश एयूएम में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ़ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 के अंत में खुदरा एयूएम में डायरेक्ट प्लान की हिस्सेदारी 36.7 फीसदी थी, जो मार्च 2021 में 21.4 फीसदी रही थी।

क्रिसिल के साथ संयुक्त रूप से तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है, डायरेक्ट प्लान की ओर झुकाव, खुद से निवेश करने के चलन में लगातार हो रही बढ़ोतरी दिखाता है। इसे डिजिटल पहुंच, योजना के बारे में बेहतर जानकारी और लागत के प्रति बढ़ती जागरूकता से बढ़ावा मिला है।

अमीर व्यक्तिगत निवेशकों के मामले में भी डायरेक्ट प्लान का हिस्सा बढ़ा है। हालांकि, यह बढ़ोतरी खुदरा निवेशकों जितनी तेजी से नहीं हुई है। 5 साल की अवधि में अमीर निवेशकों की एयूएम में डायरेक्ट प्लान का हिस्सा 28.8 फीसदी से बढ़कर 35.1 फीसदी हो गया है। कॉरपोरेट निवेशकों के मामले में रेग्युलर प्लान का हिस्सा बढ़ा है और यह 22 फीसदी से बढ़कर लगभग 29 फीसदी हो गया है।

म्युचुअल फंड निवेशक डायरेक्ट और रेग्युलर प्लान में से कोई भी चुन सकते हैं। रेग्युलर प्लान बैंक और एजेंट जैसे बिचौलियों के जरिये बेचे जाते हैं। इनमें उनकी सर्विस के लिए कमीशन शामिल होता है। इसके उलट, डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन नहीं लगता और ये उन निवेशकों के लिए होते हैं, जो बिना किसी मदद के इस प्रोसेस को समझने और इस्तेमाल करने में सहज होते हैं। ये प्लान म्युचुअल फंड कंपनियों की वेबसाइट और ग्रो व जीरोधा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिन्होंने इनके विस्तार में अहम भूमिका निभाई है।

हाल के वर्षों में रेग्युलर प्लान के मुकाबले डायरेक्ट प्लान में खुलने वाले खातों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2026 में फंड योजनाओं के डायरेक्ट प्लान में शुद्ध रूप से 2.52 करोड़ खाते जुड़े, जबकि रेग्युलर प्लान में यह संख्या 1.42 करोड़ थी। शेयर बाजार के अनुकूल न होने के बावजूद खातों की संख्या में यह बढ़ोतरी हुई। जानकारों का कहना है कि डायरेक्ट प्लान में खातों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) और फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) में निवेशकों की दिलचस्पी का बढ़ना था।

डायरेक्ट प्लान में विभिन्न श्रेणियों का हिस्सा (प्रतिशत में)

श्रेणी	2021	2026
बैंक/एफआई	89.1	87.8
कॉरपोरेट	78	72.2
एचएनआई	28.8	35.1
एनआरआई	19.4	27.3
खुदरा	21.4	36.7

स्रोत : एम्फी

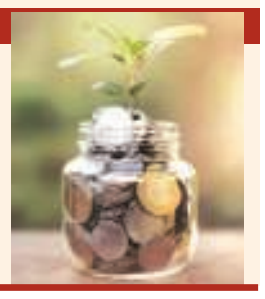

फंडों ने इस साल आईपीओ में डाले 12,944 करोड़ रुपये

शिल्पा रंगराजन
मुंबई, 6 सितंबर

साल 2026 में भारत के म्युचुअल फंडों ने मुख्य प्लेटफॉर्म पर आए आईपीओ में 12,944 करोड़ रुपये का निवेश किया। इनमें कुछ बड़े ऐसेट मैनेजरों का ही दबदबा रहा। तीन फंड हाउस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्युचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्युचुअल फंड ने कुल संस्थागत आवंटन का करीब 52 फीसदी हिस्सा लिया और सार्वजनिक निर्गम में 6,770 करोड़ रुपये का निवेश किया।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड कुल वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ा संस्थागत खरीदार बनकर उभरा। उसने मुख्य बोर्ड पर सूचीबद्ध 13 अलग-अलग शेयरों में पैसा लगाया। एसबीआई म्युचुअल फंड ने सिर्फ छह कंपनियों में हिस्सा लिया। बावजूद उसने सबसे ज्यादा 3.8 फीसदी मार्केट कैप के हिसाब से ओनरशिप पोजीशन बनाई। कुछ चुनिंदा कंपनियों में बड़ी मात्रा में पैसा लगाकर एसबीआई म्युचुअल फंड ने एक लक्षित रणनीति के प्रदर्शन किया। इससे इश्यू के आकार के मुकाबले पोर्टफोलियो निवेश अधिकतम हो गया।

बाजार में शुरुआती तौर पर सबसे मजबूत प्रदर्शन दिखाने वाली कंपनियों को बड़े फंडों का जबरदस्त समर्थन मिला। शैडोफ़ैक्स, अमागी, ओम्नीटेक और सेडमैक मेकाट्रॉनिक्स जैसी साल की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली सूचीबद्धता को इन प्रमुख संस्थागत खरीदारों का मजबूत सहारा मिला। बड़े फंडों ने अहम वैल्यूएशन एंकर के तौर पर काम किया और बाजार में कीमत तय होने के दौरान जरूरी नकदी उपलब्ध कराई और संस्थागत मुहर लगाई।

बड़े संस्थागत परिदृश्य से नए शेयरों के लिए अलग-अलग तरह की मांग का पता चला। जहां छोटे ऐसेट मैनेजरों ने छोटी-छोटी रकम कई जगह लगाई, वहीं बड़े फंड मैनेजरों ने अच्छी नकदी का फायदा उठाकर एंकर हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा हासिल किया। 2026 में जैसे-जैसे नए शेयर जारी होने का सिलसिला चलेगा, ऐसे में परिसंपत्ति का आकार और खास शेयरों का चयन ही भारत के इक्विटी पूंजी बाजार में संस्थागत हिस्सेदारी तय करने वाले मुख्य कारक बने रहेंगे।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्युचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्युचुअल फंड ने कुल संस्थागत आवंटन का करीब 52 फीसदी हिस्सा लिया

अगले कुछ दिन में 11 कंपनियों के आईपीओ

प्राथमिक बाजार में अगले कुछ दिन में एक बार फिर जोरदार हलचल देखने को मिलेगी। रेंटोमोजो, कनोहर इलेक्ट्रिकल्स और कर्मात्रा इंजीनियरिंग सहित 11 कंपनियां मुख्य प्लेटफॉर्म के आईपीओ के जरिये कुल 7,055 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं। ये आईपीओ 7 सितंबर से 15 सितंबर के बीच बाजार में खुले रहेंगे। इनमें से अधिकांश निर्गम मंगलवार और बुधवार को खुलेंगे। येस सिक्योरिटीज के मुख्य निवेश अधिकारी राजकुमार राठी ने कहा कि एक साथ इतने आईपीओ आना इस बात का संकेत है कि निवेशक इसके लिए उत्सुक हैं।

भाषा

Ravindra Energy Limited

Regd. Off.: BC 105, Havelock Road, Camp, Belagavi – 590001, Karnataka, India.
Tel.: +91-831-2406600 | CIN: L40104KA1980PLC075720 | **Website**: www.ravindraenergy.com

Notice of the 46th Annual General Meeting to be held through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), and E-Voting Information

1. Notice is hereby given that, the 46th Annual General Meeting ('AGM') of the members of RAVINDRA ENERGY LIMITED will be held through VC/OAVM on **Monday, the 28th day of September, 2026, at 12:00 Noon**, to transact the business set out in the Notice calling the AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] and circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities Exchange Board of India(SEBI) for extension for holding AGM through VC/OAVM. Members will be able to attend the AGM only through VC/OAVM or view the live web cast at https://emeetings.kfintech.com Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder. The instructions for joining the AGM and the manner of remote e-voting/electronic voting system are provided in the Notice of the AGM.
2. In compliance with the MCA Circulars, the Notice of 46th AGM and Annual Report FY2025-26, will be sent to all the shareholders of the Company in electronic mode to those members whose email address is registered with the Company/Depository Participant(s)/Registrar and Transfer agents. The requirements of sending physical copy of the aforesaid documents, has been dispensed with vide MCA & SEBI Circulars. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.ravindraenergy.com under "Investors">> 'Annual Report', on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the Website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com
3. **Manner of registering / updating email addresses and mobile:**
Shareholders holding shares in physical form are hereby notified that based on SEBI Circular number: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91, dated June 23, 2025, all holders of physical securities shall register their postal address with PIN for their corresponding folio numbers. It shall be mandatory for the security holders to provide mobile number. Moreover, to avail online services, the security holders can register e-mail ID. Holder can register/update the contact details through submitting Form ISR 1 along with the supporting documents.
Form ISR-1 can be obtained by accessing the link: **https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx**
ISR Form(s) and the supporting documents can be provided in hard copies which are self-attested and shared to "KFIN Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana India - 500 032. The soft copies of the same may be mailed to **einward.ris@kfintech.com**
Detailed FAQ can be found on the link: **https://ris.kfintech.com/faq.html**
For more information on updating the email and mobile details for securities held in electronic mode, please reach out to the respective DP(s), where the DEMAT a/c is being held.
4. **Manner of casting vote(s) through Remote e-Voting/Electronic Voting**
   a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting or electronic voting system at the AGM (Insta Poll).
   b) The instructions of voting remotely ("remote e-voting") and by electronic voting system at the AGM, by the members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The facility for voting through electronic voting system will be made available at the AGM ("Insta Poll") and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting, will be able to vote at the AGM through Insta Poll. The instructions for remote e-voting & electronic voting at the AGM will also be available on the website of the Company at www.ravindraenergy.com under "Investors" and on the website of KFinTech at https://evoting.kfintech.com/
   c) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses is not registered with the Company/DP/RTA, may generate login credentials by following instructions given in the Notes to the Notice of AGM.
   d) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.
5. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or Insta Poll during the AGM.

For Ravindra Energy Limited
Sd/-
Madhukar Shipurkar
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. A64947

Date:September 4, 2026
Place: Belagavi

एमएफ में घटा खुदरा निवेशकों का हिस्सा

पृष्ठ 1 का शेष

इस बीच म्युचुअल फंड परिसंपत्तियों में धनाढ्य निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है लेकिन बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हुई है। एम्फी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में धनाढ्य निवेशकों की हिस्सेदारी 30.4 फीसदी थी जो मार्च 2024 में बढ़कर 32.3 फीसदी हो गई और फिर मार्च 2026 में मामूली बढ़कर 32.7 फीसदी पहुंच गई। म्युचुअल फंड उद्योग में किसी निवेश खाते को धनाढ्य या एचएनआई फोलियो तब माना जाता है, जब उसमें एक लेनदेन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक का निवेश होता है।

परिसंपत्ति प्रबंधन प्लेटफॉर्म वेल्दी डॉट इन के सह-संस्थापक आदित्य अग्रवाल ने कहा, 'एचएनआई निवेशकों की संख्या में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी से काफी ज्यादा निवेश आता है क्योंकि धनाढ्य श्रेणी का निवेश खुदरा निवेश के मुकाबले काफी बड़ा होता है। बढ़ती दौलत, म्युचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी और अमीर निवेशकों द्वारा बाजार से जुड़े उत्पादों को ज्यादा पसंद किए जाने से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।'

पैसिव फंडों में धनाढ्य निवेशकों की हिस्सेदारी में यह बदलाव कहीं अधिक स्पष्ट है। पैसिव फंड एयूएम में एचएनआई की हिस्सेदारी मार्च 2021 के 6.6 फीसदी से लगभग तीन गुना बढ़कर मार्च 2026 में 19.9 फीसदी हो गई।

कॉरपोरेट निवेशक अभी भी सबसे बड़ा निवेशक समूह बने हुए हैं लेकिन उनकी हिस्सेदारी इसी अवधि में 78.4 फीसदी से घटकर 69.6 फीसदी रह गई। खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी भी 13.4 फीसदी से घटकर 9.1 फीसदी हो गई।

निवेशकों की बदलती संरचना से संकेत मिलता है कि पैसिव निवेश धीरे-धीरे संपन्न व्यक्तिगत निवेशकों के एक बड़े वर्ग को आकर्षित कर रहा है। हालांकि इस खंड में संस्थागत निवेशकों का दबदबा अब भी कायम है।

विशेषज्ञों के मुताबिक एचएनआई भागीदारी में तेज बढ़ोतरी की वजह इंडेक्स फंडों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के बारे में बेहतर जानकारी और सोने तथा चांदी से जुड़ी एमएफ योजनाओं में बढ़ता निवेश है। संपन्न निवेशक लार्जकैप निवेश के लिए भी पैसिव रणनीतियों को तेजी से अपना रहे हैं। यह बदलाव इसके बावजूद है कि अब वितरक और पंजीकृत निवेश सलाहकार भी पैसिव फंड की सलाह नहीं दे रहे हैं।

फिड्यूशरीज डॉट इन में पंजीकृत निवेश सलाहकार अविनाश लुथरिया ने कहा, 'ज्यादातर पंजीकृत निवेश सलाहकार इंडेक्स फंड की सलाह देना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि सामान्य पंजीकृत निवेश सलाहकार के लिए सालाना 1 फीसदी शुल्क को सही ठहराना मुश्किल होता है जबकि निवेश उत्पाद का शुल्क केवल 0.2 फीसदी सालाना है। दूसरी अहम वजह यह है कि इंडेक्स फंड में किए गए निवेश की हर साल समीक्षा की जरूरत नहीं होती है जिससे ग्राहक के पंजीकृत निवेश सलाहकार के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखने की संभावना कम हो जाती है।'

सोने और चांदी में निवेश का भी पैसिव उत्पादों में एचएनआई भागीदारी बढ़ाने में योगदान हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ तथा फंड ऑफ फंड्स के जरिये किया गया निवेश भी एचएनआई की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की वजह रहा होगा।

मार्च 2026 में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का एयूएम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये रहा जो मार्च 2021 के मुकाबले 17 गुना अधिक है।

सवाल जवाब

सकल घरेलू उत्पाद की पद्धति को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं : करंदीकर

फरवरी में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नई जीडीपी श्रृंखला जारी होने के समय राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल जून में समाप्त हुआ। असित रंजन मिश्र के साथ टेलीफोन पर बातचीत में करंदीकर ने कहा कि पारदर्शिता और आंकड़ों पर भरोसा दोतरफा राह की तरह है। संपादित अंश:

जीडीपी के आंकड़ों को लेकर छिड़े विवाद पर आपके क्या विचार हैं?

दो अलग-अलग बातों को मिलाया जा रहा है। एक यह है कि क्या आधार वर्ष बदला जाना चाहिए था। यदि हां, तो कब और वे इसे कैसे बदलते हैं, आदि। दूसरा मुद्दा है कि लोग बस यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि यह 7.8 प्रतिशत वृद्धि नहीं, 2.6 प्रतिशत वृद्धि है, जो बेतुका है। यह कहना कि 2.6 प्रतिशत वृद्धि है, यह सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। दुर्भाग्य से राजनीति में यह सब मिल गया है। कोई भी इसे सीधे शब्दों में नहीं कहता, बल्कि संकेत दिया जाता है कि आधार वर्ष को इस तरह बदला गया है कि जीडीपी के आंकड़े अधिकतम आएं। मैं कह सकता हूं कि यह कहना गलत है। आधार वर्ष बदलने का फैसला कई महीने पहले हुआ था, जब में एनएससी का चेयरमैन था। हमने ऐसी सभी चर्चाओं में भाग लिया है। यह एक नियमित कवायद है। केवल इतना मसला है कि आप इसे कब करते हैं। दूसरा, जब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने फरवरी में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के लिए नॉमिनल जीडीपी 86 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपये किया था, तब इसकी घोषणा की गई थी। लोग पढ़ते नहीं हैं। यह उनकी समस्या है। बदलाव का मतलब यह नहीं है कि इसमें पद्धति से जुड़ा असंतुलन है या इसे हेरफेर किया गया है। संकेत दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश इस सरकार, उस सरकार, इस दल, उस दल से ऊपर है।

जब आप एनएससी अध्यक्ष थे, तब क्या एनएससी ने नई जीडीपी पद्धति का सत्यापन किया था? उसकी सिफारिशें और राय क्या थीं?

मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। पिछली प्रथाओं का पालन करते हुए मेरी अध्यक्षता में एनएससी ने स्टीयरिंग कमेटी नियुक्त की थी। यह बड़ी समिति थी। हम ऐसे सभी सवालों पर विचार कर रहे थे। मैं गवाही नहीं दे सकता, लेकिन मुझे याद है कि स्टीयरिंग कमेटी में जीडीपी पद्धति पर गहराई से चर्चा की गई थी। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी की रिपोर्टें एनएससी को प्रस्तुत की जाती हैं, जो अपनी मंजूरी देता है। तो, ऐसा नहीं है कि यह एनएससी की जानकारी के बिना गुप्त तरीके से किया गया था।

जब श्रृंखला को मंजूरी दी गई थी, तब उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) जारी नहीं किया गया था। क्या कमेटी ने पीपीआई के डिफ्लेटर के रूप में उपयोग पर चर्चा की थी?

देखिए अगर मैं समिति की चर्चा की गहराई में जाऊं तो शायद मैं इसका उत्तर दे सकूंगा। लेकिन हमने आम तौर पर हर मसले पर चर्चा की। स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सुझाई गई किसी भी पद्धतिगत परिवर्तन को या तो स्वीकार कर लिया गया था, या अधिकारियों ने समझाया कि इसे क्यों नहीं किया जा सकता। मुझे याद है कि पीपीआई पर काफी समय से चर्चा हो रही थी और स्टीयरिंग कमेटी की बैठकों में इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी।

क्या आप पीपीआई की मजबूती से खुश हैं? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पीपीआई में बहुत ज्यादा आंकड़ों की जरूरत है और उत्पादक हमेशा वह आंकड़े देने में हिचकिचाते रहे हैं?

यह मजबूत है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। किसी को इस पर संदेह हो सकता है। कोई क्या कर सकता है? किसी भी बदलाव पर हमेशा संदेह होता है।

क्या इसे जीडीपी के आंकड़ों में डिफ्लेटर के रूप में शामिल किया जाना चाहिए?

फिर कहूंगा कि मुझे ठीक से याद नहीं कि क्या चर्चा हुई थी। हमारे सामने जो प्रस्तुत किया गया, वह उचित लग रहा था। पिछले एनएससी अध्यक्ष, प्रोफेसर विमल रॉय सहित हम सभी संतुष्ट थे और हमने इसे मंजूरी दे दी। दूसरे, यह ध्यान में रखा जाना चाहिएकि एनएससी आखिरकार केवल एक सलाहकार निकाय है, निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है।

2024 में आपने कहा था कि सरकार को एनएससी को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता है?

हाँ। उसके बाद सचिव बदल गए, और खुलापन बदल गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पहले वे जो कर रहे थे वह गलत था, लेकिन वे हमें सूचित नहीं कर रहे थे।

क्या आपको लगता है कि मंत्रालय को अलग-अलग आंकड़े जारी करने चाहिए, जिससे शोधकर्ता जीडीपी का अनुमान लगा सकें?

यह एक विवादास्पद प्रश्न है। फिर कोई और कहेगा कि यह गोपनीयता प्रभावित हो रही है। ऐसे में कौन सा आंकड़ा जारी करना चाहिए और किसे नहीं जारी करना चाहिए, यह अलग बहस है। मुझे लगता है कि अगर कोई आंकड़ा निजी नहीं है तो उसे जारी किया जाना चाहिए। लेकिन किस स्तर पर, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, और कौन इसका उपयोग करता है, ये गंभीर सवाल हैं।

लेकिन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग आंकड़े देते हैं?

मोस्पी का काम शोधकर्ताओं को आंकड़े देना नहीं है। इसका काम सरकार को सिफारिशें देना है। पश्चिमी दुनिया से तुलना करना बुरी बात है।

संक्षेप में

सरकार ने 10 दिन में 4,000 टन प्याज बेचा

सरकार ने बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए रियायती दर पर प्याज की बिक्री शुरू करने के पहले 10 दिन में 17 शहरों में करीब 4,000 टन बफर प्याज बेचा है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि केंद्र सरकार के पास 2026 के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के जरिये 1.21 लाख टन प्याज का बफर भंडार है। ये एजेंसियां कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए उत्पादक राज्यों से भंडारित प्याज को थोक में खपत वाले केंद्रों तक पहुंचा रही हैं। इसके लिए समर्पित रेल रैक और ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है।' *भाषा*

बागान में एफडीआई उदार करने पर विचार

सरकार बागान क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को और उदार बनाने पर विचार कर रही है। इसके तहत केले जैसी अन्य वाणिज्यिक फसलों को भी एफडीआई के दायरे में लाया जा सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हम केले जैसे बागान क्षेत्र में एफडीआई को और उदार बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।' चाय, कॉफी, रबड़, इलायची, पाम और जैतून के पेड़ों के बागान में स्वतः मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। *भाषा*

एसबीआई चालू वित्त वर्ष में 12,000 भर्तियां करेगा

सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष में करीब 11,000 से 12,000 कर्मचारियों की भर्ती करने और अपने शाखा नेटवर्क के विस्तार की योजना बना रहा है। बैंक के चेयरमैन सी. एस. शेट्टी ने कहा कि बैंक चालू वित्त वर्ष में लिपिक और अधिकारी स्तर पर करीब 11,000 से 12,000 नियुक्तियां करेगा। इसके अलावा बैंक की 200 से 250 नई शाखाएं खोलने की भी योजना है। *भाषा*

कोयले का उत्पादन करेगी एनएमडीसी

सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी एनएमडीसी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में तापीय कोयले का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगी। कंपनी का चालू वित्त वर्ष (2026-27) में 10 लाख टन कोयला बेचने का लक्ष्य है। कंपनी के चेयरमैन अमिताव मुखर्जी ने बताया कि इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाली हैदराबाद मुख्यालय वाली एनएमडीसी देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी है। *भाषा*

पेंशन पर रिटर्न की गारंटी पर बात

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 सितंबर

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एक ऐसी पेंशन योजना शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है जिसमें गारंटीशुदा रिटर्न की पेशकश की जाएगी। लेकिन यह प्रस्ताव अभी भी चर्चा के दौर में है क्योंकि गारंटीशुदा भुगतान की सुविधा देने के लिए कोष प्रबंधकों को बाजार जोखिम से बचाव (हेजिंग) करना होगा। अभी पेंशन फंडों को केवल डेरिवेटिव तक सीमित और सशर्त पहुंच की इजाजत है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, 'नियामक गारंटीड रिटर्न वाली नई योजना शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है और इस पर अभी काम चल रहा है। हम इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसकी लागत ज्यादा आएगी। सुनिश्चित रिटर्न देने के लिए हेजिंग और दूसरे तरीकों की जरूरत होती है। हमारी सबसे बड़ी खासियत हमेशा कम लागत रही है इसलिए हमें लागत को काबू में रखना होगा।'

पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए न्यूनतम गारंटीड रिटर्न योजना पर काम कर रहा है लेकिन यह योजना अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। नियामक अंशदाताओं के लिए सुनिश्चित भुगतान वाले विकल्प पर भी विचार कर रहा है।

एक सूत्र ने कहा, 'फिलहाल हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन हम नियामकों के साथ मिलकर इस संभावना का अध्ययन कर रहे हैं। उद्योग में फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स (एफआरए) का इस्तेमाल धीरे-धीरे विकसित हो रहा है और भविष्य में पेंशन फंडों को भी डेरिवेटिव तक पहुंच मिल सकती है। हालांकि इसके लिए उन्हें इनका इस्तेमाल करने के लिए जरूरी तंत्र भी तैयार करना होगा।'

इसके अलावा पीएफआरडीए ने पिछले वित्त वर्ष और चालू वित्त वर्ष में अब तक एनपीएस के नियमों में कई बदलाव किए हैं।

दिसंबर 2025 में नियामक ने 'साझा योजना' और 'विविध योजना ढांचा' के तहत गैर-सरकारी अंशदाताओं के लिए योजना से बाहर निकलने (एग्जिट) और पैसे निकालने के नियमों को आसान बनाया है। जिन अंशदाताओं की बचत 12 लाख रुपये से ज्यादा थीं उनके लिए एग्जिट के समय एकमुश्त पैसे निकालने की सीमा पहले के 60 फीसदी से बढ़ाकर कुल कोष का 80 फीसदी कर दिया गया है और उसी हिसाब से अनिवार्य वार्षिकी (एन्युटी) वाले हिस्से को कम कर दिया गया। उसी महीने पीएफआरडीए ने पेंशन फंडों को जिंसों में भी एनपीएस के पैसे को लगाने की अनुमति दी है।

जनवरी 2026 में पीएफआरडीए ने ऐसा ढांचा मंजूर किया जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र रूप से एनपीएस परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाले पेंशन फंडों को प्रायोजित कर सकेंगे। इसके अलावा एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड में तीन नए न्यासियों की नियुक्ति की गई। ग्राहकों को सुनिश्चित भुगतान देने के विकल्प की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है और एनपीएस वात्सल्य के एग्जिट नियमों में भी ढील दी गई। एनपीएस वात्सल्य के तहत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस खाते खोल सकते हैं।

चालू वित्त वर्ष में जून 2026 में पीएफआरडीए ने पॉइंट्स ऑफ प्रजेंस के लिए ऑडिट नियमों को और कड़ा किया। पॉइंट्स ऑफ प्रजेंस वे मध्यस्थ हैं जिनके माध्यम से ग्राहक एनपीएस खाते खोलते और संचालित करते हैं। 10,000 या उससे अधिक ग्राहकों वाले ऐसे मध्यस्थ के लिए वार्षिक ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया जबकि छोटे पॉइंट्स ऑफ प्रजेंस के लिए कम आवृत्ति पर ऑडिट का प्रावधान किया गया। इन ऑडिट में योगदान, निकासी और सेवा अनुरोधों से जुड़े परिचालन नियंत्रणों की भी जांच की जाएगी।

इसके अलावा जुलाई में संशोधित सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) शुल्क ढांचा लागू हुआ। इससे टियर 1 और टियर 2 खातों का सालाना रखरखाव शुल्क बदल गया और लगातार चार तिमाही तक कोई योगदान नहीं करने वाले निष्क्रिय खातों के पर शुल्क कम किया गया और 1,000 रुपये तक शेष राशि वाले टियर 2 खातों पर शुल्क को माफ कर दिया गया।

अजय मोहंती

पेंशन नियामक की मंत्रालय से बातचीत जारी

- पीएफआरडीए पेंशन के न्यूनतम गारंटीड रिटर्न योजना पर काम कर रहा है
- अंशदाताओं के लिए तय भुगतान वाले विकल्प पर भी विचार जारी है
- नियामक ने पिछले व चालू वित्त वर्ष में एनपीएस के नियमों में कई बदलाव किए हैं

जीएसटी की बैठक 7 अक्टूबर को होगी!

मोनिका यादव
नई दिल्ली, 6 सितंबर

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 12 सितंबर को होने वाली 57वीं बैठक अब नई दिल्ली में 7 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। यह जानकारी सूत्रों ने रविवार को दी।

उन्होंने बताया कि जीएसटी बैठक की तारीख 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से टकरा रही थी। इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय को ईमेल भेजा गया था लेकिन खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं मिला। नई तारीख की पुष्टि करने वाली आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है।

सूत्रों के मुताबिक बैठक नई दिल्ली में ही होने की संभावना है। जीएसटी अधिकारियों की बैठकें 5 और 6 अक्टूबर को तय की गई हैं। पहली बैठक 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे शुरू होगी जबकि दूसरी बैठक 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी। आने वाली बैठक एक साल से ज्यादा समय में जीएसटी परिषद् की पहली बैठक होगी।

दरअसल, 3 और 4 सितंबर, 2025 को हुई 56वीं बैठक में जीएसटी 2.0 में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई थी। इस बदलाव के तहत ज्यादातर सामान और सेवाओं को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो मुख्य कर स्लैब में रखा गया। परिषद ने कुछ खास तरह के नुकसानदेह और लग्ज़री सामानों के लिए 40 प्रतिशत की एक खास दर भी तय की, जिसने पहले के 28 प्रतिशत स्लैब और उन चीजों पर लगने वाले मुआवजा सेस की जगह ले ली। नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू हुईं। उम्मीद है कि अक्टूबर की बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिफंड और जीएसटी नियमों के पालन से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इनमें कुछ आईटीसी दावों पर पाबंदियों में ढील देने और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत जमा क्रेडिट की समस्या को हल करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं और इसमें सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। नियमों के मुताबिक परिषद की बैठक हर तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए।

एनटीपीसी की परमाणु ऊर्जा नियमों में बदलाव की मांग

नंदिनी केशरी
नई दिल्ली, 6 सितंबर

बिजली बनाने वाली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने शांति के मसौदा नियमों और विनियमन में चार बड़े बदलावों की मांग की है। इनमें नई कंपनियों की परिभाषा से तीन साल की समयसीमा हटाना, यूटिलिटी-अग्नोस्टिक मंजूरी प्रक्रिया, लाइसेंसिंग के समय को आधा करना और तकनीक डिजाइन मंजूर होने के बाद उपकरण आयात करने के लिए अलग से मंजूरी लेने से छूट शामिल है। यह जानकारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने 'बिज़नेस स्टैंडर्ड' को दी।

उन्होंने कहा कि एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) से बदलाव करने का आग्रह किया है। दरअसल, डीएई ने पिछले महीने साझेदारों की राय जानने के लिए शांति अधिनियम का मसौदा और विनियमन जारी किए थे। अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, 'हमने नई कंपनियों की परिभाषा में बदलाव की मांग की है। मसौदा में कहा गया है कि तीन साल (कंपनी का अस्तित्व) होना चाहिए। हमारा सुझाव है कि यह समयसीमा हटा दी जानी चाहिए।'

लाइसेंस चाहने वाली किसी भी कंपनी के पास साइट और टेक्नॉलजी से जुड़े अनुभव के अलावा वित्तीय, प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमताएं होनी चाहिए। आमतौर पर मजबूत बही-खाता नहीं होने पर नई कंपनियों में ऐसी क्षमताएं होने की संभावना कम होती है। अधिकारी ने कहा कि कंपनी बनने के शुरुआती तीन सालों में तो ऐसी कंपनी को अपनी पैरेंट कंपनी से मदद मिल सकती है, लेकिन उसके बाद इन क्षमताओं की जरूरतों के कारण उसे लाइसेंस नहीं मिल पाएगा।

ड्राफ्ट नियमों में 'नई बनी एंटिटी" को ऐसे योग्य के तौर पर परिभाषित किया गया है जो लाइसेंस के लिए आवेदन की तारीख पर तीन साल या उससे कम समय से अस्तित्व में हो। मसौदा में कहा गया है कि लाइसेंस देने के लिए क्षमताओं का आकलन करने के मकसद से आवेदक को अपनी वित्तीय, प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमताएं दिखानी होंगी।

एनटीपीसी की योजना 2047 तक 30 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने की है। यह काम एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएस) के संयुक्त उपक्रम 'अनु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड' (अश्विनी) और जनवरी 2025 में बनी एनटीपीसी की पूरी तरह से अपनी न्यूक्लियर सब्सिडियरी 'एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड' (एनपीयूएनएल) के जरिए किया जाएगा। संयुक्त उपक्रम अश्विनी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 2,400 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना बना रहा है। इसे 'माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट' कहा जाता है।

एनटीपीसी की शांति के मसौदा नियमों व विनियमन में बड़े बदलावों की मांग

बीएस सूडोकू 5686

		8			1	4		
6		3				9		
		2						3
			8				7	1
								2
7					4			
	4			8				7
					3	2		9
	8	9	6			1		

परिणाम संख्या 5685

4	7	3	1	2	8	5	6	9
9	2	5	6	4	7	3	1	8
8	6	1	5	3	9	2	7	4
3	5	8	9	6	1	7	4	2
6	4	9	7	5	2	8	3	1
7	1	2	4	8	3	6	9	5
2	8	4	3	9	6	1	5	7
1	9	6	8	7	5	4	2	3
5	3	7	2	1	4	9	8	6

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

मुश्किल

★★★★☆

ट्रकों का मालभाड़ा स्थिर, प्रमुख मार्गों पर आई तेजी

अगस्त में त्योहारी मांग के कारण प्रमुख मार्गों पर ट्रकों के किराए स्थिर रहे हैं। मौसम संबंधी व्यवधानों ने कुछ क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को प्रभावित किया। सभी प्रमुख मार्गों पर सालाना आधार पर किराया अधिक बना हुआ है। रविवार को जारी श्रीराम मोबिलिटी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है।

जुलाई की तुलना में अगस्त महीने में मुंबई-कोलकाता-मुंबई और बेंगलुरु-मुंबई-बेंगलुरु मार्ग पर मालभाड़े में 2-2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता मार्ग पर 1.9 प्रतिशत और दिल्ली-कोलकाता-दिल्ली मार्ग पर मालभाड़ा 1.7 प्रतिशत बढ़ा है।

निगरानी किए गए अन्य मार्गों पर किराए में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली-मुंबई-दिल्ली और दिल्ली-चेन्नई-दिल्ली मार्ग पर मालभाड़े में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि सालाना आधार पर सभी मार्गों पर मालभाड़ा बढ़ा है। दिल्ली-कोलकाता-दिल्ली मार्ग पर 15 प्रतिशत, बेंगलुरु-मुंबई-बेंगलुरु व कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता मार्ग पर मालभाड़ा 11-11 प्रतिशत बढ़ा है। शेष मार्गों पर मालभाड़ा 3 प्रतिशत से 8 प्रतिशत अधिक रहा है। हालांकि अगस्त में वाहनों की बिक्री पिछले महीने की तुलना में सुस्त रही है। वाणिज्यिक ट्रैक्टरों और कृषि ट्रेलरों की बिक्री में मासिक आधार पर 35-35 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कृषि ट्रैक्टरों की बिक्री में 27 प्रतिशत की गिरावट आई। मैक्सी कैब, बस और ई-रिक्शा की बिक्री में क्रमशः 20 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 17 प्रतिशत की गिरावट आई, और गुड्स कैरियर की बिक्री 10 प्रतिशत कम रही।

श्रीराम फाइनैंस के संयुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी (वाणिज्यिक वाहन) सुदर्शन होल्ला ने कहा, 'केरल में ओणम शुरू होने के साथ त्योहारों के सीजन की शुरुआत हो गई है। इससे परिवहन क्षेत्र की धारणा मजबूत हुई। माल ढुलाई में तेजी बनी हुई है, जिससे प्रमुख मार्गों पर ट्रकों के किराए स्थिर रहे। उपभोक्ता मांग भी मजबूत हुई है। ट्रांसपोर्टर नवंबर 1 से प्रभावी होने वाले एनसीआर में बीएस-4 ट्रकों के प्रवेश पर आगामी प्रतिबंध से राहत के लिए सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं।' *बीएस*

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 19 अंक 174

गलत उपचार

जी-20 अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय ट्रैक के नेताओं की बैठक इस सप्ताह अमेरिका की अध्यक्षता के तहत नॉर्थ कैरोलाइना के ऐशविल में हुई। अमेरिका का वित्तीय या फाइनेंस ट्रैक के प्रति नजरिया तीन मुद्दों को प्राथमिकता देता है- वृद्धि, वैश्विक असंतुलन और वित्तीय साक्षरता। ये प्राथमिकताएं भारत और समूह के अधिकांश सदस्यों की भी हैं। हालांकि ऐशविल शिखर सम्मेलन में सहमति नहीं बन सकी और इसके कारण समझना आसान है। 20 में से 19 सदस्य अध्यक्ष के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। भंडार और व्यापार अधिशेष के रूप में वैश्विक असंतुलनों से लाभान्वित होने के कारण उसने लगातार इन्हें समस्या मानने से इनकार किया है। परंतु घोषणापत्र में उल्लेख किया गया कि बड़े पैमाने पर असंतुलन प्रमुख वैश्विक अस्थिरता का कारण हैं और इनके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। ये कुछ अर्थव्यवस्थाओं में गैर-बाजार स्थितियों और गैर-शुल्क बाधाओं के लक्षण भी हैं।

इस मामले में यह स्पष्ट है कि ये चिंताएं ठोस बुनियाद पर आधारित हैं। चीन के बाजार बाहर की कंपनियों के लिए काफी हद तक बंद हैं। अर्थव्यवस्था पर कम्युनिस्ट पार्टी का अतिशय नियंत्रण उसे निवेश को प्राथमिकता देने पर विवश करता है, यहां तक कि स्वस्थ खपत पर भी जरूरत से ज्यादा निवेश को तरजीह दी जाती है जो विश्व स्तर पर समग्र मांग को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ उत्पादन और निर्यात क्षेत्रों में उसके लक्षित यद्यपि छिपे हुए सब्सिडी बाजार सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और उन शर्तों के विपरीत हैं जिन पर उसे 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल किया गया था।

इस मुद्दे पर चीन का अलग-थलग पड़ना इस बात का संकेत है कि उसने लगातार इन चिंताओं को संबोधित करने से इनकार किया है और अब तो इस बात से भी नकार रहा है कि वे मौजूद हैं। इसका मकसद इस शिखर सम्मेलन और ऐसे अन्य प्रयासों को जो उसके लगातार बने रहने वाले असंतुलन की समस्या को संबोधित करने के लिए किए जाते हैं, चीनी अर्थव्यवस्था की बढ़त को रोकने की कोशिश के तौर पर पेश करना है।

अगर इसी अवधि में अमेरिका ने खुद यह दावा करके अपनी विश्वसनीयता नष्ट नहीं की होती कि एकतरफा शुल्क वह उचित तरीका है जिसके जरिये असंतुलन की समस्या का समाधान किया जा सकता है तो इसे कोई स्वीकार नहीं करता। जिस तरह चीन अपनी गैर-बाजार नीतियों और व्यापार व्यवस्था के अपने हित में इस्तेमाल को लेकर दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है उसी तरह अमेरिका भी पिछले कुछ वर्षों में उसके द्वारा अपनाए गए एकतरफावाद और व्यापारिक राष्ट्रवाद के कारण लगभग उसी हालत में है। यह स्थिति विशेष रूप से तब से बनी है जब से डॉनल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं।

ट्रंप द्वारा शुरू में लगाए गये शुल्क सीधे तौर पर व्यापार घाटे को निशाना बनाने के लिए तैयार किए गए थे। लेकिन व्यापार असंतुलन अपने-आप में गहरी समस्याओं के लक्षण हैं-बचत और निवेश के बीच असंतुलित व्यवस्था और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो जरूरत से ज्यादा या तो बचत पर या फिर खपत पर निर्भर हैं। इसलिए बीमारी का इलाज करने के बजाय उसके लक्षण को दूर करने की कोशिश करना, खासकर एकतरफा और बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के ऐसा करना अतार्किक नीति-निर्माण है।

यह जरूरी है कि चीन के सभी व्यापारिक साझेदार उस पर अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए दबाव डालें ताकि वहां घरेलू खपत बढ़े और चीन विदेशी तैयार वस्तुओं के लिए एक बड़ा बाजार बन सके। भारत के नजरिये से ऐसे शिखर सम्मेलन का स्वागत करना आकर्षक लग सकता है जो चीन को इतनी स्पष्टता से अलग-थलग करता हो। लेकिन भारत की विकास यात्रा के सामने दो तरफ से खतरा है-एक ओर चीन द्वारा नियंत्रित और अपने हित में संचालित बंद व्यापार व्यवस्था तथा दूसरी ओर अमेरिका द्वारा लाई गई आर्थिक राष्ट्रवाद तथा शुल्क की दीवारों का नया दौर।

जी 20 का उद्देश्य इन दोनों समस्याओं का सामूहिक और सहयोगपूर्ण तरीके से समाधान करना होना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो यह शिखर सम्मेलन अपने उद्देश्य को हासिल करने में विफल रहा।

एथनॉल मिश्रण और भाजपा के मतदाताओं का गुस्सा

एथनॉल मिश्रित पेट्रोल का विचार अच्छा हो सकता है लेकिन इसकी तैयारी के लिए तीन से चार वर्ष का समय होना चाहिए था। आंशिक रूप से ही सही, इस नीति को वापस लेने पर विचार होना चाहिए।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

यह बहस गर्म है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 7.8 फीसदी की दर से बढ़ा या 2.6 फीसदी की दर से।

टीवी स्टूडियो में बैठे लोग जिस तरह रातोरात अर्थशास्त्री बनकर एक-दूसरे की आलोचना कर रहे थे, उसे देखकर सर्जियो गोर को भी जरूर काफी मजा आया होगा। यह सब मजेदार है लेकिन राजनीति के नजरिये से यह एक गलत बहस है। वैसे भी अब दूसरी तिमाही दो तिहाई से ज्यादा गुजर चुकी है तो यह बहस ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

सवाल यह है कि यह बहस गलत क्यों है और सही बहस क्या है? यह केवल इसलिए गलत नहीं है कि यह अस्थायी है। बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस ध्रुवीकृत माहौल में लोग बहुत शिद्दत के साथ अपने राजनीतिक सिद्धांतों में यकीन करते हैं। कोई भी मतदाता जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर अपना मन नहीं बदलेगा। जो बहस मायने रखती है वह एकदम अलग है: एथनॉल मिश्रण को लेकर गुस्सा।

वाहन मालिकों का एक बड़ा वर्ग, खासकर हिंदू मध्य वर्ग मोदी-शाह की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्पित मतदाता है। वे बेहद नाराज हैं। हमने इस पर कोई सर्वे नहीं देखा है लेकिन बीते कुछ महीनों में मैं ऐसे ढेर सारे लोगों से मिला जिनमें हवाई अड्डों पर मिले अजनबी, शादी समारोह में मिले लोग, होटल की लॉबी में मिले लोग, आगंतुक, उबर चालक, आदि शामिल थे। ये सभी बेहद गुस्से में नजर आए। सबके पास एक ही वजह थी: हमें पेट्रोल मिला एथनॉल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कैसे किया जा सकता है?

मोदी सरकार के विकास के आंकड़ों का बचाव करने वाले भी उसी तादाद में मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि जिस आधार को भाजपा इतनी गंभीरता से लेती है वह सिर्फ इसी एक मुद्दे को लेकर उससे नाराज है। बेशक सभी लोग मानते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की और दुनिया, जिसमें पुतिन और शी भी शामिल हैं, उनके नेता का सम्मान करती है-'जैसा कि हमने अभी बिश्केक में देखा।' तो फिर मुझे यह 'मिलावटी' पेट्रोल देकर सजा क्यों दी जा रही है?

मोटे तौर पर उनकी चिंताएं और सवाल ये हैं: मुझे इससे क्या फायदा मिलता है? मैं उतनी ही कीमत चुकाता हूं लेकिन मुझे कम माइलेज मिलता है जैसा कि सरकार खुद स्वीकार करती है। इसके अलावा मैं अभी भी अपनी गाड़ी की ईएमआई चुका रहा हूं जबकि इससे इंजन को नुकसान भी हो सकता है। मेरे देश को इससे क्या फायदा है? अगर कोई फायदा है तो मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा?

मुझे विकल्प क्यों नहीं दिया गया? पहले तो कोई मुझे यह नहीं बताता कि मुझे ईबीपी (एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। फिर कहा जाता है कि इसे इस्तेमाल करो या फिर पैदल चलो। मेरे कष्ट या मेरे त्याग का फायदा किसे मिल रहा है?

ये अहम सवाल हैं और संभवतः सरकार के पास इनके जवाब भी हैं। हैरानी की बात है कि उसने अपने मतदाताओं को विश्वास में लेने की कोई कोशिश नहीं की।

अगर परीक्षा घोटालों की लगातार सामने आती घटनाओं के अलावा कोई एक मुद्दा है जिस पर भाजपा का आधार वर्ग नाराज है तो वह एथनॉल मिश्रित पेट्रोल ही है। साल 2014 से ही हिंदू बहुल मध्यवर्ग मोदी सरकार का सबसे भरोसेमंद वोट बैंक रहा है। उसकी निष्ठा इतनी मजबूत रही है कि उसने ऊंची ईंधन कीमतों को लेकर चिंता और नाराजगी के बावजूद मोदी को वोट दिया। वह तब भी सरकार के प्रति उदार रहा जब कच्चे तेल की कीमतें सबसे निचले स्तर पर थीं और सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ाकर उस लाभ का बड़ा हिस्सा अपने पास रखना जारी रखा। इस अप्रत्याशित राजस्व को गरीबों तक मुफ्त अनाज और अन्य प्रत्यक्ष लाभों के रूप में प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया। इससे भाजपा को लगातार चुनाव जीतने में मदद मिली

मैंने इसे ही कभी रॉबिन हुड का हाइब्रिड संस्करण कहा था। यानी वफादार मध्यवर्ग से लो, गरीबों में बांटो और अमीरों को परेशान मत करो। इसका आशय यह था कि जिस तरह 'पंथ निरपेक्ष' पार्टियां मुस्लिम वोट को अपना मानकर चलती हैं उसी तरह भाजपा भी विशाल हिंदू मध्यवर्ग को अपना वोट बैंक मान सकती है। अब यही मतदाता नाराज हैं।

चाहे नोटबंदी हो या अचानक पूरे देश में लगाया गया कोविड-19 लॉकडाउन। बौद्धिक स्तर पर पार्टी हल्के प्रोत्साहन के जरिये व्यवहार में बदलाव वाली अर्थव्यवस्था के विचार को बढ़ावा देती रही है। लेकिन ईबीएम के मामले में न तो कोई स्पष्ट आह्वान किया गया और न ही कोई हल्का प्रोत्साहन दिया गया।

ऐसा लगता है मानो यह विचार अचानक किसी को पसंद आ गया और हम अपने-आप 2013-14 में 1.56 फीसदी एथनॉल मिश्रण से बढ़कर अब लगभग 20 फीसदी तक पहुंच गए। अब 30 फीसदी मिश्रण की भी जोरदार चर्चा हो रही है।

यहां दो समस्याएं हैं। पहली खरीदार नाराज हैं और उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। दूसरी अधिक एथनॉल उपलब्ध ही नहीं है। मौजूदा स्तर के मिश्रण को बनाए रखने के लिए भी पर्याप्त एथनॉल नहीं है जब तक कि आप अनाज (चावल) के भंडार में गहराई तक हाथ डालना शुरू न कर दें। इसके अलावा लोग इससे अधिक मिश्रण स्वीकार नहीं करेंगे।

कागज पर देखें तो आयातित कच्चे तेल की जगह देश में उत्पादित एथनॉल का इस्तेमाल करना अच्छा विचार लगता है। दिक्कत यह है कि आपके पास एथनॉल का कोई ऐसा भंडार नहीं है, जिसे जरूरत पड़ने पर निकालकर इस्तेमाल किया जा सके। हमारे किसानों को एथनॉल के लिए फसल उगानी पड़ती है-गन्ना, मक्का या धान।

यह विचार सालों से चले आ रहे चीनी के अधिशेष की स्थिति से निकला था। चीनी मिलें अपना पैसा वसूल कर सकती थीं और किसानों का बकाया चुका सकती थीं। स्थिति इतनी अनुकूल लग रही थी कि चीनी मिलों को गन्ने के रस को सीधे एथनॉल में बदलने की अनुमति तक दे दी गई। बाजार में पहले ही चीनी की भरमार थी।

यह योजना सुनने में बहुत अच्छी थी लेकिन इसमें खेती की अनिश्चितताओं का कोई हिसाब नहीं लगाया गया। मसलन जिंस बाजार, बारिश और सबसे बढ़कर कीट। महज एक फसल वर्ष के भीतर गन्ना नाटकीय रूप से अधिशेष से किल्लत की स्थिति में पहुंच गया। खासकर रेड रॉट (फफूंद) और टॉप बोरर (कीट) ने पैदावार को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया।

इस सीजन की शुरुआत चीनी के शुरुआती भंडार में 50 लाख टन की कमी के साथ हुई और अब यह भंडार घटकर करीब 2.8 करोड़ टन की ओर बढ़ रहा है। नतीजा यह हुआ कि चीनी की कीमतों में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। त्योहारों का मौसम सामने है, तो क्या हम चीनी की कीमतों को आसमान छूने दे सकते हैं?

जैसे-जैसे एथनॉल की खरीद में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई और यह 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर इस साल 1,200 करोड़ लीटर तक पहुंच गया। इसके साथ ही रिफाइनर मक्के की ओर मुड़ गए। इसके बाद मक्के की कीमतों में भी करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब यह है कि दूध, पोल्ट्री और मांस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि मक्का पशु आहार में इस्तेमाल होता है।

अब बारी धान की आई। पहले टुकड़ा चावल का इस्तेमाल किया गया और फिर किसी भी अतिरिक्त चावल का। इस साल ईंधन के लिए 75 लाख टन चावल आवंटित किया गया है और सरकार ब्लेंडिंग जारी रखने के लिए इसे बाजार कीमत की लगभग आधी कीमत पर बेच रही है। इनमें से काफी आंकड़े मैंने द इंडियन एक्सप्रेस में हरीश दामोदरन और अशोक गुलाटी के बेहतरीन विश्लेषणों से लिए हैं। इसे आपके लिए संक्षेप में कहूं तो बात यह है: ईबीपी भले ही एक शानदार विचार हो, लेकिन चूंकि यह कृषि पर निर्भर था इसलिए इसे लागू करने से पहले तीन-चार साल की तैयारी जरूरी थी।

किसान को अपनी फसल का चुनाव बदलने के लिए तैयार करना था, उसके लिए बाजार तैयार करना था, यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी जरूरी खाद्य वस्तु की कमी न हो और हम खाद्य बनाम ईंधन के जाल में न फंस जाएं। और अंत में, उपभोक्ता को मिश्रित पेट्रोल के लिए तैयार करना था।

आदर्श स्थिति यह होती कि उन्हें विकल्प दिया जाता और मिश्रित पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से काफी कम रखी जाती। यह काम उत्पाद शुल्क में बदलाव करके आसानी से किया जा सकता था।

परिणामस्वरूप चीनी की किल्लत है। विदेशी मुद्रा का भंडार तेजी से खर्च हो रहा है, त्योहारों के मौसम में कीमतें बढ़ गई हैं और ईबीपी के लिए चावल के बफर स्टॉक को लगभग आधी कीमत पर खपाया जा रहा है। कई मायनों में यह कई अहम मुद्दों पर मोदी सरकार के काम करने के तरीके को रेखांकित करता है। अतीत में खासकर नोटबंदी और कृषि कानूनों के बाद, जिनका मैंने संपादकीय रूप से समर्थन किया था हमने मोदी सरकार के इस तरह के फैसले लेने के तरीके की तुलना ऐसे पैराट्रूपर से की है जो पैराशूट की जांच किए बिना ही छलांग लगा देता है।

ईबीपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे पास चीनी की कमी है, एथनॉल की कमी है और जिन चीजों का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, उन सभी की कीमतें बढ़ रही हैं यहां तक कि कच्चे तेल की कीमत भी। ऐसे में एक और नीतिगत वापसी पर विचार होना चाहिए भले ही आंशिक रूप से। या तो मिश्रण को घटाकर 10 फीसदी किया जाए या उपभोक्ताओं को विकल्प दिया जाए। ध्यान रहे यह नाराजगी भाजपा के प्रतिबद्ध मतदाताओं की ओर से आ रही है।

टाटा समूह: दोहरे संकट के पीछे के सवाल

सामयिक सवाल

निवेदिता मुखर्जी

टाटा समूह एक पारिवारिक व्यवसाय है या पेशेवर रूप से प्रबंधित संस्था? क्या टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा संस (नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक के इस विशाल समूह की होल्डिंग कंपनी) में 66 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है, पारंपरिक अर्थों में एक प्रमोटर है? समूह के शीर्ष नेतृत्व में टाटा नाम का कितना महत्त्व है? क्या टाटा ट्रस्ट्स जैसा कोई धर्मार्थ संगठन लगभग 320 अरब डॉलर के मूल्य वाले करीब 26 सूचीबद्ध इकाइयों के एक विविध समूह का संचालन और नियंत्रण कर सकता है? क्या टाटा समूह के स्वामी के रूप में कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह प्रतिनिधित्व करता है? क्या टाटा समूह की संरचना में बदलाव की आवश्यकता है ताकि उक्त प्रश्नों को जन्म देने वाली कुछ विसंगतियों का समाधान किया जा सके?

पिछले कुछ दिनों में ये सवाल अलग-अलग संदर्भ में बार-बार उठे हैं। अगस्त में एक सप्ताह के भीतर घटी दो घटनाओं ने इन्हें और हवा दी। पहली घटना 12 अगस्त को हुई, जब एन चंद्रशेखरन (जिन्हें चंद्रा कहा जाता है) ने घोषणा की कि फरवरी 2027 में उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह टाटा संस के अध्यक्ष पद के लिए फिर उम्मीदवार नहीं बनेंगे। इस अप्रत्याशित कदम के पीछे का कारण चंद्रा द्वारा टाटा संस के निदेशक मंडल को लिखे पत्र और कंपनी द्वारा जारी बाद के बयान में स्पष्ट था: 24 फरवरी, 2026 को टाटा संस की बोर्ड बैठक में एक सदस्य ने उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जिसे पिछले साल टाटा ट्रस्ट्स ने सर्वसम्मति से पारित किया था। टाटा संस नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा दर्ज और अनुशंसित इस प्रस्ताव में चंद्रा को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अगले पांच वर्ष के लिए नवीनीकृत करने की बात कही गई थी।

दूसरा घटनाक्रम टाटा संस की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का 18 अगस्त को स्थगित होना था। टाटा संस के 100 साल के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी एजीएम को स्थगित करना पड़ा। स्थगन का कारण कोरम की कमी थी। टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) के अनुसार एजीएम में दो प्रमुख ट्रस्टों सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) का संयुक्त प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। यह संभव नहीं था क्योंकि एसआरटीटी के निर्णय लेने पर महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में स्थायी न्यास नियमों से संबंधित कथित उल्लंघन के आधार पर रोक लगा दी गई थी।

पिछले महीने कुछ ही दिनों के अंतराल में उत्पन्न हुए दोहरे संकटों के कारणों को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है, लेकिन गहन विश्लेषण से दोनों मामलों में कार्यप्रणालीगत मनमानी स्पष्ट होती है। चंद्रा का तीसरी बार पदभार ग्रहण न करने का निर्णय किसी विशेष परिस्थिति में उनकी व्यक्तिगत पसंद का मामला हो सकता है। लेकिन इससे पहले की घटनाओं से टाटा ट्रस्ट्स में एक प्रणालीगत समस्या का पता चलता है। टाटा ट्रस्ट्स के दो प्रमुख निकायों एसआरटीटी और एसडीडीटी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का कुछ महीनों बाद समूह के सबसे बड़े निर्णय लेने वाले निकाय, टाटा संस बोर्ड में सर्वसम्मति खो देना एक संगठनात्मक कमजोरी का संकेत है। चंद्रा पर टाटा ट्रस्ट्स के प्रस्ताव को इसके अध्यक्ष नोएल टाटा ने अनुमोदित किया था, और टाटा संस बोर्ड की बैठक में उन्हीं व्यक्ति ने नामित न्यासी के रूप में इसका विरोध किया था।

नोएल टाटा ने चंद्रा के तीसरे कार्यकाल का विरोध करते हुए एअर इंडिया और टाटा डिजिटल जैसी कुछ संस्थाओं की लाभप्रदता पर सवाल उठाए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में उनके रुख में आए बदलाव का असली कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। सेवानिवृत्ति की आयु भी चर्चा का विषय रही है, लेकिन इस पर खुलकर बात नहीं हुई है। टाटा समूह में कार्यकारी अधिकारी 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। इस नियम के अनुसार, 63 वर्षीय चंद्रा को अगर तीसरा कार्यकाल मिलता है, तो टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल दो साल से भी कम होगा। यह तथ्य तब छिपा नहीं था जब टाटा ट्रस्ट्स ने पिछले साल चंद्रा की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए और समूह के भविष्योन्मुखी क्षेत्रों पर दांव लगाने के समय 'निरंतरता' का सर्वसम्मति से समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। यदि आयु एक बाधा थी, तो क्या रतन टाटा की तरह चंद्रा के लिए गैर-कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बोर्ड स्तर पर कोई चर्चा हुई थी? ऐसा प्रतीत नहीं होता।

टाटा संस की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के स्थगन के मामले में, एसआरटीटी द्वारा न्यास नियमों के कथित उल्लंघन को समय रहते सुलझाया जा सकता था। महाराष्ट्र सरकार ने 1 सितंबर, 2025 को एक अध्यादेश के माध्यम से महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 में संशोधन किया। इस कानून के अनुसार, आजीवन न्यासियों की संख्या सार्वजनिक न्यास के बोर्ड की कुल संख्या के एक-चौथाई तक सीमित कर दी गई। टाटा ट्रस्ट्स को यह मानने का कारण हो सकता था कि नया कानून मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए नहीं है, लेकिन उन्हें पिछले कई महीनों में कानूनी स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए था और सुधार के उपायों पर चर्चा करनी चाहिए थी।

टाटा समूह को चाहे पेशेवर रूप से प्रबंधित व्यवसाय कहा जाए या पारिवारिक स्वामित्व वाला व्यवसाय, टाटा संस के सबसे बड़े शेयरधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों और स्थिरता के प्रतीक माने जाने वाले इस समूह में आगे कोई और संकट न आए।

आपका पक्ष

मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ

देश में कृषि आज भी काफी हद तक मौसम के भरोसे है। बारिश कम हुई तो सूखा, अधिक हुई तो जलभराव, तापमान बिगड़ा तो फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है। इस मौसम जनित जोखिम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इसमें खेत में हुए वास्तविक नुकसान का आकलन करने के बजाय निर्धारित मौसम सूचकांकों जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता और पाला के पूर्वनिर्धारित स्तर से विचलन के आधार पर बीमा भुगतान किया जाता है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मौसम के आंकड़ों के आधार पर दावा निर्धारित होने से पारंपरिक फसल-कटाई प्रयोगों पर निर्भरता कम हो सकती है और क्षतिपूर्ति अपेक्षाकृत शीघ्र मिल सकती है। किसान के लिए यह महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि फसल नष्ट होने के बाद उसे अगली बोआई और परिवार के खर्च के लिए आर्थिक सहारा मिलता है। यह बीमा किसान का आर्थिक नुकसान घटाने का साधन है। इसकी सफलता केवल बीमा खरीदने में नहीं, बल्कि सटीक मौसम-डेटा, सरल नियम, समयबद्ध भुगतान में है।

इशरत अली कादरी, भोपाल

प. बंगाल के नदिया जिले में जूट की कटाई के सीजन में किसान

जल सुरक्षा के लिए वर्षाजल संचयन

भारत को सूखे की चुनौती से निपटने के लिए वर्षाजल की बरबादी रोककर उसके प्रभावी संचयन पर गंभीरता से काम करना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन-आधारित जल-संचयन अभियान चलाने की आवश्यकता है। सिंगापुर और जापान के अनुभव बताते हैं कि वर्षाजल को व्यवस्थित रूप से संग्रहित, पुनः उपयोग और शहरी जल-प्रबंधन से जोड़ा जा सकता है। भारत में घरों, स्कूलों, संस्थानों, उद्योगों और किसानों को छतों पर वर्षाजल संचयन, रिचार्ज पिट तथा जल-पुनर्चक्रण प्रणालियां अपनाने के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। संपत्ति कर में छूट, सब्सिडी, रियायती वित्त और जल-संचय करने वाली इमारतों को प्रोत्साहन संरक्षण को आर्थिक रूप से आकर्षक बना सकती हैं। देश में सफल सामुदायिक मॉडलों को स्थानीय स्तर पर दोहराया जाए। हर नागरिक को जल-सुरक्षा का सहभागी बनाना होगा।

बृज भूषण गोयल, लुधियाना

एफएसएसएआई की कार्रवाई

एफएसएसएआई की कार्रवाई पर प्रकाशित समाचार चिंताजनक हैं। विशेषकर युवा वर्ग को स्ट्रीट फूड का बहुत शौक है। हर गली नुक्कड़, लोकल बाजार, मॉल, बस और रेलवे स्टेशनों पर स्ट्रीट फूड की बाढ़ आ गई है परंतु खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, आसपास की साफ-सफाई, बचे भोजन के निस्तारण, भोजन में प्रयोग होने वाले पदार्थों की एक्सपायरी, डीप फ्रीज तैयार भोज्य पदार्थों के सप्लायर, अंडे-मीट की गुणवत्ता और उनकी खरीद का स्रोत, प्लास्टिक प्लेटों और थैलियों का प्रयोग जैसी स्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इससे जनमानस के स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए एफएसएसएआई का प्रमाण पत्र अनिवार्य होना आवश्यक है। भोज्य पदार्थों का निर्माण असंगठित क्षेत्र में अधिक होता है, इस पर एफएसएसएआई के नियमों और मानकों का कठोरता से अनुपालन आवश्यक है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गोवा में मादक पदार्थों के मुद्दे पर हुई उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

एनएसई डेरिवेटिव में एफआईआई निवेश

	Week ended Aug 28		Week ended Sep 04	
	Contract (Nos)	Tovr (` bn)	Contract (Nos)	Tovr (` bn)
Index Future	164371	268.4	144577	230.9
Stock Future	2258833	1579.0	2042113	1422.2
Index Option	59858938	95740.8	71190799	111795.7
Stock Option	1662900	1177.7	3443926	2308.4
Total	63945042	98766.0	76821415	115355.0

बीएसई 500 कंपनियों में एफआईआई शेयरधारिता

IN %	Jun-25	Sep-25	Dec-25	Mar-26	Jun-26
Chambal Fertilisers & Chem	18.48	19.72	17.12	16.60	16.44
Chennai Petroleum Corp	9.76	9.80	13.79	13.68	16.04
Choice International	14.13	13.13	12.28	11.64	10.23
Choice International	14.13	13.13	12.30	11.64	10.23
Cholamandalam Financial	19.11	18.17	17.25	14.60	13.81
Cholamandalam Investment	28.37	27.44	27.15	25.41	24.97
CIE Automotive India	4.82	4.88	4.96	5.36	5.62
Cipla	26.24	25.82	25.30	23.94	21.32
City Union Bank	28.33	26.95	24.58	24.44	19.75
Clean Science & Technology	6.57	11.79	10.65	14.36	14.37
Coal India	8.39	8.19	8.46	8.62	10.61
Cochin Shipyard	4.69	4.09	3.60	3.96	3.70
Coforge	38.29	35.03	35.56	31.77	46.81
Coforge	38.29	35.03	35.56	31.77	46.55
Cohance Lifesciences	7.86	7.10	6.59	6.16	7.06
Colgate-Palmolive (India)	21.14	17.95	15.98	14.43	14.42
Computer Age Management	53.37	48.51	46.33	46.15	46.52
Concord Biotech	13.30	12.23	11.62	10.81	10.52
Container Corporation Of	12.97	12.62	9.32	8.60	8.15
Coromandel International	16.56	16.78	16.07	15.29	13.75
Craftsman Automation	20.37	19.21	17.85	15.78	17.36
Craftsman Automation	20.37	19.21	17.85	15.78	17.50
CreditAccess Grameen	12.65	12.78	12.23	13.46	13.99

एफआईआई / डीआईआई निवेश

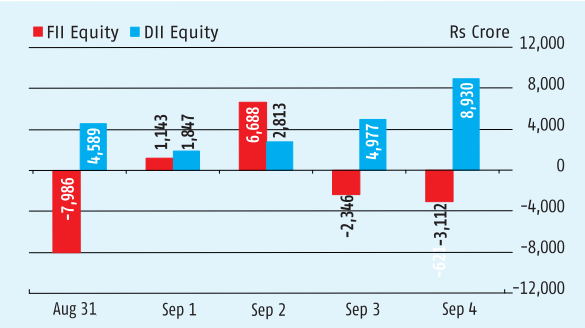

सप्ताह का शेयर (पॉलिकैब इंडिया)

Hits new all-time high at Rs 9,159 , Surged 33 per cent FYTD

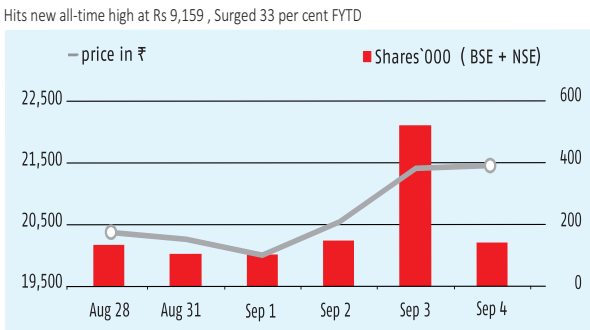

निफ्टी स्नैपशॉट

	Aug 31	Sep 01	Sep 02	Sep 03	Sep 04
Nifty 50 Spot	24080.4	24055.8	23914.4	23873.4	23897.7
Nifty 50 Future	24251.4	24090.3	24000.3	24000.1	24048.1
Prem/Discount	171.0	34.5	85.9	126.7	150.4
Fut(Open Int)	17497	17967	18651	19188	19073
Fut(Contract)	51118	64849	61893	42648	31481
Fut(Value Rs Cr)	8056.8	10186.9	9656.6	6674.3	4927.8
PCR(Open Int)	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
PCR(Contract)	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
Major Call(Strike Price)	24500.0	24100.0	24200.0	24000.0	24000.0
Major Call(LTP)	3.2	4.5	31.5	74.8	69.1
Major Put(Strike Price)	24000.0	24050.0	23000.0	23000.0	23000.0
Major Put(LTP)	30.2	10.2	4.9	2.7	2.0

पुट/कॉल रेशियो

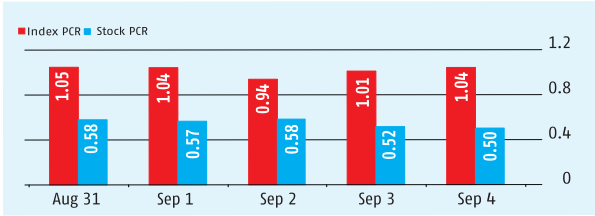

सेक्टर पर नजर

TOP GAINERS	OI '000	% chg	TOP LOSERS	OI '000	% chg
Cables	7424	148.1	Infrastructure Develop	293480	15.6
Trading	125908	28.4	Capital Goods-Non Elect	134954	14.9
Plastic products	21371	25.6	Pharmaceuticals	253073	14.4
Retail	588708	24.4	Miscellaneous	242590	13.8
Diamond, Gems and	76333	21.8	Oil & gas	189188	13.7
Telecomm-Service	2853446	20.8	Healthcare	77912	11.9
Information Tech	30082	20.6	**Top Losers**		
Automobile	546258	18.6	Packaging	9878	-2.1
Air Transport Service	11839	17.8	Agro Chemicals	44256	-1.5

कीमत में बढ़ोतरी के साथ ओपन इंटरेस्ट

	Open Int as on			Price as on		
	Aug 28	Sep 04	% Chg	Aug 28	Sep 04	% Chg
Bank of Maha	16029000	24713000	54.2	83.8	86.0	2.6
Vodafone Idea	175113750	232222275	32.6	14.7	15.0	2.0
Sagility	49044000	62220000	26.9	46.4	46.8	1.0
Oil India	12278000	13868400	13.0	482.9	488.3	1.1
LIC Hsg Fin	41902000	37529000	-10.4	535.0	562.1	5.1
Grasim Ind	9374500	8549750	-8.8	3290.0	3322.0	1.0
RBL Bank	39436675	42783125	8.5	382.0	414.4	8.5
Policy Bazar	6759550	6240500	-7.7	1811.5	1836.0	1.4
UPL	32426505	30137910	-7.1	571.0	582.2	2.0
PI Inds	3891650	4160800	6.9	2420.1	2465.0	1.9
PAYTM	17609525	18721675	6.3	1650.9	1659.5	0.5
Aurob Pharma	10496200	11144100	6.2	1645.3	1653.1	0.5
GAIL	82871200	77883450	-6.0	171.1	173.4	1.3
ONGC	73730250	70020000	-5.0	232.3	234.7	1.0
Colgate	6379450	6063750	-4.9	1826.9	1829.2	0.1
BHEL	76080375	79810500	4.9	430.9	431.1	0.1
Inox Wind	125651200	131737600	4.8	71.8	74.4	3.6
REC	55274625	57925350	4.8	316.8	318.7	0.6

एनएसई सूचकांक

	Aug 28	Sep 04	% Chg
SPOTNifty 50	24175.7	23897.7	-1.1
Bank Nifty	57496.3	57369.6	-0.2
Nifty IT	31281.7	30695.1	-1.9
Futures (LTP)			
Nifty 50	24341.9	24048.1	-1.2
Bank Nifty	57859.0	57774.8	-0.1
Nifty IT	57859.0	57774.8	-0.1
Open Interest			
Nifty 50	16963180.0	19073340.0	12.4
Bank Nifty	2153790.0	2216580.0	2.9
Nifty IT	2153790.0	2216580.0	2.9

तेजी / गिरावट बीएसई

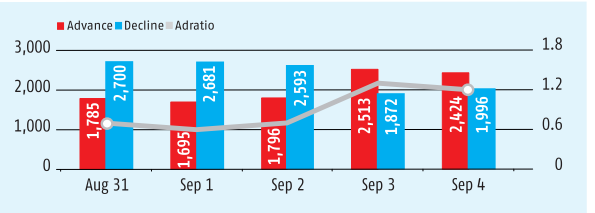

मार्केट पोजीशन

HIGHEST	OI	% of MWL	LOWEST	OI	% of MWL
Highest			Bajaj Holding	348375	2.63
Angel One	76232500	790.17	360 ONE WAM	7310500	16.37
Adani Power	306908150	317.93	L & T	22686475	16.68
LIC India	81965800	255.69	Policy Bazar	9055900	17.51
CAMS	17803500	239.90	Max Health	17151225	17.64
MCX	18209250	238.48	Phoenix Mill	5005000	17.70
Kaynes T	8432400	180.65	Zomato	253856275	18.64
IREDA	183855275	154.49	BPCL	52777925	18.74
Bharat Dyn	19936325	144.61	Nestle India	13491000	18.79

OI As on Sep 04

कीमत में गिरावट के साथ ओपन इंटरेस्ट

	Open Int as on			Price as on		
	Aug 28	Sep 04	% Chg	Aug 28	Sep 04	% Chg
Ather Energy	1807125	3454875	91.2	1616.3	1584.0	-2.0
KEI Ind	1752275	2565325	46.4	5570.0	4850.0	-12.9
Swiggy	73704450	103431875	40.3	280.5	276.1	-1.6
Havells I	7850000	10615500	35.2	1222.9	1154.0	-5.6
Adani Energy So	17361000	22930425	32.1	1581.4	1409.6	-10.9
Polycab India	2348250	2849500	21.3	9088.0	8300.0	-8.7
APL Apolo Tb	9821700	11872350	20.9	2265.6	2250.0	-0.7
Adani Enter	15443202	18614778	20.5	3168.5	2938.0	-7.3
Muthoot Finance	6009025	7164025	19.2	3091.0	2913.8	-5.7
Kaynes T	3635550	4298100	18.2	3943.1	3598.0	-8.8
Shree Cement	354450	418575	18.1	24000.0	23855.0	-0.6
Astral	7025675	5842475	-16.8	1532.3	1492.9	-2.6
Bharat Dyn	6705650	7800450	16.3	1306.0	1255.0	-3.9
Laurus Labs	17005950	19652000	15.6	1938.5	1840.0	-5.1
Maruti Suzuki	2267400	2600400	14.7	13376.0	12694.0	-5.1
Cummins (I)	5423400	6158400	13.6	5193.0	5035.0	-3.0
Radico Khatn	967200	1098000	13.5	4605.0	4494.0	-2.4
CAMS	10626825	9309300	-12.4	762.0	748.8	-1.7

बीएसई सूचकांक

	Aug 28	Sep 04	Change	% Chg
Sensex	**77264.5**	**76515.4**	**-749.1**	**-1.0**
OUTPERFORM SENSEX				
Oil & Gas	25977.7	26169.7	192.0	0.7
Dollex-30	6644.8	6647.9	3.1	0.0
Smallcap	46825.3	46825.3	0.0	0.0
Midcap	44246.3	44246.3	0.0	0.0
Bankex	64963.5	64904.4	-59.1	-0.1
Dollex-100	2806.6	2803.9	-2.7	-0.1
Dollex-200	1985.0	1982.2	-2.9	-0.1
PSU	20651.4	20544.4	-107.0	-0.5
UNDERPERFORM SENSEX				
Auto	63737.2	61406.4	-2330.8	-3.7
Cons Durable	65066.7	63244.0	-1822.7	-2.8
Cap. Goods	79515.0	77868.6	-1646.4	-2.1
IT	29978.9	29401.1	-577.8	-1.9
TECk	15606.7	15318.8	-287.9	-1.8
FMCG	17761.6	17469.9	-291.6	-1.6
Metal	42969.4	42293.7	-675.7	-1.6
Healthcare	51595.0	50913.2	-681.8	-1.3
BSE-200	11382.2	11250.2	-132.0	-1.2
BSE-100	25899.6	25611.4	-288.2	-1.1
BSE-500	36794.0	36385.9	-408.2	-1.1

मार्केट एग्रीगेट्स

BSE	WEEK END Aug 28	WEEK END Sep 04	NSE	WEEK END Aug 28	WEEK END Sep 04
Shares(In Lakhs)	33774	42898	Shares(In Lakhs)	268062	274477
Turnover(In Crore)	55350	63685	Turnover(In crore)	548506	643402
Traded(000)	18301	20320	Traded(000)	174577	186973

डिलिवरी

	BSE		NSE	
DATE	Trd. shares (bn)	% Delivery	Trd. shares (bn)	% Delivery
Sep 04, 2026	8616.4	70.8	60139.4	33.6
Sep 03, 2026	6603.9	69.2	47677.2	37.8
Sep 02, 2026	14049.4	83.5	48053.2	35.9
Sep 01, 2026	6945.2	71.4	48943.2	38.4
Aug 31, 2026	6691.1	67.9	64024.1	47.6
Aug 28, 2026	6225.2	68.0	45496.8	38.2
Aug 27, 2026	6524.1	71.3	48655.3	37.0
Aug 26, 2026	6911.2	67.2	52337.8	38.5
Aug 25, 2026	6352.6	64.3	59073.2	34.8
Aug 24, 2026	7764.6	70.2	55101.9	37.3

शेयर सूचकांकों में उतार चढ़ाव

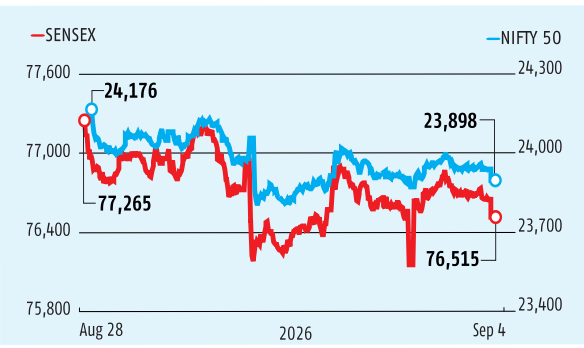

बीएसई 500

	Aug 28	Sep 04	% chg
मुनाफे में			
New India Assurance	186.4	229.8	23.3
IFCI	89.9	101.5	12.8
Caplin Point Lab	2516.1	2810.3	11.7
Tejas Networks	551.5	613.9	11.3
Engineers India	253.9	279.5	10.1
Welspun Living	189.4	208.2	9.9
Welspun Corp	2374.3	2591.2	9.1
RBL Bank	380.3	414.4	9.0
Capri Global	257.7	280.5	8.9
C P C L	1336.2	1451.8	8.7
Sammaan Capital	145.9	158.5	8.6
Nuvoco Vistas	324.5	352.2	8.5
Vedant Fashions	548.2	594.3	8.4
Brigade Enterpr.	643.1	696.0	8.2
PTC Industries	22118.2	23829.3	7.7
Urban Company	168.5	181.4	7.6
Lenskart Solut.	636.2	684.1	7.5
Indraprastha Gas	147.6	158.1	7.1
Sai Life	1480.6	1585.0	7.1
Torrent Power	1217.9	1296.2	6.4
ACME Solar Hold.	393.3	418.1	6.3
City Union Bank	222.3	236.2	6.2
Godrej Agrovet	608.0	645.2	6.1
Physicswallah	119.4	126.6	6.0
Wockhardt	1975.7	2086.8	5.6
LIC Housing Fin.	535.5	565.0	5.5
Aster DM Quality	745.2	785.8	5.5
Aegis Vopak Term	270.1	284.7	5.4
Graphite India	696.7	734.0	5.3
Solar Industries	20380.0	21460.0	5.3
Balrampur Chini	655.0	689.5	5.3
K P R Mill Ltd	1130.0	1185.7	4.9
Jubilant Pharmo	882.1	923.8	4.7
Tata Power Co.	351.7	368.0	4.6
Jindal Stain.	705.1	737.7	4.6
Titagarh Rail	835.1	871.9	4.4
Usha Martin	492.7	514.3	4.4
घाटे में			
R R Kabel	2905.0	2451.1	-15.6
Alok Industries	9.3	7.8	-15.4
KEI Industries	5567.4	4850.0	-12.9
Adani Energy Sol	1580.0	1409.9	-10.8
Zee Entertainmen	101.6	91.3	-10.1
Gravita India	1826.6	1662.3	-9.0
Aarti Industries	540.4	491.9	-9.0
Kaynes Tech	3936.0	3590.0	-8.8
Polycab India	9095.0	8300.0	-8.7
Embassy Develop	62.8	57.4	-8.6
HFCL	251.5	231.4	-8.0
Thermax	3943.0	3634.4	-7.8
Newgen Software	567.4	525.0	-7.5
Adani Enterp.	3166.0	2936.0	-7.3
Ramkrishna Forg.	751.2	700.6	-6.7
Olectra Greentec	1314.5	1228.9	-6.5
Sonata Software	304.7	285.2	-6.4
NMDC Steel	49.1	46.0	-6.2
Amara Raja Ener.	920.8	864.1	-6.2
Finolex Cables	1298.2	1219.8	-6.0
Muthoot Finance	3098.0	2920.0	-5.7
Supreme Inds.	3660.0	3450.2	-5.7
Eicher Motors	8060.0	7600.0	-5.7
Swan Corp	298.2	281.3	-5.7
Bikaji Foods	618.7	583.9	-5.6
Zydus Lifesci.	1187.0	1121.0	-5.6
KPIT Technologi.	609.0	576.0	-5.4
Havells India	1222.0	1156.0	-5.4
ICICI AMC	3140.8	2971.5	-5.4
Hero Motocorp	5604.8	5303.0	-5.4
Paradeep Phosph.	165.8	157.0	-5.3
360 ONE	1200.5	1137.0	-5.3
Dalmia BharatLtd	1845.6	1748.8	-5.2
P & G Hygiene	8095.9	7671.9	-5.2

सेक्टर सूचकांक

Return (%)	Sep 04	1 week	1 month	3 month	6 month	1 year
BSE Sensex	76,515.4	-1.0	-2.4	2.9	-3.3	-5.2
Nifty 50	23,897.7	-1.1	-2.9	2.1	-2.4	-3.4
BSE 100	25,611.4	-1.1	-2.2	2.9	-0.2	-1.1
BSE 200	11,250.2	-1.2	-2.0	2.8	1.2	0.4
BSE 500	36,385.9	-1.1	-1.5	3.4	3.6	1.5
Nifty Midcap	63,079.1	-1.5	-0.6	3.5	10.8	10.7
Nifty Next50	72,880.9	-1.7	-1.8	4.1	9.1	8.5
Nifty 500	23,254.2	-1.2	-1.8	3.4	3.8	1.9
BSE Auto	61,406.4	-3.7	-3.6	6.6	3.5	5.6
BSE Bankex	64,904.4	-0.1	-0.6	6.0	-1.7	7.3
BSE CG	77,868.6	-2.1	-0.4	-2.9	14.3	16.2
BSE CD	63,244.0	-2.8	-3.2	8.3	11.3	1.4
BSE FMCG	17,470.0	-1.6	-5.2	-2.3	-4.2	-16.8
BSE Healthcare	50,913.2	-1.3	0.2	9.0	18.1	15.1
BSE IT	29,401.1	-1.9	-2.5	3.3	0.0	-14.7
BSE TECk	15,318.8	-1.8	-3.0	1.8	-1.6	-9.7
BSE Realty	7,093.0	0.2	1.9	19.0	22.7	3.5
BSE Metal	42,293.7	-1.6	1.3	-3.7	8.8	32.4
BSE Oil&Gas	26,169.7	0.7	-1.0	-1.9	-6.3	1.2
BSE PSU	20,544.4	-0.5	-0.9	-1.7	-4.9	9.9

मोटा सौदा

Date	Stock	Client	Type	Quantity	Price (`)
Sep 02	Altius Telecom Infra Trust	Cdpq Infrastructures Asia Iii Inc.	BUY	731375000	165.0
Sep 02	Altius Telecom Infra Trust	Bif Iv Jarvis India Pte	SELL	520275000	165.0
Sep 02	Altius Telecom Infra Trust	Anahera Investment Pte.	SELL	211100000	165.0
Sep 04	Gland Pharma	Fosun Pharma Industrial Pte.	SELL	9897000	2828.8
Sep 01	EPL	Epsilon Bidco Pte	SELL	84479781	240.6
Aug 31	Lenskart Solutions	Blackrock Emerging Markets Fund Inc	BUY	28008710	662.6
Aug 31	Eternal	Bnp Paribas Financial Markets	SELL	50887261	327.9
Sep 03	Meesho	SVF Ii Meerkat (De) Llc	SELL	80000000	206.3
Aug 31	Eternal	Integrated Core Strategies (Asia) Pte.	SELL	48600304	327.9
Aug 31	Laurus Labs	Bnp Paribas Financial Markets	SELL	6256776	1914.3
Aug 31	Laurus Labs	Integrated Core Strategies (Asia) Pte.	SELL	5132643	1914.0
Aug 31	Lenskart Solutions	Societe Generale	SELL	14040544	661.5
Aug 31	Lenskart Solutions	Integrated Core Strategies (Asia) Pte.	SELL	13511695	661.2
Aug 31	Lenskart Solutions	Bnp Paribas Financial Markets	SELL	12896246	662.2
Sep 04	Gland Pharma	Kotak Mahindra Mutual Fund	BUY	2793000	2826.6
Aug 31	SBI Cards	Bnp Paribas Financial Markets	BUY	9783762	646.0
Aug 31	Astral	Bnp Paribas Financial Markets	BUY	3733051	1522.8
Sep 02	Pine Labs	Alpha Wave Ventures	SELL	35456317	155.1
Sep 04	Swiggy	Goldman Sachs Investments Mauritius I	BUY	19884733	276.1
Aug 31	Laurus Labs	Societe Generale	SELL	2810437	1903.8
Sep 04	Swiggy	BNP Paribas Financial Markets	BUY	17819404	276.1
Aug 31	Ather Energy	Blackrock Global Funds	BUY	2599574	1713.0
Sep 04	Gland Pharma	Axis Mutual Fund	BUY	1357000	2826.6
Sep 02	Aster DM Quality Care	Union (Mauritius) Holdings	BUY	4609800	760.0
Sep 02	Aster DM Quality Care	Centella Mauritius Holdings	SELL	4609800	760.0
Sep 01	EPL	Quant Mutual Fund	BUY	14365577	240.2
Aug 31	SBI Cards	Blackrock Intl	SELL	5286841	647.7
Aug 31	SBI Cards	Blackrock Global Funds	SELL	4998879	644.8
Sep 03	Meesho	Franklin Templeton Mutual Fund	BUY	15250000	206.3
Aug 31	Concord Biotech	1575773 Ontario Inc	SELL	2092325	1404.1
Sep 04	Gland Pharma	ICICI Prudential Mutual Fund	BUY	1039000	2826.6
Aug 31	Northern Arc Capital	Eight Roads Investments Mauritius Ii	SELL	9496000	278.8
Sep 03	Meesho	Hdfc Standard Life Insurance Co Ltd	BUY	12000000	206.3
Aug 31	Balkrishna Ind.	Bnp Paribas Financial Markets	BUY	1020085	2281.0
Aug 31	Astral	Societe Generale	BUY	1350560	1526.6
Sep 03	Clean Max Enviro Energy	Dsdg Holding Aps	SELL	1633727	1220.0
Aug 31	Concord Biotech	Dsp Mutual Fund	BUY	1288114	1404.1
Sep 03	Meesho	Societe Generale - Odi	BUY	8000000	206.3

वैश्विक सूचकांक

Return (%)	Sep 04	1 week	1 month	3 month	6 month	1 year
FTSE 100	10,831.1	0.1	-0.4	4.5	2.5	17.5
Nikkei 255	65,020.9	-2.1	1.7	-3.6	19.9	52.7
Hang Seng	25,650.9	0.3	-0.8	1.6	1.6	2.4
Nasdaq	26,507.0	0.4	-0.3	-1.2	16.2	22.1
Dow Jones	53,414.3	-0.3	-1.2	3.6	9.6	17.1
Rs/$	94.5	0.9	0.9	1.4	-2.5	-6.7
Brent Crude (spot)$/Bbl	94.9	7.0	20.4	0.3	15.5	41.0

ओपन इंटरेस्ट ब्रेकअप

	Price as on Sep 04		Open interest		% of Open interest		
	Close (cash)	LTP (future)	Shares	` crore	Futures	Call	Put
Adani Enter	2938.0	2960.6	31466	9244.8	59.2	26.4	14.5
Adani Ports	1707.3	1710.6	33689	5751.8	61.3	21.4	17.3
Apollo Hosp	8650.0	8700.0	4739	4099.5	58.3	24.9	16.8
Asian Paints	2527.3	2533.2	15976	4037.6	55.8	27.4	16.8
Axis Bank	1273.0	1278.8	122199	15555.9	78.8	11.6	9.6
Bajaj Auto	11919.0	11932.0	4106	4894.4	41.4	33.1	25.5
Bajaj Fin	1060.5	1066.0	100106	10616.2	71.9	15.7	12.4
Bajaj Finsrv	1970.0	1980.3	16589	3268.1	51.5	32.0	16.5
Bharat Elctn	405.4	409.0	181622	7362.0	62.8	21.4	15.8
Bharti Airtel	1840.0	1856.8	95083	17495.2	67.8	20.1	12.1
Cipla	1385.0	1391.8	19677	2725.3	57.2	27.6	15.2
Coal India	415.4	415.9	169529	7041.4	59.0	25.9	15.0
Dr Reddys	1151.0	1154.2	31791	3659.1	60.2	25.2	14.6
Eicher Motor	7630.5	7695.5	7153	5457.7	52.5	26.0	21.5
Grasim Ind	3322.0	3325.8	11118	3693.4	76.9	15.5	7.6
HCL Techno	1293.4	1301.7	35934	4647.8	68.0	20.2	11.8
HDFC Bank	712.1	718.7	656142	46723.9	61.5	25.2	13.3
HDFC Std Life	546.4	549.3	88416	4831.0	64.8	20.8	14.4
Hindalco	1011.0	1020.5	70728	7150.6	70.2	17.8	12.1
HUL	1973.4	1978.1	36142	7132.2	50.2	31.6	18.2
ICICI Bank	1423.2	1434.1	144241	20528.4	73.8	15.5	10.7
Infosys	1130.0	1138.1	115258	13024.2	66.6	20.7	12.7
InterGlobe Avia	4977.0	5009.5	11839	5892.4	56.6	27.1	16.3
ITC	264.1	265.5	344208	9090.5	53.3	30.7	16.1
Jio Financial	239.5	240.4	398654	9547.8	59.8	25.4	14.8
JSW Steel	1325.0	1332.1	52586	6967.6	76.4	13.2	10.4
Kotak Mah Bank	424.5	427.1	294964	12521.2	66.9	18.5	14.5
L & T	3964.1	3995.5	22686	8993.1	57.0	29.2	13.8
Mah & Mah	3170.0	3179.3	24445	7748.9	54.4	30.1	15.5
Maruti Suzuki	12694.0	12722.0	7879	10001.8	33.0	47.9	19.1
Max Health	984.8	988.8	17151	1689.1	71.5	16.4	12.0
Nestle India	1410.5	1412.6	13491	1902.9	70.9	19.0	10.2
NTPC	332.5	334.0	178077	5921.1	71.0	20.9	8.1
ONGC	234.7	235.1	134777	3162.5	52.0	33.7	14.3
Power Grid	266.0	267.1	132525	3525.2	59.8	26.5	13.6
Reliance Ind	1322.0	1335.6	255982	33840.8	55.3	26.0	18.7
SBI	1016.1	1024.0	193213	19632.3	53.5	29.6	16.9
SBI Life Ins	1775.0	1774.9	14403	2556.6	63.9	24.0	12.1
Shriram TrFn	1041.0	1046.9	50886	5297.2	56.5	28.5	15.0
Sun Pharma	1899.0	1903.6	29742	5648.0	54.8	31.8	13.4
Tata Consumer P	1010.0	1015.4	27034	2730.4	67.0	19.8	13.2
Tata Motors	311.5	313.9	172685	5379.1	53.4	28.1	18.5
Tata Steel	188.8	190.5	450742	8510.0	61.2	22.2	16.6
TCS	2304.0	2321.7	49590	11425.6	62.3	20.5	17.2
Tech Mahindra	1596.9	1601.4	27979	4467.9	67.2	18.4	14.4
Titan Company	5020.0	5043.0	10013	5026.6	51.2	27.8	21.0
Trent	2853.0	2866.8	15797	4506.8	67.4	22.4	10.2
UltraTech	11408.0	11428.0	3047	3476.1	69.6	20.5	9.9
Wipro	176.4	177.6	309033	5451.3	66.6	19.0	14.4
Zomato	322.8	323.4	253856	8193.2	65.0	23.1	11.8

विषय: प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 साल पर आपकी राय?

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने बदली भारत की आर्थिक तस्वीर

जनधन से जन-सशक्तीकरण

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 12 वर्षों में वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी है। शून्य-बैलेंस खाते, बीमा, ओवरड्राफ्ट और डीबीटी जैसी सुविधाओं ने बैंकिंग को गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचाया है। अब चुनौती खाते के सक्रिय और उपयोग की है। बचत, बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान और छोटे ऋण से जुड़ाव ही जनधन को वास्तविक आर्थिक सशक्तीकरण में बदल सकता है।

इशरत अली कादरी
भोपाल, मध्य प्रदेश

जन-जन तक पहुंची बैंकिंग की शक्ति

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने उन परिवारों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा, जो लंबे समय तक बैंकिंग सेवाओं से दूर रहे थे। बैंक खाते के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचने लगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका और अनावश्यक विलंब कम हुआ। वित्तीय पहचान मिलने से लोगों में बचत, लेन-देन और भविष्य की आर्थिक योजना के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

विभा पांडेय
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

योजना ने बदली बैंकिंग की तस्वीर

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 12 वर्षों में वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी है। करीब 59 करोड़ खातों में औसत जमा लगभग 5,356 रुपये है और कुल जमा 3.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। करीब 78 प्रतिशत खाते ग्रामीण-अर्धशहरी क्षेत्रों और 56 प्रतिशत महिलाओं के हैं। इससे वंचित वर्गों को बैंकिंग से जोड़ने के साथ सरकारी योजनाओं की राशि सीधे खातों में पहुंची।

भगवानदास छारिया
इंदौर, मध्य प्रदेश

जनधन योजना से वित्तीय सशक्तीकरण

प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य हर व्यक्ति को बैंकिंग से जोड़ना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में पहुंचाना था। 12 वर्षों में योजना ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाओं ने गरीबों को सामाजिक सुरक्षा, ऋण, बीमा और पेंशन से जोड़ा है। इसने वित्तीय समावेशन को मजबूत करते हुए बिचौलियों की भूमिका भी घटाई है।

रविंद्र प्रकाश
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

उपयोगी बनाए रखना अगली चुनौती

इन खातों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने लगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ी। बैंक खाता केवल बचत का माध्यम नहीं रहा, बल्कि वह सरकारी सहायता, बीमा, पेंशन और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं तक पहुंच का आधार बन गया। अब अगली चुनौती इन खातों को सक्रिय और उपयोगी बनाकर व्यापक वित्तीय सुरक्षा से जोड़ने की है।

यशवंत लोभाने
इंदौर, मध्य प्रदेश

आर्थिक समावेशन को मिली नई दिशा

इस योजना ने 12 वर्षों में बैंकिंग को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना ने बैंक खाते को केवल सरकारी लाभ का माध्यम न बनाकर आर्थिक पहचान का आधार बनाया है। डीबीटी, डिजिटल भुगतान, बीमा, पेंशन और ऋण ने वित्तीय सुरक्षा बढ़ाई है। अब इसकी अगली चुनौती खाते से बचत, निवेश और आत्मनिर्भरता तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

शिशिर शुक्ला
शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश

उपलब्धि के साथ चुनौतियां भी कम नहीं

समाज के कमजोर वर्ग के लिए जनधन खाता सिर्फ बैंक खाता ही नहीं अपितु आर्थिक सुरक्षा और अवसर का माध्यम बन रहा है। इस उपलब्धि के साथ ही निष्क्रिय खाते, डिजिटल बैंकिंग का अल्प ज्ञान और ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त तकनीकी दिक्कतें भी किसी चुनौती से कम नहीं है। अब तक खोले गए बैंक खातों का प्रभावी उपयोग और वित्तीय साक्षरता पर जोर देने में ही योजना की सार्थकता है।

कृतिका अग्रवाल
गोरेगांव, महाराष्ट्र

आर्थिक रूप से मजबूत हुई महिलाएं

इस योजना ने गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज जनधन खातों में करोड़ों महिलाएं जुड़ी हैं और सरकारी योजनाओं की राशि सीधे खातों में पहुंच रही है। जीरो बैलेंस से शुरू हुए ये खाते अब बड़ी बचत का माध्यम बन चुके हैं। जनधन ने साबित किया है कि अवसर मिलने पर गरीब बचत के साथ डिजिटल बैंकिंग भी अपनाता है।

मनमोहन राजावत
शाजापुर, मध्य प्रदेश

बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में मददगार

जनधन खाते कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जैसे लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, ऑनलाइन लेन-देन को बढ़ावा देना, सब्सिडी और सरकारी सहायता सीधे बैंक खाते में पहुचाना तथा बाजार में नकदी के प्रवाह को कम करना। रेहड़ी-पटरी वालों और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी ऑनलाइन भुगतान, पैसों की सुरक्षा तथा लगभग 57 प्रतिशत खातों का महिलाओं के नाम पर होना उपल्धि रही है।

बृजेश माथुर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

वित्तीय साक्षरता से जोड़ने की चुनौती

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 12 वर्षों में वित्तीय समावेशन को व्यापक आधार दिया है। योजना ने बैंक खाते को सरकारी सहायता, बचत, बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान और ऋण तक पहुंच का माध्यम बनाया है। अब चुनौती खातों की संख्या बढ़ाने से आगे बढ़कर उन्हें सक्रिय रखने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और बचत को ऋण व उद्यम से जोड़ने की है।

प्रेरणा अवस्थी
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश

समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची

इस योजना ने बैंकिंग सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया। जनधन खातों के माध्यम से डीबीटी से सरकारी लाभ सीधे खाताधारकों तक पहुंचा और बिचौलियों की भूमिका घटी। ग्रामीण महिलाओं की बैंकिंग और बचत में भागीदारी बढ़ी। रुपे कार्ड और यूपीआई ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल लेनदेन से जोड़ा। अब चुनौती खातों को सक्रिय रखने की है।

डॉ. मोहिनी नेवासकर
गोरेगांव, महाराष्ट्र

अब बैंकिंग समझ बढ़ाने की जरूरत

योजना के 12 वर्ष पूरे होने को वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर है क्योंकि 59.09 करोड़ खाते जिनमें 32.92 करोड़ खाते महिलाओं के पास और लगभग 78 फीसदी खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। परंतु कई नागरिकों को अभी भी एटीएम, डिजिटल भुगतान, बीमा दावे और बैंकिंग शिकायत तंत्र का उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता होती है।

बाल गोविंद
नोएडा, उत्तर प्रदेश

बकौल विश्लेषक

आर्थिक सशक्तीकरण का कदम है जनधन

प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत के पीछे सरल विचार था कि देश का कोई भी वयस्क नागरिक बैंकिंग सुविधा से वंचित न रहे। जनधन योजना का सबसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण में दिखाई देता है। वित्तीय समावेशन की इस यात्रा का अगला पड़ाव वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करना है। ग्रामीण और वंचित वर्ग के ग्राहकों के लिए बैंकिंग प्रक्रियाएं जितनी सरल, सहज और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग उतना ही व्यापक होगा। भविष्य का जनधन खाता केवल शून्य या न्यूनतम शेष राशि वाला खाता नहीं, बल्कि बचत, ऋण, बीमा, पेंशन, निवेश और डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जुड़ा एक सक्रिय वित्तीय मंच होना चाहिए। ऐसा होने पर परिवार न केवल अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, बल्कि आपात स्थिति के लिए वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति निर्माण भी कर सकेंगे।

बातचीत: सिद्धार्थ कलहंस

अशोक चंद्र
एमडी एवं सीईओ, पंजाब नैशनल बैंक

महिलाएं बैकिंग से जुड़ीं

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने पिछले 12 वर्षों में देश में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वर्ष 2014 में शुरू हुई इस पहल का मूल उद्देश्य देश की वंचित आबादी को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ना था। आज 59.15 करोड़ जनधन खाते और 3.16 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि इस व्यापक बदलाव की एक बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। जनधन खातों ने लोगों के लिए केवल बचत की सुविधा नहीं दी, बल्कि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में पहुंचाने, डिजिटल भुगतान करने और बीमा तथा पेंशन जैसी सुविधाओं से जुड़ने का रास्ता आसान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और बड़ी संख्या में महिलाओं को इससे जोड़ने में भी इन खातों की अहम भूमिका रही है। अब यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक अपने खातों का उपयोग जरूरत अनुसार कर सकें, चाहे वह बचत हो, ऋण हो या बीमा और पेंशन जैसी सुरक्षा।

बातचीत: सिद्धार्थ कलहंस

विनोद कुमार
एमडी एवं सीईओ, इंडियन बैंक

पुरस्कृत पत्र

1

हेमंत पाटील
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

पुरस्कार राशि
500 रुपये

खातों से आगे आर्थिक सशक्तीकरण

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को नई दिशा देते हुए 59 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है। इसमें महिलाओं और ग्रामीण आबादी की बड़ी भागीदारी उल्लेखनीय है। 12 वर्ष बाद इसकी सफलता का पैमाना केवल खुले खातों की संख्या तक सीमित नहीं होना चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए खातों की सक्रियता, नियमित लेनदेन और बचत भी अहम हैं। अब चुनौती खाते खोलने से आगे उन्हें आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बनाने की है।

श्रेष्ठ पत्र

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

उपयोगिता पर उठते सवाल

प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों तक पहुंचाना था। योजना ने करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ा, लेकिन समय के साथ इन खातों के सक्रिय रहने और वास्तविक उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब निष्क्रिय खातों की स्थिति पर ध्यान दिया जाए और खाताधारकों को डिजिटल बैंकिंग से लगातार जोड़ा जाए।

रोशनी यादव
अयोध्या, उत्तर प्रदेश

बदली वित्तीय तस्वीर

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीबों, किसानों और मजदूरों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी। 12 वर्षों में देश में 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुले हैं, जिनमें करीब 3.17 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। लगभग 56 फीसदी खाते महिलाओं के हैं। जनधन, आधार और मोबाइल की व्यवस्था ने डीबीटी के जरिये सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद की है।

सुभाष बुड़ावन वाला
रतलाम, मध्य प्रदेश

समृद्धि कब खुलेगी

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 12 वर्षों में करोड़ों गरीबों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है। 19 अगस्त तक 59.09 करोड़ खाते खुल चुके हैं, जिनमें 32.92 करोड़ महिलाओं के और 45.95 करोड़ ग्रामीण-अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। असली सवाल है कि इन खातों से गरीब की आर्थिक स्थिति कितनी बदली? वित्तीय साक्षरता, आसान ऋण, डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता अभी चुनौती हैं।

...और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम समसामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी में आपके विचारों को प्रकाशित करते हैं। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -

जीडीपी के आंकड़ों पर आपकी राय?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

नेपाल में बाढ़ से व्यापार और ...

पृष्ठ 1 का शेष

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का कृष्णानगर कस्बा भी नेपाल से कारोबार का प्रमुख रास्ता है। वहां से नेपाल को अनाज, गुड़, फल और सब्जियां जाती हैं। मगर वहां भी ट्रकों की आवाजाही पर असर पड़ा है। कृष्णानगर के करीब बसे कस्बे बढ़नी के ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हर रोज 100 से ज्यादा ट्रक नेपाल जाते थे मगर अब दर्जन भर भी नहीं जा रहे।

बढ़नी व्यापार मंडल के महामंत्री संजय सिंह का कहना है कि यहां से हर दिन 20 से 25 लाख रुपये की सब्जी व फल नेपाल जाते थे और इतनी ही कीमत का अनाज भी भेजा जाता था। आपदा के बाद हफ्ते भर तो सब बंद रहा, अब शुरू हुआ है मगर पूरी क्षमता से माल नहीं भेज पा रहे हैं। सिंह के अनुसार पिछले दस दिन में ही 12 करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की सीमा पर बसे नेपाली कस्बे कोयलबास के बाजार में भी सन्नाटा पसरा है और माल की आवाजाही बंद है।

बरेली के व्यापारी रोहित खंडेलवाल ने बताया कि नेपाल से भारत आने वाले सामान में प्लाई का पट्टा प्रमुख है। मगर हर साल बारिश के दिनों में इसकी आवक कम हो जाती है, इसलिए इस आपदा का प्लाईवुड कारोबार पर फिलहाल खास असर नहीं पड़ा है। अलबत्ता पर्यटन को नेपाल की बाढ़ ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बरेली मंडल के उप निदेशक (पर्यटन) रवींद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि बरेली से होकर नेपाल जाने वाले पर्यटकों की संख्या कम हुई है। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार नेपाल की हालत देखकर कई लोगों ने अपनी यात्रा टाल दी है। कृष्णानगर में ट्रैवल एजेंसी सिद्धार्थ ट्रैवल्स के अजीम बताते हैं कि वहां के बस स्टॉप से हर घंटे पोखरा, बुटवल, काठमांडू के लिए बस चलती थीं, जिनकी तादाद अब आधे से भी कम रह गई है। वह बताते हैं कि पोखरा और काठमांडू में बाढ़ का कोई असर नहीं है मगर भारतीय सैलानी नेपाल में कहीं भी जाने से कतरा रहे हैं।

टूर-ट्रैवल उद्योग के लोग बताते हैं कि सितंबर से नवंबर तक नेपाल में पर्यटन का पीक सीजन होता है, लेकिन इस बार लोग बुकिंग ही नहीं करा रहे हैं। अजीम बताते हैं कि दुर्गा पूजा पर पिछले साल पोखरा और काठमांडू के लिए 40,000 से ज्यादा टिकट कृष्णानगर-बुटवल की एजेंसियों ने ही बुक किए थे। लेकिन इस साल अभी तक 400 टिकट भी नहीं हुए हैं।

यात्रा परामर्श केवल बाढ़ क्षेत्रों के लिए हो : नेपाल

नेपाल ने नए यात्रा परामर्श में कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों को छोड़कर देश का शेष हिस्सा यात्रा एवं पर्यटन के लिए खुला और सुरक्षित है। उसने अपने मित्र देशों से आग्रह किया कि वे यात्रा परामर्श को केवल बाढ़ प्रभावित विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रखें।

विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि सरकार अपने मिशनों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर काम कर रही है। यह अनुरोध ऐसे वक्त आया है, जब अमेरिका ने 4 सितंबर को अपने यात्रा परामर्श में प्राकृतिक आपदाओं के कारण नेपाल को 'लेवल 2' यानी 'अधिक सावधानी बरतने वाले देश' की श्रेणी में रखा था। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिपोर्टिंग करने के इच्छुक विदेशी पत्रकारों को सूचना और प्रसारण विभाग की ऑनलाइन सेवा के जरिए प्रेस मान्यता लेना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ से अब तक 1,344 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 589 विदेशियों सहित करीब पांच हजार लोग लापता हैं। **भाषा**

भारत को आकर्षक बनाएगा नवाचार परिवेश

पृष्ठ 1 का शेष

वैश्विक स्तर पर निवेश और राजस्व के लिहाज से भारत की स्थिति क्या है?

जूडिथ लव: मेरे क्षेत्र में 31 देश शामिल हैं और यह बहुत विविध एवं तेजी से बदलने वाला क्षेत्र है। मैं देशों को केवल राजस्व के आधार पर नहीं देखती बल्कि वहां भविष्य की संभावनाओं को भी देखती हूं। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और बीमारी का बोझ भी बढ़ रहा है। विज्ञान एवं नवाचार की जरूरत बढ़ रही है और उन्हें महत्त्व भी मिल रहा है। भारत का पूरा स्वास्थ्य एवं नवाचार तंत्र विकसित हो रहा है। हमारी भारत में व्यापक साझेदारियां हैं। इसलिए भारत को केवल किसी रैंक या क्रम में देखना उचित नहीं है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम भारत में भविष्य की संभावनाओं को कैसे साकार कर सकते हैं।

भारत में निवेश की रफ्तार कैसी है?

जूडिथ लव: भारत में हमारा वैश्विक दक्षता केंद्र (जीसीसी) है जहां स्वास्थ्य क्षेत्र के लगभग 9,000 कर्मचारी काम करते हैं। हमने पिछले कई वर्षों से भारत में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया है। यहां अनुसंधान, व्यवसायीकरण और वैश्विक कार्यों से लेकर कई गतिविधियां संचालित होती हैं। दुनिया में हमारे तीन प्रमुख विकास केंद्र हैं और उनमें सबसे बड़ा भारत में है। हम क्लीनिकल परीक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। आज हम भारत में 330 क्लीनिकल परीक्षण स्थल के साथ काम कर रहे हैं और 60 से अधिक वैश्विक क्लीनिकल परीक्षण को संचालित करते हैं। हमारे लिए निवेश को केवल किसी एक संख्या या फीसदी से नहीं मापा जा सकता। हम पूरे स्वास्थ्य एवं नवाचार परिवेश में निवेश कर रहे हैं ताकि उसे विकसित किया जा सके।

अमिताभ दुबे: भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां नोवार्तिस की लगभग पूरी गतिविधियों की श्रृंखला यानी बायोमेडिकल रिसर्च एवं शुरुआती दवा खोज से लेकर विकास, संचालन और व्यवसायीकरण तक मौजूद है। इसलिए भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता काफी व्यापक है।

चीन और भारत की दवा क्षेत्र की संभावनाओं में क्या अंतर है?

जूडिथ लव: चीन और भारत के बीच दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि दोनों अलग-अलग समय पर विकास कर रहे हैं। अगर मैं कुछ साल पीछे जाकर चीन को देखूं तो उस समय चीन कुछ हद तक वैसा ही दिखाई देता था जैसा आज भारत दिखाई देता है। दूसरा बड़ा अंतर यह है कि भारत में आबादी और बीमारी का बोझ दोनों बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत में स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें अधिक हैं। किसी स्वास्थ्य सेवा कंपनी के लिए इसे समझना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

क्या भारत में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण एक चुनौती है?

अमिताभ दुबे: मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी समस्या है। भारत का नियामकीय ढांचा तेजी से बदल रहा है। कीमतों से जुड़े सुधार भी हो रहे हैं और सरकार भारत को एक प्रतिस्पर्धी बाजार बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे-जैसे ये सुधार आगे बढ़ेंगे और हम नवाचार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे भारत चीन जैसे बाजारों के समान स्तर पर आ सकता है।

भारत में गैरसंचारी रोगों (एनसीडी) का बोझ बहुत अधिक है जिसमें दिल की बीमारियां और कैंसर मुख्य हैं। ऐसे में नोवार्तिस अपनी कुछ कैंसर दवाओं के पेटेंट की अवधि खत्म होने से पैदा होने वाली चुनौती से निपटने की क्या योजना बना रही है?

जूडिथ लव: किसी दवा का पेटेंट खत्म होना दवा उद्योग के जीवनचक्र का सामान्य हिस्सा है। जब कोई दवा विकास के चरण में आती है तो हमें उसके पेटेंट अवधि का पता होता है। हम यह भी जानते हैं कि हमारी पाइपलाइन में आने वाली नई दवाएं और उत्पाद उस अवधि के बाद कंपनी की वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे। हमारी पाइपलाइन फार्मास्युटिकल उद्योग की सबसे

जूडिथ लव

अमिताभ दुबे

मजबूत पाइपलाइनों में से एक है। इसलिए हम इन बदलावों का सामना करने के लिए तैयार हैं। नियामकीय डेटा सुरक्षा (आरडीपी) और भारत में मजबूत बौद्धिक संपदा (आईपी) जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। हम अपनी पाइपलाइन में लगातार नई सफल और महत्त्वपूर्ण दवाएं जोड़ रहे हैं ताकि पेटेंट खत्म होने से होने वाले प्रभाव की भरपाई की जा सके।

नई दवा के लिए 10 साल की नियामकीय डेटा सुरक्षा की मांग पर बात कहां पहुंची है?

अमिताभ दुबे: हमारा स्पष्ट मानना है कि नियामकीय डेटा सुरक्षा (आरडीपी) एक मजबूत नवाचार आधारित दवा व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि दवा अनुसंधान एवं विकास हो, चाहे वह बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हो या भारत के स्थानीय नवाचार तंत्र द्वारा, तो आरडीपी बुनियादी जरूरत है। नई दवा विकसित करने में जो डेटा तैयार किया जाता है उसे कुछ वर्षों तक सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही उस नवाचार के लिए मिलने वाला एक महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन है। हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ सक्रिता से चर्चा कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार भी हमारी बात सुन रही है और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उचित विकल्प पर विचार कर रही है। जिन देशों में आरडीपी लागू है वहां क्लीनिकल परीक्षण में लगभग आठ गुना वृद्धि हुई है और नवाचार में निवेश में 100 फीसदी तक वृद्धि देखी गई है। ऐसे देशों में नई दवाएं भी तेजी से बाजार में आती हैं।

जूडिथ लव: हमारा मानना है कि हमें भारत में एक मजबूत जेनेरिक दवा तंत्र भी चाहिए और एक मजबूत नवाचार तंत्र भी। यह दोनों में से किसी एक को चुनने का मामला नहीं है। दोनों का साथ-साथ मजबूत होना जरूरी है। आरडीपी नवाचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है लेकिन इसका उद्देश्य जेनेरिक दवा तंत्र की कीमत पर नवाचार तंत्र बनाना नहीं है।

नवाचार के क्षेत्र में भारत के लिए नोवार्तिस की क्या योजनाएं हैं?

जूडिथ लव: जल्द ही एक महत्त्वपूर्ण पहल सामने आने वाली है। हम अर्टिकैरिया (पित्ती) के इलाज में एक बड़े सुधार को भारत में जल्द उपलब्ध कराने के लिए अर्ली फाइलिंग रणनीति तैयार कर रहे हैं। भारत में लगभग 1 करोड़ अर्टिकैरिया मरीज हैं। यह एक गंभीर बीमारी का बोझ है और लंबे समय से इस क्षेत्र में कोई बड़ा चिकित्सकीय बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए हम इस नवाचार को भारत में लाने के लिए काम कर रहे हैं। हृदय रोगों के क्षेत्र में लिपिड कम करने को एसआईआरएनए पर आधारित उपचार सबसे पहले उपलब्ध कराया। हम केवल उन हृदय रोग जोखिमों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन्हें खानपान और व्यायाम से कम किया जा सकता है बल्कि आनुवंशिक कारणों से होने वाली बीमारियों पर भी काम कर रहे हैं। कैंसर के क्षेत्र में हम रेडियोलिगैंड थेरेपी (आरएलटी) में अग्रणी हैं और अलग-अलग प्रकार के ट्यूमर के लिए इस क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। इस वर्ष की दूसरी छमाही में हमारी पाइपलाइन से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण परिणाम आने वाले हैं।

भारत में विनिर्माण की क्या योजना है?

जूडिथ लव: हम महज विनिर्माण से कहीं आगे की सोच रखते हैं। भारत में जेनेरिक दवाओं का मजबूत तंत्र हो सकता है लेकिन हमें साथ-साथनवाचार का मजबूत तंत्र भी बनाना होगा। इसी सोच के कारण हमने अनुसंधान, विकास, व्यावसायीकरण और संचालन जैसे पूरे तंत्र में निवेश किया है। हमने कुछ स्थानीय निर्माताओं के साथ साझेदारी भी की है और उनसे ऐक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट्स (एपीआई) प्राप्त किए हैं।

भारत को नोवार्तिस के लिए एक आकर्षक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए क्या जरूरी है?

जूडिथ लव: हमारे लिए भारत को आकर्षक बनाने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण चीजएक मजबूत नवाचार तंत्र होगा। ऐसा माहौल होना चाहिए जहां कंपनियां तेजी से भारत में निवेश करने के लिए तैयार हों। इसके लिए नियामकीय डेटा सुरक्षा, क्लीनिकल परीक्षण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा, स्पष्ट और तेज नियामकीय प्रक्रिया तथा मरीजों तक दवाओं की पहुंच से जुड़े उचित तंत्र जरूरी हैं। पूरे परिवेश को विकसित करना होगा। यह केवल किसी एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार, उद्योग, शोध संस्थानों और अन्य कई पक्षों को मिलकर काम करना होगा। अगर सही परिवेश तैयार होता है तो इससे केवल विनिर्माण ही नहीं, बल्कि भारत में कुल मिलाकर निवेश भी अधिक आकर्षक होगा।

क्या नोवार्तिस के वैश्विक सीईओ वसंत नरसिम्हन के भारतीय मूल का होना भारत की रणनीति को प्रभावित करता है?

जूडिथ लव: भारत में विकास केंद्र उस समय स्थापित हुआ था जब हमारे मौजूदा सीईओ दवा विकास के प्रमुख थे। इस लिहाज से उनका भारतीय मूल होना एक लाभ है। लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पृष्ठभूमि आरऐंडडी में रही है। हम भाग्यशाली हैं कि पिछले नौ वर्षों से हमारे पास उनका नेतृत्व है।

भारत में कारोबार करने की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और कारोबारी सुगमता में कितना बदलाव आया है?

जूडिथ लव: इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने और भारत को नवाचार के लिए अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। लेकिन आज एक नवाचार-आधारित कंपनी के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बाधाओं में नियामकीय डेटा सुरक्षा (आरडीपी) प्रमुख है। किसी भी नवाचार की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि आपके द्वारा किए गए नवाचार को उचित अवधि तक सुरक्षा मिलेगी।

अमिताभ दुबे: अगर पांच साल पहले की तुलना आज से करें तो भारत में उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कई जरूरी सुधार हो रहे हैं। सरकार में बदलाव करने की मजबूत इच्छा और प्रतिबद्धता दिखाई देती है। हालांकि हम सुधारों की गति थोड़ी और तेज देखना चाहते हैं। दुनिया में तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार बहुत तेजी से हो रहा है। सरकार के सुधारों की गति भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। आज अलग-अलग देशों के बीच निवेश आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। यदि भारत को सबसे अलग और आकर्षक बनना है तो उसे जरूरी सुधार करने होंगे और सही समय पर करने होंगे।

भारत वास्तव में विनिर्माण के लिए एक प्रमुख विकल्प कब बन पाएगा?

जूडिथ लव: जब जरूरी सुधार पूरे हो जाएंगे। जब आप जापान, चीन और जर्मनी को देखेंगे तो पाएंगे कि वहां नियामकीय डेटा सुरक्षा, मजबूत बौद्धिक संपदा और भरोसेमंद नियामकीय प्रक्रियाएं मौजूद हैं। ये सभी एक मजबूत नवाचार तंत्र की बुनियादी जरूरतें हैं। यही कारण है कि इन देशों में नवाचार और निवेश तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में निवेश आएगा। इसके लिए हमें इन बुनियादी आवश्यकताओं को मजबूत करना होगा। अच्छी बात यह है कि सरकार में बदलाव करने की इच्छा और गति दोनों दिखाई दे रही हैं।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

Century
OOH Media Assets & Solutions

CENTURY BUSINESS MEDIA LIMITED

(Formerly known as Century Business Private Limited)

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME")

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name "Century Business Private Limited" on September 23, 1999 bearing Registration No. 009001 having CIN U51505BR1999PTC009001 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Bihar. Consequently, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on January 08, 2024, our company has changed its name from "Century Business Private Limited" to "Century Business Media Private Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name dated February 08, 2024 issued by the Registrar of Companies, Patna. Further, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on June 28, 2024 our company was converted into a Public Limited Company and consequently the name of our Company from "Century Business Media Private Limited" to "Century Business Media Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation dated September 16, 2024 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Our Company's Corporate Identification Number is U73100BR1999PLC009001. For further details please refer to chapter titled ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 126 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: 107, Emarat Firdaus Exhibition Road, Patna, Bihar, India, 800001
Corporate Office: P S Abacus Room No 204, 2nd Floor NH 12 Action Area II E New Town, North 24 Parganas, West Bengal, India, 700161
Tel.: 0612-2320672/76, **E-mail:** info@centurymedia.in, **Website:** www.centurymedia.in, **Contact Person:** Shashank Poddar, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: SHASHI KUMAR CHAUDHARY, SEEMA CHAUDHARY, SANGITA DOKANIA AND SHREYA CHAUDHARY

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 23,12,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF CENTURY BUSINESS MEDIA LIMITED ("OUR COMPANY" OR "CBML" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 1,16,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 21,95,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.39% AND 25.06% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

Subject to finalization of Basis of Allotment.

PRICE BAND: ₹70 TO ₹74 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹10/- EACH

THE FLOOR PRICE (₹70) IS 7.0 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS (₹74) 7.4 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL 2026 AT THE FLOOR PRICE IS (₹70) 8.13 TIMES AND AT THE CAP PRICE (₹74) IS 8.59 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 3200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1600 EQUITY SHARES THEREAFTER

Weighted average return on net worth for the last three fiscal years should be read as 35.89%

The details of the Fresh Issue and the post-Issue market Capitalisation of the Company, each at the Floor Price (₹70) and the Cap Price (₹74), are given below:

Particular	At Floor price of ₹70 per equity share		At Cap price of ₹74 per equity share	
	Up to No of equity Shares of face value of Rs. 10/- each	Up to amount (Rs in Lakhs)	Up to No of equity Shares of face value of Rs. 10/- each	Up to amount (Rs in Lakhs)
Fresh Issue	23,12,000	1618.40	23,12,000	1710.88
Offer for Sale	-	-	-	-
Total Issue Size	**23,12,000**	**1618.40**	**23,12,000**	**1710.88**
Post-Issue Market Capitalization of the Company	**87,61,280**	**6132.90**	**87,61,280**	**6483.35**

BID/ ISSUE PROGRAMME

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026
BID/ ISSUE OPENS ON: FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2026
BID/ ISSUE CLOSES ON: WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026

^UPI mandate end time shall be at 05:00 p.m. on the Bid/Issue closing date.

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

Established in 1999, our Company provides advertising services with a primary focus on Out-of-Home ("OOH") media formats, including both digital and non-digital solutions. We operate primarily in the Airport Out-of-Home ("AOOH") and Railway Out-of-Home ("ROOH") segments by offering advertising spaces within and outside airport terminal buildings and through digital and static hoardings across railway stations and railway land. We have recently commenced Metro Out-of-Home ("MOOH") advertising, including advertisements on Platform Screen Doors ("PSDs"), and have also started offering in-shop branding services. Additionally, we provide a variety of traditional city media formats, including hoardings, billboards, unipole, multipoles, pole kiosks, wall wraps, wall paintings, lollipops, gantries, in-shop branding, and other related media assets.

THIS ISSUE IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS, IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI (ICDR) REGULATIONS"), AS AMENDED READ WITH RULE 19(2)(B) OF SECURITIES CONTRACT (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED FROM TIME TO TIME (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME")

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME"). FOR THE PURPOSE OF THE ISSUE, THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE WILL BE BSE LIMITED.

ALLOCATION OF THE ISSUE

- **QIB PORTION :** NOT MORE THAN 50.00% OF THE NET ISSUE
- **NON-INSTITUTIONAL PORTION :** NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET ISSUE
- **INDIVIDUAL PORTION :** NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET ISSUE
- **MARKET MAKER PORTION :** UPTO 1,16,800 EQUITY SHARES OR 5.05% OF THE ISSUE

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE ISSUE, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE ISSUE AVAILABLE IN ANY MANNER, potential investors should only refer to this pre-issue and price band advertisement for the issue and should not rely on any media articles/ reports in relation to the valuation of the company as these are not endorsed, published or confirmed either by the company or the Book Running Lead Manager to the issue ("BRLM").

In accordance with the recommendation of the Independent Directors of our Company, pursuant to their resolution dated August 14, 2026 the above provided price band is justified based on quantitative factors/ KPIs disclosed in the **'Basis for Issue Price'** section beginning on page 85 of the Red Herring Prospectus ('RHP') vis-a-vis the weighted average cost of acquisition ("WACA") of primary and secondary transaction(s), as applicable, disclosed in ***'Basis for Issue Price'*** section beginning on page 85 of the Red Herring Prospectus and provided below in the advertisement.

RISKS TO INVESTORS

For details refer to section titled "Risk Factors" on page 20 of the Red Herring Prospectus.

1. Risk to investors summary description of key risk factors based on materiality

a) Our Company and Promoters our involved in certain legal proceeding(s) and potential litigations. Any adverse decision in such proceeding(s) may render them liable to liabilities/ penalties.

b) Our business is significantly dependent on concession, licensing, and marketing agreements granted by government and quasi-government authorities, and failure to renew or retain such rights could materially and adversely affect our revenues and market position.

c) We are required to provide substantial security deposits under our concession agreements, the forfeiture or invocation of which could materially affect our liquidity.

d) Certain concession agreements require us to pay Minimum Monthly Guarantees (MMG) irrespective of revenue, and any inability to meet these obligations could materially affect our business and financial condition.

e) We are yet to place orders for certain static and digital media assets for our Out-of-Home ("OOH") advertising business, and any delays could postpone implementation and increase costs.

f) Our operations are geographically concentrated in a few Indian states, exposing us to region-specific economic, political, and regulatory risks.

g) Our ability to execute city-based Out-of-Home (OOH) advertising campaigns depends on the availability and cost of suitable media sites, including hoardings, and any shortage or price escalation in such inventory may adversely affect our business, financial condition, and results of operations.

h) Our Trade Payables Holding Period for Fiscal 2024 and Fiscal 2025 was inadvertently miscalculated in the DRHP and the revised holding periods may differ from the previously disclosed figures.

i) We are dependent on a limited number of high-revenue advertising rights and concession contracts at select airports and railway zones, and any failure to retain or renew these contracts could materially affect our revenue and profitability.

j) Our Company's logo is not registered as on date of this Red Herring Prospectus. We may be unable to adequately protect our intellectual property. Furthermore, we may be subject to claims alleging breach of third-party intellectual property rights which could have a material adverse effect on our business, results of operations and financial condition.

- *Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoters are*

Sr. No.	Name of Promoter	Type	No. of Shares held	Average Cost of Acquisition (in ₹)
1.	Shashi Kumar Chaudhary	Promoter	52,19,720	0.34
2.	Seema Chaudhary	Promoter	2,49,920	0.86
3.	Sangita Dokania	Promoter	6,47,400	2.47
4.	Shreya Chaudhary	Promoter	5,080	0.00

And the Issue Price at the upper end of the Price Band is Rs. 74 per Equity Share.

- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2026 for the company at the upper end (₹74) of the Price Band is 8.59
- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2026, 2025 and 2024 is 35.89%.

2. Details of suitable ratios of the company for the latest full financial year:

(₹ In lakhs)

Name of Company	Current Market Price (₹)	Face Value	EPS		PE	RoNW (%)	Book Value (₹)	Total Income (₹ In lakhs)
			Basic	Diluted				
Century Business Media Limited	[●]*	10	8.61	8.61	[●]^	30.83%	27.94	4,643.34
Peer Group								
Bright Outdoor Media Limited	361.40	10	12.26	12.26	29.48	12.96%	85.03	15,302.65
Signpost India Limited	270.05	2	13.14	13.14	20.55	24.13%	54.44	57,593.43
Simca Advertising Limited	240.80	10	18.88	18.88	12.75	57.24%	24.24	12,721.81

**CMP of our Company is considered as Issue Price.*
^to be included post finalization of the Issue Price.

Notes:

i. Source-All the financial information for listed industry peer "Bright Outdoor Media Limited" and "Signpost India Limited" mentioned above is sourced from the Annual Reports of the aforesaid companies for the year ended March 31, 2025, March 31, 2024 and "Simca Advertising Limited" the same is sourced from, prospectus filed with stock exchange dated August 05, 2025 & May 13, 2026 respectively. For the year ended March 31, 2026 Financial Information is sourced from Outcome of Board meeting submitted to exchange for all 3 listed peers companies mentioned above.

ii. Market Price for the listed peer mentioned above is sourced from stock exchange data dated August 12, 2026 to compute the corresponding financial ratios.

iii. Further, P/E Ratio is based on the current market price of the respective scrips available on BSE SME, NSE Emerge and BSE respectively.

iv. The EPS, NAV, RoNW and Total Income of our Company are taken as per Restated Financial Statement for the Financial Year 2025-26.

v. NAV per share is computed as the closing net worth divided by the closing outstanding number of paid-up equity shares.

vi. P/E Ratio of the peer companies are based on the audited financial results of the company for the year ended March 31, 2026. RoNW has been computed as net profit after tax divided by closing net worth.

vii. Net worth has been computed as total of Equity Share Capital and Reserves & Surplus.

viii. The face value of Equity Shares of our Company is ₹10/- per Equity Share and the Issue price is [●] times the face value of equity share.

3. Weighted average return on net worth for the last 3 FYs:

As per restated financial statements:

Sr. No.	Period	RONW (%)	Weights
1.	Period ending March 31, 2024	47.38	1
2.	Period ending March 31, 2025	37.74	2
3.	Period ending March 31, 2026	30.83	3
	Weighted Average	**35.89**	**6**

Note:

i. The figures disclosed above are based on the Restated Financial Statements of the Company.

ii. The RoNW has been computed by dividing restated net profit after tax (excluding exceptional items) with restated Net worth as at the end of the year/period

iii. Weighted average = Aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. (RoNW x Weight) for each year/Total of weights.

4. Weighted average cost of acquisition of all the shares transacted in the three years, 18 months and one year preceding the date of the Red Herring Prospectus-

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Cap Price (₹74) is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
Last one year, last 18 Months & three years preceding the date of the Red Herring Prospectus	Nil	Nil	0-0

5. Disclosures as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI:

a) The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities)

There has been no issuance of Equity Shares other than Equity Shares issued pursuant to bonus issue made on March 23, 2025, during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days.

b) The price per share of our Company based on the secondary sale/ acquisition of shares (equity shares)

There have been no secondary sale/ acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts of shares), during the 18 months preceding the date of the certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-Issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

c) Price per share based on the last five Primary Issuances or Secondary Transactions

Since there are no such transactions to report to under (a) and (b) therefore, information based on last 5 primary or secondary transactions (secondary transactions where Promoter/ Promoter Group entities or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of our Company, are a party to the transaction), not older than 3 years prior to the date of the certificate irrespective of the size of transactions, is as below:

Primary Transaction:

Except as disclosed below, there have been no primary transactions in the last three years preceding the date of the Red Herring Prospectus:

Date of Allotment	No. of equity Shares allotted	Face value per Equity share (₹)	Issue price per Equity share (₹)	Nature of Allotment	Nature of consideration	Total Consideration (in ₹ lakhs)
March 23, 2025	56,43,120	10	Nil	Bonus Issue in the ration of 7:1	Other than Cash	Nil

Secondary Transaction:

S. No.	Date of Transfer	Name of Transferors	Name of Transferee	Number of Equity Shares	Percentage of pre-issue share capital of the company	Nature of Issue
1.	August 14, 2026	Sangita Dokania	Shashi Kumar Choudhary	472600	7.33%	Gift
2.		Seema Chaudhary	Neeraj Kumar Kedia	2000	0.03%	Gift
3.		Shashi Kumar Choudhary	Khushi Choudhary	5000	0.08%	Gift
4.			Shreya Choudhary	5000	0.08%	Gift
5.	February 29, 2024	Shashi Kumar Choudhary	Shreya Choudhary	10	Negligible	Gift

Weighted average cost of acquisition & Issue price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 70)	Cap price (i.e. ₹ 74)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition	NA^^	NA^^	NA^^
Weighted average cost of acquisition of primary issuances / secondary transactions	Nil	Nil	Nil

Note:

^There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) in last 18 months from the date of the Red Herring Prospectus.

^^There were no secondary transactions as mentioned above, in last 18 months from the date of the Red Herring Prospectus.

The Issue Price shall be determined by our Company in consultation with the BRLM, on the basis of the demand from investor for the Equity Shares through Book Building Process.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS:

1. **Details of proposed /undertaken pre-Issue placements from the DRHP filing date** - Not Applicable
2. **Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date:** Our Promoters, Shashi Kumar Choudhary, Seema Choudhary and Sangita Dokania have transferred/ Sold 4,84,600 Equity Shares to certain individuals, as detailed below (together the "Secondary Transaction"). The details of the transfer/sale are as follows:

Continued on next page

Continued from previous page

S. No.	Date of Transfer	Name of Transferors	Nature of relationship with company	Name of Transferee	Nature of Relationship with Company	Nature of Transaction	Number of Equity Shares	Percentage of pre-issue share capital of the company	Transfer Price per Equity Share (Rs.)	Total Consideration (in Rs.)
1	August 14, 2026	Shashi Kumar Choudhary	Promoter	Khushi Choudhary	Promoter Group	Secondary Sale	5,000	0.08%	-	-
2				Shreya Choudhary	Promoter		5,000	0.08%	-	-
TOTAL							**10,000**	**0.16%**	-	-
3	August 14, 2026	Seema Choudhary	Promoter	Neeraj Kedia	Promoter Group	Secondary Sale	2,000	0.03%	-	-
TOTAL							**2,000**	**0.03%**	-	-
4	August 14, 2026	Sangita Dokania	Promoter	Shashi Kumar Choudhary	Promoter	Secondary Sale	4,72,600	7.33%	-	-
TOTAL							**4,72,600**	**7.33%**	-	-
GRAND TOTAL							**4,84,600**	**7.52%**	-	-

3. Pre and Post Issue Shareholding of Promoter(s), Members of the Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the Company:

Sr. No.	Shareholders	Pre-Issue shareholding as at the date of Advertisement		Post-Issue shareholding as at Allotment (3)^			
				At the lower end of the price band (₹70)		At the upper end of the price band (₹74)	
		Number of Equity Shares (2)	Share Holding (in%) (2)	Number of Equity Shares (2)	Share holding (in%) (2)	Number of Equity Shares (2)	Share holding (in%) (2)
Promoters							
1.	Shashi Kumar Chaudhary	52,19,720	80.93	52,19,720	59.58	52,19,720	59.58
	Seema Chaudhary	2,49,920	3.88	2,49,920	2.85	2,49,920	2.85
	Sangita Dokania	6,47,400	10.04	6,47,400	7.39	6,47,400	7.39
	Shreya Chaudhary	5,080	0.08	5,080	0.06	5,080	0.06
	Sub-total (A)	**61,22,120**	**94.93**	**61,22,120**	**69.88**	**61,22,120**	**69.88**
Promoter Group (1)							
2.	Shreyash Dokania	1,60,000	2.48	1,60,000	1.83	1,60,000	1.83
	Shivangi Dokania	1,60,000	2.48	1,60,000	1.83	1,60,000	1.83
	Khushi Chaudhary	5,080	0.08	5,080	0.06	5,080	0.06
	Niraj Kumar Kedia	2,080	0.03	2,080	0.02	2,080	0.02
	Sub-total (B)	**3,27,160**	**5.07**	**3,27,160**	**3.73**	**3,27,160**	**3.73**
Top 10 Shareholders							
	NIL	Nil					
	Sub-total (C)	Nil					
	Total (A+B+C)	**64,49,280**	**100.00%**	**64,49,280**	**73.61%**	**64,49,280**	**73.61%**

Notes:
1) The Promoter Group shareholders are Shreyash Dokania, Shivangi Dokania, Khushi Chaudhary and Niraj Kumar Kedia.
2) Includes all options that have been exercised until date of prospectus and any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-issue and price band advertisement until date of prospectus.
3) Based on the Issue price of ₹[●] and subject to finalization of the basis of allotment.

BASIS FOR ISSUE PRICE

The ***"Basis of the Issue Price"*** on page 85 of the issue document has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM i.e. www.hemsecurities.com for the ***"Basis of the Issue Price"*** updated with the above price band.
(You may scan the QR code for accessing the website of Hem Securities Limited)

INDICATIVE TIMELINE FOR THE ISSUE

Our Company may in consultation with the BRLM, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

Sequence of Activities	Listing within T+3 days (T is Issue Closing Date)
Application Submission by Investors	Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – **Upto 4 pm on T Day.** Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc.) – **Upto 4 pm on T Day.** Electronic Applications (Syndicate Individual Bidder, Non-Institutional Applications) – **Upto 3 pm on T Day.**
	Physical Applications (Bank ASBA) – **Upto 1 pm on T Day.** Physical Applications (Syndicate Individual Bidder, Non-Institutional Applications of QIBs and NIIs) – **Upto 12 pm on T Day** and Syndicate members shall transfer such applications to banks before **1 pm on T Day.**
Bid Modification	From Issue opening date up to **4 pm on T Day.**
Validation of bid details with depositories	From Issue opening date up to **5 pm on T Day.**
Reconciliation of UPI mandate transactions (Based on the guidelines issued by NPCI from time to time): Among Stock Exchanges –Sponsor Banks – NPCI and NPCI – PSPs/TPAPs** – Issuer Banks; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines.	On daily basis Merchant Bankers to submit to SEBI, sought as and when.
UPI Mandate acceptance time	**T Day– 5 pm**
Issue Closure T day	**T Day – 4 pm** for Individual Investor, QIB, NII and other reserved categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be completed before **9:30 AM on T+1 day**
Third party check on Non-UPI applications	On daily basis and to be completed before **1 pm on T+1 day**
Submission of final certificates: -For UPI from Sponsor Bank -For Bank ASBA, from all SCSBs -For syndicate ASBA UPI ASBA	**Before 09:30 pm onT+1 day** All SCSBs for Direct ASBA – **Before 07:30 pm on T Day** Syndicate ASBA - **Before 07:30 pm on T Day**
Finalization of rejections and completion of basis	Before **6 pm on T+1 day.**
Approval of basis by Stock Exchange	Before **9 pm on T+1 day**
Issuance of fund transfer instructions in separate files for debit and unblock. For Bank ASBA and Online ASBA – To all SCSBs For UPI ASBA – To Sponsor Bank	Intimation not later than **9:30 am on T+2 day.** Completion before 2 pm on T+2 day for fund transfer; Completion before 4 pm on T+2 day for unlocking
Corporate action execution for credit of shares	Initiation before **2 pm on T+2 day** Completion before **6 pm on T+2 day**
Filing of listing application with Stock Exchanges and issuance of trading notice	Before **7:30 pm on T+2 day**
Publish allotment advertisement	On the website of Issuer, Merchant Banker and RTI - before **9 pm on T+2 day.** In newspapers - on **T+3 day but not later than T+4 day**
Trading starts T+3 day	**T+3 day**

Submission of Bids (other than Bids from Anchor Investors):

Bid/Issue Period (except the Bid/ Issue Closing Date)	
Submission and Revision in Bids	Only between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. (Indian Standard Time ("IST")
Bid/ Issue Closing Date* (i.e. September 16, 2026)	
Submission of Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – For Individual Investors other than QIBs and Non-Institutional Investors	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST
Submission of Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST
Submission of Electronic Applications (Syndicate Non- Individual Applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 3.00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Bank ASBA)	Only between 10.00 a.m. and up to 1.00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Applications of QIBs and Non-Institutional Investors)	Only between 10.00 a.m. and up to 12.00 p.m. IST
Modification/ Revision/cancellation of Bids	
Upward Revision of Bids by Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors categories #	Only between 10.00 a.m. on the Bid/Issue Opening Date and up to 4.00 p.m. IST on Bid/Issue Closing Date

**UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Issue Closing Date*
#Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors can neither revise their bids downwards nor cancel/ withdraw their Bids. On the Bid/Issue Closing Date, the Bids shall be uploaded until: 4.00 p.m. IST in case of Bids by Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors.

Event	Indicative Dates
Bid/ Issue Opening Date	Friday, September 11, 2026
Bid/ Issue Closing Date	Wednesday, September 16, 2026
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	Thursday, September 17, 2026
Initiation of Allotment/ Refunds/ Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI Id Linked Bank Account (T+2)	Friday, September 18, 2026
Credit of Equity Shares to Demat Accounts of Allottees (T+2)	Friday, September 18, 2026
Commencement of Trading of The Equity Shares on the Stock Exchange (T+3)	Monday, September 21, 2026

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!** | ***Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.** | **Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted**

UPI – Now available in ASBA for Individual investors and Non-Institutional investor applying for amount up to ₹5,00,000/- applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. UPI Bidder also have the option to submit the Application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the Bank Account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020, issued by the CBDT and the subsequent press release, including press release dated June 25, 2021 and September 17, 2021 and CBDT circular no. 7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by (i) Individual Investors Portion. (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹5,00,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section ***"Issue Procedure"*** on page 254 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognised Fpi=yes&intmId=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. Kotak Mahindra Bank Limited has been appointed as Sponsor Banks for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018 as amended. For Issue related queries, please contact the BRLMs on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and mail Id: ipo.upi@npci.org.in.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional working days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding 10 working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company in consultation with the Book Running Lead Manager for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Issue Period for a minimum of one working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Manager and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs"), other Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253(1) and 253(2) of the SEBI ICDR Regulations read with SEBI ICDR (Amendment) Regulations, 2025, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLMs may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). Pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2025, out of the Anchor Investor Portion, 40% shall be reserved, of which (i) 33.33% shall be available for allocation to domestic Mutual Funds and (ii) 6.67% shall be available for allocation to life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds, life insurance companies, and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription under (ii) above, the allocation may be made to domestic Mutual Funds. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the remaining QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, the SEBI ICDR Regulations read with SEBI ICDR (Amendment) Regulations, 2025, states that not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size. Not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Investors of which one-third of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots as equivalent to not more than ₹10.00 Lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹10.00 Lakhs and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion. Subject to the availability of shares in non-institutional investors' category, the allotment to each Non-Institutional Investors shall not be less than the minimum application size in Non-Institutional Category and the remaining available Equity Shares, if any, shall be allocated on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XIII of the SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025. All Potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Issue by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, please refer to the chapter titled ***"Issue Procedure"*** on page 254 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Corporate Structure" on page 126 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 293 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The liability of the member(s) is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of Red Herring Prospectus, the Authorized share Capital of the Company is Rs. 10,00,00,000/- (Rupees Ten Crore only) divided into 1,00,00,000 (One Crore) Equity Shares of face value of Rs.10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue Rs. 6,44,92,800/- (Rupees Six Crore Forty Four Lakhs Ninety Two Thousand and Eight Hundred Only) divided into 64,49,280 (Sixty Four Lakh Forty Nine Thousand Two Hundred and Eighty) Equity Shares of face value Rs.10/- each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 62 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Shashi Kumar Chaudhary-10 and Banwari Lal Chaudhary-10, aggregating to 20 Equity Shares of face value of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 126 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see **"Capital Structure"** on page 62 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares Issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited **("BSE SME")**. Our Company has received an "In-principle" approval from the BSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated November 27, 2025. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be BSE **("BSE SME")**. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been filed and the Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Section 26 and Section 32 of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus until the Bid/ Issue Closing Date, see ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** beginning on page 293 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 232 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE ("BSE SME") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the **'Disclaimer Clause pertaining to BSE'**.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 20 of the Red Herring Prospectus.

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Issue has handled 65 Public Issues in the past three years, out of which 4 issues were closed below the Issue/ Issue Price on listing date

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	63	4 (SME)

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Hem Securities	KFINTECH EXPERIENCE TRANSFORMATION	Century
HEM SECURITIES LIMITED **Address:** 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India. **Tel. No.:** +91- 22- 4906 0000 **Email:** ib@hemsecurities.com **Investor Grievance Email:** redressal@hemsecurities.com **Website:** www.hemsecurities.com **Contact Person:** Ravi Kumar Gupta **SEBI Registration Number:** INM000010981 **CIN:** U67120RJ1995PLC010390	**KFIN TECHNOLOGIES LIMITED** **Address:** Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana, India. **Tel No.:** 40 6716 2222' **Email:** cbml.ipo@kfintech.com **Investor Grievance Email:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Contact Person:** M Murali Krishna **Designation:** Vice President **SEBI Registration Number:** INR000000221 **CIN:** L72400TG2017PLC117649	**Shashank Poddar** **CENTURY BUSINESS MEDIA LIMITED** 107, Emarat Firdaus Exhibition Road, Patna, Bihar, India, 800001 **Telephone:** 0612-2320672/76 **Email:** info@centurymedia.in; **Website:** www.centurymedia.in **CIN:** U73100BR1999PLC009001 Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non- receipt of funds by electronic mode, etc. For all Issue related queries and for redressal of complaints investors may also write to the BRLMS.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at https://www.sebi.gov.in/, website of the Company at www.centurymedia.in/, the website of the BRLM to the Issue at https://www.hemsecurities.com/, the website of BSE at www.bseindia.com respectively.
AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and BSE at www.centurymedia.in/, https://www.hemsecurities.com/ and www.bseindia.com, respectively.
SYNDICATE MEMBER: Hem Finlease Private Limited
AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Century Business Media Limited, Telephone: 0612-2320672/76; BRLM: Hem Securities Limited, Telephone: +91-22-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91-141-4051000 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of BSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.
BANKER TO THE ISSUE/ ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: Kotak Mahindra Bank Limited.
UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.
All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors
Century Business Media Limited
Sd/-
Shashank Poddar
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Patna
Date: September 05, 2026

Disclaimer- Century Business Media Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public Offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated September 05, 2026 has been filed with the Registrar of Companies, Patna, Bihar and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of BSE www.bseindia.com at and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 20 of the Red Herring Prospectus.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act"**) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

SHAKUN

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

RAKSAN TRANSFORMERS LIMITED

(Formerly known as Raksan Transformers Private Limited)

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME")

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956, in the name and style of "Raksan Transformers Private Limited", pursuant to a Certificate of Incorporation dated July 21, 1995, issued by the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh, bearing CIN: U31103PB1995PTC016812. Subsequently, pursuant to a Special Resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on January 30, 2008, our Company shifted its registered office from the State of Punjab to the National Capital Territory of Delhi, with effect from October 15, 2008, and consequently, the CIN of our Company was changed to U31103DL1995PTC184910. Further, pursuant to a Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting held on March 26, 2025, our Company was converted into a Public Limited Company and the name of our Company was changed from "Raksan Transformers Private Limited" to "Raksan Transformers Limited". A fresh Certificate of Incorporation dated May 14, 2025 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, Manesar, bearing CIN: U31103DL1995PLC184910.

Registered Office: Shop No. 16, Local Shopping Centre-3, Sector-8, Rohini, North Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110085;
Corporate Office: Plot No 1675-76-77, HSIIDC Industrial Estate, Rai, P.S. Rai, Sonipat, Sonipat, Haryana, India, 131029 ;
Tel No: +91 8199946578 ; **E-mail:** cs@raksantransformers.com ; **Website:** www.raksantransformers.com ; **Contact Person:** Mukesh Sharma, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: SANJEEV KANDA, DIEVAM SINGH KANDA AND RENU KANDA

THE OFFER

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 55,12,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF RAKSAN TRANSFORMERS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN OFFER PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("PUBLIC OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF 44,12,800 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 11,00,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS {COMPRISING 11,00,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS BY SANJEEV KANDA (REFFERD AS "PROMOTER SELLING SHAREHOLDER")}, OUT OF WHICH 2,76,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹[●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 52,36,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.39% AND 25.06% RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

Subject to finalization of Basis of Allotment.

DETAILS OF THE SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION

NAME OF SELLING SHAREHOLDER	TYPE OF SHAREHOLDER	NO. OF EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹10/- EACH OF OUR COMPANY OFFERED/ AMOUNT (IN ₹ LAKHS)	WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION (IN ₹ PER EQUITY SHARE)*
Sanjeev Kanda	Promoter Selling Shareholder	Up to 11,00,000 Equity Shares of face value ₹10/- each of our Company aggregating to ₹ [●] lakhs	0.58

*** As certified by M/s. TU & Co., Chartered Accountants, Statutory Auditor by way of their certificate dated August 03, 2026.***

PRICE BAND: ₹ 258 TO ₹ 273 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹10/- EACH

THE FLOOR PRICE (₹258) IS 25.8 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE (₹273) IS 27.3 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL 2026 AT THE FLOOR PRICE (₹258) IS 12.65 TIMES AND AT THE CAP PRICE (₹273) IS 13.39 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 800 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 400 EQUITY SHARES THEREAFTER

Weighted average return on net worth for the last three fiscal years should be read as 42.45%

The details of the Fresh Issue and the post-Issue market Capitalisation of the Company, each at the Floor Price (₹258) and the Cap Price (₹273), are given below:

Particular	At Floor price of ₹258 per equity share		At Cap price of ₹273 per equity share	
	Up to No of equity Shares of face value of Rs. 10/- each	Up to amount (Rs in Lakhs)	Up to No of equity Shares of face value of Rs. 10/- each	Up to amount (Rs in Lakhs)
Fresh Issue	44,12,800	11385.02	44,12,800	12046.94
Offer for Sale	11,00,000	2838.00	11,00,000	3003.00
Total Issue Size	**55,12,800**	**14,223.02**	**55,12,800**	**15,049.94**
Post-Issue Market Capitalization of the Company	**2,08,93,400**	**53,904.97**	**2,08,93,400**	**57038.98**

BID/ OFFER PROGRAMME

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: WEDNESDAY, SEPTEMBER 09, 2026
BID/ OFFER OPENS ON: THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026
BID/ OFFER CLOSES ON: TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026^

^UPI mandate end time shall be at 05:00 p.m. on the Bid/Offer closing date.

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

We are an ISO 9001:2015 certified company engaged in the manufacturing of transformers across different voltage ratings. Our product offerings include distribution transformers, power transformers, transformers for solar applications, and special purpose transformers. These transformers are utilized across multiple sectors to facilitate the transmission and distribution of electrical energy. We focus on delivering quality and reliability in our product range, supported by standardized manufacturing practices and compliance with applicable industry norms. Transformers serve critical functions in power generation, transmission, and distribution networks, and are deployed in diverse industrial and infrastructure projects.

THIS OFFER IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS, IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI (ICDR) REGULATIONS"), AS AMENDED READ WITH RULE 19(2)(B) OF SECURITIES CONTRACT (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED FROM TIME TO TIME (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME") THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME"). FOR THE PURPOSE OF THE OFFER, THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE WILL BE BSE LIMITED.

ALLOCATION OF THE OFFER

- **QIB PORTION :** NOT MORE THAN 50.00% OF THE NET OFFER
- **NON-INSTITUTIONAL PORTION :** NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET OFFER
- **INDIVIDUAL PORTION :** NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET OFFER
- **MARKET MAKER PORTION :** UPTO 2,76,000 EQUITY SHARES OR 5.01% OF THE OFFER

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE OFFER, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER, potential investors should only refer to this pre-issue and price band advertisement for the issue and should not rely on any media articles/ reports in relation to the valuation of the company as these are not endorsed, published or confirmed either by the company or the Book Running Read Manager to the issue ("BRLM").

In accordance with the recommendation of the Independent Directors of our Company, pursuant to their resolution dated September 04, 2026, the above provided price band is justified based on quantitative factors/ KPIs disclosed in the **'Basis for Offer Price'** section beginning on page 96 of the Red Herring Prospectus ('RHP') vis-a-vis the weighted average cost of acquisition ("WACA") of primary and secondary transaction(s), as applicable, disclosed in ***'Basis for Offer Price'*** section beginning on page 96 of the Red Herring Prospectus and provided below in the advertisement.

RISKS TO INVESTORS

For details refer to section titled "Risk Factors" on page 21 of the Red Herring Prospectus.

1. Risk to investors summary description of key risk factors based on materiality

a) We derive a substantial portion of our revenue from government and public utility customers, the supply of transformers to public utility companies including government entities who constituted 50.73%, 72.99%, and 56.13% of our revenue from operations during the in Fiscal 2026, Fiscal 2025 and Fiscal 2024 respectively, and our business is highly dependent on government policies, project allocations, and payment cycles.

b) A significant portion of our revenue is derived from government-controlled entities, through competitive bidding processes. Our business, results of operations, and cash flows may be adversely affected if we are unable to qualify for or win tenders, face pricing pressures, experience delays in award or execution of contracts, or are restricted from participating in future bids.

c) Our order book may not be representative of our future results and our actual income may be significantly less than the estimates reflected in our order book, which could adversely affect our business, financial condition, results of operations and prospects.

d) We significantly depend upon few of the raw material suppliers for our manufacturing activities. Volatility in the supply and pricing of our raw materials may have an adverse effect on our business, financial condition and results of operations.

e) Any under-utilization or inability to efficiently utilize our existing manufacturing capacities could adversely affect our operational efficiency, financial performance, and future business prospects.

f) We derive a significant portion of our revenue from the sale of distribution transformers, and any reduction in demand or purchases for these transformers may adversely affect our business, results of operations, and financial condition.

g) We are significantly dependent on our relationships with key customers. The loss of one or more of these key customers, or a reduction in the volume of business from any of them, could have a material adverse effect on our revenue, profitability, and overall financial performance.

h) Any delays in manufacturing, supply chain, or third-party execution may result in liquidated damages or order cancellations

i) We are subject to strict quality requirements, regular inspections and audits. An inability to maintain the quality of our products could lead to the cancellation of existing and future orders, recall claims or warranty claims and penalties.

j) Our business inherently requires significant working capital, and any shortfall in meeting these requirements may adversely impact our operations, profitability, and future growth.

- **Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoters are:**

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Sanjeev Kanda	1,41,03,662	0.58
2.	Dievam Singh Kanda	4,75,000	0.00
3.	Renu Kanda	9,50,000	0.31

And the Offer Price at the upper end of the Price Band is Rs. 273 per Equity Share.

- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2026 for the company at the upper end (₹273) of the Price Band is 13.39.
- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2026, 2025 and 2024 is 42.45%.

2. Details of suitable ratios of the company and its peer group for the latest full financial year:

Name of Company	Current Market Price (₹)	Face Value	EPS		PE	RONW (%)	Book Value (₹)	Total Income (₹ In lakhs)
			Basic	Diluted				
Raksan Transformers Limited	[●]*	10	20.39	20.39	[●]^	43.41%	46.97	36,362.63
Marsons Limited	133.50	1	2.69	2.69	49.63	21.28%	12.64	24,503.09
Shilchar Technologies Limited	4074.85	10	138.25	138.25	29.47	32.22%	429.05	65,193.99
Supreme Power Equipment Limited	226.20	10	8.18	8.15	27.75	17.49%	47.30	18,164.04

**CMP of our Company is considered as Offer Price. ^to be included post finalization of the Offer Price.*

Notes:

i. Source – All the financial information for listed industry peers mentioned above is sourced from the Annual Reports of the aforesaid companies for the year ended March 31, 2026 and stock exchange data dated August 28, 2026 to compute the corresponding financial ratios. For our Company, we have taken Current Market Price as the Offer price of equity share. Further, P/E Ratio is based on the current market price of the respective scrips.

ii. The EPS, NAV, RoNW and total Income of our Company are taken as per Restated Financial Statement for the Financial Year 2025-26.

iii. NAV per share is computed as the closing net worth divided by the weighted average number of paid-up equity shares as on March 31, 2026.

iv. RONW has been computed as net profit after tax divided by closing net worth.

v. Net worth has been computed in the manner as specifies in Regulation 2(1) (hh) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

vi. The face value of Equity Shares of our Company is ₹ 10/- per Equity Share and the Offer price is [●] times the face value of equity share.

3. Weighted average return on net worth for the last 3 FYs:

As per restated financial statements:

Sr. No	Period	RONW (%)	Weights
1	Period ending March 31, 2026	43.41%	3
2	Period ending March 31, 2025	46.23%	2
3	Period ending March 31, 2024	32.03%	1
	Weighted Average	42.45%	-

Note:

i. The figures disclosed above are based on the Restated Financial Statements of the Company.

ii. The RoNW has been computed by dividing net profit after tax (excluding exceptional items) with restated Net worth as at the end of the year/period

iii. Weighted average = Aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. (RoNW x Weight) for each year/Total of weights.

4. Weighted average cost of acquisition of all the shares transacted in the three years, 18 months and one year preceding the date of the Red Herring Prospectus-

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Cap Price (₹273) is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
Last one year	0.00	NA	0-0
Last 18 months and Last 3 years	0.00	NA	0-273.67

**Allotment was done at the face value of Rs. 10 each.*

5. Disclosures as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI:

a) The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities)

There has been no issuance of Equity Shares during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested and issuance of bonus shares), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days.

b) The price per share of our Company based on the secondary sale/ acquisition of shares (equity shares)

There have been no secondary sale/ acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts of shares), during the 18 months preceding the date of the RHP, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

c) Since there are no such transactions to report to under (a) and (b) therefore, information based on last 5 primary or secondary transactions (secondary transactions where Promoter / Promoter Group entities or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of our Company, are a party to the transaction), not older than 3 years prior to irrespective of the size of transactions, is as below:

Primary Transaction

Date of Allotment	No. of equity Shares allotted	Face value per Equity share (₹)	Issue price per Equity share (₹)	Nature of allotment	Total Consideration	Total Consideration (in ₹ lakhs)
September 06, 2025	1,56,13,200	10/-	-	Bonus Allotment	Other than cash	Nil

Secondary Transaction

Date of Transfer	Name of Transferor	Name of Transferee	No. of Equity Shares	Price per Equity shares	Adjusted Price Per equity share (post bonus) *	Nature of Transaction	Total Consideration (in Rs. Lakhs)
March 15, 2025	Sanjeev Kanda	Prem Wati Kanda	1	Nil	Nil	Gift	Nil
		Renu Kanda	20,650				
		Dievam Singh Kanda	25,000				
		Daksh Singh Kanda	25,000				
		Ashok Kumar Kanda	1				
March 15, 2025	Sanjeev Kanda	SHR Powers Private Limited	100	273.67	14.40	Transfer	0.03

Continued on next page

Continued from previous page

Weighted average cost of acquisition & Issue price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price* (i.e., ₹ 258/-)	Cap Price (i.e., ₹ 273/-)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue as per paragraph (a) above.	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition as per paragraph (b) above.	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition of primary issuances / secondary transactions as per paragraph (c) above	Negligible	Nil	Nil

Note:

^There were no primary/ new issue of shares or secondary sale/acquisition of shares(equity/ convertible securities) as mentioned in paragraph (a) & (b) above, in last 18 months from the date of the Red Herring Prospectus.

The Offer Price shall be determined by our Company in consultation with the BRLM, on the basis of the demand from investor for the Equity Shares through Book Building Process.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS:

1. **Details of proposed /undertaken pre-Issue placements from the DRHP filing date:** Not Applicable
   Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date: Not Applicable
2. **Pre and Post Offer Shareholding of Promoter(s), Members of the Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the Company:**

Sr. No.	Shareholders	Pre-Offer shareholding as at the date of Advertisement[2]		Post-Offer shareholding as at the date of Allotment[3]			
				At Floor Price (₹ 258)		At Cap Price (₹ 273)	
		Number of Equity Shares[2]	Share Holding (in %)[2]	Number of Equity Shares[2]	Share holding (in %)[2]	Number of Equity Shares[2]	Share holding (in %)[2]
Promoter(s)							
1.	Sanjeev Kanda ^	1,41,03,662	85.58	1,30,03,662	62.24	1,30,03,662	62.24
	Dievam Singh Kanda	4,75,000	2.88	4,75,000	2.27	4,75,000	2.27
	Renu Kanda	9,50,000	5.76	9,50,000	4.55	9,50,000	4.55
Total (Promoters)		**1,55,28,662**	**94.22**	**1,44,28,662**	**69.06**	**1,44,28,662**	**69.06**
Members of Promoter Group							
2.	Prem Wati Kanda	19	Negligible	19	Negligible	19	Negligible
	Sanjeev Kanda HUF	4,75,000	2.88	4,75,000	2.27	4,75,000	2.27
	Daksh Singh Kanda	4,75,000	2.88	4,75,000	2.27	4,75,000	2.27
	SHR Powers Private Limited	1900	0.01	1900	0.01	1900	0.01
	Ashok Kumar Kanda	19	Negligible	19	Negligible	19	Negligible
	Total (Promoter Group)	**9,51,938**	**5.78**	**9,51,938**	**4.55**	**9,51,938**	**4.55**
Public Shareholders[1]							
	Total (Public Shareholders)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total (aggregate)	**1,64,80,600**	**100**	**1,53,80,600**	**73.61**	**1,53,80,600**	**73.61**

Notes:

^Promoter Selling Shareholder

1) *There are no public shareholder.*
2) *Assuming all vested ESOPs as on date of advertisement are exercised. The post issue shareholding shall be updated in the prospectus based on ESOPs exercised until such date.*
3) *Assuming full subscription in the Issue (fresh issue and/or offer for sale). The post-issue shareholding details as at allotment will be based on the actual subscription and the final Issue price and updated in the prospectus, subject to finalization of the basis of allotment. Also, this table assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement and allotment (if any such transfers occur prior to the date of prospectus, it will be updated in the shareholding pattern in the prospectus).*
4) *Based on the Offer price of ₹ [●] and subject to finalization of the basis of allotment.*

BASIS FOR OFFER PRICE

The ***"Basis of the Offer Price"*** on page 96 of the Offer document has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM i.e. www.hemsecurities.com for the ***"Basis of the Offer Price"*** updated with the above price band.

(You may scan the QR code for accessing the website of Hem Securities Limited)

INDICATIVE TIMELINE FOR THE OFFER

Our Company may in consultation with the BRLM, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

Sequence of Activities	Listing within T+3 days (T is Offer Closing Date)
Application Submission by Investors	Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – **Upto 4 pm on T Day.** Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc.) – **Upto 4 pm on T Day.** Electronic Applications (Syndicate Individual Bidders, Non-Institutional Applications) – **Upto 3 pm on T Day.**
	Physical Applications (Bank ASBA) – **Upto 1 pm on T Day.** Physical Applications (Syndicate Individual Bidders, Non-Institutional Applications of QIBs and NIIs) – **Upto 12 pm on T Day** and Syndicate members shall transfer such applications to banks **before 1 pm on T Day.**
Bid Modification	From Offer opening date up to **4 pm on T Day.**
Validation of bid details with depositories	From Offer opening date up to **5 pm on T Day.**
Reconciliation of UPI mandate transactions (Based on the guidelines issued by NPCI from time to time): Among Stock Exchanges –Sponsor Banks – NPCI and NPCI – PSPs/TPAPs** – Issuer Banks; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines.	On daily basis Merchant Bankers to submit to SEBI, sought as and when.
UPI Mandate acceptance time	**T Day– 5 pm**
Offer Closure T day	**T Day – 4 pm** for Individual Investor, QIB, NII and other reserved categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be completed before **9:30 AM on T+1 day**
Third party check on Non-UPI applications	On daily basis and to be completed before **1 pm on T+1 day**
Submission of final certificates: -For UPI from Sponsor Bank -For Bank ASBA, from all SCSBs -For syndicate ASBA UPI ASBA	**Before 09:30 pm on T+1 day** All SCSBs for Direct ASBA – **Before 07:30 pm on T Day** Syndicate ASBA - **Before 07:30 pm on T Day**
Finalization of rejections and completion of basis	Before **6 pm on T+1 day.**
Approval of basis by Stock Exchange	Before **9 pm on T+1 day**
Issuance of fund transfer instructions in separate files for debit and unblock. For Bank ASBA and Online ASBA – To all SCSBs For UPI ASBA – To Sponsor Bank	Intimation not later than **9:30 am on T+2 day.** Completion before **2 pm on T+2** day for fund transfer; Completion before **4 pm on T+2** day for unlocking
Corporate action execution for credit of shares	Initiation before **2 pm on T+2 day** Completion before **6 pm on T+2 day**
Filing of listing application with Stock Exchanges and issuance of trading notice	Before **7:30 pm on T+2 day**
Publish allotment advertisement	On the website of Issuer, Merchant Banker and RTI - before **9 pm on T+2 day.** In newspapers - on **T+3 day but not later than T+4 day**
Trading starts T+3 day	**T+3 day**

Submission of Bids (other than Bids from Anchor Investors):

Bid/Offer Period (except the Bid/ Offer Closing Date)	
Submission and Revision in Bids	Only between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. (Indian Standard Time ("IST")

Bid/ Offer Closing Date* (i.e. Tuesday, September 15, 2026)	
Submission of Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – For Individual Investors other than QIBs and Non-Institutional Investors	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST
Submission of Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST
Submission of Electronic Applications (Syndicate Non- Individual Applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 3.00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Bank ASBA)	Only between 10.00 a.m. and up to 1.00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Applications of QIBs and Non-Institutional Investors)	Only between 10.00 a.m. and up to 12.00 p.m. IST
Modification/ Revision/cancellation of Bids	
Upward Revision of Bids by Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors categories #	Only between 10.00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 4.00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date

**UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date*

#Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors can neither revise their bids downwards nor cancel/ withdraw their Bids. On the Bid/Offer Closing Date, the Bids shall be uploaded until: 4.00 p.m. IST in case of Bids by Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors.

Event	Indicative Dates
Bid/ Offer Opening Date	Thursday, September 10, 2026
Bid/ Offer Closing Date	Tuesday, September 15, 2026
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	Wednesday, September 16, 2026
Initiation of Allotment/ Refunds/ Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI Id Linked Bank Account (T+2)	Thursday, September 17, 2026
Credit of Equity Shares to Demat Accounts of Allottees (T+2)	Thursday, September 17, 2026
Commencement of Trading of The Equity Shares on the Stock Exchange (T+3)	Friday, September 18, 2026

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!** | ***Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.** | **Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted**

UPI – Now available in ASBA for Individual investors and Non-Institutional investor applying for amount up to ₹5,00,000/- applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. UPI Bidder also have the option to submit the Application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the Bank Account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020, issued by the CBDT and the subsequent press release, including press release dated June 25, 2021 and September 17, 2021 and CBDT circular no. 7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by (i) Individual Investors Portion. (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹5,00,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section ***"Offer Procedure"*** on page 268 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Banks for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018 as amended. For Offer related queries, please contact the BRLMs on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and mail Id: ipo.upi@npci.org.in.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period shall be extended for at least three (3) additional working days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Offer Period not exceeding ten (10) working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company in consultation with the Book Running Lead Manager for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Offer Period for a minimum of one (1) working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding ten (10) working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Manager and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs"), other Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

This Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253(1) and 253(2) of the SEBI ICDR Regulations read with SEBI ICDR (Amendment) Regulations, 2025, wherein not more than 50.00% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLMs may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). Pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2025, out of the Anchor Investor Portion, 40% shall be reserved, of which (i) 33.33% shall be available for allocation to domestic Mutual Funds and (ii) 6.67% shall be available for allocation to life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds, life insurance companies, and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription under (ii) above, the allocation may be made to domestic Mutual Funds. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the remaining QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, the SEBI ICDR Regulations read with SEBI ICDR (Amendment) Regulations, 2025, states that not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size. Not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors of which one-third of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots as equivalent to not more than ₹10.00 Lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹10.00 Lakhs and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion. Subject to the availability of shares in non-institutional investors' category, the allotment to each Non-Institutional Investors shall not be less than the minimum application size in Non-Institutional Category and the remaining available Equity Shares, if any, shall be allocated on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XIII of the SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025. All Potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Offer by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, please refer to the chapter titled ***"Offer Procedure"*** on page 268 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see ***"History and Corporate Structure"*** on page 140 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see the section ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 310 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The liability of the member(s) is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of Red Herring Prospectus, the Authorized share Capital of the Company is Rs. 25,00,00,000/- (Rupees Twenty-Five Crores only) divided into 2,50,00,000 (Two Crore Fifty Lakhs) Equity Shares of face value of Rs.10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Offer Rs. 16,48,06,000/- (Rupees Sixteen Crore Forty Eight Lakhs Six Thousand Only) divided into 1,64,80,600 (One Crore Sixty-Four Lakhs Eighty Thousand SixHundred) Equity Shares of face value Rs.10/- each. For details of the Capital Structure, see ***"Capital Structure"*** on the page 70 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Rakesh Kanda– 100 equity shares and Sanjeev Kanda – 100 equity shares, aggregating to 200 Equity Shares of face value of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see ***"History and Corporate Structure"*** on page 140 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see ***"Capital Structure"*** on page 70 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares Issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited (**"BSE SME"**). Our Company has received an "In-principle" approval from BSE Limited for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated February 05, 2026. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be BSE Limited (**"BSE SME"**). A signed copy of the Red Herring Prospectus has been filed and the Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Section 26 and Section 32 of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus until the Bid/ Offer Closing Date, see ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** beginning on page 310 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Offer is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 244 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE LIMITED ("BSE SME") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):

"It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to BSE."

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 21 of the Red Herring Prospectus.

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Offer has handled 65 Public Issues in the past three years, out of which 4 issues were closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	63	4 (SME)

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Hem Securities	Bigshare Services Pvt. Ltd.	RAKSAN
Hem Securities Limited 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India **Tel. No.:** +91- 22- 49060000; **Email:** ib@hemsecurities.com **Investor Grievance Email:** redressal@hemsecurities.com **Website:** www.hemsecurities.com **Contact Person:** Sourabh Garg **SEBI Regn. No.** INM000010981	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** **Address:** S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, India. **Telephone:** +91 22 6263 8200 ; **Facsimile:** +91 22 6263 8299 **Email:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance Email:** investor@bigshareonline.com **Contact Person:** Babu Rapheal C. **SEBI Registration No.:** INR000001385 **Website:** www.bigshareonline.com **CIN:** U99999MH1994PTC076534	**Mukesh Sharma** **Raksan Transformers Limited** Plot No. 1675-76-77, HSIIDC Industrial Estate, Rai, P.S. Rai, Sonipat, Sonipat, Haryana, India, 131029 **Tel.:** +91 8199946578 **E-mail:** cs@raksantransformers.com **Website:** www.raksantransformers.com Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non- receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer related queries and for redressal of complaints investors may also write to the BRLM.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at https://www.sebi.gov.in/, website of the Company at www.raksantransformers.com, the website of the BRLM to the Offer at https://www.hemsecurities.com/, the website of BSE at www.bseindia.com respectively.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and BSE at www.raksantransformers.com, https://www.hemsecurities.com/ and www.bseindia.com, respectively.

SYNDICATE MEMBER: Hem Finlease Private Limited

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Raksan Transformers Limited, Telephone: +91 8199946578; BRLM: Hem Securities Limited, Telephone: +91-22-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91-141-4051000 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of BSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

BANKER TO THE OFFER/ ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited.

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors
Raksan Transformers Limited
Sd/-
Mukesh Sharma
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Sonipat, Haryana
Date: September 04, 2026

Disclaimer- Raksan Transformers Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public Offer of its Equity Shares and the Red Herring Prospectus dated September 04, 2026 has been filed with the Registrar of Companies, New Delhi-II and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of BSE at https://www.bsesme.com/PublicIssues/RHP.aspx and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 21 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act"**) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public Issuing in the United States.

SHAKUN

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

[Please scan this QR Code to view the Prospectus]

PHYCHEM TECHNOLOGIES LIMITED

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME")

Our Company was originally incorporated as "Phychem Technologies Private Limited", a private limited company under the Companies Act, 1956, in Maharashtra, Mumbai, pursuant to a Certificate of Incorporation dated June 13, 2013, issued by the Registrar of Companies, Mumbai. Further, by way of a Special Resolution passed by the shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting held on August 02, 2025, our Company was converted into a public limited company, and consequently, its name was changed from "Phychem Technologies Private Limited" to "Phychem Technologies Limited". A fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from private company to public company was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, on August 18, 2025. The Corporate Identity Number (CIN) of our Company is U36109MH2013PLC244466. For further details of Incorporation, change of registered office of our Company, please refer to chapter titled ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 133 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: Gat No. 172, Khatwad, Dindori, Nashik, Mumbai, Maharashtra, India – 422004
Contact Person: Pooja Sharma, Company Secretary & Compliance Officer ; **Tel No:** +91-95187-20873; **E-mail:** cs@phychem.com; **Website:** www.phychem.com

OUR PROMOTERS: UMAKANT NIVRUTTI SAVADEKAR, ULKA UMAKANT SAVADEKAR, NIVRUTTI SONU SAVDEKAR AND VIJAYA NIVRUTTI SAVDEKAR

Our Company has filed the Prospectus dated September 03, 2026 with ROC and Equity Shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited (BSE SME) on September 07, 2026. **"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED (BSE SME)."**

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

We are engaged in the manufacturing of rotational molding (roto molding) compounds, which serve as a key raw material for producing a wide range of hollow plastic products through the rotational molding process. Our product portfolio primarily comprises customized polyethylene-based compounds, formulated using Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), High-Density Polyethylene (HDPE), and other specialty additives. These compounds are supplied in powder or granulated form to rotational molding manufacturers, enabling them to produce durable and application-specific plastic products across diverse end-use industries.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 27,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF PHYCHEM TECHNOLOGIES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "PTL" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 54 PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹44 PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 1458.00 LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 1,38,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 54 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 74.52 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 25,62,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 54 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹1383.48 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.37% AND 25.02 % RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS RS. 10/- AND ISSUE PRICE IS RS. 54/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 5.4 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE
ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: RS. 54/- PER EQUITY SHARE.
THE ISSUE PRICE IS 5.4 TIMES OF THE FACE VALUE

BID/ ISSUE PERIOD

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: FRIDAY, AUGUST 28, 2026
BID/ ISSUE OPENED ON: MONDAY, AUGUST 31, 2026
BID/ ISSUE CLOSED ON: WEDNESDAY, SEPTEMBER 02, 2026

RISKS TO INVESTORS:

a) *Our business is dependent and will continue to depend on our manufacturing facility, and we are subject to certain risks in our manufacturing process. Any slowdown or shutdown in our manufacturing operations or strikes, work stoppages or increased wage demands by our employees that could interfere with our operations could have an adverse effect on our business, financial condition and results of operations.*

b) *We derive a significant part of our revenue from major customers and we do not have long term agreements with any of these customers. If one or more of such customers choose not to source their requirements from us our business, financial position and results of operations may be adversely affected.*

c) *We are heavily reliant on few suppliers for the supply of our raw materials, with our single largest supplier contributing to more than 50% of our purchases during the last 3 financial years. Moreover, we do not have long-term agreements with these suppliers and an increase in the cost of, or a shortfall in the availability or quality of such raw materials could have an adverse effect on our business, financial condition and results of operations.*

d) *We derive a portion of our revenues from exports and are subject to risk of international trade.*

e) *Exchange rate fluctuations may adversely affect our results of operations as our sales from exports and purchases from imports are denominated in foreign currencies.*

f) *We are subject to strict quality requirements and the success and wide acceptability of our products is largely dependent upon our quality controls and standards. Any failure to comply with quality standards may adversely affect our business prospects and financial performance, including cancellation of existing and future orders.*

g) *The restated financial statements have been provided by peer reviewed chartered accountants who is not statutory auditor of our Company*

h) *Inventories and trade receivables form a major part of our current assets. Failure to manage our inventory and trade receivables could have an adverse effect on our sales, profitability, cash flow and liquidity.*

i) *Geographical concentration of our manufacturing facility and business may adversely affect our operations, business and financial condition*

j) *We are subject to increasingly stringent environmental, health and safety laws, regulations and standards. Non-compliance with and adverse changes in health, safety, labour, and environmental laws and other similar regulations to our manufacturing operations may adversely affect our business, results of operations and financial condition.*

k) *The BRLM associated with the Issue has handled 65 Public Issues in the past three years, out of which 4 issues were closed below the Issue/ Offer Price on listing date:*

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	63	4 (SME)

l) Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoters is

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Umakant Nivrutti Savadekar	37,18,633	0.05
2.	Ulka Umakant Savadekar	25,38,999	0.00
3.	Nivrutti Sonu Savdekar	2,26,122	0.38
4.	Vijaya Nivrutti Savdekar	75,400	0.38

m) The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2026 for the company at the upper end (₹54) of the Price Band is 9.96

n) Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2026, 2025 and 2024 is 28.71%.

o) The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one year, 18 months and three years from the date of Prospectus is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Cap Price (₹54) is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
Last one year preceding the date of the Red Herring Prospectus	1.57	34.39	0-52*
Last 18 Months & three years preceding the date of the Red Herring Prospectus	1.56	34.62	0-52*

*Allotment was done at the face value of Rs. 10 each.

p) The Weighted average cost of acquisition compared to Floor Price and Cap Price.

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 51)	Cap price (i.e. ₹ 54)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue as per paragraph 8(a) above.	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition as per paragraph 8(b) above.	NA^^	NA^^	NA^^
Weighted average cost of acquisition of primary issuances / secondary transactions as per paragraph 8(c) above	52/-	0.98	1.04

Note:

^There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) in last 18 months from the date of the Prospectus.

^^There were no secondary transactions as mentioned above, in last 18 months from the date of the Prospectus.

PROPOSED LISTING: SEPTEMBER 07, 2026*

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), 40% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for, (i) 33.33% shall be available for allocation to domestic Mutual Funds, and (ii) 6.67% for life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds, life insurance companies and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription in (ii) above, the allocation may be made to domestic Mutual Funds in accordance with the SEBI ICDR Regulations. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders (1/3rd of the portion available to NIBs shall be reserved for applicants with an application size of more than 2 lots and upto such lots equivalent to not more than ₹ 10.00 Lakhs and 2/3rd of the portion available to NIBs shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 10.00 Lakhs and the unsubscribed portion in either of the sub categories, could be allocated to applicants in the other sub-category of NIBs) and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of Individual Investors using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see **"Issue Procedure"** beginning on page 269 of the Prospectus.

The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to BSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the BSE Limited. The trading is proposed to be commenced on September 07, 2026 *

Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE **("BSE SME").*

SUBSCRIPTION DETAILS

The bidding for Anchor Investors opened and closed on Friday, August 28, 2026. The Company received 4 Anchor Investors applications for 14,88,000 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation price was finalized at ₹54/- per Equity Share. A total of 7,62,000 Equity Shares were allotted under the Anchor Investors portion aggregating to ₹ 4,11,48,000.

The Issue (excluding Anchor Investors Portion) received 5,912 Applications for 3,76,66,000 Equity Shares (after considering invalid bids, Other than RC10 Transaction declined by Investors, RC10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal/ Cancelled Bids reported by SCSB and rejections) resulting 19.44 times subscription (including reserved portion of market maker, and excluding anchor investor portion). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (before rejections):

Detail of the Applications Received (excluding Anchor Investors Portion):

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Total amount of allotment (Rs.)
1	Individual Investors	4,684	1,87,36,000	9,00,000	20.82	2,75,40,000.00
2	Non-institutional Investors (More than 2 lots and up to ₹10 lakhs)	580	36,22,000	1,32,000	27.44	71,28,000.00
3	Non-institutional Investors (above ₹10 lakhs)	645	1,29,70,000	2,58,000	50.27	1,39,32,000.00
4	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchors Investors)	2	22,00,000	5,10,000	4.31	4,86,00,000.00
5	Market Maker	1	1,38,000	1,38,000	1.00	74,52,000.00
	Total	**5,912**	**3,76,66,000**	**19,38,000**	**19.44**	**10,46,52,000.00**

Final Demand:

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

SR NO	RATE	SHARES	% to TOTAL	CUMULATIVE TOTAL	CUMULATIVE % TO TOTAL
1	51	1,36,000	0.28	1,36,000	0.28
2	52	50,000	0.10	1,86,000	0.39
3	53	74,000	0.15	2,60,000	0.54
4	54	4,79,70,000	99.46	4,82,30,000	100.00
	TOTAL	**4,82,30,000**	**100.00**		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the designated Stock Exchange, being BSE Limited ("BSE SME") on September 03, 2026.

1) Allotment to Individual Investors (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at or above the Issue Price of ₹ 54/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 20.64 times i.e. for 1,85,76,000 Equity Shares. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 9,00,000 Equity to 225 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
4000	4,644	100.00	1,85,76,000	100.00	4000	3:62	9,00,000
TOTAL	**4,644**	**100.00**	**1,85,76,000**	**100.00**			**9,00,000**

2) Allotment to Non-Institutional Investors (More than 2 lots and up to ₹ 10,00,000) (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Issue Price of ₹ 54/- or above per Equity Share was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 27.26 times i.e. for 35,98,000 Equity Shares (after rejection). The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,32,000 Equity Shares to 22 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No of equity shares	Ratio of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/ allotted
6,000	548	94.81	32,88,000	91.38	6,000	21:548	1,26,000
8,000	18	3.11	1,44,000	4.00	6,000	1:18	6,000
10,000	5	0.87	50,000	1.39	6,000	0:5	0
12,000	1	0.17	12,000	0.33	6,000	0:1	0
16,000	2	0.35	32,000	0.89	6,000	0:2	0
18,000	4	0.69	72,000	2.00	6,000	0:4	0
TOTAL	**578**	**100.00**	**35,98,000**	**100.00**			**1,32,000**

3) Allotment to Non-Institutional Investors (More than ₹ 10,00,000)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Issue Price of ₹ 54/- or above per Equity Share was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 50.19 times i.e. for 1,29,50,000 Equity Shares (after rejection). The total number of Equity Shares Allotted in this category is 2,58,000 Equity to 43 successful applicants. The details of the Basis of Allotment on sample basis of the said category are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Ratio of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/ alloted
20000	632	98.14	1,26,40,000	97.61	6,000	42:632	2,52,000
22000	8	1.24	17,60,000	1.36	6,000	1:8	6000
24000	1	0.16	24,000	0.19	6,000	0:1	0
26000	1	0.16	26,000	0.20	6,000	0:1	0
40000	1	0.16	40,000	0.31	6,000	0:1	0
44000	1	0.16	44,000	0.34	6,000	0:1	0
TOTAL	**644**	**100.00**	**1,29,50,000**	**100.00**			**2,58,000**

Continued on next page

कैसे बेपटरी हो गई सबसे बड़े एफडीआई सौदे के रूप में चर्चित पोस्को परियोजना

हेमंत कुमार राउत
भुवनेश्वर, 6 सितंबर

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली म्युंग-बाक 26 जनवरी, 2010 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। उन्हें ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में पोस्को की प्रस्तावित नई इस्पात परियोजना की जगह का भी मुआयना करना था। उन्हें इस परियोजना के उद्घाटन से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होना था। इस परियोजना में अनुमानित निवेश 12 अरब डॉलर (उस समय की विनिमय दर के हिसाब से करीब 51,000 करोड़ रुपये) था।

मगर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति का पोस्को परियोजना स्थल का दौरा कभी पूरा नहीं हो पाया। आखिरी समय में इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने प्रस्तावित जगह तक जाने वाला मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। यह घटनाक्रम पोस्को और ओडिशा सरकार के बीच समझौते के करीब पांच वर्ष बाद हुआ। उस समझौते को वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों की बदौलत भारत में विदेशी निवेश की राह आसान होने के बाद सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्ताव माना गया था। करीब चार वर्ष बाद फिर उम्मीद जगी। ओडिशा सरकार ने लगभग जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया था और उम्मीद थी कि पोस्को इंडिया जल्द ही काम शुरू कर देगी।

मगर, यह उम्मीद भी अधिक दिनों तक नहीं टिक पाई। कुछ ही महीनों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसकी जगह आई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम यानी एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन कर खनिज रियायत के लिए नीलामी व्यवस्था लागू कर दी। इससे पोस्को के लिए अपनी जरूरत लायक लौह-अयस्क खनन की व्यवस्था का इंतजाम कर पाना मुश्किल हो गया जो मूल इस्पात परियोजना का अहम हिस्सा था।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की निजी पहल मानी जाने वाली इस परियोजना से पोस्को रत्ती भर भी इस्पात उत्पादन किए बिना ही भारत से बाहर निकल गई।

यह परियोजना बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आसान बनाने की भारत की क्षमता की परीक्षा थी। फिर भी जरूरी मंजूरी हासिल करने में कई वर्ष लग गए जबकि प्रभावित परिवारों और कार्यकर्ताओं के लगातार विरोध के कारण राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संप्रग के दौर में इस परियोजना पर नजर रखने और मंजूरी प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एक समर्पित समिति होने के बावजूद प्रशासनिक, नियामकीय और राजनीतिक अड़चनों में फंसी रही।

अब लगभग एक दशक बाद दक्षिण कोरिया की इस्पात बनाने वाली यह कंपनी वापस आ रही है मगर एक बिल्कुल अलग योजना के साथ। इस बार वह राज्य में हर साल 60 लाख टन क्षमता वाला एकीकृत इस्पात संयंत्र तैयार करने के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ बराबर हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यम लगा रही है।

इस बीच, दूसरे बड़े निवेश सौद हुए जो 12 अरब डॉलर के प्रस्तावित निवेश से अधिक हैं। इनमें वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में बड़ी हिस्सेदारी खरीदना (16 अरब डॉलर में) और डेटा सेंटर बनाने के लिए अल्फाबेट का 15 अरब डॉलर का प्रस्तावित निवेश शामिल हैं।

पोस्को की पहली दस्तक

ओडिशा के साथ पोस्को का नाता वर्ष 2005 के समझौते से काफी पहले शुरू हो गया था। वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के निमंत्रण के बाद उसने संयंत्र लगाने की संभावना तलाशी थी। मगर यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वैश्विक इस्पात बाजार मुश्किल दौर से गुज़र रहा था।

एक दशक बाद हालात बहुत अलग थे। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक के तौर पर उभर रहा था, इस्पात की खपत तेज़ी से बढ़ रही थी और दुनिया भर की इस्पात कंपनियां उत्पादन के लिए नए स्थान की तलाश कर रही थीं। ओडिशा खास तौर पर आकर्षक था। यहां भरपूर खनिज संसाधन, लंबा समुद्री तट, अपेक्षाकृत सस्ता श्रम, जरूरत से अधिक बिजली और गहरे पानी वाले बंदरगाह तक पहुंच थी। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार तेजी से औद्योगीकरण की रणनीति पर भी काम कर रही थी जिसका मकसद ओडिशा को कच्चे खनिज निर्यातक से बदल कर एक विविध विनिर्माण एवं औद्योगिक केंद्र में तब्दील करना था।

अगस्त 2004 में पोस्को ने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी खनन कंपनी बीएचपी बिलिटन के साथ मिलकर ओडिशा सरकार के सामने हर साल 1 करोड़ टन क्षमता वाला एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। पहली बड़ी बाधा लौह-अयस्क की थी।

नैशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज के एक अध्ययन के मुताबिक पोस्को ने शुरू में 50 वर्षों में लगभग 1 अरब टन भारतीय अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग रखी थी। उसका तर्क था कि भारतीय अयस्क में एल्युमिना की मात्रा अधिक होने के कारण इसे ऑस्ट्रेलियाई खनिज के साथ मिलाने की जरूरत थी। हालांकि, मौजूदा नीति के तहत 1.2 करोड़ टन क्षमता वाले संयंत्र के लिए अयस्क का आवंटन 48 करोड़ टन तक सीमित था और 25 वर्षों से अधिक समय के लिए खनन अधिकार देने की इजाजत नहीं थी।

इन मुश्किलों के बावजूद राज्य ने परियोजना की तैयारी के लिए तेजी से कदम उठाए। उसने गंधमार्दन और मलंगटोली में मौजूद लौह-अयस्क के भंडार अपने लिए सुरक्षित कर लिया। माना जाता है कि यहां लगभग 40 करोड़ टन उच्च श्रेणी का अयस्क है। साथ ही, जगतसिंहपुर जिला प्रशासन को प्रस्तावित संयंत्र के लिए जटाधारी नदी के मुहाने के पास जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया गया। कई महीनों की बातचीत और नीति से जुड़ी मुश्किलों के बाद ओडिशा सरकार और पोस्को ने आखिरकार 22 जून, 2005 को 1.2 करोड़ टन क्षमता वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मई 2012 में ओडिशा सचिवालय में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ पोस्को इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक योंग वोन यून तथा अन्य।

पोस्को परियोजना: कब क्या हुआ?

जून 2005: पोस्को ने ओडिशा सरकार के साथ 12 अरब डॉलर लागत से पारादीप के पास 1.2 करोड़ टन क्षमता वाला नया इस्पात संयंत्र लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

अगस्त 2005: स्थानीय किसानों और मछली पकड़ने वाले समुदायों ने 'पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति' (पीवीएसएस) बनाई और परियोजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर नाकेबंदी शुरू की

दिसंबर 2006: संसद ने 'वन अधिकार अधिनियम' (एफआरए) पारित किया जिसमें कहा गया कि स्थानीय ग्राम सभाओं की स्पष्ट सहमति के बिना वन भूमि निगम को नहीं सौंपी जा सकती। यह प्रदर्शनकारियों के लिए एक मुख्य कानूनी हथियार बन गया

मई 2007: निजी इस्तेमाल वाले बंदरगाह के लिए तटीय नियामकीय क्षेत्र (सीआरजेड) से मंजूरी मिली

जुलाई 2007: 40 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र और कैप्टिव पावर प्लांट के लिए शुरुआती पर्यावरणीय मंजूरी मिली

नवंबर 2007: पोस्को के समर्थक और विरोधी समूहों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें 50 से अधिक लोग घायल हुए

मार्च 2008: एफआरए के आधार पर ढिंकिया ग्राम सभा ने अपनी पारंपरिक पान की खेती और वन भूमि को सौंपने से किया इनकार

अगस्त 2008: उच्चतम न्यायालय ने परियोजना के लिए वन भूमि के इस्तेमाल की 'सिद्धांत रूप में' मंजूरी बरकरार रखी

दिसंबर 2009: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन जमीन के दूसरे काम में इस्तेमाल के लिए औपचारिक मंजूरी दी जिससे स्थानीय भूख हड़ताल और टकराव की नौबत आ गई

फरवरी 2010: स्थानीय विरोध प्रदर्शन तीन महीने तक चलने वाले धरने में तब्दील हो गया

जून 2010: मूल 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया और जमीन से जुड़े चल रहे विवादों के बीच सरकार ने इसका नवीकरण नहीं किया

जुलाई 2010: ओडिशा उच्च न्यायालय ने खांडाहार लौह-अयस्क खदानों के लिए खनिज खोज का लाइसेंस देने का फैसला रद्द कर दिया

अक्टूबर 2010: ओडिशा सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की

जनवरी 2011: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ पर्यावरण मंजूरी दी

मई 2011: सरकार ने जगतसिंहपुर में जमीन अधिग्रहण का कार्य फिर शुरू किया

मार्च 2012: एनजीटी ने पोस्को को मिली पर्यावरण मंजूरी पर लगाई रोक

मई 2013: ओडिशा ने कंपनी को काम शुरू करने में मदद के लिए 2,700 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की घोषणा की

मई 2013: उच्चतम न्यायालय ने खांडाधार लौह-अयस्क खदानों के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस से जुड़े ओडिशा उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया

नवंबर 2014: केंद्र सरकार के यह कहने पर कि पट्टे में अधिसूचित और गैर-अधिसूचित इलाकों को साफ तौर पर अलग-अलग बताया जाए, ओडिशा सरकार ने प्रस्तावित खनन पट्टे के अधिसूचित इलाकों के लिए प्रस्ताव भेजा

जनवरी 2015: केंद्र ने एमएमडीआर संशोधन अध्यादेश, 2015 जारी किया जिसमें नीलामी के आधार पर खनन पट्टा देने का नियम बनाया गया

मार्च 2015: एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया

मार्च 2017: नियमों से जुड़ी अड़चनों और स्थानीय लोगों के लगातार विरोध का सामना करते हुए पोस्को ने आधिकारिक तौर पर अपनी सारी आवंटित जमीन वापस करने का अनुरोध किया और परियोजना से औपचारिक रूप से बाहर हो गई

अप्रैल 2017: ओडिशा सरकार ने ऐलान किया कि उसने पोस्को को जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है

अक्टूबर 2024: स्थानीयकरण रणनीति अपनाते हुए पोस्को ने नई इस्पात एवं हरित ऊर्जा परियोजनाओं की संभावना तलाशने के लिए जेएसडब्ल्यू समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

जुलाई 2025: दोनों बड़ी कंपनियों ने परियोजना में आधी-आधी हिस्सेदारी के लिए एक गैर-बाध्यकारी 'हेड्स ऑफ एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर कर अपना सहयोग और मजबूत किया

अप्रैल 2026: जेएसडब्ल्यू स्टील और पोस्को ने खनिज-समृद्ध क्योंझर और ढेंकानाल इलाकों में 60 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाली इस्पात परियोजना के लिए अपना पक्का संयुक्त उद्यम समझौता (जेवीए) किया

लौह-अयस्क का मुद्दा

इस समझौता ज्ञापन में लौह-अयस्क और कोयले के लिए कैप्टिव माइनिंग सुविधाओं की योजना थी। इसमें पोस्को को सुंदरगढ़ जिले में 13,000 एकड़ के खांडाधार लौह-अयस्क भंडार की खोज करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी शामिल था। माना जाता है कि यहां लगभग 60 करोड़ टन अयस्क है। समझौते में यह भी प्रावधान था कि पोस्को अपने द्वारा निकाले गए उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिना से लैस अयस्क का 30 प्रतिशत तक निर्यात कर सके और ब्लेंडिंग (मिलाने) के लिए इसे आयात किए गए कम-एल्युमिना वाले अयस्क के साथ बदल सके। हालांकि, ओडिशा को दी जाने वाली रॉयल्टी को लेकर सवाल उठाए गए। समझौते के तहत पोस्को को 30 वर्ष की अवधि (जिसे 20 साल और बढ़ाया जा सकता था) के लिए 60 करोड़ टन अयस्क पर 27 रुपये प्रति टन की निश्चित रॉयल्टी देनी थी। इससे राज्य को रॉयल्टी के तौर पर लगभग 1,620 करोड़ रुपये मिलते। विपक्षी पार्टियों और कार्यकर्ताओं का तर्क था कि वर्ष 2007-08 की दूसरी तिमाही में लौह अयस्क की कीमत लगभग 100 डॉलर (मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से 4,000 रुपये से अधिक) प्रति टन थी, ऐसे में 60 करोड़ टन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये होती।

इसके अलावा, खांडाधार लौह अयस्क भंडार पर खोज के अधिकारों के लिए पोस्को की 2005 की अर्जी कानूनी और नियामकीय प्रक्रियाओं में उलझ गई।

जमीन को लेकर जद्दोजहद

जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ी और तत्काल बाधा के रूप में सामने आ गई। मूल परियोजना के लिए जगतसिंहपुर जिले में 4,004 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इनमें 437.68 एकड़ जमीन निजी थी और 3,566.32 एकड़ जमीन सरकार की थी। ओडिशा के कई दूसरे हिस्सों की तुलना में इस परियोजना वाले इलाके की ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी, खासकर पान की खेती की वजह से। इस वजह से कई ग्रामीणों के लिए जमीन एक ऐसी उपजाऊ संपत्ति थी जिसकी भरपाई एक बार के मुआवजे से आसानी से नहीं हो सकती थी। फिर भी, ओडिशा सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

हालांकि, केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंजूरी तो दे दी मगर वन के इस्तेमाल की मंजूरी का मामला लंबे समय तक जांच के दायरे में रहा। इसके बाद, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के आकलन में त्रुटियों का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए परियोजना की पर्यावरण मंजूरी पर रोक लगा दी। इन रुकावटों का सामना करते हुए पोस्को ने धीरे-धीरे अपनी योजनाओं का आकार छोटा कर दिया। उसने पहले चरण में 80 लाख टन क्षमता पर विचार किया और तत्काल जरूरत वाली जमीन का आकार 4,004 एकड़ से घटा कर लगभग 2,700 एकड़ कर दिया। वर्ष 2012 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई। वर्ष 2013 तक राज्य सरकार ने लगभग 2,700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था मगर पूरी जमीन पोस्को के कब्जे में नहीं आई थी। लगभग 1,880 एकड़ जमीन कंपनी को सौंपी गई, जबकि एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार के पास ही रहा। तब तक इस परियोजना ने समय का फायदा भी गंवा दिया था। वर्ष 2005 का समझौता ज्ञापन वर्ष 2010 में खत्म हो गया और राजनीतिक व पर्यावरणीय गतिरोध के कारण इसका कभी औपचारिक रूप से नवीकरण नहीं किया गया।

जेएसडब्ल्यू के जरिये वापसी

अपनी मूल योजना असफल होने के लगभग दो दशक बाद पोस्को ओडिशा लौट आई है मगर इस बार जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ। यह बदलाव पोस्को के पीछे हटने के दो महीने बाद शुरू हुआ जब जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और इस्पात परियोजना लगाने में दिलचस्पी दिखाई।

राज्य प्रशासन ने गांव-स्तर पर मुआवजा के विवादों, पुनर्वास के मुद्दों और जमीन हस्तांतरण की समस्याओं को सुलझाया जिनकी वजह से पहले गतिरोध पैदा हुआ था। फरवरी 2024 में जेएसडब्ल्यू ने उसी इलाके में 1.32 करोड़ टन के इस्पात संयंत्र की आधारशिला रखी। निर्माण कार्य शुरू हो गया है और यह परियोजना लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ एक एकीकृत इस्पात परिसर के तौर पर विकसित की जा रही है। मगर पोस्को की वापसी का मामला केवल इतना नहीं है कि जेएसडब्ल्यू ने दक्षिण कोरियाई इस्पात निर्माता कंपनी की जगह ले ली है। दोनों कंपनियों ने अक्टूबर 2024 में भारत में 50 लाख टन के एकीकृत इस्पात संयंत्र की संभावना तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का गृह जिला क्योंझर पसंदीदा जगह के तौर पर उभरा। राज्य ने जमीन के टुकड़े चिह्नित किए हैं और 35,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

जिंदल ने कहा कि प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में अत्याधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा तंत्र पर सहयोग शामिल होगा। उन्होंने कहा, 'हम साथ मिलकर तकनीक और स्थिरता एवं टिकाऊपन में एक ऐसा मानक स्थापित करना चाहते हैं जो भारत और उससे बाहर विनिर्माण के भविष्य को आकार दे सके।' पोस्को के चेयरमैन चांग इन-ह्वा ने कहा कि यह साझेदारी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगी और अधिक टिकाऊ विनिर्माण को बढ़ावा देते हुए उनके आर्थिक विकास में योगदान देगी।

इस वर्ष अप्रैल में जेएसडब्ल्यू स्टील और पोस्को ने जेएसडब्ल्यू समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई सैफ्रन रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के जरिये ओडिशा के ढेंकानाल जिले में 60 लाख टन एकीकृत हरिय इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'पोस्को, जेएसडब्ल्यू द्वारा क्योंझर और ढेंकानाल में चलाए जा रही दो परियोजनाओं में से किसी एक में निवेश करेगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसे पहले मंजूरी मिलती है।'

अगर दोनों में कोई भी परियोजना शुरू होती है तो यह भारत में पोस्को का दूसरा बड़ा संयुक्त उद्यम होगा। वर्ष 2022 में कंपनी ने गुजरात में एक एकीकृत इस्पात मिल के लिए अदाणी समूह के साथ 5 अरब डॉलर का समझौता किया था।

नागपुर के प्रबंधन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमटी) में सहायक प्राध्यापक श्याम श्रीकुमारन नायर ने इस संयुक्त उद्यम के जरिये पोस्को की वापसी को एक समझ-बूझ वाला रणनीतिक कदम बताया। नायर ने कहा, 'जेएसडब्ल्यू के पास भारत के नियामकीय माहौल को समझने, कैप्टिव खदानें चलाने और जमीन अधिग्रहण का काम संभालने का बहुत अनुभव है। आखिरकार, यह संयुक्त उद्यम पोस्को को इस बात का अनुभव देती है कि गैर-बाजार रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर एक जटिल उभरते बाजार में काम कैसे किया जाता है।'

Continued from previous page

4) **Allotment to Market Maker:** The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹ 54/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 1,38,000 Equity shares the total number of shares allotted in this category is 1,38,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/allotted
1,38,000	1	100.00	1,38,000	100.00	1,38,000	1:1	1,38,000

5) **Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections):**

The Basis of Allotment to QIBs, who have bid at Issue Price of ₹ 54/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 4.31 times i.e. for 22,00,000 Equity shares. As per the SEBI Regulations, 5% of Net QIB portion was reserved for mutual funds i.e. 26,000 Equity Shares and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were allotted the remaining available Equity Shares i.e. 4,84,000 Equity Shares on a proportionate basis. The total number of shares allotted in this category is 5,10,000 Equity Shares to 2 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	VC'S	TOTAL
ALLOTMENT	-	-	-	4,18,000	92,000	-	-	**5,10,000**

6) **Allotment to Anchor Investors (After Rejections):**

The Company in consultation with the BRLM has allocated Equity Shares to 4 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of ₹ 54/- per Equity Shares in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. This represents upto 60% of the QIB Category.

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FPC	OTHERS	TOTAL
ANCHOR	-	-	-	1,86,000	5,76,000	-	-	**7,62,000**

The Board of Directors of our Company at its meeting held on September 03, 2026, has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched / mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on September 03, 2026. In case the same is not received within ten days, Investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on September 04, 2026 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE and the trading of the Equity Shares is expected to commence trading on September 07, 2026.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated September 03, 2026 filed with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra ("RoC").

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited)

q) **TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER:** The BRLM associated with the Issue has handled 65 Public Issues in the past three years, out of which 4 issues were closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	63	4 (SME)

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:

MUFG MUFG Intime

MUFG Intime India Private Limited
(Formerly Link Intime India Private Limited)
Address: C-101, Embassy 247, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083, (Maharashtra), India
Telephone: +91 810 811 4949
Website: www.in.mpms.mufg.com ; **Email:** phychemtechnologies.smeipo@in.mpms.mufg.com
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan
SEBI Registration No.: INR000004058 ; **CIN:** U67190MH1999PTC118368

On behalf of Board of Directors
Phychem Technologies Limited
Sd/-
Pooja Sharma
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Nashik
Date: September 04, 2026

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF PHYCHEM TECHNOLOGIES LIMITED

Disclaimer: *Phychem Technologies Limited has filed the Prospectus with the RoC on September 03, 2026 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of the BRLM, Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com and the Company at: www.phychem.com and shall also be available on the website of the BSE and SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see **"Risk Factors"** beginning on page 20 of the Prospectus.*

*The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act"**) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Issues and sales are made. There will be no public Issuing in the United States.*

SHAKUN

This is an advertisement issued, pursuant to Regulation 30(1) and Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, for information purposes only.

(Please scan the QR code to view the Tranche V Abrdiged Prospectus)

PAPPACHAN muthoot FINCORP

MUTHOOT FINCORP LIMITED

Our Company, Muthoot Fincorp Limited (the "**Company**" or the "**Issuer**") was incorporated in the Republic of India under the Companies Act, 1956, as amended as a public limited company on June 10, 1997 at Trivandrum as Muthoot Debt Management Services Limited. Subsequently, the name of the Company was changed to Muthoot Fincorp Limited, and a fresh certificate of incorporation dated March 19, 2002 was issued to the Company by the RoC. The Company is registered as a Non-Banking Financial Company ("**NBFC**") vide registration number N-16.00170 dated July 23, 2002 within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934, as amended (the "**RBI Act**"). For further details, see *"General Information"* on page 50 and *"History and Certain Corporate Matters"* on page 136, respectively, of the Tranche V Prospectus.

CIN: U65929KL1997PLC011518; **PAN:** AACCM1453E, **Website:** www.muthootfincorp.com

Registered office: Muthoot Centre, TC No 27/3022 Punnen Road, Trivandrum - 695 001, Kerala; Tel: +91 471 491 1550; **Email:** cs@muthoot.com;

Corporate office: Muthoot Centre, Near Spencer Junction, M.G. Road, Trivandrum 695 039, Kerala; Tel: +91 471 491 1430; **Email:** cs@muthoot.com;

Compliance Officer and Company Secretary: Sachu Sivas; **Email:** sachu.sivas@muthoot.com; **Tel:** +91 471 491 1621, **Chief Financial Officer:** Joseph Oommen; **Email:** joseph.oommen@muthoot.com; **Tel:** +91 471 491 1588

Link to download the Tranche V Abridged Prospectus: https://www.nuvama.com/wp-content/uploads/2026/09/Muthoot-Fin-Abridged_Sept-2026.pdf

PROMOTERS OF THE COMPANY

(i) Thomas John Muthoot, Email: muthoot@muthoot.com; Tel: +91 471 491 1505, (ii) Thomas George Muthoot; Email: muthoot@muthoot.com; Tel: +91 484 416 1650 and (iii) Thomas Muthoot, Email: muthoot@muthoot.com Tel: +91 484 416 1616; (iv) Preethi John Muthoot, Email: muthoot@muthoot.com, Tel: +91 471 491 1505; (v) Preethi John Muthoot (MF) Trust, Email: muthoot@muthoot.com, Tel: +91 471 491 1505; (vi) Nina George (MF) Trust, Email: muthoot@muthoot.com, Tel: +91 471 491 1505; (vii) Remmy Thomas (MF) Trust, Email: muthoot@muthoot.com, Tel: +91 471 491 1505; (viii) Thomas John Muthoot (MF) Trust, Email: muthoot@muthoot.com, Tel: +91 471 491 1505; (ix) Thomas George Muthoot (MF) Trust, Email: muthoot@muthoot.com, Tel: +91 471 491 1505; and (x) Thomas Muthoot (MF) Trust, Email: muthoot@muthoot.com, Tel: +91 471 491 1505. For further details, please see *"Our Promoters"* on page 202 of the Tranche V Prospectus.

PUBLIC ISSUE BY THE COMPANY OF UPTO 70,00,000 SECURED, RATED, LISTED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE ₹ 1,000 EACH ("NCDs" OR "DEBENTURES"), AMOUNTING UP TO ₹ 35,000 LAKHS ("BASE ISSUE SIZE") WITH A GREEN SHOE OPTION OF UP TO ₹ 35,000 LAKHS ("GREEN SHOE OPTION") AGGREGATING UP TO ₹ 70,000 LAKHS ("TRANCHE V ISSUE SIZE" OR "TRANCHE V ISSUE"). THE TRANCHE V ISSUE SIZE IS WITHIN THE SHELF LIMIT OF ₹ 3,00,000 LAKHS AND IS BEING OFFERED BY WAY OF THE TRANCHE V PROSPECTUS DATED SEPTEMBER 3, 2026 CONTAINING *INTER ALIA* THE TERMS AND CONDITIONS OF TRANCHE V ISSUE ("TRANCHE V PROSPECTUS"), WHICH SHOULD BE READ TOGETHER WITH THE SHELF PROSPECTUS DATED JANUARY 29, 2026 ("SHELF PROSPECTUS") FILED WITH THE ROC, STOCK EXCHANGES AND SEBI. THE SHELF PROSPECTUS AND THE TRANCHE V PROSPECTUS CONSTITUTES THE PROSPECTUS. THIS TRANCHE V ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF NON – CONVERTIBLE SECURITIES) REGULATIONS, 2021, AS AMENDED (THE "SEBI NCS REGULATIONS"), THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER AS AMENDED (THE "COMPANIES ACT, 2013") TO THE EXTENT NOTIFIED AND THE SEBI MASTER CIRCULAR, AS AMENDED FROM TIME TO TIME. THIS TRANCHE V ISSUE IS NOT UNDERWRITTEN.

CREDIT RATING : "Crisil AA/Stable" (pronounced as Crisil double A rating with stable outlook) by Crisil Ratings Limited and "BWR AA+/Stable" by Brickwork Ratings India Private Limited

Instruments with this rating are considered to have high degree of safety regarding timely servicing of financial obligations and carry very low credit risk

The following are the salient terms of the NCDs to be issued pursuant to the Tranche V Prospectus dated September 3, 2026

Series	I	II	III	IV	V	VI**	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nature	Secured	Secured	Secured	Secured	Secured	Secured	Secured	Secured	Secured	Secured	Secured	Secured
Tenure	24 Months	36 Months	60 Months	72 Months	24 Months	36 Months	60 Months	72 Months	24 Months	36 Months	60 Months	72 Months
Frequency of Interest Payment	Monthly	Monthly	Monthly	Monthly	Annual	Annual	Annual	Annual	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative
Minimum Application	₹ 10,000 (10 NCDs)											
In multiples, of	1 NCD after minimum application											
Face Value of NCDs (₹ /NCD)	₹ 1,000 (1 NCD)											
Issue Price (₹ /NCD)	₹ 1,000 (1 NCD)											
Mode of Interest Payment/ Redemption	Through various options available											
Coupon (%) (per annum) for Debenture Holders in Category I, II, III and IV	8.56%	8.75%	8.84%	8.88%	8.90%	9.10%	9.20%	9.25%	NA	NA	NA	NA
Coupon Type	Fixed											
Redemption Amount (₹ /NCD) for Debenture Holders in Category I, II, III and IV***	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1186.20	1298.91	1553.17	1701.14
Effective Yield (%) (per annum) for Debenture Holders in Category I, II, III and IV	8.90%	9.10%	9.20%	9.24%	8.89%	9.09%	9.19%	9.24%	8.90%	9.10%	9.20%	9.25%
Put and Call Option	N.A.											
Nature of Indebtedness	Secured											

****Subject to applicable tax deducted at source, if any.*

*** Our Company would allot the Series VI of NCDs, as specified in the Tranche V Prospectus to all valid Applications, wherein the Applicants have not indicated their choice of the relevant Series of NCDs.*

1. *With respect to Series where interest is to be paid on an annual basis, relevant interest will be paid on each anniversary on the face value of the NCDs. The last interest payment under annual Series will be made at the time of redemption of the NCDs.*
2. *With respect to Series where interest is to be paid on monthly basis, relevant interest will be paid on the first date of every month on the face value of the NCDs. The last interest payment under monthly Series will be made at the time of redemption of the NCDs. For the first interest payment for NCDs under the monthly options, interest from the Deemed Date of Allotment till the last day of the subsequent month will be clubbed and paid on the first day of the month next to that subsequent month.*
3. *Please refer to Annexure C of the Tranche V Prospectus for details pertaining to the illustrative cash flows of the Company in accordance with the SEBI Master Circular.*

TRANCHE V ISSUE PROGRAMME

TRANCHE V ISSUE OPENS ON: TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026

TRANCHE V ISSUE CLOSES ON**: TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026

*** The Tranche V Issue shall remain open for subscription on Working Days from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the period as indicated in the Tranche V Prospectus. Our Company may, in consultation with the Lead Manager, consider closing this Tranche V Issue on such earlier date or extended date (subject to a minimum period of two working days and a maximum period of ten working days from the date of opening of the Tranche V Issue and subject to not exceeding thirty days from filing the Tranche V Prospectus with ROC, including any extensions), as may be decided by the Board of Directors or the Stock Allotment Committee, subject to relevant approvals, in accordance with the Regulation 33A of the SEBI NCS Regulations. In the event of an early closure or extension of the Tranche V Issue, our Company shall ensure that notice of the same is provided to the prospective investors through an advertisement in an English daily national newspaper with wide circulation and a regional daily with wide circulation where the registered office of the Company is located (in all the newspapers or electronic modes such as online newspapers or websites of the Issuer or the stock exchange in which pre-issue advertisement for opening of the Tranche V Issue has been given on or before such earlier or initial date of Tranche V Issue closure). On the Tranche V Issue Closing Date, the Application Forms will be accepted only between 10:00 a.m. and 3:00 p.m. (Indian Standard Time) and uploaded until 5:00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as may be permitted by the Stock Exchange. Further, pending mandate requests for bids placed on the second last day and the last day of bidding will be validated by 5:00 p.m. (Indian Standard Time) on the Tranche V Issue Closing Date. For further details please see "General Information" on page 50 of the Tranche V Prospectus.*

A copy of the Shelf Prospectus and the Tranche V Prospectus has been filed with the RoC, in terms of Section 26 and Section 31 of the Companies Act, 2013, along with the requisite endorsed/certified copies of all requisite documents. For further details please see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 429 of the Tranche V Prospectus.

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application

* Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) is a better way of applying to issues by simply blocking of the funds in the bank account. For further details, check section on *"Issue Procedure - Method of Application"* on page 384 of the Tranche V Prospectus.

Mandatory in public issues from October 01, 2018. No Cheques will be accepted.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors and High Networth Individuals applying through Registered Brokers, DPs and RTAs submitting bids up to an application value of ₹5,00,000/- ("UPI Limit"). Retail Individual Investors and High Networth Individuals submitting bids up UPI Limit also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN.

UPI is now available for Retail Individual Investors and High Networth Individuals submitting bids up to an application value of ₹ 2,00,000/- and ₹ 5,00,000/- respectively, applying through Designated Intermediaries, SCSBs or through the BSE Direct App / Web interface of Stock Exchange or any other permitted methods. For details of the ASBA and UPI Process, refer to the details given in the Application Form and also refer to the section titled *"Issue Procedure"* beginning on page 381 of the Tranche V Prospectus. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at "http://www.sebi.gov.in". Axis Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Tranche V Issue, in accordance with the requirement of SEBI Master Circular dated October 15, 2025 as amended.

NCD allotment will be made in dematerialised form only. Allotment in consultation with the Lead Manager and the Designated Stock Exchange shall be made on the basis of the date of upload of each application into the electronic platform of the Stock Exchange, in each proportion subject to the allocation ratio indicated in the section titled "*Issue Procedure*" at page 381 of the Tranche V Prospectus.

Information required under Section 30 of Companies Act, 2013:

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regard to its objects: For information on the main objects of our company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 136 of the Tranche V Prospectus and clause V of the Memorandum of Association of our company. The Memorandum of Association is a document for inspection in relation to the Tranche V Issue. For further details, see the section titled *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 429 of the Tranche V Prospectus.

Liability of Members: Limited by Shares

Amount of share capital of the Company as on August 11, 2026: The Authorised Share Capital of the Company is ₹6,00,00,00,000 divided into 3,00,00,00,000 equity shares of face value of ₹2 each and ₹4,00,00,00,000 divided into 40,00,00,000 Preference Shares of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company as on August 11, 2026, is ₹5,95,59,82,510 divided into 97,79,91,255 equity shares of ₹2 each and 40,00,00,000 preference shares of ₹10 each.

Names of the signatories at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company and the number of shares subscribed for by them at the time of signing the Memorandum of Association: Given below are the Names of the signatories to the Memorandum of Association of our Company and shares held by them at the time of the signing of the Memorandum of Association: Mr. Thomas John Muthoot: 100 equity shares, Mr. Mathew M Thomas: 100 equity shares, Ms. Janamma Thomas : 100 equity shares, Mr. Thomas George : 100 equity shares, Mr. Thomas Muthoot :100 equity shares, Ms. Preethi John : 100 equity shares, Ms. Nina George : 100 equity shares and Ms. Remy Thomas : 100 equity shares.

LISTING: The NCDs offered through the Shelf Prospectus and the Tranche V Prospectus are proposed to be listed on BSE Limited ("**BSE**" or "**Stock Exchange**"). Our Company has received an 'in-principle' approval from BSE *vide* their letter no. DCS/AS/PI-BOND/30/25-26 dated January 29, 2026. BSE shall be the Designated Stock Exchange for the Issue.

GENERAL RISK: Investment in non-convertible securities is risky and investors should not invest any funds in such securities unless they can afford to take the risk attached to such investments. Investors are advised to take an informed decision and to read the risk factors carefully before investing in the Tranche V Issue. For taking an investment decision, the investors must rely on their own examination of the Issuer and the Issue, including the risks involved in it. Specific attention of the Investors is invited to the section *"Risk Factors"* on page 19 and *"Material Developments"* on page 212, respectively, of the Tranche V Prospectus, before making an investment in such Issue. These risks are not, and are not intended to be, a complete list of all risks and considerations relevant to the non-convertible securities or investor's decision to purchase such securities. The Tranche V Prospectus has not been and will not be approved by any regulatory authority in India, including the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), the Reserve Bank of India ("**RBI**"), any Registrar of Companies, Kerala and Lakshadweep, or any stock exchange in India nor do they guarantee the accuracy or adequacy of this document.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in anyway be deemed or construed that the Tranche V Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Tranche V Prospectus. The investors are advised to refer to the Tranche V Prospectus for the full text of the disclaimer clause of the BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF BSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by the BSE to use their network and software of the Online system should not in any way be deemed or construed as compliance with various statutory requirements approved by the Exchange; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of the Company, its promoters, its management or any scheme or project of the Company.

DISCLAIMER STATEMENT OF CRISIL: Crisil Ratings Limited (Crisil Ratings) has taken due care and caution in preparing the material based on the information provided by its client and / or obtained by Crisil Ratings from sources which it considers reliable (information). A rating by Crisil Ratings reflects its current opinion on the likelihood of timely payment of the obligations under the rated instrument and does not constitute an audit of the rated entity by Crisil Ratings. Crisil Ratings does not guarantee the completeness or accuracy of the information on which the rating is based. A rating by Crisil Ratings is not a recommendation to buy, sell, or hold the rated instrument; it does not comment on the market price or suitability for a particular investor. The rating is not a recommendation to invest / disinvest in any entity covered in the material and no part of the material should be construed as an expert advice or investment advice or any form of investment banking within the meaning of any law or regulation. Crisil Ratings especially states that it has no liability whatsoever to the subscribers / users / transmitters / distributors of the material. Without limiting the generality of the foregoing, nothing in the material is to be construed as Crisil Ratings providing or intending to provide any services in jurisdictions where Crisil Ratings does not have the necessary permission and/or registration to carry out its business activities in this regard. Muthoot Fincorp Limited will be responsible for ensuring compliances and consequences of non-compliances for use of the material or part thereof outside India. Current rating status and Crisil Ratings' rating criteria are available without charge to the public on the website, www.crisilratings.com. For the latest rating information on any instrument of any company rated by Crisil Ratings, please contact customer service helpdesk at 1800-267-3850.

DISCLAIMER CLAUSE OF BRICKWORK: The credit rating assigned by Brickwork Ratings India Private Limited (**"BWR"** or **"CRA"**) to the debt instruments of the Issuer has been undertaken in accordance with the provisions of the SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, and the applicable SEBI master circulars, guidelines and directions, as amended from time to time. The rating is based on information and data furnished by the Issuer and other sources believed by the CRA to be reliable. The CRA does not audit, verify, or independently validate such information and does not guarantee its accuracy, adequacy, or completeness. The credit rating is not a recommendation to buy, sell or hold the securities, nor does it constitute an opinion on the price, marketability, legal compliance, or suitability of the issue for any particular investor. The rating is an opinion on the relative credit risk of the rated instrument as on the date of assignment and is subject to revision, or withdrawal at any time, in accordance with applicable regulations and the CRA's internal policies, without prior notice. The CRA shall not be liable for any losses, damages, claims or expenses (direct, indirect, incidental, special or consequential) arising out of the use of, or reliance upon, the credit rating, the consent, or the contents of any of the above documents, except to the extent mandated under applicable law. The Issuer shall not state or imply that the CRA has verified, endorsed, guaranteed or assured the performance, repayment, or compliance of the issuer or the rated instruments.

DISCLAIMER CLAUSE OF CRISIL INTELLIGENCE (INDUSTRY REPORT): Crisil Intelligence, a division of Crisil Limited, provides independent research, consulting, risk solutions, and data & analytics to its clients. Crisil Intelligence operates independently of Crisil's other divisions and subsidiaries, including, Crisil Ratings Limited. Crisil Intelligence's informed insights and opinions on the economy, industry, capital markets and companies drive impactful decisions for clients across diverse sectors and geographies. Crisil Intelligence's strong benchmarking capabilities, granular grasp of sectors, proprietary analytical frameworks and risk management solutions backed by deep understanding of technology integration, makes it the partner of choice for public & private organisations, multi-lateral agencies, investors and governments for over three decades.

For the preparation of the report, Crisil Intelligence has relied on third party data and information obtained from sources which in its opinion are considered reliable. Any forward-looking statements contained in the report are based on certain assumptions, which in its opinion are true as on the date of the report and could fluctuate due to changes in factors underlying such assumptions or events that cannot be reasonably foreseen. The report does not consist of any investment advice and nothing contained in the report should be construed as a recommendation to invest/disinvest in any entity. The industry report is intended for use only within India. Provided that, the company shall be responsible for ensuring compliances and consequences of non-compliance for use of the report, material & issue documents or any part thereof outside India in relation to the issue.

DISCLAIMER CLAUSE OF RBI: The company is having a valid certificate of registration dated July 23, 2002 bearing registration no. N-16.00170 issued by the Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits/ discharge of liability by the company.

CREDIT RATING: Our Company has received rating of "Crisil AA/Stable" (pronounced as Crisil double A rating with stable outlook) each, for an amount of ₹ 2,73,704 lakhs (of which ₹ 1,11,205 lakhs is unutilised) of NCDs by Crisil Ratings Limited vide its letter dated August 18, 2026 along with the rating rationale dated August 17, 2026 for the NCDs proposed to be issued pursuant to the Tranche V Issue. Further, our Company has received rating of "BWR AA+/Stable" for an amount of ₹ 3,00,000 lakhs by Brickwork Ratings India Private Limited vide its letter dated July 23, 2026 along with rating rationale dated July 23, 2026, for the NCDs proposed to be issued pursuant to the Tranche V Issue. The rating given by Crisil Ratings Limited and Brickwork Ratings India Private Limited is valid as on the date of the Tranche V Prospectus and shall remain valid on date of issue and Allotment of the NCDs and the listing of the NCDs on BSE. The ratings of the NCDs indicates that instruments with this rating are considered to have high degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. Such instruments carry very low credit risk. The ratings provided by Crisil Ratings Limited and Brickwork Ratings India Private Limited may be suspended, withdrawn or revised at any time by the assigning rating agency and should be evaluated independently of any other rating. These ratings are not a recommendation to buy, sell or hold securities and Investors should take their own decisions. Please refer to Annexure A on page 433 of the Tranche V Prospectus for the rationale and press release for the above ratings. There are no unaccepted ratings and any other ratings other than as specified in the Tranche V Prospectus.

Availability of Application Form : Application form can be obtained from: Muthoot Centre, Near Spencer Junction, M.G. Road, Trivandrum - 695 039, Kerala; **Tel:** +91 471 491 1430, **Lead Manager :** Nuvama Wealth Management Limited, **Tel:** +91 22 4009 4400 and offices of Sub Syndicate Members, Trading Members and Designated Branches of the SCSBs. Application forms may be downloaded from the websites of the Company, BSE and the Lead Manager.

Availability of Shelf Prospectus and Tranche V Prospectus : Investors are advised to refer to the Shelf Prospectus and Tranche V Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Tranche V Issue. Physical copy of the Shelf Prospectus and Tranche V Prospectus may be obtained from Registered Office of the Company and the Lead Manager. The soft copy of the Abridged Prospectus can be downloaded from the website of Company at www.muthootfincorp.com, Lead Manager to the Issue at www.nuvama.com and Registrar to the Issue at www.integratedregistry.in.

Public Issue Account Bank, Sponsor Bank and Refund Bank : Axis Bank Limited.

Note: All Capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Shelf Prospectus dated January 29, 2026 and Tranche V Prospectus dated September 3, 2026.

Name of the Consortium Member: Nuvama Wealth and Investment Limited.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	DEBENTURE TRUSTEE	CREDIT RATING AGENCY		JOINT STATUTORY AUDITORS	
nuvama	INTEGRATED CORPORATE SOLUTIONS SIMPLIFIED	VARDHMAN TRUSTEESHIP PVT LTD Nurturing & Protecting your Trust	Crisil Ratings	BRICKWORK RATINGS		
Nuvama Wealth Management Limited 801-804, Wing A, Building No 3 Inspire BKC, G Block, Bandra Kurla Complex Bandra East, Mumbai – 400 051 **Tel:** +91 22 4009 4400 **Email:** mfl.ncd@nuvama.com **Website:** www.nuvama.com **Contact Person:** Ms. Saili Dave	**Integrated Registry Management Services Private Limited** 2nd Floor, Kences Towers, No. 1 Ramakrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600 017 **Tel:** +91 44 2814 0801 to 2814 0803 **Fax:** +91 44 2814 2479 **Email:** yuvraj@integratedindia.in **Website:** www.integratedregistry.in **Contact Person:** S Yuvaraj	**Vardhman Trusteeship Private Limited*** Unit No. 412, The Capital, C-70 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Audit Bhavan, Mumbai, Bandra, Maharashtra, India, 400051 **Tel:** 022 4264 8335/ 022 4014 0832 **E-mail:** compliance@vardhmantrustee.com **Website:** www.vardhmantrustee.com **Contact Person:** Yogesh Limbachiya	**Crisil Ratings Limited** Lightbridge IT Park, Saki Vihar Road, Andheri East, Mumbai - 400 072 **Tel:** +91 22 6137 3000 (B) **Email:** crisilratingdesk@crisil.com **Contact Person:** Ajit Velonie	**Brickwork Ratings India Private Limited** 3rd Floor, Raj Alkaa Park, No. 29/3 & 32/2, Kalena Agrahara, Bannerghata Road, Bengaluru, Karnataka - 560076 **Tel.:** +91 80404009940 **Email:** aditya.b@brickworkratings.com **Contact Person:** Aditya Balachandra	**M/s. Isaac & Suresh, Chartered Accountants** 1st Floor, NRA-52, Thennala Towers, Nandavanam, Palayam, Thiruvananthapuram – 695033, Kerala **Tel:** +91 471 2329875, +91 9447427862 **Email:** isaacandsureshtvm@gmail.com, 58suresh@gmail.com **Website:** www.isaacandsuresh.com **Contact Person:** Sobha Sethumadhavan **Peer Review No.:** 017346 **Firm Registration No.:** 001150S	**M/s. Vishnu Rajendran & Co, Chartered Accountants** No: 55/359, South Bridge Avenue Road, Panampilly Nagar, Ernakulam – 682036 **Tel:** +91 9400627999 **Email:** kochi@vrc.co.in **Website:** htpp://www.vrc.co.in **Contact Person:** M.P. Jose **Peer Review No.:** 025312 **Firm Registration No.:** 004741S

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER		
	Sachu Sivas **Muthoot Fincorp Limited,** Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Trivandrum - 695 001, **Tel:** +91 471 491 1621, **Email:** sachu.sivas@muthoot.com	Investors may contact the Registrar to the Issue or the Compliance Officer in case of any pre- Issue or post Issue related issues such as non-receipt of Allotment Advice, demat credit, or interest on application money etc.

** Vardhman Trusteeship Private Limited has by its letter dated June 15, 2026 given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Tranche V Issue and for its name to be included in the Tranche V Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the NCDs issued pursuant to this Tranche V Issue.*

Disclaimer: MUTHOOT FINCORP LIMITED ("Company"), subject to market conditions, and other considerations, is proposing a public issue of secured, rated, listed, redeemable, non-convertible debentures **("NCDs")** and has filed Tranche V prospectus dated September 3, 2026 (**" Tranche V Prospectus"**) which should be read together with the Shelf Prospectus dated January 29, 2026 (the **"Shelf Prospectus"**) (together with the Tranche V Prospectus, the **"Prospectus"**) with the Registrar of Companies, Kerala and Lakshadweep (**"RoC"**), BSE Limited (**"BSE"** or **"Stock Exchange"**) and Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**. The Shelf Prospectus and Tranche V Prospectus is available on the website of the Company at www.muthootfincorp.com, on the website of BSE at www.bseindia.com, on the website of the lead manager at www.nuvama.com, and on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Investors proposing to participate in the Tranche V Issue should invest only on the basis of the information contained in the Shelf Prospectus and Tranche V Prospectus. Investors should note that investment in the NCDs involves a high degree of risk and for details in relation to the same, refer to the Tranche V Prospectus, including the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 19 of the Tranche V Prospectus and *"Material Developments"* beginning on page 212 of the Tranche V Prospectus. The Issuer and the Lead Manager accept no responsibility for statements made otherwise than in the Shelf Prospectus and Tranche V Prospectus or in the advertisement or any other material issued by or at the instance of the Company and that anyone placing reliance on any other source of information would be doing so at their own risk. Capitalised terms not defined herein shall have the same meaning as assigned to such terms in the Tranche V Prospectus dated September 3, 2026.

For **MUTHOOT FINCORP LIMITED**
Sd/-
Thomas John Muthoot
Managing Director
(DIN : 00011618)

Place: Trivandrum
Date: September 4, 2026

Adfactors 345/26

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR AN INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. Initial Public Offer of equity shares on the SME platform of BSE Limited in compliance with Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations").

(Please scan this QR code to view Red Herring Prospectus and the Abridged Prospectus)

speedex™

MAHARAJA & SPEEDEX INDIA LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: U28997DL2006PLC146383

Our Company was originally incorporated and registered as a private limited company under the name "Maharaja Cookers Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation dated February 15, 2006 issued by the Registrar of Companies, N.C.T of Delhi & Haryana. Subsequently, our Company changed its name to add its brand name with the company name for better and smooth business flow, pursuant to a resolution passed by our Board of Directors at their meeting held on December 11, 2023 and a special resolution passed by our Shareholders at the EGM held on December 12, 2023, the name of our Company was changed to "Maharaja & Speedex India Private Limited", pursuant to a certificate of incorporation dated February 01, 2024, issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. Thereafter, our Company converted from a private limited company to a public limited company, pursuant to a resolution passed by our Board of Directors at their meeting held on December 02, 2025 and by our Shareholders at the EGM held on December 24, 2025, following which the name of our Company was changed to "Maharaja & Speedex India Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre on January 15, 2026. Further details of Incorporation, change of registered office of our Company, please refer to chapter titled ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 203 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: Kh. No. 53/27 GT Karnal Road Village, Alipur, Near Alipur Police Station, New Delhi – 110 036, India;
E-mail: cs@speedexind.com; **Website:** https://speedexind.com; **Contact Person:** Mansee Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS – RAKESH KUMAR AGGARWAL, KUSUM AGGARWAL, AKASH AGGARWAL, ANKIT BANSAL, ATUL TULSIAN AND ROHIT GARG

DETAILS OF THE OFFER

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 43,08,000 * EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF MAHARAJA & SPEEDEX INDIA LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN OFFER PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("PUBLIC OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UPTO 34,46,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 8,61,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH COMPRISING OF 4,30,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH BY RAKESH KUMAR AGGARWAL AND UPTO 4,30,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH BY AKASH AGGARWAL ("THE SELLING SHAREHOLDERS" OR "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS, OUT OF WHICH 2,16,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹[●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 40,92,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE [●] % AND [●]% RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

Subject to Basis of Allotment

DETAILS OF PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS AND THEIR WEIGHTED AVERAGE PRICE EQUITY SHARE

Name of Selling Shareholders	Type	Maximum number of Offered Shares	Weighted average cost of acquisition per Equity Share (In ₹)*
Rakesh Kumar Aggarwal	Promoter Selling Shareholder	Up to 4,30,800	0.01
Akash Aggarwal	Promoter Selling Shareholder	Up to 4,30,800	0.01

**As certified by the Statutory Auditor pursuant to a certificate dated September 03, 2026.*

PRICE BAND: ₹177 TO ₹186 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹10 EACH

● QIB Portion: Not More than 50.00% of the Net Offer ● Individual Investors Portion: Not Less than 35.00% of the Net Offer
● Non-Institutional Bidders Portion: Not Less than 15.00% of the Net Offer ● Market Maker Portion: 2,16,000 Equity Shares or 5.01% of the Offer

THE FLOOR PRICE IS 17.70 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS 18.60 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FY 2026 AT THE FLOOR PRICE IS 14.89 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 15.64 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 600 EQUITY SHARES THEREAFTER. | WEIGHTED AVERAGE RETURN ON NET WORTH FOR THE LAST THREE YEARS SHOULD BE READ AS 68.17%.

The details of the Fresh Issue and the Post-Issue market Capitalisation of the Company, each at the Floor Price (₹177) and the Cap Price (₹186), are given below

Particulars	At Floor Price of ₹177 per Equity Share — No. of Equity Shares of Face Value ₹10/- each (Up to)	At Floor Price of ₹177 per Equity Share — Amount (₹ in Lakhs) (Up to)	At Cap Price of ₹186 per Equity Share — No. of Equity Shares of Face Value ₹10/- each (Up to)	At Cap Price of ₹186 per Equity Share — Amount (₹ in Lakhs) (Up to)
Fresh Issue	34,46,400	6,100.13	3,446,400	6,410.13
Offer for Sale	8,61,600	1,525.03	861,600	1,602.58
Total Issue Size	43,08,000	7,625.16	4,308,000	8,012.88
Post-Issue Market Capitalization of the Company	1,28,98,740	28,930.90	16,345,140	30,401.96

BID/ OFFER PERIOD	
	ANCHOR INVESTOR BID/OFFER DATE: WEDNESDAY, SEPTEMBER 09, 2026*
	BID/OFFER OPENS ON: THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026
	BID/OFFER CLOSES ON: TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026**^

**The Company in consultation with the Book Running Lead Manager, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/ Offer Period shall be one Working Day prior to the Bid/Offer Opening Date.*
***Our Company may in consultation with the Book Running Lead Manager, consider closing the Bid/Offer Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/Offer Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations.*
^ UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date.

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE ISSUER COMPANY

Our Company is a drinkware manufacturing and distribution company focused on stainless-steel bottles and allied drinkware products, catering to both retail consumers and institutional customers across India. Our Company is engaged in the manufacturing, branding, marketing and distribution of stainless-steel bottles and value-added drinkware products, with a diversified portfolio designed to address evolving consumer preferences for durable, hygienic and reusable drinkware solutions.Our Company's product portfolio is broadly classified into Standard Products and Novelty Products. Standard Products include stainless steel bottles catering to routine usage, while Novelty Products comprise tumblers, feeding bottles and gym shakers, designed to meet evolving consumer preferences. These products are offered across multiple price points and consumer segments including mass, premium and lifestyle categories, enabling our Company to cater to a broad customer base. Over the past few years, our Company has expanded its product mix to include value-added and specialized drinkware products, reflecting growing consumer awareness around health, sustainability and the shift from plastic-based products to stainless-steel alternatives.

THE OFFER IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS 2018 ("SEBI (ICDR) REGULATIONS"), AS AMENDED READ WITH RULE 19(2)(B) OF SECURITIES CONTRACT (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME").

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE OFFER, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER.

In accordance with the recommendation of the Independent Directors of our Company, pursuant to their resolution dated September 04, 2026 the above price band is justified based on quantitative factors/ KPIs disclosed in the ***"BASIS OF OFFER PRICE"*** section beginning on page 109 of the Red Herring Prospectus vis-à-vis the weighted average cost of acquisition ("**WACA**") of primary and secondary transaction(s), as applicable

RISK TO INVESTORS
For details refer to section titled *"Risk Factors"* on page 21 of the RHP.

1. We source a significant portion of our raw material requirements from a limited number of suppliers, and any disruption in supply or deterioration of our relationship with such supplier(s) could have a material adverse effect on our business, results of operations and financial condition.
2. We are dependent on and derive a substantial portion of our revenue from certain key customers. Loss of relationship with any of these customers or delays or reductions in their orders may have an adverse effect on our business, results of operations, financial condition and cash flows.
3. We are dependent on our distribution network in India to sell and distribute our products and any disruption in our distribution network could have an adverse effect on our business, results of operations, financial condition and cash flows.
4. Manufacturing products for third parties under OEM and private-label arrangements may create potential channel conflicts and competitive overlap with our branded products, which could adversely affect our brand positioning and growth strategy.
5. Our revenue is concentrated in certain states, and any adverse developments in these regions could materially affect our business.
6. Our Company does not own any of the premises from which we operate, and all such premises are leased. Disruption of our rights as lessee or termination of the agreement with our lessor may adversely impact our operations and, consequently, our business, financial condition and results of operations.
7. Our Company and certain of our Promoters, Directors, Key Managerial Personnel, Senior Management and Subsidiaries are involved in certain legal proceedings. Any adverse decision in such proceedings may render us/them liable to liabilities/penalties and may adversely affect our business and results of operations.
8. We are dependent on third party transportation and logistics service providers. Any increase in the charges of these entities could adversely affect our business, results of operations and financial condition.
9. Under-utilization of our manufacturing capacities may have an adverse effect on our business, future prospects and future financial performance. Moreover, information relating to capacity utilization of our production facility included in the Red Herring Prospectus is based on certain assumptions and future production and capacity utilization may vary.
10. Our inability to accurately forecast demand for our products and manage our inventory may have an adverse effect on our business, results of operations, financial condition and cash flows.

Other Risks :

AVERAGE COST OF ACQUISITION OF PROMOTERS

Average Cost of Acquisition of Equity Shares by our Promoters (including the Promoter Selling Shareholders)

Name of the Promoters / Promoter Selling Shareholders	Number of Equity Shares held	Average cost per Equity Share (₹)
Rakesh Kumar Aggarwal**	3,192,258	0.01
Kusum Aggarwal	595,696	0.01
Akash Aggarwal**	2,127,326	0.01
Atul Tulsian	560,867	59.26
Rohit Garg	1,692,630	0.01
Ankit Bansal	1,206,199	0.01

*** These shareholders are Promoter Selling Shareholders.*

Comparison with Listed Industry Peers

We believe the following companies constitute our peer group, identified on the basis of listed public companies operating in business segments that are similar, in part or in full, to the segments in which our Company operates. Their business portfolios may not be exactly comparable in terms of size, product mix, or overall operations to those of our Company. Further, Company is engaged primarily in the manufacturing of stainless steel bottles, whereas, the peer companies are also engaged in other segments of the consumer ware industry. Accordingly, there are no directly comparable peers available that are fully aligned with our product profile and business model.

Name of the Company	Revenue from Operations (₹ in lakhs)	Face Value per equity share (₹)	P/E	EPS (Basic) (₹)	EPS (Diluted) (₹)	RoNW (%)	NAV per equity share (₹)
Maharaja & Speedex India Limited	12,265.38	10.00	[●]	11.89	11.89	80.47	20.73
Listed Peers							
Borosil Limited	1,19,591.63	1.00	38.23	6.24	6.24	9.30	74.12
Cello World Limited	2,32,370.79	5.00	25.69	14.70	14.70	14.35	101.62

Source: All the financial information for listed industry peers mentioned above is on a consolidated basis (unless otherwise available only on standalone basis) and is sourced from the annual reports/ financial results as available of the respective company for the Fiscal 2026 submitted to stock exchanges. The financial information of our Company is based on the restated Consolidated financial information for Fiscal 2026.

Notes:

a. P/E Ratio has been computed based on the closing market price of equity shares on NSE on August 14, 2026, divided by Diluted EPS.
b. Return on Net Worth (%) = Net Profit after tax as restated for the end of the fiscal divided by Average Net worth as at the end of the fiscal.
c. Average net worth means the average of the net worth of current and previous Fiscal. Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and Reserves and Surplus excluding capital reserves.
d. Net Asset Value per share = Net Worth at the end of the fiscal divided by weighted/outstanding average no. of equity shares outstanding during the fiscal.
e. The basic and diluted earnings per share for the Equity Shares of our Company has been presented to reflect the adjustments as per AS 20.

Return on Net Worth

Fiscal	RoNW(%)	Weight
Fiscal 2026	80.47	3
Fiscal 2025	68.03	2
Fiscal 2024	31.57	1
Weighted Average	**68.17**	

As certified by our Statutory Auditors pursuant to their certificate dated September 04, 2026.

Notes:

a. Return on Net Worth (%) = Net Profit after tax as restated for the end of the fiscal divided by Average Net worth as at the end of the fiscal.
b. Average net worth means the average of the net worth of current and previous Fiscal. Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and Reserves and Surplus.
c. Weighted average is aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. {(RoNW x Weight) for each fiscal} / {Total of weights}.

Weighted average cost of acquisition of all the shares transacted in the three years, 18 months and one year preceding the date of the Red Herring Prospectus.

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in ₹)	Cap Price is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price - Highest Price (in ₹)
Last one year	Nil^	Nil	Nil
Last eighteen months	58.28	3.19	0-58.33
Last three years	56.65	3.28	0-58.33

^ Equity Shares were acquired pursuant to bonus issue hence, cost of acquisition is Nil.

Weighted average cost of acquisition ("WACA")

1. **The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities).**
   The details of the Equity Shares, excluding shares issued under ESOP and issuance of bonus shares, during the eighteen (18) months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of our Company (calculated based on the pre-Issue capital before such transaction(s) and excluding ESOPs granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling thirty (30) days ("**Primary Issuance**") are as follows:
   Nil
2. **The price per share of our Company based on secondary sale/ acquisitions of shares (equity / convertible securities).**
   The details of secondary sale / acquisitions of Equity Shares or any convertible securities ("**Security(ies)**"), where the Promoter, members of the Promoter Group, or Shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of our Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the eighteen (18) months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of our Company (calculated based on the pre-Issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling thirty (30) days are as follows:

Date	Name of the transferor	Name of the transferee	Number of shares	Adjusted Number of shares*	Face value per equity share	Price per equity share	Nature of transaction	Nature of consideration	Total consideration (Rs in lakhs)
29/03/2025	Versha Aggarwal	Gaurav Tulsian	593	712,193	10	12,748	Transfer	Cash	75.60
29/03/2025	Versha Aggarwal	Nikita Tulsian	215	258,215	10	12,748	Transfer	Cash	27.41
18/12/2025	Akash Aggarwal	Abhishek	60	72,060	10	84,730	Transfer	Cash	50.84
18/12/2025	Akash Aggarwal	Richa	55	66,055	10	84,730	Transfer	Cash	46.60
18/12/2025	Akash Aggarwal	Vanilla Consultants	106	127,306	10	84,730	Transfer	Cash	89.81
18/12/2025	Akash Aggarwal	Rahul Garg	53	63,653	10	84,730	Transfer	Cash	44.91
18/12/2025	Akash Aggarwal	Utkarsh Patel HUF	108	129,708	10	84,730	Transfer	Cash	91.51
18/12/2025	Akash Aggarwal	Bhanuben Patel	60	72,060	10	84,730	Transfer	Cash	50.84
17/12/2025	Akash Aggarwal	Gaurav Tulsian	27	32,427	10	84,730	Transfer	Cash	22.88
18/12/2025	Rohit Garg	Chirag Jain	25	30,025	10	84,730	Transfer	Cash	21.18
18/12/2025	Rohit Garg	Neeru Khurana	8	9,608	10	84,730	Transfer	Cash	6.78
5/1/2026	Rohit Garg	Ravi Kumar Aggarwal	5	6,005	10	84,730	Transfer	Cash	4.24
24/12/2025	Rohit Garg	Dhairya Sethi	6	7,206	10	84,730	Transfer	Cash	5.08
18/12/2025	Rohit Garg	Lurk Estate Private Limited	21	25,221	10	84,730	Transfer	Cash	17.79
18/12/2025	Rohit Garg	Atul Tulsian	37	44,437	10	84,730	Transfer	Cash	31.35
31/08/2026	Akash Aggarwal	Sachin Sodhi	7,353	7,353	10	136	Transfer	Cash	10.00
31/08/2026	Akash Aggarwal	Harshita Bansal	11,030	11,030	10	136	Transfer	Cash	15.00
01/09/2026	Akash Aggarwal	Abakkus Venture Opportunities Fund	1,63,814	163,814	10	136	Transfer	Cash	222.79
01/09/2026	Rohit Garg	Founders Collective Fund	2,90,221	290,221	10	136	Transfer	Cash	394.70
01/09/2026	Ankit Bansal	Abakkus Venture Opportunities Fund	59,361	59,361	10	136	Transfer	Cash	80.73
01/09/2026	Ankit Bansal	Founders Collective Fund	3,897	3,897	10	136	Transfer	Cash	5.30
01/09/2026	Gaurav Tulsian	Abakkus Venture Opportunities Fund	70,943	70,943	10	136	Transfer	Cash	96.48
Total			**6,07,998**	**2,262,798**					**1,411.82**
Weighted Average Cost of Acquisition									**62.39***

**Adjusted for bonus shares allotted in the ratio of 1200 Equity Shares for every one Equity Share held pursuant to board resolution dated January 28, 2026.*

4. **Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price:**

Type of Transactions	WACA (in ₹)	Floor Price (₹177) *	Cap Price (₹186) *
Weighted average cost of acquisition for last 18 months for primary / new issue of shares (equity/ convertible securities), excluding shares issued under ESOP 2018 and issuance of bonus shares, during the 18 months preceding the date of this certificate, where such issuance is equal to or more than five per cent of the fully diluted paid-up share capital of our Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	Nil	Nil	Nil
Weighted average cost of acquisition for last 18 months for secondary sale / acquisition of shares equity/convertible securities), where our Promoters or Promoter Group entities or Promoter Selling Shareholders or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in our Board are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of this certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than five per cent of the fully diluted paid-up share capital of our Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	62.39	2.84 times	2.98 times

As certified by our Statutory Auditors pursuant to their certificate dated September 04, 2026.

5. **Explanation for Offer Price / Cap Price being 2.98 times of weighted average cost of acquisition of primary issuance price / secondary transaction price of Equity Shares (set out above) along with our Company's key performance indicators and financial ratios for the Fiscals 2026, 2025 and 2024.**

1. The Company operates an integrated manufacturing and distribution framework supported by its two manufacturing units located at village Akbarpur Barota, sub-tehsil Rai, District Sonipat, Haryana. Key activities such as product development, fabrication, finishing, quality control, packaging and dispatch are coordinated across these facilities to support an integrated production process. The Company's manufacturing operations are supported by structured systems for raw material procurement, production planning, quality assurance and logistics coordination. On the distribution side, the Company leverages its Pan-India distributor network comprising approximately 101 distributors across 17 states and 2 Union Territories, along with online sales channels, to reach customers across multiple markets.
2. The Company offers a diversified portfolio of stainless-steel consumer products across multiple price points, ranging from mass market offerings to premium products. The Company's product portfolio is broadly classified into Standard Products and Novelty Products. Standard Products include stainless steel bottles catering to routine usage, while Novelty Products comprise tumblers, feeding bottles and gym shakers, designed to meet evolving consumer preferences. These products are offered across multiple price points and consumer segments including mass, premium and lifestyle categories, enabling the Company to cater to a broad customer base.
3. The Company undertakes original equipment manufacturing (OEM) and private-label manufacturing, providing customized drinkware solutions for corporate gifting programs, institutional buyers and brand partners. These capabilities enable the Company to serve both business-to-consumer ("**B2C**") and business-to-business ("**B2B**") markets. In Fiscal 2026, Branded Business Revenue contributed 41.81% and OEM Revenue contributed 54.87% of revenue from operations. The Company continues to focus on product innovation, expansion of value-added categories and strengthening distribution reach.
4. The Company has demonstrated significant improvement in its financial performance over the past three fiscals. Revenue from Operations increased from ₹6,132.33 lakhs in Fiscal 2024 to ₹9,350.81 lakh in Fiscal 2025 and ₹12,265.38 lakhs in Fiscal 2026. EBITDA increased from ₹290.04 lakh in Fiscal 2024 to ₹1,060.97 lakh in Fiscal 2025 and ₹2,252.33 lakhs in Fiscal 2026, while EBITDA Margin increased from 4.73% to 11.35% and 18.36%, respectively. Net Profit after Tax increased from ₹107.85 lakh in Fiscal 2024 to ₹556.55 lakh in Fiscal 2025 and ₹1,534.19 lakhs in Fiscal 2026.
5. The Company's long-standing relationships with customers and suppliers constitute an important competitive strength and have contributed to the stability and growth of their business. Over the years, they have developed relationships with a diverse set of customers and vendors based on consistent product quality, reliable delivery and responsive customer service. The Company has established stable relationships with trusted vendors and enduring relationships with several institutional and commercial customers.

The Offer Price of ₹[●] has been determined by our Company, in consultation with the BRLM, on the basis of the demand from investors for the Equity Shares issued through the Book-Building Process. Our Company, in consultation with the BRLM, is justified of the Offer Price in view of the above qualitative and quantitative parameters. Investors should read the abovementioned information along with ***"Risk Factors"***, ***"Business Overview"*** and ***"Financial Information"*** on pages 21, 169 and 239 of the RHP, respectively to have a more informed view.

The trading price of the Equity Shares could decline due to the factors mentioned in the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 21 of the RHP or any other factors that may arise in the future and you may lose all or part of your investments.

TRACK RECORD OF THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Offer has handled 10 public issues in the past three Financial Years, out of which 1 issue closed below the Offer price on the listing date.

Name of the BRLM	Total Offer		Offer closed below IPO price on listing date
	Mainboard	SME	
Choice Capital Advisors Private Limited	4	6	1

Continued on next page...

...continued from previous page.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS

Details of proposed /undertaken pre-issue placements from the DRHP filing date: Our Company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the DRHP filing date.

Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date: The Promoters or members of the Promoter Group have undertaken transaction of shares aggregating up ot 1% or more of the paid-up equity share capital of the Company from the date of filling of the Draft Red Herring Prospectus till date of this Pre-Issue and Price Band Advertisement as follows:

Date of Transfer	Name of Allotee/Transferee	Transferor	No. of Equity Shares transferred	Face Value of Equity Shares of ₹10/- each	Issue Price per Equity share (₹)	Nature of Consideration	Total Consideration (₹)	% of Pre-offer share capital of the Company
31-Aug-26	Sachin Sodhi	Akash Aggarwal	7,353	10	136	Cash	1,000,008	0.06%
31-Aug-26	Harshita Bansal	Akash Aggarwal	11,030	10	136	Cash	1,500,080	0.09%
1-Sep-26	Abakkus Venture Opportunities Fund	Akash Aggarwal	163,814	10	136	Cash	22,278,704	1.27%
1-Sep-26	Founders Collective Fund	Rohit Garg	290,221	10	136	Cash	39,470,056	2.25%
1-Sep-26	Abakkus Venture Opportunities Fund	Ankit Bansal	59,361	10	136	Cash	8,073,096	0.46%
1-Sep-26	Founders Collective Fund	Ankit Bansal	3,897	10	136	Cash	529,992	0.03%
1-Sep-26	Abakkus Venture Opportunities Fund	Gaurav Tulsian	70,943	10	136	Cash	9,648,248	0.55%

PRE AND POST ISSUE SHAREHOLDING OF PROMOTER(S), MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP AND TOP 10 SHAREHOLDERS:

Sr. No.	Pre- Issue shareholding as at the date of Advertisement			Post- Issue shareholding as at Allotment[(1)]			
	Shareholders	No. of Equity Shares of Facevalue ₹10/- each	% of pre-issue share capital	At the Lower end of the Price band (₹177)	Shareholding (%)	At the Upper end of the Price band (₹186)	Shareholding (%)
				No. of Equity Shares	% of post-issue capital	No. of Equity Shares	% of post-issue capital
	(A) Promoters						
1	Rakesh Kumar Aggarwal^	3,192,258	24.75	3,623,058	22.17	3,623,058	22.17
2	Akash Aggarwal^	2,127,326	16.49	2,558,126	15.65	2,558,126	15.65
3	Rohit Garg	1,692,630	13.12	1,692,630	10.36	1,692,630	10.36
4	Ankit Bansal	1,206,199	9.35	1,206,199	7.38	1,206,199	7.38
5	Atul Tulsian	560,867	4.35	560,867	3.43	560,867	3.43
6	Kusum Aggarwal	595,696	4.62	595,696	3.64	595,696	3.64
	Total (A)	**9,374,976**	**72.68**	**10,236,576**	**62.63**	**10,236,576**	**62.63**
	(B) Promoter Group						
7	Gaurav Tulsian	673,677	5.22	673,677	4.12	673,677	4.12
8	Shikha Goel	604,103	4.68	604,103	3.70	604,103	3.70
9	Versha Aggarwal	271,426	2.10	271,426	1.66	271,426	1.66
10	Nikita Tulsian	258,215	2.00	258,215	1.58	258,215	1.58
11	Priyanka Bansal	128,507	1.00	128,507	0.79	128,507	0.79
	Total(B)	**1,935,928**	**15.01**	**1,935,928**	**11.84**	**1,935,928**	**11.84**
	Additional top 10 shareholders						
12	Founders Collective Fund	294,118	2.28	294,118	1.80	294,118	1.80
13	Abakkus Venture Opportunities Fund	294,118	2.28	294,118	1.80	294,118	1.80
14	Utkarsh Patel	186,155	1.44	186,155	1.14	186,155	1.14
15	Richa Garg	162,135	1.26	162,135	0.99	162,135	0.99
16	Abhishek Garg	162,135	1.26	162,135	0.99	162,135	0.99
17	Utkarsh Patel HUF	129,708	1.01	129,708	0.79	129,708	0.79
18	Vanilla Consultants	127,306	0.99	127,306	0.78	127,306	0.78
19	Bhanuben Bharatbhai Patel	72,060	0.56	72,060	0.44	72,060	0.44
20	Rahul Garg	63,653	0.49	63,653	0.39	63,653	0.39
21	Chirag Jain	30,025	0.23	30,025	0.18	30,025	0.18
	Total ©	**1,521,413**	**11.80**	**1,521,413**	**9.31**	**1,521,413**	**9.31**

^ Also a Promoter Selling Shareholder

Notes:

(1) Assuming full subscription in the Issue. The post-Issue shareholding details as at Allotment will be based on the actual subscription and the Issue Price and updated in the Prospectus, subject to finalization of the Basis of Allotment .Also, this table assumes there is no transfer of shares by the Shareholders between the date of the price band advertisement and Allotment, and if any such transfers occur prior to the date of Prospectus, it will be updated in the shareholding pattern in the Prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE

The section titled ***"Basis of Offer Price"*** on page 109 of the Offer Document has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM i.e. www.choiceindia.com for the ***"Basis of Offer Price"*** updated with the above price band. (You may scan the QR Code for accessing the website of Choice Capital Advisors Private Limited.)

AN INDICATIVE TIMETABLE IN RESPECT OF THE OFFER IS SET OUT BELOW:

Submission of Bids (other than Bids from Anchor Investors):

Bid/Offer Period (except the Bid/Offer Closing Date)	
Submission and Revision in Bids	Only between 10:00 a.m. and 5:00 p.m. (Indian Standard Time ("**IST**")
Bid/Offer Closing Date*	
Submission of Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – For Individual investors, other than QIBs and Non-Institutional investors	Only between 10:00 a.m. and up to 5:00 p.m. IST
Submission of Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA applications) where Bid Amount is upto ₹5,00,000	Only between 10:00 a.m. and up to 5:00 p.m. IST
Submission of Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications)	Only between 10:00 a.m. and up to 3:00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Bank ASBA)	Only between 10:00 a.m. and up to 1:00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications of QIBs and Non-Institutional Investors where Bid Amount is more than ₹500,000)	Only between 10:00 a.m. and up to 12:00 p.m. IST
Modification/Revision of Bids	
Upward Revision of Bids by QIBs and Non-Institutional Investors categories	Only between 10:00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 4:00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date
Upward Revision of Bids by IIs	Only between 10:00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 5:00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date

**UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date.*

 # Any category of Investors can neither revise their bids downwards nor cancel/ withdraw their Bids.

On the Bid/Offer Closing Date, the Bids shall be uploaded until:

(i) 4.00 P.M. IST in case of Bids by QIBs and Non-Institutional Bidders, and

(ii) until 5.00 P.M. IST or such extended time as permitted by the Stock Exchange, in case of Bids by Individual Bidders

On the Bid/Offer Closing Date, extension of time will be granted by the Stock Exchange only for uploading Bids received from Individual Bidders after taking into account the total number of Bids received and as reported by the Book Running Lead Manager to the Stock Exchange.

BID/OFFER PROGRAM

Events	Indicative Date
Bid/Offer Opens On	Thursday, September 10, 2026[1]
Bid/Offer Closes On	Tuesday, September 15, 2026[2]*
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	On or about Wednesday, September 16, 2026
Initiation of Refunds (if any, for Anchor Investors)/ unblocking of Funds from ASBA Account or UPI ID (T+2)	On or about Thursday, September 17, 2026
Credit of Equity Shares to Demat accounts of Allottees (T+2)	On or about Thursday, September 17, 2026
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchange (T+3)	On or about Friday, September 18, 2026

Note:-

[1] Our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager, may consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. The Anchor Investor Bid/Offer Period shall be one Working Day prior to the Bid/Offer Opening Date in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.

[2] Our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager, consider closing the Bid/Offer Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/Offer Closing Date in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.

** In case of any delay in unblocking of amounts in the ASBA Accounts (including amounts blocked through the UPI Mechanism) exceeding three Working Days from the Bid/Offer Closing Date for cancelled /withdrawn / deleted ASBA Forms, the Bidder shall be compensated at a uniform rate of INR I00 per day or 15% per annum of the Bid Amount, whichever is higher from the date on which the request for cancellation/withdrawal/deletion is placed in the Stock Exchange bidding platform until the date on which the amounts are unblocked; (ii) any blocking of multiple amounts for the same ASBA Form (for amounts blocked through the UPI Mechanism), the blocked funds other than the original application amount shall be instantly revoked and the Bidder shall be compensated at a uniform rate INR 100 per day or 15% per annum of the total cumulative blocked amount except the original application amount, whichever is higher from the date on which such multiple amounts were blocked till the date of actual unblock; (iii) any blocking of amounts more than the Bid Amount, the different amount (i.e., the blocked amount less the Bid Amount) shall be instantly revoked and the Bidder shall be compensated at a uniform rate of INR 100 per day or 15% per annum of the difference in amount, whichever is higher from the date on which such excess amounts were blocked till the date of actual unblock; (iv) any delay in unblocking of non-allotted/ partially allotted Bids, exceeding three Working Days from the Bid/Offer Closing Date, the Bidder shall be compensated at a uniform rate of INR 100 per day or 15% per annum of the Bid Amount, whichever is higher for the entire duration of delay exceeding three Working Days from the Bid/Offer Closing Date by the intermediary responsible for causing such delay in unblocking. The BRLM shall, in their sole discretion, identify and fix the liability on such intermediary or entity responsible for such delay in unblocking.*

The Bidder shall be compensated in the manner specified in the SEBI ICDR Master Circular and the SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/76 dated May 30, 2022, which for the avoidance of doubt, shall be deemed to be incorporated in the agreements to be entered into between our Company with the relevant intermediaries, to the extent applicable.

The processing fees for applications made by UPI Bidders using the UPI Mechanism may be released to the remitter banks (SCSBs) only after such banks provide a written confirmation of compliance with SEBI ICDR Master Circular.

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!** | ***Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details check section on ASBA.** | **Mandatory in Public Issues. No cheque will be accepted.**

UPI — UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UPI-Now available in ASBA for all individual investors and non-institutional investors applying in public issues where the application amount is up to ₹500,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, DPs & RTAs. UPI Bidders also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and the subsequent press releases, including press release dated June 25, 2021 read with press release dated September 17, 2021 and CBDT circular no.7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by (i) Individual Investors in the Retail Portion. (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹5,00,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section ***"Offer Procedure"*** on page 312 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("**AIBI**") and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. Axis Bank Limited has been appointed as the Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of SEBI circular dated November 1, 2018 as amended. For Offer related queries, please contact the BRLM on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and mail Id: ipo.upi@npci.org.in. For Offer related grievance investors may contact: Choice Capital Advisors Private Limited - Nimisha Joshi/Madhuri Mandhania (+91 22 6707 9999 / 7919) (Email: msil.ipo@choiceindia.com).

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period shall be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Offer Period for a minimum period of one Working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank as applicable.

This Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 229(2) of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Portion**"), provided that our Company in consultation with the Book Running Lead Manager may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), out of which 40% shall be reserved in the following manner, (i) 33.33% of the Anchor investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, and (ii) 6.67% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for Life Insurance Companies and Pension Funds registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India under the provisions of the Insurance Act, 1938 and pension funds registered with the Pension Fund Regulatory and Development Authority under the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds and life insurance companies and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors out of which (a) one third of such portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for applicants with application size of more than 2 lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs and (b) two-third of such portion available to Non Institutional Investor shall be reserved for applicants with application size of more than ₹10 lakhs provided that the unsubscribed portion in either of such subcategories (a) (b) may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) are required to participate in the Offer by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA Account and UPI ID in case of individual investors using the UPI Mechanism, if applicable, (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, refer to the chapter titled ***"Offer Procedure"*** on page 311 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/ Applicants should ensure that DP ID, PAN, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism) are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism) as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorised the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders'/Applicants' sole risk. Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021, read with press release dated September 17, 2021 and CBDT circular no.7 of 2022,dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards to its objects: For information on the main objects and other objects of our Company, see ***"History and Corporate Structure"*** on page 202 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 353 of the Red Herring Prospectus.

Liability of members of the Company: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the Red Herring Prospectus, the Authorized Share Capital is ₹2,000.00 lakhs divided into 2,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. Issued, Subscribed & Paid-up Share Capital prior to the Issue ₹1,289.87 lakhs divided into 1,28,98,740 Equity Shares of ₹10/- each. For details of the Capital Structure, please refer ***"Capital Structure"*** on page 76 of the Red Herring Prospectus.

NAME OF THE SIGNATORIES TO MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our company, Rakesh Kumar Aggarwal and Kusum Aggarwal, 5,000 equity shares each agreegation to 10,000 equity share of ₹10 each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see section titled ***"History and Corporate Structure"*** on page 203 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the company see section titled ***"Capital Structure"*** on page 76 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares offered through this Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited (**BSE SME**) in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an 'in-principle' approval letter dated June 25, 2026 from BSE SME for using its name in this offer document for listing our shares on BSE. For the purpose of this Offer, the Designated Stock Exchange will be BSE. A copy of the Red Herring Prospectus and the Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Sections 26(4) and 32 of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus until the Bid/ Issue Closing Date, please refer to the chapter titled ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** beginning on page 353 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI in terms of the Regulation 246 (5) of the SEBI ICDR Regulations, and the SEBI has not issued any observation on Issue Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire **"Disclaimer Clause of SEBI"** on page 284 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the contents of the Offer Document of the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of BSE on page 285 of the Red Herring Prospectus.

GENERAL RISK: Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For making an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer including the risks involved. The Equity Shares offered in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited of the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 21of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Choice Capital	Maashitla	speedex
CHOICE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED Sunil Patodia Tower, Plot No. 156-158, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 099, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 6707 9999 / 7919; **E-mail:** msil.ipo@choiceindia.com **Investor Grievance ID:** investorgrievances_advisors@choiceindia.com **Website:** www.choiceindia.com/merchant-investment-banking; **Contact Person:** Nimisha Joshi/Madhuri Mandhania **SEBI Registration Number:** INM000011872; **CIN:** U65990MH2010PTC198262	**MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED** 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 **Telephone:** 011-47581432; **E-mail:** investor.ipo@maashitla.com **Investor grievance:** investor.ipo@maashitla.com; **Website:** www.maashitla.com **Contact Person:** Mukul Agrawal; **SEBI Registration Number:** INR000004370 **CIN:** U67100DL2010PTC208725	**Name: Mansee Agarwal, MAHARAJA & SPEEDEX INDIA LIMITED** **Address:** Kh. No. 53/27 GT Karnal Road, Village Alipur, Near Alipur Police Station, New Delhi – 110 036, India. **Telephone No.:** 9650589457 **Email:** cs@speedexind.com; **Website:** https://speedexind.com Bidders may contact the Company Secretary and Compliance Officer and/or the Registrar to the Offer in case of any pre- Offer or post- Offer related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLM.

Continued on next page...

...continued from previous page.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application Forms can be obtained from the Registered Office of Company, MAHARAJA & SPEEDEX INDIA LIMITED, Telephone No.: 9650589457; Registered Office of Book Running Lead Manager, Choice Capital Advisors Private Limited, Tel No.: +91 22 6707 9999 / 7919; Syndicate Member, Choice Equity Broking Private Limited, Tel No.: 022-67079999/867; and the selected location of sub syndicate members, Self Certified Syndicate Banks; Registered Brokers; Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Offer. Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchange and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchange and SEBI.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus shall be available on the website of SEBI www.sebi.gov.in at the website of Stock Exchange at www.bsesme.com, the website of Book Running Lead Manager at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking and the website of the Issuer Company at https://speedexind.com.

AVAILABILITY OF ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the Abridged Prospectus shall be available at the website of Stock Exchange at www.bsesme.com, the website of Book Running Lead Manager at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking and the website of the Issuer Company at https://speedexind.com.

SYNDICATE MEMBER: Choice Equity Broking Private Limited.

ESCROW COLLECTION BANK, REFUND BANK, PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK, SPONSOR BANK: Axis Bank Ltd.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): The investors are required to fill the application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and Red Herring Prospectus and also please refer to the section titled ***"Offer Procedure"*** on page 312 of the Red Herring Prospectus.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus dated September 03, 2026.

For MAHARAJA & SPEEDEX INDIA LIMITED
Sd/-
Rakesh Kumar Aggarwal
Chairman and Managing Director
DIN: 00437999

Date : September 04, 2026
Place : New Delhi

Disclaimer: MAHARAJA & SPEEDEX INDIA LIMITED has filed a Red Herring Prospectus dated September 03, 2026 with the Registrar of Companies, NCT of Delhi-I at South Delhi. The Red Herring Prospectus shall be made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., Choice Capital Advisors Private Limited at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking, the website of the BSE LIMITED i.e. www.bsesme.com and the website of the Issuer Company at https://speedexind.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see ***"Risk Factors"*** on page 21 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares issued in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold outside the United States in offshore transaction in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those issue and sales occur. There will be no public issuing in the U.S.

KIRIN

यूको बैंक **UCO BANK**
Honours Your Trust
(A Govt. of India Undertaking)

Head Office – II,
DIT- Procurement and Infrastructure
3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake,
Kolkata–700064

निविदा की सूचना

यूको बैंक प्रधान कार्यालय के विभागों में लगे डेस्कटॉप और प्रिंटर्स के लिए ए.एम.सी, ऍफ.एल.एम सपोर्ट एवं आईटी सुविधा प्रबंधन सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता के चयन के लिए निविदा आमंत्रित करता है। विवरण के लिए कृपया **https://www.uco.bank.in** और **https://gem.gov.in** वेबसाइट पर देख।

(उप–महाप्रबंधक)
दिनांक :– 07.09.2026 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग– खरीद एवं अवसंरचना

NSE

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-१, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र, भारत

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियम ३२(३) के अंतर्गत कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के संबंध में सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ ('असूचीबद्धता विनियम') के विनियम ३२(३) तथा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) अधिनियम, १९५६ की धारा २१ए के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एक्सचेंज") के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अनुसार, एतद्वारा **सूचित किया जाता है** कि एक्सचेंज निम्नलिखित कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखता है क्योंकि उक्त कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा कर चुकी है, अर्थात् उसकी प्रतिभूतियों में कारोबार सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ के विभिन्न प्रावधानों तथा इस संबंध में सेबी/एक्सचेंज द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन न करने के कारण छह माह से अधिक समय से निलंबित है।

एक्सचेंज ने अपने अभिलेखों में उपलब्ध अंतिम ज्ञात पते तथा पंजीकृत ई-मेल पते पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध क्यों न किया जाए। इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को २० जुलाई २०२६ को ई-मेल द्वारा एक्सचेंज के पास उपलब्ध ई-मेल आईडी पर **कारण बताओ नोटिस** जारी किया गया था तथा २१ जुलाई २०२६ को उसके पंजीकृत पते पर कूरियर द्वारा भेजा गया था, जो २२ जुलाई २०२६ को सुपुर्द कर दिया गया। कंपनी का नाम तथा एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार अंतिम ज्ञात पता निम्नलिखित है:

अनु. क्र.	कंपनी	*कंपनी का पंजीकृत पता
१.	इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	११०७, इंद्रप्रकाश बिल्डिंग, २१, बाराखंभा रोड, सी-५६/४१, सेक्टर ६२, नोएडा, नई दिल्ली - २०१३०१।

**पता एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध है।*

नोट:
अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणाम निम्नलिखित हैं:

- उपर्युक्त कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं रहेगी। इसे स्टॉक एक्सचेंज के प्रसार बोर्ड (डिसेमिनेशन बोर्ड) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- असूचीबद्धता विनियम के विनियम ३४ के अंतर्गत:

१. असूचीबद्ध कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उसके प्रवर्तक तथा उनके द्वारा प्रवर्तित कोई भी कंपनी, ऐसी असूचीबद्धता की तिथि से दस वर्ष तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाज़ार का उपयोग नहीं कर सकेगी, न ही किसी इक्विटी शेयर की सूचीबद्धता के लिए आवेदन कर सकेगी और न ही प्रतिभूति बाज़ार में किसी मध्यस्थ की भूमिका निभा सकेगी।

२. यदि किसी कंपनी का उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) धनात्मक हो -

क. ऐसी कंपनी तथा डिपॉजिटरी, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह द्वारा धारित किसी भी इक्विटी शेयर का हस्तांतरण (बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से) नहीं कर सकेंगे तथा प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह द्वारा धारित समस्त इक्विटी शेयरों पर लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभ तब तक स्थगित रहेंगे, जब तक ऐसी कंपनी के प्रवर्तक, विनियम ३३ के उप-विनियम (४) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास विकल्प (एग्जिट ऑप्शन) उपलब्ध नहीं करा देते, जिसकी पुष्टि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की जाए;

ख. अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक तथा प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी तब तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित निकास विकल्प उपलब्ध न करा दिया जाए।

- असूचीबद्धता विनियम के विनियम ३३ के अंतर्गत:

१. जहां किसी कंपनी के इक्विटी शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीबद्ध किए जाते हैं, वहां वह स्टॉक एक्सचेंज एक या अधिक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता (वैल्यूअर) नियुक्त करेगा, जो असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का उचित मूल्य निर्धारित करेंगे।

२. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं का एक विशेषज्ञ-मंडल (पैनल) गठित करेगा और उप-विनियम (१) के प्रयोजनों के लिए उसी विशेषज्ञ-मंडल (पैनल) में से मूल्यांकनकर्ता(ओं) की नियुक्ति की जाएगी।

३. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्य, मूल्यांकनकर्ता(ओं) द्वारा सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियम २० के उप-विनियम (२) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।

४. कंपनी के प्रवर्तक(कों) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्धता की तिथि से तीन माह के भीतर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान कर, सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीबद्ध इक्विटी शेयर अधिग्रहीत किए जाएंगे। सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने शेयर अपने पास रखने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

५. यदि विनियम ३३ के उप-विनियम (३) के अनुसार देय मूल्य का भुगतान विनियम ३३ के उप-विनियम (४) में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर समस्त शेयरधारकों को नहीं किया जाता, तो प्रवर्तक उन सभी शेयरधारकों को, जो अनिवार्य असूचीबद्धता ऑफर के अंतर्गत अपने शेयर प्रस्तुत करते हैं, दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा।

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रस्तावित असूचीबद्धता से प्रभावित या व्यथित हो, **इस सूचना के १५ कार्य दिवसों के भीतर, अर्थात् २९ सितंबर २०२६ तक या उससे पहले,** एक्सचेंज की असूचीबद्धता समिति को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति(यों) के पूर्ण संपर्क विवरण (ई-मेल आईडी, पता और फोन नंबर) सहित अभ्यावेदन निम्नलिखित को संबोधित किया जाए:

असूचीबद्धता कमेटी, लिस्टिंग डिपार्टमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एक्सचेंज प्लाजा', सी-१, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ **तथा** ९वीं मंजिल, इंस्पायर, बीकेसी मेन रोड, जी ब्लॉक बीकेसी, पत्थर नगर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र ४०००५१। संपर्क नंबर: +९१ २२ २६५९८१०० (३२०१४), ई-मेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in (प्रतिलिपि: dl-insp-enf-delisting@nse.co.in)। अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से उपर्युक्त निर्दिष्ट ई-मेल पते पर भेजा जाना चाहिए। कोई भी अनाम अभ्यावेदन मान्य नहीं माना जाएगा।

कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि प्रवर्तक(कों)/निदेशक(कों) के विवरण में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर वह उपर्युक्त दूरभाष नंबरों तथा ई-मेल पते पर एक्सचेंज से संपर्क करे।

स्थान: मुंबई **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड**
दिनांक: ७ सितंबर २०२६

Nifty50

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18 (12) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND AMENDMENTS THERETO ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

DEVINSU TRADING LIMITED

*(**CIN:** L51900MH1985PLC036383)*
Registered Office: 2, Floor-1, Plot-90/94, Zaveri Mansion, Shaikh Memon Street, Zaveri Bazar, Kalbadevi, Mumbai-400002, Maharashtra, India.
Contact No.: +91 98980 69723 | **Email ID:** devinsutrading@gmail.com | **Website:** www.devinsutrading.com

Open Offer for acquisition up to 1,52,880 fully paid-up equity shares having face value of ₹ 10 each representing 26.00% of Voting Share Capital of Devinsu Trading Limited ("Devinsu"/"Target Company") at a price of ₹ 355.00 per equity share from the public shareholders of the Target Company by Mr. Jaison Vijay Shah ("Acquirer 1"), Mr. Mukesh Kumar Bothra ("Acquirer 2") and Yora Gems & Jewellery Private Limited ("Yora"/"Acquirer 3") ("Acquirer 1", "Acquirer 2" and "Acquirer 3" hereinafter collectively referred to as "Acquirers"), pursuant to and in compliance with Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations, 2011").

This Post Offer Advertisement is issued by Mark Corporate Advisors Private Limited (**"Manager to the Offer"**), in respect of the Open Offer, on behalf of the Acquirers, pursuant to and in compliance with Regulation 18 (12) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Detailed Public Statement with respect to the Offer was made on Wednesday, May 27, 2026, in the following newspapers:

Publication	Language	Edition(s)
Business Standard	English	All Editions
Business Standard	Hindi	All Editions
Navshakti	Marathi	Mumbai Edition

1)	Name of the Target Company	:	Devinsu Trading Limited
2)	Name of the Acquirers		**1.** Mr. Jaison Vijay Shah **("Acquirer 1")** **2.** Mr. Mukesh Kumar Bothra **("Acquirer 2")** **3.** Yora Gems & Jewellery Private Limited **("Yora"/"Acquirer 3")**
3)	Name of the Manager to the Offer	:	Mark Corporate Advisors Private Limited
4)	Name of the Registrar to the Offer	:	Bigshare Services Private Limited
5)	**Offer Details:** a) Date of Opening of the Offer	:	Monday, August 17, 2026
	b) Date of Closure of the Offer	:	Monday, August 31, 2026
6)	Date of Completion of Payment of Consideration and communication of Rejection/Acceptance	:	Wednesday, September 02, 2026

7. Details of Acquisition:

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Letter of Offer		Actuals	
7.1.	Offer Price (in ₹)	₹ 355.00 per Equity Share		₹ 355.00 per Equity Share	
7.2.	Aggregate number of Shares tendered	Up to 1,52,880 Equity Shares(1)		Nil	
7.3.	Aggregate number of Shares accepted Up to	1,52,880 Equity Shares(1)		Nil	
7.4.	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹ 5,42,72,400(1)(2)		Not Applicable	
7.5.	**Shareholding of the Acquirers before Public Announcement** • Number • % of Voting Share Capital	Nil Not Applicable		Nil Not Applicable	
7.6.	**Shares acquired by way of Share Purchase Agreement ("SPA")** • Number • % of Voting Share Capital	1,71,493 29.17%		1,71,493 29.17%	
7.7.	**Shares Acquired by way of Open Offer** • Number • % of Voting Share Capital	1,52,880 (1) 26.00%		Nil Not Applicable	
7.8.	**Shares acquired after Detailed Public Statement ("DPS")** • Number • Price Per Share • % of Voting Share Capital	Nil Not Applicable Not Applicable		Nil Not Applicable Not Applicable	
7.9.	**Post Offer Shareholding of the Acquirers** • Number • % of Voting Share Capital	3,24,373 55.17%		1,71,493 29.17%	
		Pre-Offer	Post Offer	Pre-Offer	Post Offer
7.10.	**Pre & Post offer Shareholding of the Public:** • Number • % of Voting Share Capital	4,16,507 70.83%	2,63,627 44.83%	4,16,507 70.83%	4,16,507 70.83%

(1) Assuming full acceptance in the Open Offer.
(2) Excludes Brokerage and other charges.

8) The Acquirers accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and for the obligations under SEBI (SAST) Regulations, 2011.
9) A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and will be dispatched to the registered office of the Target Company.

Capitalized terms used in this advertisement, but not defined herein, shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dated August 04, 2026.

Issued by the Manager to the Offer

MARK
Mark Corporate Advisors Private Limited
CIN: U67190MH2008PTC181996
404/1, The Summit, Sant Janabai Road (Service Lane), Off W. E. Highway, Vile Parle (East), Mumbai- 400 057
Tel. No.: +91 22 2612 3207/08
Contact Person: Mr. Manish Gaur
E-Mail ID: openoffer@markcorporateadvisors.com
Investor Grievance Email ID: investorgrievance@markcorporateadvisors.com
SEBI Registration No.: INM000012128

For and on behalf of the Acquirers:

Sd/-	Sd/-	For **Yora Gems and Jewellery Private Limited ("Acquirer 3")** Sd/-
Jaison Vijay Shah ("Acquirer 1")	**Mukesh Kumar Bothra ("Acquirer 2")**	**Mukesh Kumar Bothra** **Director** **DIN:** 02309927

Place: Mumbai
Date: September 07, 2026

Ravindra Energy Limited

Regd. Off.: BC 105, Havelock Road, Camp, Belagavi – 590001, Karnataka, India.
Tel.: +91-831-2406600 | CIN: L40104KA1980PLC075720 |
Website: www.ravindraenergy.com | Email ID :madhukar.shipurkar@ravindraenergy.com

Notice of the 46th Annual General Meeting to be held through VC/OAVM, Book Closure and E-Voting Information

1. NOTICE is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of the members of RAVINDRA ENERGY LIMITED will be held on Monday, the **28th day of September, 2026, at 12:00 Noon**, through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM').
2. The Ministry of Corporate affairs ("MCA") has, vide its General Circular No. MCA General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025, and master circular issued by SEBI for extension for holding AGM through VC/OAVM, without physical presence of the members at a common venue. In accordance with the MCA Circulars, provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.
3. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the **46th AGM** and the standalone and restated consolidated financial statements for the financial year 2025-26, along with the Board's Report, Corporate Governance Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, are sent to all the Members of the Company only in electronic mode to those members whose email address is registered with the Company/Depository Participant(s)/ Registrar & Transfer agent. The requirements of sending physical copy of above mentioned documents, has been dispensed with vide MCA Circulars. The dispatch of notice and annual report has been completed on **September 5, 2026**.
4. Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility of voting through electronic means to its members.
5. **1.Manner of casting vote(s) through Remote e-Voting or Electronic Voting at the AGM:**
   (**a**) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through Remote e-Voting or e-Voting system at the AGM (Insta Poll).
   (**b**) The instructions Remote e-Voting and electronic voting at the AGM, by the members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The Members attending the AGM and who have not cast their vote(s) by Remote e-Voting, will be able to vote at the AGM through Insta Poll. The instructions for Remote e-Voting & Electronic Voting at the AGM are available on the websites viz. www.ravindraenergy.com and https://evoting.kfintech.com
6. Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e. **Monday, September 21, 2026**, are eligible to cast their vote electronically on all the businesses as set out in the AGM notice, through Remote e-voting or e-voting system at the AGM (Insta poll) provided by KFin Technologies Limited ("KFinTech"). The members are informed that:
   i. the businesses set out in the notice be transacted through voting by electronic means;
   ii. the Remote e-Voting shall commence on W**ednesday, September 23, 2026 at 09:00 AM;**
   iii. the Remote e-Voting shall end on **Sunday, September 27, 2026 at 05:00 PM;**
   iv. the **cut-off date** for determining the eligibility for Remote e-Voting /e-Voting at the AGM is **Monday, September 21, 2026**;
   v. any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holds shares as of the cut-off date may obtain the user ID and Password by sending email at evoting@kfintech.com;
   vi. Members may please note that: **(a)** the Remote e-Voting module shall be disabled by KFinTechafter the aforesaid date and time provided for e-Voting **(b)** the members will be provided electronic voting system (Insta poll) facility at the AGM **(c)** the Members who have cast their vote by Remote e-Voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting; and **(d)** a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as of the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting as well as voting in the AGM through electronic means;
   vii. The notice and the annual report are available on the Company's website at www.ravindraenergy.com under **INVESTORS** sub-head >>Annual Report, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the Website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on KFinTech's website, at https://evoting.kfintech.com
   viii. In case of any query, members may refer to the Frequently Asked Questions (**FAQs**) and e-Voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com or email at einward.ris@kfintech.com or call on the toll free No. 1800 309 4001 for any further clarifications.

RTA Details for query : KFin Technologies Limited (Unit: Ravindra Energy Limited), Office Selenium Tower B, 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. **Contact Person :**Sanapati Prasad ;**Contact No. :** 040 - 7961 5565 /67162222/7961 1000/ (+91) 910 009 4099/ 1800 309 4001 ; **Email** :einward.ris@kfintech.com; investorsupport.mfs@kfintech.com ; **Website :**www.kfintech.com	**FOR RAVINDRA ENERGY LIMITED** Sd/- **Madhukar Shipurkar** Company Secretary & Compliance Officer Membership No. A64947 Date: September 6, 2026 Place: Belagavi

---

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — *every day* with **The Compass** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

PG

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड

(CIN: L32109DL2003PLC119416)
पंजीकृत कार्यालयः डीटीजे–209, दूसरा फ्लोर, डीएलएफ टॉवर–बी, जसोला, नई दिल्ली–110025
कार्पोरेट कार्यालयः पी–4/2 से 4/6, साइट बी, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर (यू.पी) 201306
फोन नं.: +91-120-2569323 फैक्स नं.: +91-120-2569131 ईमेलः investors@pgel.in वेबसाइटः www.pgel.in

सदस्यों के लिए 24वीं वार्षिक आम बैठक और ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 (''**अधिनियम**'') के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''**सेबी एलओडीआर विनियम**'') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''**एमसीए**'') द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, और इस संबंध में बाद में परिपत्र जारी किए गए, जिसमें नवीनतम है सामान्य परिपत्र सं. 03/2025 दिनांक 22 सितम्बर, 2025 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''**सेबी**'') द्वारा जारी किए गए सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 (यहां के बाद ''**परिपत्र**'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में कथित एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड (''**कंपनी**'') के सदस्यों की 24वीं वार्षिक आम बैठक (''**एजीएम**'') **मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को दोप. 02.30 बजे** विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''**वीसी**'')/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (''**ओएवीएम**'') के द्वारा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त कथित एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में 24वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई–वोटिंग सहित वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण उन सभी सदस्यों को भेजने की प्रक्रिया 05 सितंबर, 2026 को पूरी हो गई है जिनके ई–मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत थे और साथ ही यह कंपनी के वेबसाइट www.pgel.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com और कंपनी के रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (**"केफिनटेक"**) की वेबसाइट https://evoting.Kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति उन शेयरधारकों को भी भेजी जाएगी जो हमें investors@pgel.in पर लिखकर इसके लिए अनुरोध करेंगे।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015, यथासंशोधित, के विनियम 36 (1) (बी) के अनुसार, एक पत्र जिसमें वेब–लिंक/क्यूआर कोड, सटीक पथ सहित, जहां 24वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, साधारण डाक के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजा गया है, जिन्होंने डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी की विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट https://pgel.in/annual_reports.html पर उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को 24वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर केफिनटेक द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। एजीएम की सूचना में वे निर्देश भी शामिल हैं जिसमें शेयरधारक रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के समय ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं और वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। कट–ऑफ तिथि अर्थात् **18 सितंबर, 2026 ("कट–ऑफ तिथि")** पर भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण केफिनटेक के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने बुधवार, 27 मई 2026 को हुई अपनी बैठक में, 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए रू 1/– प्रति इक्विटी शेयर पर रू 0.25 (25%) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। अगर 24वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह लाभांश उन सभी शेयरधारकों को 28 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले क्रेडिट/भेज दिया जाएगा, जिनके पास रिकॉर्ड तिथि यानी **शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 ("कट–ऑफ़ तिथि")** को बिज़नेस के समय के अंत तक शेयर थे।

शेयरधारकों को मिलने वाले लाभांश पर टैक्स लगता है, और कंपनी को शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश से तय दरों पर सोर्स पर ही टैक्स काटना होता है।

लाभांश पर 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' (टीडीएस) से जुड़ी जानकारी एजीएम सूचना का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा, एजीएम सूचना के साथ शेयरधारकोंको एक अलग सूचना भी अटैचमेंट के तौर पर भेजी जाती है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. 24वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का संचालन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा किया जाएगा;
2. रिमोट ई–वोटिंग **26 सितंबर, 2026 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)** प्रारंभ होगी;
3. रिमोट ई–वोटिंग **28 सितंबर 2026 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी;
4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या 24वीं एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तारीख **18 सितंबर, 2026** है और कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है वह इस सूचना को केवल जानकारी का उद्देश्य मान सकता है;
5. एक व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और 24वीं एजीएम की सूचना भेजने के बाद सदस्य बनता है तथा और शेयर रखता है एवं वोट देने के लिए पात्र है तो वह एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार या हमें ई–मेल investors@pgel.in पर लिखकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड जेनरेट करने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक के साथ पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
6. सदस्यगण कृपया ध्यान दें किः क) मतदान के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगेः ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और घ) वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के साथ–साथ एजीएम में वोटिंग का भी हकदार होगा।
7. कंपनी द्वारा अधिनियम और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच के लिए मैसर्स पूजा मिश्रा एंड क. एक पेशेवर कंपनी सचिव (एसीएस नंबर 42927, सीपी नंबरः 17148) को 24वीं एजीएम में संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
8. संवीक्षक अपनी अंतिम रिपोर्ट 24वीं वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के बाद लेकिन एजीएम के समापन से 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत करेगा; और बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, संवीक्षक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर एक साथ 24वीं वार्षिक आम बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.pgel.in पर प्रकाशित किए जाएंगे और साथ ही बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई"**) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (**"एनएसई"**) और केफिनटेक को इसकी सूचना दी जाएगी तथा इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा।
9. एनएसडीएल एवं सीडीएसएल में डिमेट खाता धारक सदस्य लॉगइन में कोई भी तकनीकी परेशानी होने पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क को ई–मेल evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 18001020990 या 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं और सीडीएसएल हेल्पडेस्क ई–मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क कर सकते हैं या फोन नं. 022–23058738 या 022–23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।
10. एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ या एजीएम से पूर्व किसी भी तकनीकी परेशानी या एजीएम के दौरान बैठक में भागीदारी के लिए किसी भी परेशानी के मामले में सदस्यगण केफिन के ई–मेल emeetings@Kfintech.com या हेल्पलाइन नं. 18003094001 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर पत्राचार प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत कराएं।
11. कंपनी की वेबसाइट का क्यूआर कोडः

कृते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड
हस्ता/–
दीपेश केडिया
कंपनी सचिव

स्थानः ग्रेटर नोएडा
तिथिः 05 सितम्बर, 2026

CFM thoughtful regeneration

सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि.

कार्पोरेट कार्यालयः प्रथम तल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई–400038.

कब्जा सूचना

परिशिष्ट IV (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8(1) के साथ पठित

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, जो कि सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएमएआरसी ट्रस्ट–193 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) के प्राधिकृत अधिकारी हैं, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(12), 13(2) के साथ पठित सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करने की अपेक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, एक्सक्लूसिव लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांकित 30.09.2025 को विधिवत पंजीकृत असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से, जो एक्सक्लूसिव लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एवं सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मध्य निष्पादित हुआ, उपर्युक्त ऋण खाते से संबंधित संपूर्ण बकाया ऋण तथा उससे संबद्ध अंतर्निहित प्रतिभूतियों पर अपने समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं हित सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित कर दिए हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, एतद्द्वारा उधारकर्ताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, ऊपर वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ''कब्जा की तिथि'' स्तंभ में उल्लिखित तिथि को ग्रहण कर लिया है। संबंधित पक्षकारों का विवरण तथा बंधक रखी गई संपत्ति, जिसका कब्जा सीएफएमएआरसी द्वारा ग्रहण किया गया है का विवरण निम्नानुसार है :–

ग्राहक (उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता और गारंटर / पार्टनर/ बंधककर्ता) का नाम	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि रु. में	कब्जा सूचना की तिथि
रूप सिंह (उधारकर्ता), गीता (सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता), ऋण खाता संख्या: Lap-Gzb-1109	मांग सूचना दिनांकः 16–12–2025, रु. 7,06,105.05/– (रुपये सात लाख छह हजार एक सौ पांच और पांच पैसे मात्र) दिनांक 31.10.2025 तक	01-09-2026
बंधक संपत्तिः प्लॉट का समस्त भाग एवं अंश जोकि क्षेत्रफल 21.73 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1551, सीसीएस एन्क्लेव ग्राम बेहटा हाजीपुर के क्षेत्र में, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तरः डिगर का प्लॉट, दक्षिणः जगदीश का प्लॉट, पूर्वः रोहित का प्लॉट, पश्चिमः 13 फीट चौड़ी सड़क		
राहुल शर्मा (उधारकर्ता), पूजा (सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता), ऋण खाता संख्याः MSME-GZB-1246	मांग सूचना दिनांकः 16–12–2025, रु. 753565.43/– (रुपये सात लाख तिरपन हजार पांच सौ पैंसठ और तैंतालीस पैसे मात्र) दिनांक 31–10–2025 तक	01-09-2026
बंधक संपत्ति : आवासीय प्लॉट सं. 13 एवं 14 का संपूर्ण भाग एवं टुकड़े जिसका क्षेत्रफल 28 वर्ग गज, मनीष विहार कॉलोनी, ग्राम लोनी (चकबंदी बाहर), परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं : उत्तरः रणजीत की दुकान, दक्षिणः हसरत की दुकान, पूर्वः मनोज अग्रवाल का मकान, पश्चिमः 12 फुट चौड़ी सड़क		
संगीता (उधारकर्ता), गुलाब (सह–उधारकर्ता), ऋण खाता संख्याः Lap-Dh-1301	मांग सूचना दिनांकः 20–03–2026, रु. 442924/– (चार लाख बयालीस हजार नौ सौ चौबीस मात्र) दिनांक 31–01–2026 तक	01-09-2026
बंधक संपत्ति : खसरा सं. 1473 का संपूर्ण भाग एवं टुकड़े जोकि साई एन्क्लेव, बेहटा हाजीपुर, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102 संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं : उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः अन्य संपत्ति, पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः 14 फुट चौड़ी सड़क		
जगन नाथ शुक्ला (उधारकर्ता), नीलम शुक्ला (सह–उधारकर्ता), ऋण खाता सं. Lap-Dh-1692	मांग सूचना दिनांकः 26–03–2026, रु. 4,68,731.00/– (चार लाख अड़सठ हजार सात सौ इकतीस मात्र) दिनांक 28–02–2026 तक	01-09-2026
बंधक संपत्ति : खसरा सं. 375 में सम्मिलित संपत्ति का संपूर्ण भाग एवं टुकड़े जोकि रेखा गार्डन–3, ग्राम लुत्फुल्लापुर, नवादा, परगना लोनी, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 201102 संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं : उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः अन्य का प्लॉट, पूर्वः 20 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिमः अन्य का प्लॉट		
महाराम (उधारकर्ता), गजना (सह–उधारकर्ता), ऋण खाता सं. Msme-Frd-347	मांग सूचना दिनांकः 23–04–2026, रु. 2,01,986/– (दो लाख एक हजार नौ सौ छियासी रुपये मात्र) दिनांक 28–02–2026 तक	02-09-2026
बंधक संपत्तिः खेवट/खाता सं. 1258/142 का संपूर्ण भाग एवं टुकड़े जोकि खसरा सं. 380(0–7), ग्राम लिखी, तहसील होडल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा 121107 संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं : उत्तरः 10 फुट चौड़ी गली, दक्षिणः उदल की संपत्ति, पूर्वः अशोक की संपत्ति, पश्चिमः 10 फुट चौड़ी गली का प्रवेश		
गुलशन जायसवाल (उधारकर्ता), रोशन (सह–उधारकर्ता), धन देवी (सह–उधारकर्ता), ऋण खाता सं. Lap-Dh-266	मांग सूचना दिनांकः 23–04–2026, रु. 5,04,472/– (पांच लाख चार हजार चार सौ बहत्तर रुपये मात्र) दिनांक 28–02–2026 तक	01-09-2026
बंधक संपत्ति : खसरा सं. 835डीए का संपूर्ण भाग एवं टुकड़े जोकि ग्राम मेहवला अंगारी, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201004 संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं : उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः अन्य की संपत्ति, पूर्वः 15 फुट चौड़ी गली, पश्चिमः अन्य की संपत्ति		
सचिन (उधारकर्ता), आजाद सिंह (सह–उधारकर्ता), सुमन (सह–उधारकर्ता), ऋण खाता संख्या : Lap-Dh-899	मांग सूचना दिनांकः 31–03–2026, रु. 4,24,704.00/– (रुपये चार लाख चौबीस हजार सात सौ चार मात्र) दिनांक 28–02–2026 तक	01-09-2026
बंधक संपत्ति : मकान सं. जी–503 का संपूर्ण भाग एवं टुकड़ा जोकि वाल्मीकि बस्ती, शहीद नगर, थाना साहिबाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201005। संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्वः गली, उत्तरः ऋषिपाल की संपत्ति, पश्चिमः अजीत की संपत्ति, दक्षिणः गोविंद की संपत्ति		
संजय (उधारकर्ता), अनीता (सह–उधारकर्ता), अजीत सिंह (सह–उधारकर्ता), प्रीतम (गारंटर), ऋण खाता सं. Lap-Frd-804	मांग सूचना दिनांकः 31–03–2026, रु. 6,68,696.00/– (रुपये छह लाख अड़सठ हजार छह सौ छियानवे मात्र) दिनांक 28–02–2026 तक	02-09-2026
बंधक संपत्ति : खेवट सं. 235/287 का संपूर्ण भाग एवं टुकड़ा जोकि खसरा सं. 74 (1–6) संपत्ति, ग्राम भोलरा, तहसील एवं जिला पलवल, हरियाणा 121102 संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्वः इंदर की संपत्ति, उत्तरः महीपाल का प्लॉट, पश्चिमः बांदा, दक्षिणः सड़क		
संतोष देवी (उधारकर्ता), मुकेश कुमार (सह–उधारकर्ता), ऋण खाता सं. Lap-Gzb-1261	मांग सूचना दिनांकः 09–03–2026, रु. 3,54,950/– (रुपये तीन लाख चौवन हजार नौ सौ पचास मात्र) दिनांक 31–01–2026 तक	01-09-2026
बंधक संपत्ति : खसरा सं. 1237 मि. का संपूर्ण भाग एवं टुकड़े जोकि रती राम, ग्राम बेहटा हाजीपुर, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं : उत्तरः राजेश की संपत्ति, दक्षिणः 20 फुट की सड़क, पूर्वः नरेश की संपत्ति, पश्चिमः अन्य संपत्ति		

उपर्युक्त उल्लिखित उधारकर्ताओं तथा सामान्य जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यवहार न करें तथा उक्त संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी व्यवहार, इस सूचना में उल्लिखित राशि तथा उपर्युक्त विवरण में दर्शित बकाया राशि की तिथि के अगले दिन से पूर्ण भुगतान और/अथवा वसूली की तिथि तक संविदात्मक दर से देय ब्याज, आनुषंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि सहित, सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूत आस्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय से संबंधित है।
कृपया ध्यान दें कि संपत्तियों का विवरण उपर्युक्तानुसार है।

तिथिः 07.09.2026
स्थानः दिल्ली/एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी, सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
(सीएफएमएआरसी ट्रस्ट–193 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

IDBI BANK

CIN : L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एनएमजी विभाग
एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉकः 2, 8वीं मंजिल, प्लेटः बी, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023
संपर्क .: 011-69297678

इरादतन चूककर्ताओं की पहचान समिति का प्रस्ताव

उधारकर्ता(ओं): वी एस मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत पताः 486 एफ आई ई पटपड़गंज दिल्ली 110092

यहाँ नीचे उल्लिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचना

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') ने यहां नीचे उल्लिखित व्यक्तियों (''आप''/''आपके'') के विरुद्ध 'भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का उपचार) निर्देश, 2025' दिनांक 28 नवंबर, 2025 (''आरबीआई मास्टर निर्देश'') के तहत कार्यवाही शुरू की थी और ' इरादतन चूककर्ता पहचान समिति–।।' (''डब्ल्यूडीआईसी–।।'') के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के आधार पर 02 मार्च, 2026 को कारण बताओ नोटिस (''एससीएन'') जारी किया था कि जिसमें ''इरादतन चूक'' की एक या अधिक घटनाओं में शामिल प्रतीत होती है। तदनुसार, रिकॉर्ड की जांच करने और तथ्यों और परिस्थितियों (प्राप्त प्रस्तुतियों सहित) को ध्यान में रखते हुए, डब्ल्यूडीआईसी–।। संतुष्ट थी कि आप नीचे उल्लिखित मानदंडों पर ''इरादतन चूककर्ता (ओं)'' के रूप में घोषित होने के लिए योग्य हैं।

नाम और पताः	पदनाम	इरादतन चूक के लिए मानदंड
श्री अमित गुप्ता, ए – 70, निर्माण विहार, आनंद विहार एस.ओ., लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली – 110 092	**वी एस मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक / गारंटीकर्ता**	खंड संख्या 3 (1) (xviii) (ए) (डी) और 3 (1) (xviii) (बी)
श्रीमती ज्योति गुप्ता, ए – 70, निर्माण विहार, आनंद विहार, एस ओ, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली – 110 092	**वी एस मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक / गारंटीकर्ता**	खंड संख्या 3 (1) (xviii) (ए) (डी) और 3 (1) (xviii) (बी)
श्रीमती कृष्णा गुप्ता, ए – 70, निर्माण विहार, आनंद विहार, एस ओ, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली–110092	**वी एस मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटीकर्ता**	खंड संख्या धारा 3 (1) (xviii) (बी)

तदनुसार, आपको यह सूचित करने के लिए एक पत्र जारी किया गया था कि (i) डब्ल्यूडीआईसी ।। आरबीआई मास्टर निर्देशों के तहत आगे की कार्यवाही के लिए बैंक की 'इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति ।।' (''डब्ल्यूडीआरसी ।।'') के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिससे विधिवत अपना प्रस्ताव संलग्न होगा, और यह कि (ii)आरबीआई मास्टर निर्देशों के पैरा 5(7) के संदर्भ में, आपको उक्त प्रस्ताव पर डब्ल्यूडीआरसी ।। के समक्ष अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए, यदि कोई हो, **15 (पंद्रह) दिनों** के भीतर, यह बताने के लिए कि आपको ''इरादतन चूककर्ता '' के रूप में क्यों वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

चूंकि उक्त पत्र वापस कर दिया गया था/अप्राप्त था; आपको उक्त प्रस्ताव के बारे में नोटिस दिया जाता है, और उक्त प्रस्ताव पर डब्ल्यूडीआरसी–।। के समक्ष अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त समय अवधि के बारे में सूचित किया जाता है। यदि कोई हो।

कृपया ध्यान दें कि, यदि आपका लिखित अभ्यावेदन डब्ल्यूडीआरसी ।। को उक्त **15 (पंद्रह) दिनों** के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आपके पास किसी भी लिखित अभ्यावेदन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं है, और बैंक आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

आपकी रुचि डब्ल्यूडीआरसी ।। के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ उठाने के संबंध में आरबीआई मास्टर निर्देश के पैरा 5(9) की ओर भी आकर्षित की जाती है, यदि आप चाहें तो।

आप उक्त पत्र/प्रस्ताव बैंक से एनएमजी विभाग, 8वीं मंजिल, प्लेटरू बी, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023 पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से (पहचान प्रमाण प्रस्तुत करके) या आपके पंजीकृत ईमेल आईडी से बैंक को sanjeev.kumar@idbi.co.in पर भेजे गए ईमेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह सूचना को आप पर डब्ल्यू.डी.आई.सी. के उक्त पत्र/प्रस्ताव की वैध और पर्याप्त सेवा माना जाएगा, भले ही उक्त पत्र/प्रस्ताव आपको बैंक से प्राप्त हुआ हो या नहीं।

भवदीय,
हस्ताक्षरित/–
(संजीव कुमार सिरवालिया)
उप महाप्रबंधक

दिनांकः 07 सितंबर 2026

SOM

सोम डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड

पूर्व में सोम डिस्टिलरीज ब्रेवरीज एण्ड वाइनेरीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: I–ए, ज़ी प्लाजा, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, कमल सिनेमा रोड, नई दिल्ली–110029,
फोन: + 91–11–26169909, 26169712, **फैक्स:** + 91–11–26195897
कॉर्पोरेट कार्यालय: सोम हाउस, 23, जोन II, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)–462011
फोन: + 91–755–4278827, 4271271, **फैक्स:** + 91–755–2557470 **ईमेल:** compliance@somindia.com,
वेबसाइट: www.somindia.com **CIN : L74899DL1993PLC052787 (BSE : 507514, NSE : SDBL)**

33वीं (तैंतीसवीं) वार्षिक आम बैठक आयोजित किए जाने की सूचना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों द्वारा आयोजित की जाएगी एवं ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

सूचना एतद् द्वारा दी जाती है कि कंपनी की तैंतीसवीं (33वीं) वार्षिक आम बैठक ("AGM") मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को दोपहर 01.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम (VC/OAVM) द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें AGM बुलाने संबंधी सूचना में उल्लिखित कार्यों को संपादित किया जाएगा।

मंत्रालय कॉर्पोरेट कार्य ("MCA") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों, जिनमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 शामिल है (''MCA परिपत्र''), तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 और नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 तथा वर्तमान में लागू अन्य संबंधित परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 33वीं AGM VC/OAVM के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें शेयरधारकों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। VC/OAVM के माध्यम से AGM में भाग लेने वाले शेयरधारकों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम निर्धारित करने के उद्देश्य से उपस्थित माना जाएगा।

AGM की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं संबंधित जानकारी का प्रेषण:

वित्तीय वर्ष 2025–26 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें AGM आयोजित करने संबंधी सूचना तथा उससे संलग्न किए जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं, उपर्युक्त MCA परिपत्रों एवं Listing Regulations के अनुसार रविवार, 06 सितंबर, 2026 को उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("DP's")/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट ("RTA") के पास पंजीकृत हैं।

इसके अतिरिक्त, Listing Regulations के विनियम 36(1)(b) के अनुपालन में, जिन सदस्यों के ई–मेल पते कंपनी/RTA/DP के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें AGM की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट देखने हेतु वेब लिंक एवं QR कोड सहित लिखित सूचना भेजी जा रही है।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (DP) के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट MAS Services Limited, द्वितीय तल, टी–34, ब्लॉक टी, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज़–2 रोड, पॉकेट डब्ल्यू, ओखला फेज़–II, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली, दिल्ली 110002 को लिखित रूप से आवेदन कर अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं।

सदस्य ध्यान दें कि 33वीं AGM की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.somindia.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात BSE Limited की वेबसाइट www.bseindia.com तथा National Stock Exchange India Limited की वेबसाइट www.nseindia.com और National Securities and Depositories Limited ("NSDL") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

AGM के लिए बुक क्लोजर:

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा अन्य लागू प्रावधानों एवं Listing Regulations के विनियम 42 के अनुसार, AGM के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, 23 सितंबर, 2026 से मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान (ई–वोटिंग):

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों को Companies (Management and Administration) Rules, 2014 के नियम 20, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है, तथा Listing Regulations के विनियम 44 के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी अपने सभी सदस्यों को NSDL द्वारा प्रदान की जा रही रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने की सुविधा प्रदान कर रही है।

कंपनी के वे सदस्य, जो मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 की कट–ऑफ तिथि को भौतिक अथवा डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत दे सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

(a) 33वीं AGM की सूचना में निर्धारित सभी कार्यों को रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संपादित किया जा सकता है।
(b) रिमोट ई–वोटिंग शनिवार, 26 सितंबर, 2026 को प्रातः 9.00 बजे IST से प्रारंभ होगी।
(c) रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को शाम 5.00 बजे IST पर समाप्त होगी।
(d) सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को शाम 5.00 बजे के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
(e) AGM में उपस्थित सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
(f) सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत देने के बाद भी AGM में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें AGM में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
(g) एक बार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा मत दे दिए जाने के बाद, वह बाद में अपना मत बदल नहीं सकेगा।
(h) केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 की कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई–वोटिंग या AGM में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा।
(i) कोई भी व्यक्ति, जो इस सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा 22 सितंबर, 2026 की कट–ऑफ तिथि को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.com पर ई–मेल भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि सदस्य पहले से NSDL के साथ ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए 33वीं AGM में रिमोट ई–वोटिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की विस्तृत प्रक्रिया 33वीं AGM की सूचना में दी गई है।

स्क्रूटिनाइज़र का विवरण:

श्री नीलेश जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (ICSI Membership No. FCS 6436) को रिमोट ई–वोटिंग (AGM से पूर्व) अथवा ई–वोटिंग (AGM के दौरान) की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया गया है।

ई–वोटिंग सहायता हेतु संपर्क विवरण:

किसी भी प्रश्न के लिए शेयरधारकों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा ई–वोटिंग यूज़र मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हैं।

आप टोल–फ्री नंबर 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं अथवा www.evoting.nsdl.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट तक त्वरित पहुंच:

सदस्य वित्तीय वर्ष 2025–26 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट तथा 33वीं AGM आयोजित करने संबंधी सूचना को सीधे देखने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के लिए:

AGM की सूचना के लिए:

सोम डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड
Sd/-
जितेंद्र परिहार
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः A40734

स्थान: भोपाल
दिनांक: 06.09.2026

ACME RESOURCES LIMITED

CIN No. : L65993DL1985PLC314861
Regd. Office : 984, 09th Floor, Aggarwal Cyber Plaza-II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034, Phone: (011)27026766, Fax: 91-11 47008010
Email : acmeresources@gmail.com Website : www.acmeresources.in

NOTICE is hereby given that the 41st Annual General Meeting of the Members of **M/S ACME RESOURCES LIMITED** will be held on Wednesday, the 30th day of September 2026 at 10:00 A.M. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') to facility the following business.

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Standalone Balance Sheet as at March 31, 2026, Statement of Profit and Loss for the financial year ended on March 31, 2026, Cash Flow Statement for the financial year ended March 31, 2026 and reports of Directors and Auditors thereon.
2. To receive, consider and adopt the Audited Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, Statement of Profit and Loss for the financial year ended on March 31, 2026, Cash Flow Statement for the financial year ended March 31, 2026 and report of Auditors thereon.
3. Appointment of M/s. H.N. Pradhan & Co., Chartered Accountants (Firm Registration No. 002208N) as the Statutory Auditors of the Company for a further period of 5 Financial Years.

SPECIAL BUSINESS

4. Appointment of M/s Azharuddin & Associates, Company Secretaries (Firm Registration No.: S2016UP401600) Secretarial Auditor of the Company for a period of 5 Financial Years.
5. Approval for the continuation of Directorship of Mr. Kuldeep Saluja (DIN:00289187) as a Non-Executive Director of the Company beyond the attainment of age of Seventy-five (75) years in his current tenure.

Notice of the AGM, setting out the business to be transacted thereat, have been sent in electronic mode to those members who have registered their e-mail addresses and a physical dispatch of the notice shall be completed by 5th September 2026.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'SEBI Listing Regulations') and MCA Circulars, the AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM hereinafter called as 'e-AGM'.

The details relating to E-Voting in terms of said act and rules, are as under:

1. The date and time of commencement and end of remote e-voting: From 27th September 2026 (09:00 A.M.) till 29th September 2026 (05:00 P.M.)
2. Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The remote e-voting module shall be blocked by NSDL for voting thereafter.
3. The cut-off date: September 23rd, 2026, members holding shares as on the cut-off date, may caste their votes by remote e-voting.
4. A person who acquires shares and becomes a shareholder of the Company after the dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date may obtain their login-id and password by sending an e-mail mentioning their folio no./DP ID no., to acmeresources@gmail.com or mdpldc@yahoo.com. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting their vote.
5. A person, whose name is recorded in the register of member or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the e-AGM.
6. Mr. Amit Choraria, Practicing Chartered Accountant (M. No. 066838) has been appointed by the Board of Directors of the Company as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as voting at the e-AGM.
7. Website address where the notice of the AGM is displayed: Company: www.acmeresorces.in, NSDL: www.evoting.nsdl.com.
8. Contact details of the persons responsible to address the grievances connected with e-voting:

Particulars	NSDL	Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd.
Name & Designation	Ms. Pallavi Mahatre	Mr. Subhabrata Biswas- Compliance Officer
Address	National Securities Depository Limited, 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Maharashtra - 400 051	23 R N Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata – 700 001
Email ID	evoting@nsdl.co.in	compliance@mdplcorporate.com
Phone No.	(022) 48867000	(033) 2248 2248

By the Order of Board
For **Acme Resources Limited**
Sd/- **Amanpreet Kaur**
Company Secretary and Compliance Officer

Date : 03-09-2026
Place : New Delhi

RAJNANDINI METAL LIMITED

राजनंदिनी मेटल लिमिटेड

CIN : L51109HR2010PLC040255
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 344, सेक्टर 3 फेज–II, आईएमटी बावल–123501 हरियाणा (इंडिया)
फोन : 01284–264194 | **ईमेल :** info@rajnandinimetal.com
वेबसाइट : www.rajnandinimetal.com

16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और दूरस्थ ई–मतदान की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजनंदिनी मेटल लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार ,28 सितम्बर, 2026 को अपर्राह्न 01:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों की आम स्थल पर शारीरिक उपस्थिति के बिना ई–मतदान /दूरस्थ ई–मतदान के जरिये बैठक का आयोजन किया जाएगा, ताकि 13 अगस्त, 2026 को जारी 16वीं एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निपटाया जा सके। बैठक का स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को माना जाएगा।

जनरल परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रेल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, और इस संबंध में जारी बाद के परिपत्र, नवीनतम 23/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए परिपत्र'') और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र (''सेबी परिपत्र'') का पालन करते हुए, कंपनीयों अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (''सूचीकरण विनियमों'') के प्रावधानों के अ नुसार, कंपनी ने 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष–2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट 5 सितंबर, 2–26 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी सदस्यों को भेजा है जिनके नाम 28 अगस्त, 2026 की स्थिति में सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं और शएयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'')/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (''डीपी'') के प ा पंजीकॉत हैं।

सूचीकरण विनियमों के नियम 36(1)(बी) के अनुसार, उस पत्र को उन सदस्य(ओं) को भेजा जा रहा है जिन्होनें अपनी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए/ डीपी के साथ पंजीकृत नहीं की है, जिसमें वेब–लिंक और सही पथ का उल्लेख है, जहां एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की पूरी जानकारी उपलब्ध है।

16वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.raknandinimetal. पर 'इनवेस्टर्स' सेक्शन में, एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उबलब्ध है। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आने वाली एजीएम में हिस्सा ले सकते हैं और ऐसा सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत आवश्यक कोरम के लिए गिने जाएंगे।

सदस्यों और शएयर ट्रांसफर पुस्तकों का रजिस्टर 22 सितंब, 2026 से 28 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन शामिल)बंद रहेगा।

दूरस्थ ई–मतदान

कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अ नुसार, कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियमो, 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों , 2015 के नियम 44 के साथ, कंपनी ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनेल सिक्योरिटीज डिपॉदिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं ताकि वे 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर मतदान कर सकें। सदस्यों के म तदान अधिकार कंपनी की चुकाई गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे, जैसा कि कट–ऑफ दिनांक यानी सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को लागू होगा।

दूरस्थ ई–मतदान की अवधि 25 सितंबर, 2026 को पूर्वाह्न 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और 27 सितंबर, 2026 अपर्राह्न 05:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान , शेयरधारक अपने मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एनएसडीएल द्वार ई–मतदान को बंद कर दिया जाएगा। जो शेयरधारक एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधाओं के म ाध्यम से उपस्थित होंगे और जिन्होने दूरस्थ ई–मतदान के ज रिए प्रस्तावओं पर अपना मददान नहीं किया है और जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम के दौरान ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

जो शेयरधारक पहले से एजीएम से पहले दूरस्थ ई–मतदान के जरिए अपने मत डाल चुके हैं , वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं , लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति जिसने एजीएम सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजे जाने के बाद लेकिन 21 सितंबर, 2026 की कट–ऑफ दिनांक से पहले कंपनी के शेयर खरीदे हैं , और सदस्य बन गया है, वह कंपनी के आरटीए से ई–मेल के जरिए bssdelhi@bigshareonline.com या एनएसडीएल के evoting@nsdl.co.in से दूरस्थ ई–मतदान के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि , यदि व्यक्ति पहले से एनएसडीएल के साथ दूरस्थ ई–मतदान के लिए पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान करने के लिए किया जा सकता है। जो व्यक्ति कट–ऑफ दिनांक यानी सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के लिए मानना चाहिए।

किसी भी प्रश्न के मामले में , सदस्य evoting@nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–मतदान मैनुअल को देख सकते हैं या 022–4886 7000 और 022–2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, टी–301, तीसरा तल, नामन चेम्बर्स, जी–ब्लॉक, प्लॉट सी–32, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, महाराष्ट्र 400 051 से संपर्क कर सकते हैं , जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी किसी भी शिकायतों का समाधान भी करेंगी। सदस्य कंपनी सेक्रेटरी को cs@rajnandinimetal.com पर भी लिख सकते हैं।

निदेशक मंडल ने श्री अभिषेक जैन को, जो कि मैसर्स अभिषेक जे.एंड कं. प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (एफसीएस 11233; सीपी सं. 16592) के हैं , दूरस्थ ई–मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

उक्त बैठक के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.rajnandinimetal.com पर और एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलबेध हैं।

बोर्ड के आदेश से
प्रति राजनंदिनी मेटल लिमिटेड
हस्ता./–
अशोक कालरा
प्रबंध निदेशक

दिनांक : 05 सितंबर, 2026
स्थान : बावल

इंडियन बैंक Indian Bank
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
इलाहाबाद ALLAHABAD

दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा
प्रथम तल, पुरानी बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ–226001, फोन नं. 0522–2288988

उधारकर्ता / ज़मानतकर्ता / प्रवर्तक / निदेशक / संबंधित व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता (विल्फुल डिफाल्टर) के रूप में वर्गीकृत किए जाने संबंधी समीक्षा समिति के निर्णय की सूचना देने हेतु पत्र।

पत्र सं.: **SAMB/LKO/WFD/2026-27/225** दिनांकः **19.08.2026**

सेवा में

क्र. सं.	नाम	पता
1.	मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट (ऋणी कंपनी)	645–ए / 57, प्लॉट संख्या 15, सेक्टर–आई, जानकी विहार, जानकीपुरम, लखनऊ–226021
2.	श्री सिद्धार्थ रविंद्रन पुत्र श्री करुपुमुरलाल रामकृष्णन रविंद्रन (निदेशक)	डी–2 / 9, अरडी सिटी, सेक्टर–51, गुड़गांव, हरियाणा–122003
3.	सुश्री दीपिका मलिक (निदेशक)	बी–36, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली–110017
4.	श्री सुमन सौरभ पुत्र श्री महेंद्र कुमार (निदेशक)	645–ए / 57, प्लॉट संख्या 15, सेक्टर–आई, जानकी विहार, जानकीपुरम, लखनऊ–226021
5.	श्री विजय पाण्डेय (निदेशक / जमानतकर्त्ता)	645–ए / 57, प्लॉट संख्या 15, सेक्टर–आई, जानकी विहार, जानकीपुरम, लखनऊ–226021
6.	सुश्री माया पाण्डेय (निदेशक / जमानतकर्त्ता)	645–ए / 57, प्लॉट संख्या 15, सेक्टर–आई, जानकी विहार, जानकीपुरम, लखनऊ–226021

महोदय / महोदया,
मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट ने मूल रूप से हजरतगंज, लखनऊ मुख्य शाखा से ऋण सुविधाएँ प्राप्त की थीं और वर्तमान में मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत खाता एसएएम लखनऊ में संचालित है। खाता दिनांक 27.09.2019 से एनपीए में परिवर्तित हो गया। दिनांक 12.04.2026 को कुल बकाया राशि रु. 18.98 करोड़ है। उधारकर्ता कंपनी और उसके निदेशकों / जमानतकर्त्ताओं द्वारा किए गए वे कृत्य अथवा चूक, जिनके कारण खाता डिफॉल्ट में चला गया, की जाँच भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति (डब्ल्यूडीआईसी) द्वारा दिनांक 25.06.2024 को की गई।

पृष्ठभूमिः
विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति (डब्ल्यूडीआईसी) ने दिनांक 25.06.2024 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव की जाँच की तथा उनके समक्ष प्रस्तुत निम्नलिखित जानकारी और अभिलेखों पर विचार कियाः

विलफुल डिफॉल्ट के आधारः

भारतीय रिजर्व बैंक (जानबूझकर चूककर्ता एवं बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार) निदेश, 2024 के पैरा 3 (1) (t) की प्रासंगिक धारा	उधारकता / प्रवर्तक(गण) / निदेशक(गण) / जमानतकर्त्ता(गण) द्वारा किए गए कृत्यों और / या चूक को दर्शाने वाले जानबूझकर किए गए डिफॉल्ट के साक्ष्य, जिसके आधार पर जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण किया गया
भुगतान करने की क्षमता होने के बावजूद भुगतान करने की अनिच्छाः इकाई ने ऋणदाता के प्रति अपने भुगतान / पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है, जबकि उसके पास उक्त दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है।	दिनांक 20.12.2017 के स्वीकृति पत्र के अनुसार, उधारकर्ताओं / जमानतकर्त्ता / निदेशकों की निवल संपत्ति निम्नानुसार हैः (रु. करोड़ में) — तालिका नीचे; इस प्रकार, जमानतकर्त्ताओं के पास भुगतान करने की क्षमता है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

नाम	निवल संपत्ति	दिनांक के अनुसार	व्यवसाय में निवेश
श्री विजय पाण्डेय	8.68	02.03.2017	3.95
सुश्री माया पाण्डेय	2.95	02.03.2017	1.23
कुल	11.63		

इस प्रकार, जमानतकर्त्ताओं के पास भुगतान करने की क्षमता है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

धनराशि का दुरुपयोगः इकाई ने ऋणदाता के प्रति अपने भुगतान / पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है तथा धनराशि का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उक्त धनराशि का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया, जिसके लिए वित्तीय सुविधा प्राप्त की गई थी, और न ही उक्त धनराशि इकाई के पास अन्य परिसंपत्तियों के रूप में उपलब्ध है।

धनराशि का अंतिम उपयोग निर्धारित नहीं किया जा सका। टर्म लोन–2 खाता संख्या 6517350230 और टीएल–3 खाता संख्या 6593069520 के वितरण का विवरण निम्नानुसार हैः (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	टीएल–II खाता सं. 6517350230 से डेबिट किया: दिनांक	राशि	चालू खाता सं. 6516889987 में क्रेडिट किया गया	चालू खाता सं. 6516889987 से डेबिट किया गया	इसे हस्तांतरित किया गया
1	13.04.2017	2.50	2.50	15.04.2017	आरटीजीएस के माध्यम से रु. 2.00 करोड़ मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट के अन्य बैंक में संचालित खाते में हस्तांतरित किए गए।
				17.04.2017	0.20 करोड़ रुपये का नकद भुगतान
				19.04.2017	0.32 करोड़ रुपये का नकद भुगतान
2	18.05.2017	2.50	2.50	18.05.2017	0.25 करोड़ रुपये का नकद भुगतान
				18.05.2017	आरटीजीएस के माध्यम से रु. 1.00 करोड़ मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट के अन्य बैंक में संचालित खाते में हस्तांतरित किए गए।
				19.05.2017	0.15 करोड़ रुपये का नकद भुगतान
				19.05.2017	आरटीजीएस के माध्यम से रु. 0.50 करोड़ मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट के अन्य बैंक में संचालित खाते में हस्तांतरित किए गए।
				23.05.2017	आरटीजीएस के माध्यम से रु. 0.05 करोड़ मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट के अन्य बैंक में संचालित खाते में हस्तांतरित किए गए।
				23.05.2017	आरटीजीएस के माध्यम से रु. 0.05 करोड़ श्री पवन कुमार द्विवेदी को हस्तांतरित किए गए।

क्र. सं.	टर्म लोन–III खाता सं. 6593069520 से डेबिट किया गया: दिनांक	राशि	चालू खाता सं. 6516889987 में क्रेडिट किया गया	चालू खाता सं. 6516889987 से डेबिट किया गया	इसे हस्तांतरित किया गया
1	27.12.2017	5.00	5.00	27.12.2017	मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट के अन्य बैंक में संचालित खाते में रु. 1.00 करोड़ प्रत्येक के 5 आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित किया गया।
2	27.12.2017	5.00	5.00	28.12.2017	मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट के अन्य बैंक में संचालित खाते में रु. 1.00 करोड़ प्रत्येक के 4 आरटीजीएस तथा रु. 0.50 करोड़ प्रत्येक के 2 आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित किया गया।

स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन न करनाः

स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन की स्थिति
हमारे बैंक के पैनल ऑडिटर द्वारा प्रमाणित बुक डेट का त्रैमासिक विवरण।	नियमित अंतराल पर बुक डेट का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
अभिलेख कि बीएमसी, सीआईसी विनियमन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कम से कम एक सीआईसी की सदस्य थी।	ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
अभिलेख कि बीएमसी, आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एसआरओ में से एक की सदस्य बनी।	ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
क. चार्टर्ड अकाउंटेंट से "धनराशि के अंतिम उपयोग का प्रमाण–पत्र" प्राप्त किया जाना है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि आहरित धनराशि का उपयोग ऋण आवेदन में उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया गया है। ख. हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित लाभार्थियों / जेएलजी से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र / नकदी प्रवाह विवरण, डीसीबी सहित।	ऋण उपयोग प्रमाण–पत्र, जिसे सीए फर्म मेसर्स उमेश के. अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा विधिवत प्रति–हस्ताक्षरित किया गया था, प्रस्तुत किया गया, जिसमें टीएल–2 में स्वीकृत रु. 5.00 करोड़ की ऋण राशि के विरुद्ध 1064 लाभार्थियों को रु. 2.78 करोड़ की राशि का विवरण शामिल था। शेष राशि रु. 2.22 करोड़ (5.00–2.78) के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, टीएल–3 के लिए स्वीकृत रु. 10.00 करोड़ की राशि के विरुद्ध 3574 लाभार्थियों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक खाते के विरुद्ध डीसीबी की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि धनराशि के अंतिम उपयोग का सत्यापन नहीं किया जा सका तथा उधारकर्ता विभिन्न स्वीकृति शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप धनराशि का दुरुपयोग हुआ।

डब्ल्यूडीआईसी ने यह अवलोकन किया कि खाते / खातों के संचालन / व्यवहार में अनियमितताएँ / चूक तथा स्वीकृति की शर्तों एवं नियमों का अनुपालन न करना, आरबीआई के विलफुल डिफॉल्टर के साथ व्यवहार संबंधी मास्टर निदेश के पैरा 3 (1) (टी) में निर्धारित एक या अधिक शर्तों के अंतर्गत आता है और तदनुसार उधारकर्ता कंपनी, मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट, उसके निदेशकों श्री सिद्धार्थ रविंद्रन, श्री कृष्ण मुरारी कुमार, सुश्री दीपिका मलिक, श्री सुमन सौरभ, श्री मुकुल जायसवाल तथा उसके निदेशक / जमानतकर्त्ता श्री विजय पाण्डेय और सुश्री माया पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें उन्हें देखी गई चूक के साक्ष्यों के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, एससीएन दिनांक 30.09.2024 को एसएएम शाखा लखनऊ द्वारा जारी किया गया। एससीएन दिनांक 01.10.2024 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, जो श्री मुकुल जायसवाल और श्री कृष्ण मुरारी कुमार को दिनांक 04.10.2024 को वितरित हो गया, जबकि अन्य नोटिस प्राप्तकर्ताओं को यह वितरित नहीं हो सका। अतः इसे दिनांक 24.10.2024 को अंग्रेजी भाषा के लिए "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" तथा स्थानीय भाषा के लिए "जनसत्ता" समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। निदेशकों श्री कृष्ण मुरारी कुमार और श्री मुकुल जायसवाल से दिनांक 19.10.2024 को उत्तर / अभ्यावेदन प्राप्त हुआ तथा एससीएन की सुपुर्दगी / प्रकाशन की तारीख से निर्धारित 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी उधारकर्ता कंपनी तथा शेष निदेशकों / जमानतकर्त्ताओं से कोई उत्तर / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।
एससीएन की तामील तथा निदेशकों से प्राप्त उत्तर के परिणाम को आगे विचार–विमर्श हेतु डब्ल्यूडीआईसी के समक्ष रखा गया।

विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति ने दिनांक 10.08.2026 को निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में बैठक आयोजित कीः
1. मुख्य महाप्रबंधक (सीएमसी एवं वसूली), अध्यक्ष, 2. महाप्रबंधक (वसूली एवं विधि), सदस्य, 3. महाप्रबंधक (सीएमसी), सदस्य

विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति द्वारा पारित आदेश (चरण–II):
जानबूझकर की गई चूक के कृत्यों एवं चूक को प्रमाणित / प्रकट करने वाले सहायक दस्तावेज तथा दिनांक 30.09.2024 का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) डब्ल्यूडीआईसी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। समिति ने निम्नलिखित दस्तावेजों की जाँच कीः
1. दिनांक 02.03.2017 को श्री विजय पाण्डेय एवं श्रीमती माया पाण्डेय की निवल संपत्ति, 2. खाता विवरण, 3. दिनांक 29.03.2017 का स्वीकृति पत्र, 4. दिनांक 30.09.2024 का कारण बताओ नोटिस, 5. दिनांक 24.10.2024 का समाचार पत्र में प्रकाशन।
विलफुल डिफॉल्टर समिति ने उधारकर्ता द्वारा दिनांक 19.10.2024 को प्रस्तुत किए गए उत्तर की जाँच की तथा डिफॉल्ट की निम्नलिखित विशेषताएँ पाई गईं:
1. समिति ने दिनांक 02.03.2017 को श्री विजय पाण्डेय एवं श्रीमती माया पाण्डेय की निवल संपत्ति की जाँच की, जो रु. 11.63 करोड़ थी। किसी प्रतिवाद / अस्वीकार के अभाव में यह निष्कर्ष निकाला गया कि उधारकर्ताओं के पास बकाया राशि चुकाने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।
2. रु. 5.00 करोड़ के टर्म लोन–2 तथा रु. 10.00 करोड़ के टर्म लोन–3 के लिए धनराशि के अंतिम उपयोग का निर्धारण नहीं किया जा सका।
3. उधारकर्ता स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहे है।
i. बुक डेट का त्रैमासिक विवरण नियमित अंतराल पर प्रस्तुत नहीं किया गया।
ii. इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा कि बीएमसी, सीआईसी विनियमन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कम से कम एक सीआईसी की सदस्य थी तथा यह भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि बीएमसी आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एसआरओ में से एक की सदस्य बनी।
iii. सीए फर्म मेसर्स उमेश के. अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा विधिवत प्रति–हस्ताक्षरित ऋण उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें टीएल–2 में स्वीकृत रु. 5.00 करोड़ की ऋण राशि के विरुद्ध 1064 लाभार्थियों को रु. 2.78 करोड़ की राशि का विवरण शामिल था। शेष राशि रु. 2.22 करोड़ (5.00–2.78) के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, टीएल–3 के लिए स्वीकृत रु. 10.00 करोड़ की राशि के विरुद्ध 3574 लाभार्थियों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक खाते के विरुद्ध डीसीबी की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई।
अतः, विचार–विमर्श करने तथा निदेशकों श्री कृष्ण मुरारी कुमार और श्री मुकुल जायसवाल से प्राप्त उत्तर एवं जानबूझकर की गई चूक को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की जाँच करने के पश्चात, यह समिति इस निष्कर्ष पर संतुष्ट है कि डिफॉल्ट की घटना घटित हुई है और उधारकर्ता कंपनी, मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट, उसके निदेशकों श्री सिद्धार्थ रविंद्रन, सुश्री दीपिका मलिक, श्री सुमन सौरभ तथा उसके निदेशक / जमानतकर्त्ता श्री विजय पाण्डेय और सुश्री माया पाण्डेय को भारतीय रिजर्व बैंक (जानबूझकर चूककर्ताओं एवं बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार) निदेश, 01.07.2015 (अब आरबीआई के दिनांक 28.11.2025 के मास्टर निदेश) के अनुसार "भुगतान करने की क्षमता होने के बावजूद पुनर्भुगतान करने की अनिच्छा" एवं "धनराशि का दुरुपयोग" के आधार पर जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने हेतु विलफुल डिफॉल्टर समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी) के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुशंसा करती है। इसके अतिरिक्त, समिति ने निदेशकों श्री कृष्ण मुरारी कुमार और श्री मुकुल जायसवाल द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार कर लिया तथा दोनों निदेशकों के विरुद्ध जानबूझकर चूककर्ता की कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया।
उपरोक्त के मद्देनजर, हम आपको एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि डब्ल्यूडीआईसी द्वारा आपको "जानबूझकर चूककर्ता" के रूप में वर्गीकृत करने हेतु डब्ल्यूडीआरसी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। डब्ल्यूडीआईसी के इस निर्णय की आरबीआई के परिपत्र के अंतर्गत गठित डब्ल्यूडीआरसी द्वारा समीक्षा / पुष्टि की जानी है, जिसमें एक कार्यकारी निदेशक एवं 2 मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक शामिल होंगे। डब्ल्यूडीआरसी उधारकर्ता कंपनी, मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट, उसके निदेशकों श्री सिद्धार्थ रविंद्रन, सुश्री दीपिका मलिक, श्री सुमन सौरभ तथा उसके निदेशक / जमानतकर्त्ता श्री विजय पाण्डेय और सुश्री माया पाण्डेय को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी। उधारकर्ता कंपनी, मेसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट, उसके निदेशक श्री सिद्धार्थ रविंद्रन, सुश्री दीपिका मलिक, श्री सुमन सौरभ तथा उसके निदेशक / जमानतकर्त्ता श्री विजय पाण्डेय और सुश्री माया पाण्डेय, यदि इस निर्णय से व्यथित हैं, तो इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर बैंक की डब्ल्यूडीआरसी के समक्ष लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन / व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन / उक्त व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्राप्त करने में रुचि नहीं रखते हैं। अथवा, यदि डब्ल्यूडीआरसी आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप में (जैसा भी मामला हो) प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन / प्रस्तुतीकरण से संतुष्ट नहीं होती है, तो बैंक की डब्ल्यूडीआरसी आपको जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कारणयुक्त आदेश पारित करेगी। डब्ल्यूडीआरसी द्वारा इस प्रकार वर्गीकरण किए जाने पर, आपका फोटोग्राफ प्रकाशित किया जाएगा तथा आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार आपका नाम जानबूझकर चूककर्ता के रूप में आरबीआई, सिबिल तथा अन्य क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट किया जाएगा और बैंक लागू कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।

यह पत्र बैंक की विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति (डब्ल्यूडीआईसी) की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।
शाखा प्रबंधक का नामः नवनीत
स्केलः सहायक महाप्रबंधक
नामित अधिकारी
विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति (डब्ल्यूडीआईसी) के लिए

भारत कार्पेट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः एस–2 / डी, द्वितीय तल, शॉप कम फैसिलिटी, पॉकेट–ए, सेक्टर–3, डीएसआईआईडीसी औद्योगिक परिसर, बवाना, नई दिल्ली–110039

वार्षिक आम बैठक की सूचना
इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि **भारत कार्पेट्स लिमिटेड** के सदस्यों की 26वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को प्रातः 9:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, अर्थात् एस–2 / डी, द्वितीय तल, शॉप कम फैसिलिटी, पॉकेट–ए, सेक्टर–3, डीएसआईआईडीसी औद्योगिक परिसर, बवाना, नई दिल्ली–110039 में निम्नलिखित व्यवसायों के संचालन हेतु आयोजित की जाएगीः

सामान्य व्यवसायः
1. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन ऑडिटेड वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना, साथ ही निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भी।
2. श्री मनीष कुमार अरोड़ा (DIN:00049518) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, की पुनर्नियुक्ति पर विचार करना।
3. श्री भूपिंदर कुमार सेठ (DIN:02250789) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, की पुनर्नियुक्ति पर विचार करना।

विशेष व्यवसायः
1. श्री कुणाल मेहरा को कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त करना।
2. बकाया बिना गारंटी वाले लोन पर ब्याज के भुगतान को मंजूरी देना।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह. / –
मनोज मेहरा
निदेशक
DIN: 00236146

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.09.2026

फॉर्म नं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
समक्ष केंद्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र I, दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा(4) और कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) की उप–धारा(5) के खंड (ए) के मामले में
और
कॉन्फियाडो सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U75200UP2020PTC128336), पंजीकृत कार्यालयः एच. नं. के–7115, गौर ग्रीन सिटी, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201012, भारत के मामले में
..... याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अपने पंजीकृत कार्यालय को **"उत्तर प्रदेश राज्य"** से **"बिहार राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार, 10 अगस्त, 2026 को आयोजित असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष संकल्प के अनुसार कंपनी की संस्था बहिर्नियमावली में परिवर्तन की स्वीकृति हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 14 दिनों के अंदर इसकी सूचना या तो एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर दें या अपने हित की प्रकृति और याचिका के प्रति अपने विरोध का आधार बताते हुए शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र–I, दिल्ली को पता– बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को सुपुर्द या पंजीकृत डाक से भेजें। साथ ही, इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को अधोल्लिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में प्रेषित / प्रस्तुत करें।

पंजीकृत कार्यालय का पताः एच. नं. के–7115, गौर ग्रीन सिटी, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201012, भारत
कॉन्फियाडो सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए
रविन्द्र कुमार दुबे
अपर निदेशक
डीआईएनः 11851080
स्थानः उत्तर प्रदेश
दिनांकः 07.09.2026

efl इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड
ऑदम्बर, प्लॉट सं. 101/1, एरंडवाने, डॉ. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, इंडिया

सार्वजनिक सूचना : समर्पित मशीनों की बिक्री
एत्तदद्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित मशीनें उधारकर्ता **अभयंतर डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड_APPL00284592 + APPL00282709 + 119-154361-2025-2-3 (भूतल श्री राम पैलेस, भोज मार्केट, अट्टा नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201301, भारत),** द्वारा इलेक्ट्रानिक फाइनेंस लिमिटेड को सौंप दी गई है, और इन्हें '' जो है जैसा है'', ''जो है जहां है आधार'' पर उच्चतम बोली लगाने वाले को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है:

मशीनों का विवरण:
1. उपयोग की गई : UMABOY COLD PRESS SR NO 202505620
2. उपयोग की गई : UMABOY EDGE BANDER SR NO 2024121078
3. उपयोग की गई : UMABOY MULTY BORING SR NO 202409861
4. उपयोग की गई : UMABOY POST FORMING SR NO 833
5. उपयोग की गई : UMABOY AUTOMATIC EDGE BANDER SR NO 1231
6. उपयोग की गई : UMABOY SINPDLE MOULDER SR NO 419
7. उपयोग की गई : SERVO STABILIZER
8. उपयोग की गई : COMPRESSOR
9. उपयोग की गई : UMABOY DRILL MACHINE SR NO 424
10. उपयोग की गई : UMABOY PANEL SAW SR NO 202608864
11. उपयोग की गई : UMABOY CNC ROUTER WITH PANEL SR NO 20241120-03 With VACCUM
12. उपयोग की गई : UMABOY DUST COLLECTOR (2nos)
सभी मशीने यहां उपबध है: प्लॉट सं.2, सैनी मार्केट, ग्राम सरूरपुर, मैन रोड, फरीदाबाद– 121005, हरियाणा
इच्छुक व्यक्ति ऊपर दी गई मशीन(ओं) का पूर्व अपॉइंटमेंट लेकर दिए गए स्थान पर निरीक्षण कर सकते हैं और उन्हें **13/09/2026** से पहले अपने सील बंद बोली/कोटेशन प्रेषित करने के लिए आमांत्रित किया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड किसी भी या सभी बोलियों को बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :
इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड
पूणे शाखा :– ऑदम्बर कार्यालय, 101/1
एरंडावने, डॉ केतकर रोड, पुणे 411004
फोन :+ 91–8800517645
ईमेल : shumant.bhattacharya@efl.co.in
दिनांक : 07/09/2026 **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: उत्तर प्रदेश **इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड**

AVSL INDUSTRIES LIMITED
पंजी. कार्या.: 1001, एनडीएम-2, एनएसपी, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 • सीआईएन: L18101DL2003PLC121698, फोन: +91-11-47561234 ईमेल: AVSL_PVC@AVSL.CO.IN , वेबसाइट: WWW.AVSL.CO.IN

23वीं वार्षिक साधारण सभा और बुक क्लोजर की सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एवीएसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''कंपनी'') की 23वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') बुधवार, 30 सितंबर 2026 को दोपहर 02:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सामान्य कारोबार तथा विशेष कारोबार के संचालन एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आयोजित की जाएगी। 23वीं वार्षिक साधारण सभा कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 (क्रमशः 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 एवं 05 मई 2020 को जारी) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 (सामूहिक रूप से ''परिपत्र'' कहे जाने वाले) के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं उससे संलग्न किए जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज उन सभी सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं, तथा सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक प्रेषण 05 सितंबर 2026 को पूर्ण कर दिया गया है। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम की आवश्यकताओं के अनुसार यह सूचना भी दी जाती है कि एजीएम के प्रयोजन हेतु कंपनी के सदस्य रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण बही 20 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स तथा विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

एवीएसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से
Sd/-
संजय बंसल (प्रबंध निदेशक)
डीआईएन - 01467290
दिनांक: 05.09.2026
स्थान: दिल्ली

Plastking Litewood
PVC / WPC Boards, Doors And Chaukhat

नैनीताल बैंक
दि नैनीताल बैंक लि.
[पंजीकृत कार्यालय : सीताबीर पंत रोड, मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड-263001]
CIN No. U65923UR1922PLC000234, website: www.nainitalbank.bank.in
e-mail ID: secretarial@nainitalbank.co.in, Phone: 05942-233739

सदस्यों को नोटिस
यह सूचना दी जाती है कि 'दि नैनीताल बैंक लिमिटेड' (कंपनी / बैंक) के सदस्यों की 104वीं सालाना आम बैठक (AGM) मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को सुबह 11:30 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") या दूसरे ऑडियो–विजुअल तरीकों ("OAVM") के जरिए होगी। इसमें कंपनीज एक्ट, 2013 के लागू नियमों और MCA के संबंधित नोटिफिकेशन के अनुसार AGM के नोटिस में बताए गए आम और खास काम किए जाएंगे।
AGM से जुड़े सर्कुलर के मुताबिक, 104वीं सालाना आम बैठक (AGM) का नोटिस और फाइनेंशियल ईयर ('FY') 2025–26 की सालाना रिपोर्ट, शनिवार, 05 सितंबर, 2026 को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिन्होंने बैंक / बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('RTA'), KFin Technologies Limited ('KFintech') [फिजिकल फार्म में रखे शेयरों के मामले में / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('DP') [डीमटेरियलाइज्ड फार्म में रखे शेयरों के मामले में, के साथ अपने ई–मेल एड्रेस रजिस्टर किए हैं और संबंधित डिपॉजिटरी ने बैंक को उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, बैंक उन शेयरहोल्डर्स को एक लेटर भी भेज रहा है, जिसमें वेब–लिंक दिया गया है, जिसमें सही रास्ता भी शामिल है, जहाँ FY 2025–26 की सालाना रिपोर्ट की पूरी जानकारी उपलब्ध है, जिन्होंने बैंक/RTA या DP के साथ अपना ई–मेल एड्रेस रजिस्टर नहीं कराया है। AGM का नोटिस और FY 2025–26 की एनुअल रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट https://www.nainitalbank.bank.in और RTA के पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है।
मेंबर्स VC या OVAM के जरिए AGM में हिस्सा ले सकते हैं या मेसर्स KFin Technologies Limited के https://www.emeetings.kfintech.com के जरिए AGM का लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। मीटिंग में शामिल होने के लिए इंस्ट्रक्शन नोटिस में दिए गए हैं। मेंबर्स को मेसर्स KFin Technologies Limited के रिमोट ई–वोटिंग (https://www.evoting.kfintech.com) के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालने की सुविधा दी गई है। रिमोट ई–वोटिंग 26 सितंबर, 2026 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होगी और 28 सितंबर, 2026 (शाम 5:00 बजे) को खत्म होगी। बैंक का मेंबर्स का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 22 सितंबर, 2026 से 29 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगा। जो मेंबर्स बैंक के साथ अपने रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, वे मेसर्स KFin Technologies Limited के हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) या कॉर्पोरेट ऑफिस में कंपनी सेक्रेटरी से कॉन्टैक्ट करें।
दूरस्थ ई–मतदान के निर्देश निम्नानुसार है –
- निम्नलिखित URL का उपयोग करें : https://emeetings.kfintech.com और https://evoting.karvy.com
- ई–मेल में बताए गए लॉगिन क्रेडेंशियल (यानि, यूजर आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें. आपकी फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी आपकी USER आईडी होगी। कृपया ध्यान दें कि पासवर्ड एक प्रारंभिक पासवर्ड है।
- बैंक के शेयरधारक जो या तो भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में बैंक के शेयरधारक है शेयरों की कटऑफ डेट पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।
- लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी आपकी उपयोगकर्ता आईडी होगी।
- उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- वोटिंग पेज पर, उक्त कट–ऑफ तारीख पर शेयरों की संख्या के अनुसार पक्ष में / विरुद्ध के तहत दर्ज करें या वैकल्पिक रूप से आप आंशिक रूप से किसी भी संख्या के लिए पक्ष में दर्ज कर सकते हैं और आंशिक रूप से विरोध में किसी भी संख्या में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन पक्ष में / विरोध में कुल संख्या एक साथ उक्त कट–ऑफ तिथि के अनुसार, आपकी कुल हिस्सेदारी से अधिक नहीं हो सकती है। आप स्वयं को वोटिंग प्रक्रिया से अलग रखने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
- कई फोलियो / डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक डीमैट खाते / फोलियो के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना वोट कास्ट करें और SUBMIT पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। पुष्टि हेतु OK पर क्लिक करें। संशोधित करने के लिए CANCEL पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वोटिंग के समय, शेयरहोल्डर रेजोल्यूशन पर वोट करने तक कितनी भी बार लॉगिन कर सकते हैं।
- शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी
- रिमोट ई–वोटिंग का समय 26 सितंबर, 2026 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होगा और 28 सितंबर, 2026 (शाम 5:00 बजे) को खत्म होगा। इस दौरान, बैंक के शेयरहोल्डर, जिनके पास 20 सितंबर, 2026 की कट–ऑफ तारीख तक फिजिकल या डीमैट रूप में शेयर हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद वोटिंग के लिए मेसर्स KFin Technologies Limited रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर देगा। एक बार जब शेयरहोल्डर किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो उसे बाद में इसे बदलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा, जिन शेयरहोल्डर्स ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डाला है, वे भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे मीटिंग में दोबारा वोट नहीं कर पाएंगे।

जिन मेंबर्स को AGM से पहले और AGM की तारीख को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में मदद चाहिए, वे मेसर्स KFin Technologies Ltd. के मिस्टर रामचंद्र और मिस्टर हनुमंथा से 040 6716 2222 पर या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, मेंबर्स AGM के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण या सवाल के लिए मिस्टर विवेक साह (कंपनी सेक्रेटरी) को secretarial@nainitalbank.co.in पर लिख सकते हैं या टेलीफोन नंबर 05942–233739 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
(विवेक साह)
कंपनी सचिव
स्थान : नैनीताल
दिनांक : 07 सितम्बर, 2026

NURTURE WELL
नर्चर वेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्व में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड)
सीआईएनः L10719DL1995PLC277176
पंजीकृत कार्याः बी–14, प्रथम तल, दाहिनी ओर बी–भाग, चिराग एन्क्लेव, दिल्ली–110048 भारत
फोनः 011–45511351, ईमेलः compliance@nurturewell.com

वार्षिक आम बैठक (40वीं एजीएम) और रिमोट ई–वोटिंग की सूचना
इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि नर्चर वेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को दोपहर 1:00 बजे भारतीय मानक समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या सेबी द्वारा जारी परिपत्र(ों) के साथ पठित प्रावधानों के अनुपालन में होगी, ताकि 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष कार्यों का निष्पादन किया जा सके, जिसमें सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। वार्षिक आम बैठक का स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शुक्रवार, 04 सितंबर, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के उन सदस्यों को भेजी गई है, जो शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 को शेयर धारित कर रहे हैं और जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, उन शेयरधारकों को वेब-लिंक उपलब्ध कराने वाला एक पत्र भी भेजा जा रहा है, जिसमें 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट के वेब-लिंक का सटीक मार्ग शामिल है, जिनका ई-मेल पता कंपनी/डीपी के पास पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा, जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां प्राप्त करने का अनुरोध करेंगे, उन्हें वही compliance@nurturewell.com पर अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 23 सितंबर, 2026 को भौतिक रूप में अथवा अभौतिकीकृत रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष कार्यों पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ("दूरस्थ ई-वोटिंग") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:-

i) दूरस्थ ई-वोटिंग रविवार, 27 सितंबर, 2026 को प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ होगी और मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी।
ii) ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा 40वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि बुधवार, 23 सितंबर, 2026 है।
iii) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात कंपनी के शेयर खरीदता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा बुधवार, 23 सितंबर, 2026 ("कट-ऑफ तिथि") को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अथवा कंपनी के ई-मेल पते compliance@nurturewell.com पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता पहचान संख्या और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के पास दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो मतदान करने के लिए मौजूदा उपयोगकर्ता पहचान संख्या और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
iv) सदस्य कृपया ध्यान दें कि: a) मतदान के लिए उपर्युक्त तिथि और समय के पश्चात दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा मत डाल दिए जाने के पश्चात सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी; b) वे सदस्य जिन्होंने 40वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत डाल दिया है, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम सुविधा के माध्यम से 40वीं वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन 40वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पुनः अपना मत डालने के हकदार नहीं होंगे; c) 40वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाला सदस्य और जिसने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है, वह 40वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना मत डालने का हकदार होगा; और d) जिस व्यक्ति का नाम ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या निक्षेपागारों द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम सुविधा के माध्यम से 40वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और 40वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने का हकदार होगा।
v) 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.nurturewell.com पर, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।
vi) किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अंशधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और अंशधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से निर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें।
vii) वे सदस्य जिन्होंने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपने ईमेल पते पंजीकृत कराएं:
a) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कृपया हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति प्रपत्र आईएसआर-1 में भेजें, जिसमें आपका फोलियो नंबर, अंशधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की प्रति (आगे और पीछे), पूरा पता, पंजीकृत किए जाने वाले ईमेल पते के साथ पैन की स्व-सत्यापित प्रति की स्कैन प्रति, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153-ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-I, नई दिल्ली, दिल्ली, 110020 को भेजी जाए।
b) अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी के माध्यम से अपना ईमेल पता अद्यतन करें।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है तथा यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परिपत्रों के अनुपालन में है।

बोर्ड के आदेश से
कृते नर्चर वेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्व में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
एसडी / –
प्रियंका
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एम नं. ए69893
दिनांकः 05.09.2026
स्थानः नोएडा (यू.पी.)

एसआईआर: उत्तर में कटे ज्यादा नाम

देश भर में तीन चरणों में पूरी हुई प्रक्रिया में कुल 14 प्रतिशत मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए

जयंत पंकज

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में 14 प्रतिशत मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें से 70 प्रतिशत के बारे में कारण बताया गया है कि वे मौके पर नहीं मिले। जून 2025 से अगस्त 2026 के बीच तीन चरणों में चली इस प्रक्रिया में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13.4 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं। उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम सूची से निकाले गए हैं, जबकि 11 राज्यों में महिलाएं ज्यादा प्रभावित हुई हैं।

आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में सूची से हटाए गए कुल मतदाताओं में सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत उत्तर भारत से हैं। दक्षिणी भारत से 26 प्रतिशत, पश्चिम से 24 प्रतिशत, पूरब से 14 प्रतिशत, मध्य से 5 प्रतिशत और सबसे कम पूर्वोत्तर से 1 प्रतिशत मतदाता कम हुए हैं। यह तस्वीर उस स्थिति में सामने आई है जब कुल मतदाताओं में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी 23.6 प्रतिशत है। उत्तर की 23 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र की 22.7 प्रतिशत और पश्चिमी भाग की 21.6 प्रतिशत पर है।

आंकड़े यह भी बता कर रहे हैं कि शहरी और उत्तरी क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की तुलना में नाम हटाने की दर सबसे अधिक रही। चंडीगढ़ में सबसे अधिक 40 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर दिल्ली रही, जहां 32 प्रतिशत मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया। इसी तरह दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में मतदाता सूची से नाम काटे जाने की दर 29 प्रतिशत रही। दूसरी ओर, लक्षद्वीप में सबसे कम 2 प्रतिशत, मिजोरम 5 प्रतिशत और ओडिशा में यह दर 6 प्रतिशत रही।

मतदाता पुनरीक्षण की पूरी तस्वीर

- जून 2025 से अगस्त 2026 के बीच हुई एसआईआर में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13.4 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे
- दक्षिणी भारत से 26 प्रतिशत, पश्चिम से 24 प्रतिशत, पूरब से 14 प्रतिशत, मध्य से 5 प्रतिशत और सबसे कम पूर्वोत्तर से 1 प्रतिशत मतदाता कम हुए
- 11 राज्यों में महिलाएं ज्यादा प्रभावित हुईं, जबकि अधिक महिला साक्षरता वाले राज्यों में अधिक नाम सूची से बाहर किए गए
- चंडीगढ़ में सबसे अधिक 40 प्रतिशत तो दिल्ली में 32 प्रतिशत और दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में 29 प्रतिशत नाम हटाए गए
- प. बंगाल, गोवा और बिहार में मसौदा के मुकाबले अंतिम सूची से नाम हटाए जाने की दर में क्रमशः 4.3 व 2.3 और 0.1 प्रतिशत अंक की वृद्धि

अंतिम मतदाता सूची में कम हटे नाम

एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल रहे। इनमें जहां पहले दो चरणों में यह प्रक्रिया पूरी हुई, उन 13 राज्यों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उनकी प्रारंभिक सूचियों में शुरू में 9.7 करोड़ मतदाता ऐसे पाए गए थे, जिनका नाम हटाया जाना था। यह आंकड़ा उनके संयुक्त मतदाता आधार का 13.7 प्रतिशत था। सत्यापन के बाद अंतिम सूचियों में 8.6 करोड़ नाम हटाए गए। इससे सूचियों से नाम हटाने की दर 12.1 प्रतिशत रह गई।

पहले और दूसरे चरण के कुल 13 राज्यों में से 10 में प्रारंभिक मसौदा सूची की तुलना में अंतिम सूची से कम नाम हटाए गए। हालांकि पश्चिम बंगाल, गोवा और बिहार इसके अपवाद रहे, जहां मसौदा के मुकाबले अंतिम सूची से नाम हटाए जाने की दर में क्रमशः 4.3 प्रतिशत अंक, 2.3 प्रतिशत अंक और 0.1 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। तीसरे चरण में जिन राज्यों में एसआईआर हो चुकी हैं, वहां की अंतिम मतदाता सूची अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

पते पर नहीं मिलने से सबसे ज्यादा नाम कटे

मतदाता सूची से हटाए जाने में सबसे बड़ा कारण (70 प्रतिशत) प्रवासन या पहचान पत्र में दर्ज पते पर मौजूद नहीं मिलना रहा। इसके बाद 20 प्रतिशत मतदाताओं की मौत हो गई, जबकि दो या इससे अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या भी 9 प्रतिशत मिली, जिनका नाम सूची से काट दिया गया।

पता बदले जाने के कारण सबसे ज्यादा 75 प्रतिशत नाम उत्तर प्रदेश में काटे गए जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में यह आंकड़ा 74 प्रतिशत रहा। गुजरात में अलग ही पैटर्न देखने को मिला। यहां स्थायी रूप से पुराना पता छोड़ गए मतदाताओं की संख्या 54 प्रतिशत मिली, जबकि डुप्लिकेट या कई स्थानों पर पंजीकृत मतदाता 20 प्रतिशत पाए गए। ऐसे में इन सभी के नाम सूची से हटाए गए। पुराने घर को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने की समस्या चुनाव प्रणाली को लंबे समय से परेशान करती आ रही है। क्योंकि काम की तलाश में दूसरी जगह चले गए मतदाता स्वयं को अपने पैतृक स्थान पर ही मतदाता के रूप में रखते हैं, लेकिन मतदान के समय उन्हें कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी ऐंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की तरफ से 2024 में बनस्मिता बोरा द्वारा लिखित रिपोर्ट- 'द एब्सेंट वोटर्स ऑफ इंडियाः चैलेंजेज ऐंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर द एनफ्रैंचाइजमेंट ऑफ माइग्रेंट्स' में कहा गया है कि प्रवासियों को वोट डालते समय अक्सर दस्तावेज़ीकरण और अनौपचारिक आवास से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

ऐसी बाधाएं प्रवासी लोगों के बीच मतदान को लेकर उदासीनता पैदा कर सकती हैं और उनका मतदान प्रतिशत कम हो सकता है। बोरा लिखती हैं, 'राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधि प्रवासी मतदाताओं की जरूरतों पर बहुत कम ध्यान देते हैं।

ऐसे लोग अक्सर अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए नहीं आ पाते और जहां वे रह रहे हैं, वहां उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बेहद सीमित होता है। चुनाव आयोग ने पहले इस मुद्दे पर ध्यान दिया था। वर्ष 2015 में उसने देश में रहने वाले प्रवासियों को उनके कार्य क्षेत्र वाली जगह पर ही मतदान की सुविधा देने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई थी। इस समिति ने कई कारण बताकर इसे व्यवहार्य नहीं माना था।

सबसे ज्यादा महिलाएं हुई बाहर

पूरी एसआईआर प्रक्रिया से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मतदाता सूची से नाम कटने के मामले में 11 राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। दस राज्यों में तो महिलाएं समग्र मतदाता वर्ग में बड़ी हस्सेदारी रखती थीं, लेकिन मणिपुर इसका अपवाद था। यह रुझान महिला साक्षरता से भी मेल खाता है। जहां महिला साक्षरता अधिक है, वहां उनके नाम कटने की दर ज्याद देखी गई। उदाहरण के तौर पर पुदुच्चेरी और मिजोरम जैसे राज्यों में महिला साक्षरता दर 80 प्रतिशत से अधिक है। यहां मतदाता सूची से हटाई गई मतदाताओं की संख्या 50 प्रतिशत से 53 प्रतिशत के बीच रही।

'लंबित मामलों को फैसलों की गुणवत्ता के संदर्भ में देखें'

आशिष आर्यन

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि भारत में लंबित मामलों को हर साल दर्ज होने वाले मामलों की संख्या और सभी स्तरों पर अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों की गुणवत्ता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। खन्ना ने रविवार को पहले 'जस्टिस एस एच कापड़िया मेमोरियल लेक्चर' में कहा कि न्यायपालिका पर होने वाली पूरी चर्चा अक्सर अलग-अलग स्तर पर लंबित मामलों तक ही सीमित रह जाती है जबकि इसके पीछे के संदर्भ और लंबित मामलों के ढेर को प्रभावित करने वाले कारक नजरअंदाज कर दिए जाते हैं।

खन्ना ने यह भी कहा कि हालांकि, न्यायिक देरी से अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रगति को नुकसान पहुंचता है मगर न्याय मिलने में देरी का सबसे बड़ा शिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। उन्होंने कहा, 'आपराधिक न्याय प्रक्रिया में किसी भी देरी के नतीजे तुरंत सामने आते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसी वजह से न्यायिक आंकड़ों का आकलन जेल में बंद लोगों की संख्या और फौजदारी मामलों के निपटारे की गति के आधार पर किया जाना चाहिए।'

उदाहरण के लिए वर्ष 2021 में देश भर में अलग-अलग कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने लगभग 1.47 करोड़ लोगों को गिरफ्तार किया था जबकि वर्ष 2024 में विभिन्न अपराधों के लिए लगभग 1.4 करोड़ लोग गिरफ्तार किए गए थे। इनमें हर वर्ष लगभग 70 लाख आरोप पत्र दाखिल किए गए जिस वजह से हर कैलेंडर वर्ष में न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए। हालांकि, हर वर्ष गिरफ्तार होने वाले लगभग 1.4 करोड़ भारतीयों में करीब 50 प्रतिशत पहले 24 घंटे के भीतर ही जमानत पर रिहा हो जाते हैं मगर बाकी लोगों को न्याय प्रणाली की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उन्हें सुनवाई के लिए पांच वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इनमें लगभग 69 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों को अदालतें जेल में रहने के पहले वर्ष साल के भीतर ही रिहा कर देती हैं। खन्ना ने कहा कि न्यायपालिका के अलग-अलग स्तर पर मामलों की प्रकृति से भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के स्तर पर दायर कुल मामलों में लगभग 30 प्रतिशत फौजदारी थे जबकि लगभग 70 प्रतिशत दीवानी (सिविल) मामले थे जो सरकार के नीतिगत फैसलों को चुनौती देने से जुड़े थे। वहीं, जिला न्यायालयों के स्तर पर दायर कुल मामलों में लगभग 70 प्रतिशत फौजदारी मामले थे जबकि केवल 30 प्रतिशत दीवानी मामले थे।

बॉन्ड यील्ड में उफान से न हों निवेशक परेशान

फंड की अवधि चुनते समय देखें कि कब चाहिए आपको रकम, टुकड़ों में करें नया निवेश

संजीव सिन्हा

पिछले कुछ महीनों में बॉन्ड की यील्ड में आई उछाल से पता चलता है कि डेट फंड में रकम लगाने वालों के लिए निवेश अवधि से जुड़ा जोखिम कितना मायने रखता है। इस साल दुनिया भर में महंगाई और ऊर्जा से जुड़ी चिंताओं ने बॉन्ड यील्ड को जमकर वहा दी, जिससे 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6.98 फीसदी तक पहुंच गई, जो साल की शुरुआती में 6.58 फीसदी ही थी। यील्ड बढ़ती हैं तो लंबी अवधि के फंडों पर ज्यादा मार्क-टु-मार्केट जोखिम मंडराता है, जिसकी वजह से निवेशकों को फंड चुनते समय निवेश अवधि का खास ख्याल रखना चाहिए।

किस अवधि में डेट फंड ने दिया रिटर्न

श्रेणी	श्रेणी का औसत रिटर्न (%)				
	1 महीना	3 महीना	1 साल	3 साल	5 साल
लिक्विड	0.56	1.71	6.42	6.91	6.28
मनी मार्केट	0.72	2.23	6.61	7.35	6.61
शॉर्ट टर्म	0.25	2.15	5.78	7.41	6.68
मीडियम टु लॉन्ग टर्म	-0.10	2.33	5.30	6.79	6.09
लॉन्ग टर्म	-0.54	2.34	4.32	6.12	5.76

2 सितंबर 2026 को डायरेक्ट प्लान के रिटर्न, स्रोतः वैल्यू रिसर्च

आपका पैसा

आखिर क्यों बढ़ीं यील्ड ?

सरकारी बॉन्डों की यील्ड में हालिया इजाफा मोटे तौर पर वैश्विक घटनाक्रम की वजह से हुआ है, जिसका कुछ असर भारत में भी देखा गया है। कच्चे तेल का भी काफी असर हुआ है। मिरे एसेट म्युचुअल फंड में फंड मैनेजर और फिक्स्ड इनकम एनालिस्ट कृति छेटा कहती हैं, 'ऊर्जा को जो संकट चल रहा है, उसने महंगाई बढ़ने के डर को हवा दी है।' कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत पर काफी असर पड़ा है क्योंकि ऊर्जा की ज्यादातर जरूरत वह आयात से पूरी करता है। कृति का कहना है, 'ऊंचे राजकोषीय घाटे, रक्षा पर बढ़ते खर्च और उम्रदराज होती आबादी ने विकसित बाजारों की चरमराई बुनियाद को और खस्ता कर दिया है, जिसके कारण दुनिया भर में बॉन्ड यील्ड इस दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं।'

अभी और चढ़ेंगी यील्ड ?

ऊर्जा संकट और गहराया तो यील्ड ऊंची बनी रह सकती हैं। कृति मानती हैं, 'अगर पश्चिम में सर्दियों के दौरान भी ऊर्जा संकट बना रहता है तो मांग इतनी बढ़ सकती है कि आपूर्ति उसे पूरी नहीं कर पाएगी। इससे ऊर्जा के दाम बढ़ेंगे और यील्ड भी चढ़ेगी।'

महंगाई की चिंता फिर बढ़ने से प्रमुख केंद्रीय बैंकों का रुख आक्रामक बना रह सकता है। कृति की राय है कि विकसित देशों में राजकोषीय घाटे लगातार ऊंचे बने रहे और रक्षा बजट बढ़ते रहे तो भारी तादाद में बॉन्ड आते रह सकते हैं और यील्ड भी बढ़ती रह सकती है। अल नीनो का खतरा देख भारत में बॉन्ड यील्ड उछल सकती हैं।

नीचे कैसे आएंगी यील्ड ?

राजनयिक समाधान हो गया तो ऊर्जा की किल्लत घट सकती है और यील्ड नीचे आ सकती हैं। तेल-गैस का उत्पादन पहले ही बढ़ा चुकी अर्थ-व्यवस्थाएं इसमें और इजाफा करती हैं तो भी राहत मिल सकती है। कृति कहती हैं, 'जिन अर्थव्यवस्थाओं ने उत्पादन बढ़ाया है, उनसे ज्यादा तेल-गैस मिले और पश्चिम एशिया में अटका तेल-गैस भी जगह पर पहुंच जाए तो ऊर्जा आपूर्ति का समीकरण बिल्कुल बदल सकता है।'

छह महीने में कैसी रहेगी यील्ड ?

कई केंद्रीय बैंकों ने दरें बढ़ाई हैं, जिसके बाद बाजार दरों में और बढ़ोतरी तय मानकर चल रहे हैं। कोटक म्युचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम हेड अभिषेक बिसेन कहते हैं, 'जोखिम दूर करने वाली कोई बड़ी घटना होगी तभी यील्ड में वास्तविक कमी आएगी।' 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड की यील्ड अगले छह महीने में 6.85 फीसदी से 7.15 फीसदी के दायरे में घूम सकती है।

अवधि बड़ी तो जोखिम ज्यादा

बिसेन के मुताबिक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड श्रेणी से ऊपर वाली योजनाओं ने अगर अपने पोर्टफोलियो की अवधि नहीं घटाई है तो उन पर निकट भविष्य में जोखिम रहेगा। मीरा मनी में इन्वेस्टमेट रिसर्च हेड और फाउंडिंग पार्टनर मोहित बागड़ी भी कहते हैं, 'यील्ड थोड़ी सी भी बढ़ें तो लंबी अवधि वाले फंड में मार्क-टु-मार्केट उतार-चढ़ाव आ सकता है।'

यील्ड 40 आधार अंक बढ़ती है तो सात साल की अवधि वाले दीर्घावधि या गिल्ट फंड को 2.8 फीसदी नुकसान हो जाएगा। मगर दो साल की अवधि वाले फंड को ऐसी सूरत में केवल 0.8 फीसदी की चपत ही झेलनी होगी।

निवेश अवधि के हिसाब से चुनें फंड

साल भर पहले ऊंची यील्ड से ज्यादा रकम इकट्ठी हो जाती थी। बागड़ी कहते हैं, 'इस साल पहले तो यील्ड कम थी मगर अब यील्ड बढ़ने पर फिक्स्ड इनकम फंडों में रकम लगाने से फायदा हो सकता है।'

डेट पोर्टफोलियो बनाते समय ध्यान रखें कि आपको रकम की जरूरत कब पड़ेगी। जितने समय के लिए निवेश करना है, फंड की अवधि भी उसके आसपास की ही रखें। साल भर के भीतर जरूरत पड़ सकती हो तो रकम लिक्विड या मनी मार्केट फंड में रख सकते हैं। लो-ड्यूरेशन और अल्ट्रा-शॉर्ट-ड्यूरेशन फंड में निवेश करना भी इस समय फायदेमंद है।

1 फाइनैंस में पार्टनर अनुज मेहता की सलाह है, 'एक से तीन साल के लिए निवेश करना है तो शॉर्ट-टर्म या कॉरपोर्ट बॉन्ड फंड देखे जा सकते हैं। तीन से पांच साल के लिए रकम लगानी है तो मीडियम-टर्म फंड पर विचार किया जा सकता है।'

पांच साल से ज्यादा समय के लिए निवेश करना है तो गिल्ट फंड के बारे में सोचा जा सकता है। अगर निवेश की अवधि और भी ज्यादा है तो टारगेट मैच्योरिटी फंडों में निवेश पर भी विचार किया जा सकता है। बिसेन सुझाते हैं, 'यील्ड में तेज इजाफा देखते हुए ऐसे फंड बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जो बारबेल रणनीति (जिसमें ज्यादातर रकम सरकारी बॉन्ड जैसे बेहद सुरक्षित साधनों में लगाई जाती है और बची रकम का निवेश शेयर, क्रिप्टो या वेंचर पूंजी जैसे जोखिम भरे साधनों में किया जाता है ताकि संतुलन बना रहे) पर चलते हैं या जिनका पोर्टफोलियो मध्यम अवधि का है।'

घबराकर न निकलें फंड से

पांच साल से ज्यादा अवधि के लिए निवेश करने वालों को अधिक अवधि वाले फंडों में रकम लगी रहने देनी चाहिए। मेहता आगाह करते हैं, 'इस समय निकले तो जो घाटा लग रहा है वह वाकई में हो जाएगा।' निवेश निकाल लिया तो घाटे की भरपाई होने और अच्छा रिटर्न पाने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। दो से तीन साल के लक्ष्य के लिए गिल्ट फंड में रकम लगाना ठीक नहीं है और निवेशकों को इसे ठीक करना चाहिए। मेहता समझाते हैं, 'दो से तीन साल के लिए निवेश करने वालों ने अगर 2025 का शानदार रिटर्न देखकर पैसा गिल्ट फंड में लगा दिया है तो उन्हें अवधि की इस गड़बड़ी को फौरन दुरुस्त कर लेना चाहिए।' ज्यादा लंबी अवधि के लिए रकम लगा रहे हैं तो भी पूरी रकम अधिक लंबी अवधि के फंडों में नहीं लगाएं क्योंकि पता नहीं कि निकट भविष्य में बॉन्ड बाजार किस करवट बैठेगा। निवेशकों को पोर्टफोलियो की अवधि जोखिम लेने की अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए। बागड़ी की सलाह है, 'ज्यादा लंबी अवधि के फंड उन निवेशकों को माफिक आते हैं, जो कुछ समय की उठापटक में भी रकम लगी रहने देते हैं।'

धीरे-धीरे करें नया निवेश

निवेशकों को यह मानकर पूरी रकम एक ही बार में निवेश नहीं कर देनी चाहिए कि यील्ड अब और ऊपर नहीं जाएंगी। निवेश चरणों में करना सही होगा। बागड़ी समझाते हैं, 'निवेशकों को यह कयास नहीं लगाना चाहिए की यील्ड कब चोटी छू चुकी हैं और उसके बजाय निवेश की सही अवधि चुनकर अच्छी यील्ड कमाने पर ध्यान देना चाहिए।' निवेशकों को अलग-अलग समय पर पूरी होने वाली योजनाओं में पैसा लगाना चहिए और सारी रकम किसी खास यील्ड के समय नहीं झोंक देनी चाहिए। छोटी अवधि के लिए निवेश करने वालों को स्थिरता तथा लिक्विडिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

इसरो में निजीकरण पर उठी आवाज, मांगा स्पष्टीकरण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के 9 कर्मचारी संगठनों ने अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष वी. नारायणन को पत्र लिखकर विनिर्माण और परिचालन कार्यों को निजी कंपनियों को सौंपने के प्रस्ताव पर आधिकारिक तौर पर स्पष्टीकरण मांगा है। कर्मचारी संगठनों ने 4 सितंबर को लिखे पत्र में इसरो की भविष्य की भूमिका के साथ-साथ मौजूदा कर्मचारियों और आगे होने वाली भर्तियों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर सवाल पूछे हैं।

पत्र में कहा गया, 'निर्धारित वाणिज्यिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी मजबूत और सार्वजनिक स्वामित्व वाले इसरो के साथ-साथ जारी रह सकती है, लेकिन ऐसी नीति बिना व्यापक चर्चा के स्वीकार नहीं की जा सकती, जो इसरो की भूमिका को केवल सीमित अनुसंधान एवं विकास तक समेट दे और देश के प्रक्षेपण यानों के निर्माण एवं प्रक्षेपण संबंधी बुनियादी ढांचे का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों से बाहर चला जाए।'

पत्र में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) के अध्यक्ष पवन गोयनका द्वारा 21 अगस्त को की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है। 'इन-स्पेस' गैर-सरकारी संस्थाओं की विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, उन्हें सक्षम बनाने, अधिकृत करने और उनकी निगरानी करने वाली संस्था है। गोयनका ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर कहा था, 'अंततः इसरो कोई भी प्रक्षेपण यान नहीं बनाएगा और न ही किसी प्रक्षेपण स्थल (लॉन्चिंग पैड) का निर्माण करेगा। यह सब निजी क्षेत्र या पीएसयू द्वारा किया जाएगा।' **भाषा**

विश्व मानचित्र में कश्मीर, लद्दाख भारत 'के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप हों'

भारत ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र की पहल पर प्रस्तावित विश्व मानचित्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को देश के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप दिखाया जाना चाहिए तथा इनका कोई भी 'गलत' या 'भ्रामक' चित्रण स्वीकार्य नहीं होगा। भारत ने महाद्वीपों के भूभाग को 'अधिक सटीकता से प्रदर्शित' करने के उद्देश्य से विश्व मानचित्र में सुधार से जुड़े संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसके दो दिन बाद विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया है। **भाषा**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra भारत सरकार का उद्यम एक परिवार एक बैंक

कॉर्पोरेट कार्यालय, मौटक्लेयर, 134/1, बानेर-पाषाण लिंक रोड, पाषाण, पुणे-411021

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पात्र एवं प्रतिष्ठित बोलीदाताओं/सेवा प्रदाताओं से **"एसएपी एचसीएम (ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट) एचआरएमएस समाधान, जीओम लर्निंग एवं भर्ती मॉड्यूल के वार्षिक तकनीकी सहायता (ATS) के नवीनीकरण तथा अनुरक्षण एवं समर्थन हेतु ऑनसाइट सुविधा प्रबंधन सेवाओं की तीन वर्ष की अवधि के लिए निविदा"** के लिए मुहरबंद निविदा प्रस्ताव (तकनीकी बोली तथा वाणिज्यिक बोली) आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट **https://www.bankofmaharashta.bank.in** पर 'टेंडर सेक्शन' में और जेम पोर्टल **https://gem.gov.in/** पर 'दिनांक **04.09.2026** से उपलब्ध है।

आरएफपी संख्या : **RFP 31/2026-27**

जीईएम बोली संख्य : **GEM/2026/B/7998476**

बोली जमा करने की अंतिम तिथि: **25.09.2026 17:00 hrs.**

इच्छुक बोलीदाता उपर्युक्त साइट से आरएफपी दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं। निविदाओं से संबंधित सभी अन्य अपडेट GeM पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। बैंक बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया को रद्द करने या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ह/-

दिनांक : 04.09.2026 मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

HDFC BANK We understand your world

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई – 400 013

क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लिमिटेड; विशेष परिचालन विभाग, भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग आईटीओ, नई दिल्ली 110002

ई–नीलामी बिक्री सूचना – अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक ई–नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक के पास बंधक अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों)/बंधककर्ता(ओं)/गारंटीदाता(ओं) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना(ओं) के अनुसरण में निम्नलिखित ऋण खाते में नीचे उल्लिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है, जिसका उद्देश्य बैंक के बकाये तथा ब्याज एवं अन्य खर्चों, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, की वसूली के लिए इसे "जहां है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है वहां है तथा बिना किसी अधिकार–दावे के आधार पर" बेचने के अधिकार के साथ है। तथा बकाये का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्ति की बिक्री द्वारा बैंक के बकाये की वसूली करने का प्रस्ताव करते हैं। अधोहस्ताक्षरी ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, एक्सिस बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (यस बैंक लिमिटेड का समनुदेशिती), पंजाब नैशनल बैंक (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का इसमें विलय), एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड (स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का समनुदेशिती) तथा इंडसइंड बैंक, जो सभी प्रतिभूत ऋणदाता हैं, जिनके साथ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड उक्त संपत्ति पर धारा 13(9) के अंतर्गत सम–परिमाण प्रभार साझा करता है, द्वारा उनकी ओर से प्रतिभूति हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्रवाई करने तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। नीचे उल्लिखित संपत्ति की बिक्री वेब पोर्टल : https://www.bankeauctions.com के माध्यम से ई–नीलामी के द्वारा आयोजित की जाएगी।

अचल संपत्ति का विवरण/खाते के विवरण/राशि/ईएमडी/इत्यादि

शाखा तथा खाता/ऋणधारक का नाम	संपत्ति के बंधककर्ता तथा गारंटीदाताओं का नाम	संपत्ति के विवरण	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार राशि: प्रतिभूत ऋणदाता	सूचना की तिथि	सूचना के अनुसार मांगी गई राशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	निरीक्षण तिथि तथा समय : 01/10/2026, अपराह्न 12:30 से 02:30 बजे
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दिल्ली मैसर्स कॉम्पैक्ट लैम्प्स प्राइवेट लिमिटेड – परिसमापन के अंतर्गत	बंधककर्ता / गारंटीदाता : श्री कपिल गुप्ता गारंटीदातागण : श्रीमती सोनिया कपिल, मैसर्स डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैसर्स कनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड – परिसमापन के अंतर्गत	प्लाट नं. ई, औद्योगिक क्षेत्र पीपलसाना, रामनगर, उत्तराखंड में स्थित कारखाना भूमि तथा भवन, भूमि क्षेत्रफल 62584 वर्ग फीट।	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	06–मार्च–2019	रू.41,00,57,449.05	रू.4,55,00,000/– रू.45,50,000/– रू.1,00,000/–	ई–नीलामी की तिथि/समय : 15/10/2026, पूर्वाह्न 10:30 बजे से 11:30 बजे
			आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	30–अप्रैल–2019	रू.14,77,23,290.83		
			एक्सिस बैंक लिमिटेड	27–फरवरी–2019	रू.19,62,74,864.97		
			यस बैंक लिमिटेड	12–जून–2019	रू.20,99,04,059.71	बोलियां प्राप्ति की अंतिम तिथि : 13/10/2026 अपराह्न 4:00 बजे तक	
			यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	14–सितंबर–2018	रू.19,01,52,888.24		
			स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	06–जुलाई–2020	रू.25,55,94,161.90	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नंबर/ईमेल आईडी : श्री अनिरुद्ध भार्गव, मोबाइल : 8802112088, anirudh.bhargav@hdfc.bank.in	
			इंडसइंड बैंक लिमिटेड	20–जनवरी–2020	रू.32,14,68,144.00		
			मांग सूचनाओं के अनुसार कुल राशि		रू.173,11,74,858.70		

नियम तथा शर्तें :–

1. ई–नीलामी **"जहां है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है वहां है तथा बिना किसी अधिकार–दावे के आधार पर"** आयोजित की जा रही है।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को अपने ईएमडी का विवरण तथा दस्तावेज वेब पोर्टल : https://www.bankeauctions.com के माध्यम से (यूजर आईडी तथा पासवर्ड https://www.bankeauctions.com पर नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से जमा करने होंगे। ईएमडी का भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाते में देय होगा : खाता संख्या : 57500000904261, खाते का नाम : DFSO TRANSITORY ACCOUNT, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईएफएससी कोड : HDFC0000240 अथवा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से खाता संख्या 57500000904261 में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को या उससे पूर्व अपराह्न 4.00 बजे तक जमा किया जाना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि चेक ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इच्छुक बोलीदाताओं को केवाईसी दस्तावेज अर्थात् पैन कार्ड की प्रति; पहचान का प्रमाण/पते का प्रमाण (केवाईसी) अर्थात् मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड आदि की स्व–सत्यापित प्रति जमा करना आवश्यक है तथा सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज साथ लाना चाहिए।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार, यहां संपत्ति के संबंध में बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार प्रकट किए गए वैधानिक बकाये जैसे संपत्ति कर, सोसाइटी बकाया, बिजली बकाया आदि के अलावा कोई विबंध या दावे नहीं हैं। हालांकि, बैंक किसी भी बकाया वैधानिक बकाये/विबंध/नगर निगम के बकाये/रखरखाव शुल्क/बिजली बकाये, शुल्क/कर बकाये आदि, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा यह पूरी तरह से क्रेता का उत्तरदायित्व होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को बोली जमा करने से पूर्व विबंधों, रखरखाव शुल्क, भूमि–उपयोग, संपत्ति के अधिकार–स्वामित्व आदि के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए तथा स्वयं निरीक्षण करके संतुष्ट होना चाहिए। एक बार बोली जमा हो जाने के पश्चात, यह मान लिया जाएगा कि इच्छुक बोलीदाता ने संपत्ति के संबंध में सभी पहलुओं से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।
4. संभावित बोलीदाता/नीलामी क्रेता को नीलामीधीन संपत्ति के संबंध में सभी मुकदमों का संज्ञान लेना चाहिए, जिसमें ऋण वसूली अधिकरण या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष दायर प्रतिभूतिकरण आवेदन, यदि कोई हो, शामिल है। उसे नीलामीधीन संपत्ति के संबंध में सभी मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए तथा बोली जमा करने से पूर्व इसका संज्ञान लेना चाहिए। यदि न्यायालय/अधिकरण, वैधानिक प्राधिकारी, सरकारी एजेंसियों द्वारा पारित किसी आदेश/निर्देश के कारण नीलामी या बिक्री को रद्द करने की आवश्यकता होती है तथा प्राधिकृत अधिकारी को बिक्री की प्राप्तियों या ईएमडी को वापस/लौटाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में कोई ब्याज या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यदि इस नीलामी/बिक्री के संबंध में नीलामी क्रेता या सफल बोलीदाता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या बैंक के विरुद्ध किसी कानूनी मामले/कार्रवाई के कारण कोई क्षति होती है, तो ऐसी स्थिति में वे प्राधिकृत अधिकारी या बैंक को हुई क्षति की सीमा तक क्षतिपूर्ति करेंगे।
5. संपत्ति का निरीक्षण केवल ऊपर उल्लिखित तिथि तथा समय पर ही किया जा सकता है।
6. जिन इच्छुक बोलीदाताओं ने ईएमडी जमा कर दी है तथा उन्हें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 301, गल्फ पेट्रो केमिकल बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज 2, गुड़गांव से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर : 0124–4302020/21/22/23/24, श्री मिथिलेश कुमार, मोबाइल : 7080804466, हेल्पलाइन ईमेल आईडी : support@bankeauctions.com** तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय समय **(पूर्वाह्न 10 बजे से सायं 5 बजे) के दौरान ऊपर उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।**
7. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा किसी विशिष्ट संपत्ति, संपत्तियों की संख्या या सभी के संबंध में नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.hdfc.bank.in तथा www.bankeauctions.com देखें)

तिथि : 07-09-2026, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड